JAGRAN Josh
Simplifying Test Prep

www.jagranjosh.com

करेंट अफेयर्स
दिसंबर 2015

पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2015

राज्यसभा द्वारा जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 पारित

- ✔ चीन की युआन एलिट रिजर्व मुद्रा के रूप में शामिल
- ✔ डेंगवक्सिया : दुनिया का पहला डेंगू का टीका
- ✔ पीपीपी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट
- ✔ साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015
- ✔ एंजेला मार्केल : टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015

प्रस्तावना 22

विशेष 24

पेरिस जलवायु शिखर सम्मलेन: जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर पेरिस संधि की घोषणा 24

सीओपी 21 ने यूएनएफसीसीसी के अधीन पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को स्वीकार किया 26

विश्व बैंक ने शॉक वेव्स : मैनेजिंग द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पोवर्टी नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की 27

पेरिस जलवायु शिखर सम्मलेन एवं भारत: संक्षिप्त समीक्षा 30

यूएनडीपी ने वर्ष 2015 की मानव विकास रिपोर्ट जारी की 32

राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 को मंजूरी दी 36

जिम्बॉब्वे ने चीनी मुद्रा युआन को आधिकारिक तौर पर अपनाने की घोषणा की 37

मेक्सिको ने विश्व के पहले डेंगू टीके को मंजूरी प्रदान की 38

पीपीपी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट जारी 39

वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा 41

जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल बनीं टाइम 'पर्सन ऑफ द ईयर' 43

इसरो ने पीएसएलवी-सी29 द्वारा सिंगापुर के छः उपग्रहों का प्रक्षेपण किया 43

अंतरराष्ट्रीय 45

ब्रिक्स देशों के बीच ब्रिक्स संघ विश्वविद्यालय के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर का अनुमोदन 45

जापान और दक्षिण कोरिया के बीच 'कम्फर्ट वीमेन' विवाद समाप्त हुआ 45

रूस ने कामोव 226टी हेलीकाप्टर बनाने के लिए एचएएल के साथ समझौता किया 46

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत एवं कनाडा के बीच समझौते का नवीनीकरण 47

चीन ने पहला आतंकवाद रोधी कानून पारित किया 47

चीन ने किया संशोधन नए साल से दो बच्चे पैदा करने की छूट 48

ओपेक ने 2015 ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक जारी किया 50

लीबिया एकता समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन, 30 दिनों में लागू करने का अनुरोध 51

सलमा बांध के निर्माण की संशोधित लागत को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी.....52
ब्रुनेई में क्रिसमिस मनाये जाने पर प्रतिबन्ध.....53
डेंगू के टीके को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना फिलिपीन्स.....53
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने तालिबान पर लगे प्रतिबंधो को विस्तारित किया.....54
नेपाल सरकार मधेसियों की समस्या हल करने हेतु संविधान में संशोधन के लिए सहमत.....54
यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध की अवधि को छह महीने बढ़ाया.....55
अमेरिकी सीनेट द्वारा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने हेतु आईएमएफ के सुधारों को स्वीकृति.....56
10वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने नैरोबी पैकेज अपनाया 57
विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड रेमिटेंस फैक्टबुक 2016 जारी किया 58
डब्ल्यूटीओ ने 163वें सदस्य के तौर पर अफगानिस्तान की सदस्यता शर्तों को मंजूरी दी.....60
संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद राष्ट्रीय एकता सरकार पर लीबियाई राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 60
आईएलओ ने ग्लोबल इस्टिमेट्स ऑन माइग्रेट वर्कर्स जारी किया 61
वर्ष 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा.....64
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से आईएस की धन की आपूर्ति रोकने का फैसला किया 65
भारत संयुक्त राष्ट्र के आपात प्रतिक्रिया कोष में पांच लाख डॉलर का योगदान देगा.....66
भारत और स्पेन के बीच बंदरगाह मामलों में सहयोग हेतु समझौते पत्र को मंजूरी 66
आतंकवाद के विरुद्ध सऊदी अरब ने की 34 देशों के गठबंधन की घोषणा.....67
भारत और जापान ने 16 दस्तावेजों के आदान-प्रदान सहित असैन्य परमाणु ऊर्जा पर समझौता किया.....68
आईएईए ने ईरान परमाणु कार्यक्रम पर 12 वर्ष लम्बी जांच समाप्त की.....70
भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन समझौते पर हस्ताक्षर.....70
सउदी अरब में पहली बार महिलाओं ने स्थानीय निकाय चुनावों में जीत दर्ज की.....71
भारत एवं जापान के बीच दोहरे कराधान समझौते में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर...72
संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीन में प्रताड़ना के खिलाफ अपील जारी.....74

यूएन ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के लिए 'साहेल ह्यूमेनिटेरियन अपील फॉर 2016' का शुभारम्भ किया....75
वर्ष 2016 को इंग्लैंड-भारत शिक्षा अनुसंधान एवं नवाचार वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया....76
अमेरिकी सदन ने वीजा वीवर प्रोग्राम इंप्रूवमेंट एक्ट ऑफ 2015 को पारित किया....77
ओप्पोसीशन डेमोक्रेटिक यूनिटी राउंड टेबल ने वेनेजुएला संसद चुनाव में जीत दर्ज की....78
न्यूजीलैंड औपचारिक रूप से एआईआईबी का नया सदस्य बना....79
बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए परिवर्तनकारी कार्बन एसेट सुविधा शुरू की गयी....80
भारत को कनाडा से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त....81
चीन के बिजली संचालित पहले विमान आरक्स1 ई (RX1E) के उत्पादन को मंजूरी दी....81
अमेरिकी सेना में सभी लड़ाकू भूमिकाएं निभाएंगी महिलाएं....82
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीजा सुविधा पर भारत और ईरान के बीच समझौता करने को मंजूरी दी....83
आईएमएफ ने चीन की मुद्रा युआन को विशिष्ट वर्ग आरक्षित मुद्रा के रूप में मंजूरी दी....84
भारत और फ्रांस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारम्भ....87
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा हेतु भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी....88
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान के साथ डीटीएसी समझौते को मंजूरी प्रदान की....88
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग पर इजरायल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी....89
जर्मनी की कैबिनेट ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ सैन्य सहायता को मंजूरी दी....90
रोच मार्क क्रिस्टियन काबोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति निर्वाचित....90
ब्रिक्स देशों का पहला मीडिया शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित....91
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर नयी पहल आरम्भ की....92

राष्ट्रीय....93
केंद्र सरकार ने छतों पर सौर पैनल के लिए 5000 करोड मंजूर किए....93
राष्ट्रीय पुस्तकालय को संस्कृति मंत्रालय द्वारा 400 करोड़ रूपये की मंजूरी....94
शहरी विकास मंत्रालय और ब्लूम्बर्ग फिलेंथ्रोपीज़ के बीच स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु समझौते को मंजूरी....96

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-2020 का शुभारम्भ.....97
केरल सरकार के शराब बिक्री नियमन पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति.....98
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए मंजूरी प्रदान की.....99
केंद्र सरकार द्वारा दस लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर एलपीजी सब्सिडी नहीं देने का निर्णय.....100
भारत पेट्रोलियम की नई क्रूड डिस्टीलेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित.....101
कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में 99 प्रतिशत मतदान का राष्ट्रीय रिकार्ड बना.....102
केंद्र सरकार ने चार आईटी-आधारित स्वास्थ्य सेवा पहलों की घोषणा की.....102
उत्तर भारत के पहले केबल पुल का जम्मू-कश्मीर के बसोहली में उद्घाटन.....103
लोकसभा द्वारा बोनस भुगतान संशोधन विधेयक-2015 को मंजूरी दी गयी.....104
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों के लिए दो मोबाइल एप्प लांच किए.....105
सीसीईए ने मत्स्य पालन हेतु 3000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी प्रदान की.....106
पर्यावरण मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कठोर मानकों को अधिसूचित किया.....107
राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 लोकसभा में पारित.....108
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर 6ठे अखिल भारतीय सर्वे का लोकार्पण किया 109
एलएनजी पोत बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया.....109
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2014-15 जारी.....111
राज्यसभा द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक-2015 पारित.....113
गुजरात झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए पीपीपी परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना.....115
सरकार ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टॉल फ्री 'आईवे नेशनल हेल्पडेस्क' आरंभ किया.....116
रक्षा मंत्रालय ने मेकइनइंडिया डिफेंस डॉट कॉम का शुभारम्भ किया.....116
यूएसएफ ने राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम स्नातकोत्तर फैलोशिप आरम्भ की.....117
डीएसी ने रूसी एस-400 ट्रिउम्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी 118
लोकसभा में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 पारित.....119

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरटीआई पर सूचना देने के लिए जवाबदेह: सर्वोच्च न्यायालय.....119
रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के मध्य विवाद सुलझाने हेतु शाह समिति का गठन.....120
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए संशोधित मॉडल टेक्स्ट को मंजूरी दी 120
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ब्रिक्स के साथ उर्जा संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी.....122
विश्व बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी.....122
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई.....123
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांर्डस सम्मेलन की अध्यक्षता की.....123
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का 26 वां सम्मेलन विजयवाड़ा में आयोजित.....124
लोकसभा ने परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया.....125
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए सेवाओं के लिए पुनर्निर्मित वेबसाइट आरंभ की.....126
केंद्र सरकार ने 'ऑपरेशन स्माइल-द्वितीय' शुरू करने की घोषणा की.....127
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को स्थायी और सांविधिक निकाय बनाने की सिफारिश.....127
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 'भारत के राष्ट्रपति की वेबसाइट' पर बच्चों के खंड का आरंभ.....128
भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट: पोषण 2015 जारी.....129
म्यांमार ने यांगून स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन किया.....130
मानव तस्करी रोकने के लिए केंद्र बनाएगा जांच एजेंसी.....131
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण उद्योग के लिए 4000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी.132
भारतीय न्यास संशोधन विधेयक-2015 लोकसभा में पारित.....133
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2015 को मंजूरी दी.....133
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी.....135
कानपुर में प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौता.....136
लोकसभा में परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तावित.....136
परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक-2015 राज्यसभा में पारित.....137
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांगों की श्रेणी में रखने का निर्देश.....138
देश की पहली डबल डेकर गोवा-मुंबई शताब्दी रेलगाड़ी शुरू.....139

भारतीय मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय मानक निकाय बनाने के लिए विधेयक पारित.....139
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश एन्क्लेव के लिए पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी 141
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नए आईआईटी को मंजूरी प्रदान की.....141
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'ज्ञान' योजना का शुभारम्भ.....142
केंद्र सरकार ने आईपीवी इंजेक्शन का शुभारंभ किया.....143

अर्थव्यवस्था.....144
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर दीपक मोहंती समिति की मध्यावधि पथ संबंधी रिपोर्ट जारी की.....144
आरबीआई ने विदेशी मुद्रा मामलों पर भारत में स्टार्ट- अप के मार्गदर्शन हेतु समर्पित हेल्पलाइन बनाई.....145
वित्त वर्ष 2015-16 में आयकर दाताओं की संख्या में 27 लाख की वृद्धि.....146
अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की 146
केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाकर 400 डॉलर प्रति टन किया.....147
सार्वजनिक ऋण में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि.....147
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर शीर्ष पर.....149
एनटीसी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता किया.....149
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु विश्व के उद्योगपतियों ने समझौता किया.....150
एक्सिस बैंक द्वारा देश के पहले डिस्प्ले डेबिट कार्ड का शुभारम्भ.....151
सरकार ने पीएफ निकालने में ख़त्म किया नियोक्ता का हस्तक्षेप.....151

पर्यावरण पारिस्थितिकी.....153
12 करोड़ साल पुराने टिड्डे का जीवाश्म मिला.....153
पश्चिम बंगाल के तट पर ईल की नई प्रजाति जिमनोथोरेक्स मिश्रई खोजी गई.....153
म्यांमार के पहले यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 'इन्ले झील' का शुभारंभ.....154
फिलिपींस में 'मेलर तूफान' के कारण नौवहन बंद और अलर्ट जारी.....155
यस बैंक द्वारा क्लाइमेट एक्शन के लिए 2020 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यवस्था की

घोषणा.....155
प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में प्रस्तावित सम - विषम नंबर प्लेट योजना.....157
भारत ने 8 विभिन्न बायोम्स को मॉनिटर करने हेतु आईएलटीईओ कार्यक्रम आरंभ किया.....160
बीजिंग में पहली बार वायु प्रदूषण पर रेड अलर्ट जारी.....161
100 मिलियन हेक्टेयर वन की पुनर्स्थापना के लिए अफ्रीकन रेस्टॉरेशन इनिशिएटिव का शुभारम्भ 162
उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुआ राज्य का पहला 'बर्ड फेस्टिवल'.....163
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु विश्व के उद्योगपतियों ने समझौता किया.....163
स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को गति देने के लिए मिशन इनोवेशन का शुभारंभ.....164

विज्ञान तकनीक.....166
ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सांप की प्रजातियां एपिसुरुस फोलियोस्क्वामा और एपीसुरुस एप्रीएफ्रॉन्टालिस की पुनः खोज 166
पेंडोरम टेक्नोलॉजी ने 3 डी प्रिंटिंग का उपयोग करते हुए भारत का पहला कृत्रिम वृक्क ऊतक विकसित किया.....167
विश्व में 3डी तकनीक के उपयोग से कृत्रिम वृक्क का विकास.....168
चीन ने डीएएमपीई उपग्रह का प्रक्षेपण किया.....168
स्पेस एक्स ने फेल्कन 9 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण और अवतरण किया.....169
भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर को अमेरिकी सेना से सौर पैनल पर अनुसंधान और विकास हेतु अनुबंध प्राप्त.....170
एंटी-कैंसर अणुओं की खोज.....170
एटलस वी रॉकेट सिग्नस कार्गो अंतरिक्ष यान आईएसएस के लिए लांच.....171
क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए संसद में जैव प्रौद्योगिकी विधेयक 2015 पारित 172

खेल खिलाड़ी.....174
ब्योर्न इज़बर्ग 2016 की हॉकी इंडिया लीग के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर नियुक्त.....174
लक्ष्मी रतन शुक्ला का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा.....176

ग्लोब फ़ुटबॉल पुरस्कार 2015.....177
गुजरात ने दिल्ली को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता.....178
गोल्फर एस चिक्कारंगाप्पा ने मैक्लोरॉड रासेल टूर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता.....179
भारत के ल्यूज खिलाड़ी शिवा केशवन ने एशियाई लूज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता.....179
मुंबई गरूड़ ने हरियाणा हैमर्स को हराकर प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्केरण का खिताब जीता.....180
फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का ख़िताब जीता.....181
ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 शतक बनाने वाली पहली टीम बनीं.....182
एंटी-डोपिंग टेस्ट में पॉज़ीटिव पाए जाने के बाद पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह निलंबित...183
विकास ठाकुर ने भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया.....184
संजीता, रमन्ना को राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल.....184
पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी कर्नल सी के नायडू पुरस्कार के लिए चयनित.....185
योनेक्स ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न.....187
माइकल ब्रैडली अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबाल खिलाड़ी घोषित.....187
स्टीव स्मिथ वर्ष 2015 के आईसीसी क्रिकेटर ऑफ़ द इयर चुने गए.....188
सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी महिला युगल विश्व चैम्पियन घोषित.....189
सेरेना विलियम्स और जोकोविच 2015 आईटीएफ विश्व चैंपियन बनें.....190
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने की सन्यास की घोषणा.....190
श्रीलंका पर आसान जीत के साथ ट्राई सीरीज पर भारतीय अंडर-19 का कब्जा.....191
फेड कप में भारत का नेतृत्व करेंगी सानिया मिर्ज़ा.....192
अंडर-19 विश्वकप में इशान किशन बने भारत के कप्तान.....193
अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने सेप ब्लेटर और माइकल प्लातिनी पर आठ वर्ष का प्रतिबंध लगाया.....193
दारियास चेनाई ने 59वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरूषों की ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता.....194
अभय सिंह ने जीता सिंगापुर ओपन का खिताब.....195
युजेंसन लिंगदोह और बाला देवी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में सम्मानित.....195
आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले पहले कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन बने.....196

फुटबॉल क्लब बार्सीलोना ने फीफा क्लब विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट का खिताब जीता.....197
सिंगापुर स्लैमर्स ने अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग 2015 का खिताब जीता.....197
चेन्नईयन एफसी ने एफसी गोवा को हराकर इंडियन सुपर लीग खिताब जीता.....198
सुनील जोशी ओमान टीम के गेंदबाजी कोच नियुक्त.....199
डैन कार्टर वर्ष 2015 के 'बीबीसी ओवरसीज़ स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी ऑफ़ द इयर' चुने गए.....200
भारतीय पुरुष टीम ने 20वीं अवध राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण.....200
ग्रीक टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर जेकुपोविक पर लगा आजीवन प्रतिबंध.....201
मनोज प्रभाकर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त.....202
हॉकी इंडिया लीग का प्रायोजक होगा कोल इंडिया लिमिटेड.....202
रोरी मैक्लराय ने यूरोपियन टूर गोल्फर आफ द ईयर का खिताब जीता.....203
शिवा, मंदीप एवं अन्य चार भारतीय मुक्केबाज आईओसी छात्रवृत्ति हेतु चयनित.....203
अपूर्वी चंदेला और चैन सिंह ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता.....204
खेल पत्रिका स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने सेरेना विलियम्स को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना.....205
जापान की नोजोमी ओकुहरा, केंटो मोमोता ने वर्ल्ड दुबई सुपर सीरीज फाइनल का एकल खिताब जीता.....206
विजय कुमार ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता.....207
आईसीसी ने वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी मलरेन सैमुअल्स को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया 208
देबोरा हेरल्ड विश्व रैंकिंग में भारत की पहली और विश्व की चौथी साइकिल चालक बनीं.....208
एलिज़ाबेथ कोशी ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता.....209
आईसीसी टी-20 विश्वकप 2016 का कार्यक्रम घोषित.....209
चेन लॉन्ग एवं कैरोलिना मरीन ने वर्ष 2015 का बीडब्ल्यूएफ प्लेयर अवार्ड जीता.....211
महेला जयवर्धने एमसीसी के मानद आजीवन सदस्य के रूप में चयनित.....212
रोहित शर्मा प्रो रेस्लिंग लीग में यूपी वरियर्स के सह-मालिक बनें.....213
अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने टायसन फ्यूरी से विश्व आईबीफ खिताब वापस लिया.....214
स्पेन की कैरोलीन बनीं साल की सर्वश्रेष्ठ महिला बैडमिंटन खिलाड़ी.....214
क्रिसन इल्युमज़िनोव ने विश्व शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया.....215

भारत के शीर्ष टेस्टक बल्ले बाज बने अजिंक्यं रहाणे....215
फीफा रेफरी एसके भट्टाचार्य का निधन....216
अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने टायसन फ्यूरी से विश्व आईबीफ खिताब वापस लिया....217
पंजाब मार्शल टीम ने चैपियंस टेनिस लीग-2015 का ख़िताब जीता....217
प्रीमियर बैडमिंटन लीग हेतु खिलाडियों की नीलामी में साइना और ली चोंग वेई सबसे महंगे खिलाड़ी बनें....218
आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने गैरी कर्स्टन को मुख्य प्रशिक्षक पद से हटाया....218
भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया....219
ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी विश्व लीग फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराया....220
भारत ने जीता इंडो-पाक निःशक्त क्रिकेट सीरीज....220
बुब्बा वाटसन हीरो वर्ल्ड चैलेंज चैम्पियन बने....221
वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल: भारत ब्रिटेन को 2-1 से हराकर, सेमीफाइनल में पहुंचा....221
अमिताभ बच्चन बने आईपीटीएल की सिंगापुर स्लैमर्स के सह-मालिक....222
रॉबर्ट लेवांडोवस्की को नौ मिनट में पांच गोल करने पर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया....222
डोपिंग रोधी एजेंसी में सुधार हेतु रूस और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) सहमत हुए....223
अनिल कुंबले का मुंबई इंडियंस के 'चीफ मेंटर' पद से इस्तीफा....224

कार्पोरेट....225
मांग पर किराना सेवा देने वाले पेपरटैप ने जिफ्फस्टोर का अधिग्रहण किया....225
अमेरिकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी अरिसेंट ने नैसकॉम फाउंडेशन के साथ समझौता किया....226
बायोकॉन लिमिटेड ने भारत में हेपेटाइटिस-सी दवा का जेनेरिक संस्करण लांच किया....226
टेक महिंद्रा ने एनएफसी आधारित मोबोमनी की शुरुआत की....227
सत्यवती बरेरा बिग फोर समूह की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त....228
विप्रो ने अमेरिकी कंपनी विटिओस का अधिग्रहण करने की घोषणा की....230
आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग हेतु आईआरसीटीसी के साथ गठबंधन किया....230
पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने पांच ब्रांड्स का अधिग्रहण किया....231

भारतीय रेल आईआईटी के साथ शोध केंद्र स्थापित करेगा.....232
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में पांच हजार करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी 232
मेक इन इंडिया: विवो ने ग्रेटर नोएडा में पहला प्रोडक्शीन प्लां ट लगाया.....233
ग्रॉसरी शॉपिंग सेवा पेपरटेप ने बेंगलुरु की डिलीवरी स्टार्टअप जिफसौर का अधिग्रहण किया.....233
आरकॉम और एयरसेल वायरलेस बिजनेस का विलय करेंगी.....234
रॉनी स्क्रूवाला की कम्पनी एर्री ने अपाल्या टेक्नोलॉजीज़ का अधिग्रहण किया.....235
टाटा मोटर्स शोध एवं विकास में निवेश के मामले में दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों की सूची में शामिल.....236
सीआईआई औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2015.....237
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इंदुलेखा का अधिग्रहण करने हेतु मोसंस समूह के साथ समझौते किया..238
सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2015.....239
रिलायंस एंटरटेनमेंट और स्टीवेन स्पिलबर्ग के मध्य करार.....239
फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2015 में व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची जारी की.....239
खाद्य भुगतान के लिए आईआरसीटीसी और पेटीएम के मध्य समझौता.....241
स्नैपडील ने हिंदी एवं तेलगु में मोबाइल वेबसाइट आरंभ की.....241
नैटको, हेटेरो को हेपेटाइटिस सी की जेनेरिक दवा बाजार में लाने की मंजूरी 242
दी.....242
जगुआर लैंडरोवर, स्लोवाकिया में एक अरब पाउंड निवेश करेगी.....244
टेक महिंद्रा एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिनिनफेरिना का अधिग्रहण किया.....245
इनफ़ोसिस ने “स्टार्टअप” में 20 करोड़ रुपए निवेश किया.....246
हैवेल्स ने सिल्वेनिया को बेचा 80 फीसदी हिस्सा.....247
भारत फोर्ज रॉल्स रायस को इंजन के कलपुर्जे की आपूर्ति करेगी.....248
मोबाइल कंपनी ओप्पो आईसीसी की ग्लोबल पार्टनर बनी.....248
फीफा क्लब विश्व कप और अलीबाबा ई-ऑटो के मध्य समझौता.....249
फेसबुक ने भारत में स्थापित की लघु एवं मध्यम उपक्रम परिषद.....249
टेक महिंद्रा, फोर्ब्स पुरस्कार से सम्मानित.....250

ऑनलाइन नि: शुल्क शिक्षा के लिए टाटा ट्रस्ट ने खान अकादमी के साथ समझौता किया.....250
जॉय बांदेकर ओला के कॉरपोरेट अध्यक्ष नियुक्त.....251
ओला ने किया दुनिया की चार दिग्गज कंपनियों के साथ करार.....252
टाटा समूह ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चायना लिमिटेड (आईसीबीसी) के साथ समझौता किया.....253
फ्लिप्कार्ट ने मैपमायइंडिया में हिस्सेदारी खरीदी.....253
अमेरिकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी अरिसेंट ने नैसकॉम फाउंडेशन के साथ समझौता किया.....254
उबेर ने विकलांगों के लिए उबेरअसिस्ट सेवा शुरु की.....254
जहाज निर्माण सामग्री सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त.....255
आईसीबीसी बना टाटा समूह का रणनीतिक सहयोगी.....255

राज्य.....257
आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रौद्योगिकी पहल हेतु माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.....257
राज्यपर्यटकों का पसंदीदा राज्य बना उत्तरप्रदेश: एसोचैम.....258
डिजिटल सेवाएं: देश में छत्तीसगढ़ प्रथम, 28 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार.....259
मानव मूत्र से पैदा की जा सकेगी बिजली.....260
प्रदूषण नियंत्रण हेतु पटना में प्रतिबंधित की जाएंगी 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां.....261
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना लागू करने का निर्णय लिया.....262
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण-1ए को मंजूरी दी.....263
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की.....264
फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और सांसद हेमामालिनी हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एंबेसडर नियुक्त 264
पर्यावरण नियंत्रण हेतु नोएडा-एनसीआर सात जोन में विभाजित.....265
डीडीसीए घोटाले पर दिल्ली सरकार ने गोपाल सुब्रह्मण्यिम आयोग बनाया 265
यूपी के विकास के लिए रतन टाटा और सीएम अखिलेश के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर....266
उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उदय योजना में शामिल हुआ.....267

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग पर लगाया प्रतिबन्ध.....268
मुख्यमंत्री ने लगभग 585 करोड़ की 148 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया.....269
छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 47.1 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत हुई.....269
ललित मोदी पुन: आरसीए अध्यक्ष नियुक्त.....270
अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित.....271
ऊर्जा संरक्षण के तहत उप्र सरकार ने नया पोर्टल शुरू किया.....272
राज्यपाल ने उप्र राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2015 को मंजूरी दी.....272
सीएम अखिलेश ने 45 अरब लागत की 105 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया.....274
वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त.....276
सड़क सुरक्षा पर राधाकृष्णन पैनल की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य बना दिल्ली.276
राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना.....277
पंचायत चुनाव हेतु हरियाणा सरकार के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति जताई....278
फ्रैंक इस्लाम को मिलेगा उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार.....279
राजस्थान में 126 मेगावाट की प्रतापगढ़ पवन परियोजना की शुरुआत.....280
महाराष्ट्र, विधानमंडल में ऑनलाइन प्रश्नों की अनुमति देने वाला देश का पहला राज्य बना.....280
आंध्र प्रदेश डिस्कॉम पुनरुद्धार योजना 'उदय' में शामिल होने वाला पहला राज्य बना.....282
झारखंड 'यूडीएवाई' योजना में शामिल.....283
हिमाचल प्रदेश रोटावायरस टीकाकरण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य 283
दिल्ली विधानसभा द्वारा विधायकों के वेतन में 400 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव पारित.....284
आर्थिक वृद्धि के मामले में बिहार सबसे आगे : ब्रिकवर्क रेटिंग्स रिपोर्ट.....285
झारखंड सरकार मत्स्य विकास निगम का गठन करेगी.....285
राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय 286
कारखाना अधिनियम, 1948 के संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी.....287
झारखण्ड सरकार ने पूर्ण राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया.....288
दिल्ली विकास प्राधिकरण ई-इंडिया पुरस्कार से सम्मानित.....288
दिल्ली सरकार ने ई-जिला परियोजना आरंभ की.....289

न्यूज कैप्सूल....290

चर्चित व्यक्ति....290

गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद मुख्य अतिथि होंगे....291

ठाकुर अनूप सिंह ने मिस्टर वर्ल्ड-2015 का खिताब जीता....292

नियुक्त....293

करण अडानी, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के सीईओ नियुक्त....293

अमिताभ कांत को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया....293

पवन कुमार अग्रवाल एफएसएसएआई के सीईओ नियुक्त....294

जेट एयरवेज़ ने अमित अग्रवाल को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया....295

जेफ विलियम्स एप्पल इंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) नियुक्त....295

पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर नए सीआईसी नियुक्त....296

न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल ने दिल्ली के लोकायुक्त पद की शपथ ली....297

वरिष्ठ राजनयिक अखिलेश मिश्रा मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त....297

अखिलेश मिश्रा मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त....298

ए के जैन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुख्य अधिकारी नियुक्त....298

भारतीय मूल के प्रवीण गोरधन दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री नियुक्त....299

अहमद जावेद सऊदी अरब के राजदूत नियुक्त....299

पीके सिंह सेल के चेयरमैन नियुक्त....300

काहेर काजेम जनरल मोटर्स (इंडिया) के प्रमुख नियुक्त....301

भारतीय मूल की अमेरिकी डॉ विजय एम राव आरएसएनए की अध्यक्ष नियुक्त....301

न्यायमूर्ति तीरथ सिंह (टीएस) ठाकुर ने भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली....302

विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए....302

सर वेंकटरमन रामकृष्णन ने रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया....303

रिपोर्ट | सर्वेक्षण 305

वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत: सीईबीआर रिपोर्ट 305

ग्रीनपीस ने 17 भारतीय शहरों के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया 306

कालाधन विदेश भेजने के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर: जीएफआई रिपोर्ट 306

डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक खाद्य जनित रोगों पर रिपोर्ट जारी की 307

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एचआईवी (एड्स) के प्रसार पर रिपोर्ट जारी 307

निधन 310

न्यूकैसल यूनाइटेड के पूर्व गोलकीपर पावेल सर्सिनेक का निधन 310

उत्तर कोरिया के प्रमुख सलाहकार किम यांग गोन का निधन 311

स्टार ट्रेक के लेखक जॉर्ज क्लेटन जॉनसन का निधन 311

कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएस मालिमत का निधन 312

जापान की पर्वतारोही केई तानीगुची की चढ़ाई करते वक्त गिरने से मौत 313

हिन्दी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना का निधन 313

ब्रिटिश उपन्यासकार पीटर डिकिंसन का निधन 314

प्रसिद्ध जर्मन कंडक्टर कर्ट मसूर का निधन 315

पूर्व माकपा सांसद नुरुल हुदा का निधन 315

उद्योगपति एमएएम रामास्वामी का निधन 316

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सैंडी बर्गर का निधन 316

सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान का निधन 317

कूडियाट्टम् कलाकार मार्गी साथी का निधन 317

पदमुक्त 319

टाटा स्टारबक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवानी दावदा ने इस्तीफा दिया 319

लातविया की प्रधानमंत्री लैमदोता स्ट्रौजुमा ने अपने पद से इस्तीफा दिया 319

कला | संस्कृति 321

'सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध महोत्सव 'लोसर' का लद्दाख क्षेत्र में शुभारम्भ 321

यूनेस्को ने वाराणसी और जयपुर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया 321

आईफा उत्सवम' चेन्नई में वर्षा के कारण स्थगित 323

46वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सम्पन्न 323

खोज | आविष्कार 325

अमेरिका और चीन के खोजी दल ने डायनासोर की नयी प्रजाति का पता लगाया 325

चर्चित स्थल 327

इंदौर: 15,000 से अधिक लोगों ने एक साथ साइकिल चलाकर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड 327

रक्षा-सुरक्षा 329

अस्त्र मिसाइल की महत्वपूर्ण एंटी जैमिंग क्षमता का सफल परीक्षण 329

भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस गोदावरी सेवानिवृत्त 329

भारत ने रूस से रक्षा प्रणाली खरीद समझौते को मंजूरी दी 330

पाकिस्तान ने शाहीन 1-ए प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया 332

भारतीय नौसेना की एलसीयू एमके 4 परियोजना के पांचवे पोत का जलावतरण 332

भारत-रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, इंद्रा नेवी-15, विशाखापत्तनम में आरंभ 334

पुरस्कार | सम्मान 336

भारतीय मूल के कैंसर विशेषज्ञ हरपाल सिंह कुमार नाइटहुड से सम्मानित 336

शाइमा कासिम अब्दुलरहमान मिस इराक 2015 चुनी गईं 337

फिलीपींस की पिया अलोंज़ो वर्त्ज़बैक मिस यूनिवर्स-2015 बनीं 337

मिस स्पेन मिरिया लालागुना रायो 'मिस वर्ल्ड 2015' चुनी गईं 338

एंडी मरे वर्ष 2015 के 'बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ़ द इयर' चुने गए 339

पति- पत्नी क्लाउड और नोर्मा अल्वारेस को 2015 सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित

किया गया 340
केयर्न इंडिया सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित.....341
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सार्वलौकिक नवाचार में उत्कृष्ट वैश्विक मागदर्शन के लिए गारवुड पुरस्कार से सम्मानित.....342
वायलिन वादक इत्जहक पर्लमैन ने जीता वर्ष 2016 का जेनेसिस पुरस्कार.....343
पश्चिम बंगाल सरकार ने बप्पी लाहिड़ी, कुमार सानू को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया.....344
अभिनेता दिलीप कुमार पद्म विभूषण से सम्मानित.....344
भारतीय मूल के लेखक जेएम साली ने 2015 साउथ ईस्ट एशियन अवार्ड फॉर सिंगापुर पुरस्कार जीता.....345
विप्रो ने आईओटी में नवाचार के लिए 2015 एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार जीता.....346
सलमान रुश्दी मेलर पुरस्कार से सम्मानित.....347
चार भारतीय शिक्षक 'वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2016' के लिए मनोनीत.....348
ब्रिटेन में दो भारतीयों ने जीता क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड.....349
नसीरुद्दीन शाह वर्ष 2015 के डीआईएफएफ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित.....350
एडिडास इंडिया के पुलिन कुमार प्रतिष्ठित आईएनबीए पुरस्कार से सम्मानित.....351
प्रख्यात वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम आईटीसी संगीत सम्मान से सम्मानित.....352
एंब्रेस ऑफ द सर्पेंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार.....352
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा डॉ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड प्रदान किये गये.....353
हिंदुजा ब्रदर्स को एशियन बिज़नेस लीडरशिप फोरम 2015 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया.....353

पुस्तक - लेखक.....355
द बोस ब्रदर्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस-एन इनसाइडर्स अकाउंट : माधुरी बोस.....355
शरद पवार की आत्मकथा "लाइफ ऑन माय टर्म्स" का विमोचन किया.....355
पूर्व पत्रकार अनुज धर द्वारा लिखित पुस्तक "व्हाट हैपेंड टू नेताजी ?" का विमोचन.....356
नंदन निलेकणी एवं विराल शाह द्वारा लिखित पुस्तक रीबूटिंग इंडिया का लोकार्पण.....357

राधा कांत भारती द्वारा लिखित इंटरलिंकिंग ऑफ़ इंडियन रिवर्स का लोकार्पण.....358

योजना | कार्यक्रम.....359

केंद्र सरकार ने शहरी नियोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु 42,000 करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी दी.....359

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा उद्योग के लिये संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को मंजूरी दी.....359

जलवायु परिवर्तन से संबंधित चार परियोजनाओं को मंजूरी.....361

वस्त्र मंत्रालय ने एनएचडीसी की ईआरपी प्रणाली की शुरुआत की.....362

देश के विश्वविद्यालयों में पटाखों से प्रदूषण पर होगी पढ़ाई.....363

कॉयर उद्यमी योजना: सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय की एक पहल.....364

केंद्र सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की.....365

भारतीय सेना ने 28 दिसंबर 2015 को 44वां नागी दिवस मनाया.....366

सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को संपूर्ण भारत में मनाया गया.....366

24 दिसंबर : राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस.....367

22 दिसंबर को 'राष्ट्रीय गणित दिवस' के रूप में मनाया गया.....368

विश्वस्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया.....369

देश भर में व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया.....370

16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया गया.....371

विश्वभर में मानवाधिकार दिवस मनाया गया.....372

नरसंहार पीड़ितों की गरिमा हेतु अन्तरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया.....373

भारत में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया गया.....374

विश्व स्तर पर मनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 374

4 दिसंबर को मनाया गया 44 वां नौसेना दिवस.....375

विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया.....375

विश्वस्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया.....376

प्रदर्शनी | मेला 378

भारतीय हथकरघा प्रदर्शनी का नई दिल्ली में शुभारंभ 378

राष्ट्रीय संग्रहालय की आर्ट गैलरी का शुभारंभ 378

प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईटी-दिल्ली में प्रारंभ 379

आयोग | समिति 380

दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार मामले की जांच हेतु एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया 380

वन रैंक वन पेंशन के लिए न्यायिक समिति का गठन 380

सुब्रमण्यन समिति ने रिपोर्ट में जीएसटी हेतु स्टैंडर्ड रेट लगाने की सिफारिश की 381

विज्ञान | अंतरिक्ष 382

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सिंगापुर के छह उपग्रहों को प्रक्षेपित किया 382

गेल ने पाइपलाइनों की निगरानी के लिए 'भूवन गेल पोर्टल' का शुभारम्भ किया 382

घटना | दुर्घटना 384

बीएसएफ का एक चार्टेड विमान सुपरकिंग दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त 384

सम्मलेन | बैठक 385

द्वितीय विश्व इंटरनेट सम्मेलन (डब्लूवाईसी) चीन के वुजेन शहर में संपन्न 385

एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों की 14वीं बैठक ज़ेंगज़ो, चीन में आयोजित 385

भारत-लाओस: अंतर-सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 386

11वें यूआईसी वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ 387

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें जागरण फोरम को संबोधित किया 387

विविध 389

नौकरशाहों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार प्रारंभ करने हेतु नए नियम की घोषणा

.....389
नमामि गंगे परियोजना हेतु जल संसाधन मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया.....389
बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के सम्मान में 125 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी 390
टीडीएस का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान 391

विश्व समसामयिकी दिसंबर 2015.....392
भारत समसामयिकी दिसंबर 2015.....402

प्रस्तावना

jagranjosh.com आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री दिसंबर 2015 माह में भारत एवं विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में घटित घटनाओं पर आधारित करेंट अफेयर्स दिसंबर 2015 ई-बुक उपलब्ध करा रहा है.

करेंट अफेयर्स दिसंबर 2015 ई-बुक (eBook) परीक्षा विशेषज्ञों द्वारा तैयार अद्यतन अध्ययन सामग्री विभिन्न विषयों/क्षेत्रों जैसे- राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, कार्पोरेट, आर्थिक, विज्ञान, तकनीक, खेल, पुरस्कार-सम्मान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, रिपोर्ट-सर्वेक्षण, पुस्तक-लेखक, चर्चित व्यक्ति आयोग-समिति, एवं चर्चित स्थल, आदि में घटित परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी घटनाओं पर आधारित अद्वितीय करेंट अफेयर्स का संकलन है.

करेंट अफेयर्स दिसंबर 2015 ई-बुक (eBook) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, एसएससी संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा, एसबीआई सहायक बैंक पीओ परीक्षा, आईबीपीएस पीओ परीक्षा, सीटीईटी परीक्षा, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2016 (एसएससी सीजीएल 2016) - टीयर 1 एवं टीयर 2, आदि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा भारतीय आर्थिक/सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2016, यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2016, भू-वैज्ञानी परीक्षा 2015, आदि हेतु अत्यंत उपयोगी करेंट अफेयर्स की अध्ययन सामग्री है.

करेंट अफेयर्स दिसंबर 2015 ई-बुक (eBook) के प्रतिदर्श (Preview or Sample) के माध्यम से आप इस ई-बुक की एक झलक पा सकते हैं.

करेंट अफेयर्स दिसंबर 2015 ई-बुक (eBook) में जिन प्रमुख घटनाओं को समाहित किया गया है उनमें से कुछ हैं:-

1. पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन : जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर पेरिस संधि की घोषणा
2. संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट 2015
3. चीन की युआन एलिट रिजर्व मुद्रा के रूप में शामिल

4. डेंगवक्सिया : दुनिया का पहला डेंगू का टीका

5 .पीपीपी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट

6. साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015

7. एंजेला मार्केल : टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015

कॉपीराइट ©Jagranjosh.com

सर्वाधिकार सुरक्षित. इस ई-बुक का कोई भी खण्ड या संपूर्ण ई-बुक को किसी भी रूप में (इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी भी अन्य माध्यम से) प्रतिलिपिकरण, पुनःप्रकाशन, पुनःप्राप्ति योग्य भण्डारण और किसी भी घटना, परिस्थिति और प्रणाली में उल्लेख तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि कॉपीराइट प्राप्तकर्ता से लिखित अनुमति न प्राप्त हो. यदि उपरोक्त में से कोई भी या संबंधित गतिविधि का कोई भी प्रमाण मिलता है या सूचित किया जाता है तो कड़ी दण्डात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

अस्वीकरण

पाठकों से विज्ञापन, एडवर्टोरियल या वाह्य सामग्री के संबंध में उचित व पर्याप्त जांच स्वयं संतुष्टि के स्तर तक अपेक्षित है. यदि इस ई-बुक में दी गयी किसी भी सूचना या संदर्भ से किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना, नुकसान, क्षति या कोई अनहोनी होती है तो इस संदर्भ में Jagranjosh.com के संपादक, मालिक, निदेशक/कों, कर्मचारियों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा. साथ ही, किसी भी विज्ञापन, एडवर्टोरियल या वाह्य सामग्री के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना, नुकसान, क्षति या अनहोनी के संबंध में भी समान अस्वीकरण लागू होगा.

विशेष

पेरिस जलवायु शिखर सम्मलेन: जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर पेरिस संधि की घोषणा

पृथ्वी को बचाने तथा पार्यवरण सुरक्षा के क्रम में पर्यावरण और विकास पर विश्व में कई सम्मलेन आयोजित किये गए. इस सन्दर्भ में 3 -14 जून 1992 रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) जिसे रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है बहुत प्रभावशाली सम्मेलन रहा. इसमें 172 सरकारों के 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया.गैर- सरकारी संगठनों के 2,400 प्रतिनिधियों के साथ ही "ग्लोबल फोरम" (फोरम ग्लोबल) के 17,000 लोगों ने इसमें भाग लेकर वैश्विक स्तर पर पृथ्वी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपनी प्रतिबद्धता जताई.ब्राज़ील में 1992 में हुए रियो पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संधि पर सहमति बनी जिसे 'युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज' या यूएनएफ़सीसीसी के नाम से जाना जाता है. पृत्वी के सतत विकास और पार्यवरण के मुद्दे को लेकर तथा धरती के बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने के लिए पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन 2015 में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर पेरिस संधि की घोषणा की गयी.

जल और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर पेरिस संधि की घोषणा

2 दिसंबर 2015 को विभिन्न देशों, नदी बेसिन संगठनों, व्यापार एवं नागरिक समाज के व्यापक गठबंधन ने जल और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर अंतरराष्ट्रीय पेरिस संधि के निर्माण की घोषणा की.

जलवायु परिवर्तन पर लीमा में पेरिस कार्रवाई एजेंडा के तहत आयोजित वाटर रीसाइलेंस फोकस इवेंट में यह घोषणा की गई. यह इवेंट पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 (सीओपी21) के मौके पर आयोजित किया गया.

पेरिस संधि की मुख्य विशेषताएं

- इसका उद्देश्य मानव विकास की नींव जल प्रणाली को जलवायु प्रभावों के मुकाबले अधिक लचीला बनाना

है.

- जल और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर बने पेरिस संधि के तहत 290 से अधिक जल बेसिन संगठन शामिल हैं.
- इसमें कई देश सीमा पार नदी बेसिन संगठन, सरकारें, वित्त पोषण एजेंसियां, स्थानीय सरकारें, कंपनियां और नागरिक समाज शामिल हैं.
- इसमें अनुकूलन योजना को लागू करने, जल निगरानी और नदी घाटी में माप प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया हैं.
- यह वित्तीय स्थिरता और जल प्रणाली प्रबंधन में नए निवेश को बढ़ावा देता है.

संधि के तहत प्रमुख सहयोगी परियोजनाएं तकनीकी सहायता में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक और वित्त पोषण में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनमें शामिल हैं-

उन्नत भूजल प्रबंधन के माध्यम से भारत का जलवायु लचीलापन बनाने की वित्तीय प्रतिबद्धता.

नाइजर बेसिन ने (9 अफ्रीकी देश शामिल हैं) जलवायु परिवर्तन में लचीलापन को मजबूत बनाने के लिए दस वर्ष का निवेश योजना शुरु किया. इसके लिए विश्व बैंक/ आईडीए, डब्ल्यूएईएमयू,

केएफडब्ल्यू, जीईएफ और इन देशों ने खुद वित्तीय समर्थन दिया है.

जॉर्डन, लेबनान, मोनाको, मोरक्को, स्पेन और ट्युनीशिया में 7 वर्षीय भूमध्यसागीय जल मंच के तहत प्रतिबद्धता की गई है ताकि जल संसाधनों की स्थिति और प्रकृति को समझा जा सके. इसे यूरोपीय आयोग का समर्थन प्राप्त है.

पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील और कोलंबिया में इकोक्युएनकास, यूरोपीय आयोग द्वारा समर्थित नदी घाटियों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए वित्तीय तंत्र की 3 वर्ष की प्रतिबद्धता.

चीन में फ्रांस समर्थित हाई नदी घाटी में प्रंबधन में सुधार के लिए 3 वर्ष की प्रतिबद्धता.

मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन में, हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत ताकि 160 मिलियन से अधिक नागरिकों को लाभ मिल सके.

सीओपी 21 ने यूएनएफसीसीसी के अधीन पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को स्वीकार किया

कांफ्रेस ऑफ़ द पार्टीज़ 21 (सीओपी) ने 12 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को स्वीकार किया जिसमें 192 देशों ने भाग लिया. भारत की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस सम्मेलन में मौजूद थे.

यह समझौता क्योटो प्रोटोकॉल के अतिरिक्त वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता है.

प्रत्येक सदस्य के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान के तहत इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था जिसमें भारत की भी अहम भूमिका है.

समझौते में विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों में इक्विटी के सिद्धांत एवं समान जिम्मेदारियों और क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है.

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता

- उद्देश्य: इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य विश्व के बढ़ते तापमान को 2 डिग्री से कम पर रोकना है.
- यह प्रयास किया जाएगा कि तापमान 1.5 डिग्री पर रोक लिया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन के अन्य खतरों से निपटा जा सके.
- सदस्यों द्वारा वनों सहित, जलाशयों एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए कदम उठाये जायेंगे.
- गोद लेना: बढ़ते वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकने एवं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु उन्हें गोद लेंगे.
- कम करना: सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन के नुकसानों में जलवायु में हो रहे परिवर्तन एवं उसके प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया. इसमें मौसम की अत्यधिक क्रूर घटनाओं और हाल में आरंभ हुए बदलावों को भी स्वीकार किया गया.
- तकनीक का महत्व: सदस्यों ने तकनीक द्वारा दीर्घावधि विकास एवं सकारात्मक बदलाव के महत्व को भी स्पष्ट किया.
- क्षमता निर्माण: समझौते के अनुसार प्रयासों का निर्धारण राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए.

- अर्थव्यवस्था: विकसित देश वर्ष 2020 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाएंगे ताकि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन रोकने के उचित प्रयास किये जा सकें.
- क्रियान्वयन: समझौते को लागू करने एवं इसके अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार की गयी.
- पुनरीक्षण: पेरिस समझौते में शामिल सदस्य वर्ष 2023 में इस विषय का पुनरीक्षण करेंगे तथा प्रत्येक पांच वर्ष बाद इसका पुनरवलोकन किया जायेगा.
- हस्ताक्षर और अनुसमर्थन : इस समझौते पर 22 अप्रैल 2016 से 21 अप्रैल 2017 के बीच हस्ताक्षर किये जायेंगे. इसके बाद, हस्ताक्षर हो जाने की तिथि से यह समझौता परिग्रहण के लिए उपस्थित रहेगा.
- प्रवर्तन: यह समझौता कम से कम 55 सदस्यों द्वारा अपनाए जाने के 13वें दिन से प्रवर्तन के लिए तैयार माना जायेगा.

समझौते का महत्व

- इसमें सार्वजनिक किन्तु भिन्न जिम्मेदारी वाले सिद्धांत को अपनाया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण किया जा सके जिस पर भारत कई वर्षों से आवाज़ उठा रहा है.
- यह विकासशील देशों के राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं और छोटे देशों के बीच सही संतुलन कायम करता है. इसमें देश स्वतः ही वर्ष 2020 के बाद उठाये जाने वाले कदमों के बारे में बताएँगे.
- इसके उद्देश्यों को वर्ष 2030 के सतत विकास एजेंडे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसमें निहित 13वें उद्देश्य के अनुसार जलवायु परिवर्तन पर तुरंत कदम उठाने के लिए कहा गया है.

विश्व बैंक ने शॉक वेव्स : मैनेजिंग द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पोवर्टी नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की

दिसंबर 2015 में विश्व बैंक ने शॉक वेव्सः मैनेजिंग द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पोवर्टी नाम से रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और गरीबी के मध्य दुहरे संबंध (परस्पर क्रिया) की जांच की गयी है और निष्कर्ष निकाला गया है कि विश्व में बढ़ती गरीबी के प्राथमिक कारकों में से एक जलवायु परिवर्तन है.

स्थिति में सुधार के लिए रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन नीतियों से गरीबी कम करने और गरीबी कम करने के लिए बनाई गई नीतियों से जलवायु परिवर्तन को कम करने और लचीलापन लाने में योगदान हेतु दिशानिर्देश

भी दिए गए हैं .

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि जलवायु परिवर्त गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण बाधा का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन गरीबी पर भावी प्रभाव नीति विकल्पों द्वारा निर्धारित होंगे.
- तीन प्रमुख चैनल हैं जिनके माध्यम से जलवायु- संवेदनशील घटनाएं पहले से ही गरीबी से बचने के लिए गरीब लोगं की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं- कृषि उत्पादन, पारिस्थितिकी और खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा एवं स्वास्थ्य.
- कृषिः विश्व स्तर पर सीमित होने के बावजूद उप- सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे कमजोर क्षेत्रों में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पहले से ही स्पष्ट हैं.
- छोटी अवधि में खाद्य भंडार, गरीब किसानों की बाजारों तक अच्छी पहुंच, उन्नत प्रौद्योगिकियां और जलवायु- स्मार्ट उत्पादन प्रथाएं जलवायु प्रभावों को कम कर सकती हैं.
- स्वास्थ्यः जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए कुछ खतरे पैदा करेगा खासकर गरीबों और कमजोर लोगों जैसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए लेकिन बड़ी अनिश्चितताएं बनी रहेंगी जो अभी भी अनुसंधान का उभरता हुआ क्षेत्र है.
- साल 2030 तक अगर आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन दोनों ही मौजूद हों तो अनुमान के अनुसार 100 मिलियन समेत 3.6 बिलियन लोगों में मलेरिया होने का खतरा हो सकता है और यह जलवायु परिवर्तन की वजह से होगा.
- स्वास्थ्य संबंधी झटके और गरीब : स्वास्थ्य समस्याएं गरीबी में योगदान देती हैं क्योंकि इनकी वजह से आमदनी में कमी, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चो और देखभाल संबंधी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसलिए स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव गरीबी को कम करने की दिशा में अतिरिक्त बाधा के तौर पर दिखते हैं और ये असमानता को बढ़ाएंगे.
- समग्र प्रभावः निराशावादी विकास परिदृष्य में साल 2030 तक जलवायु परिवर्तन 100 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी की गर्त में ढकेल सकता है.अगर लक्षित अनुकूलन कार्रवाई के साथ त्वरित, समावेशी और जलवायु- सूचित विकास को मिला दिया जाए तो यह संख्या 20 मिलियन तक कम की जा सकती है,

.प्राकृतिक आपदाः ये लोगों को गरीबी में ढकेल देते हैं और गरीब लोगों को गरीबी से निकलने नहीं देते. आगामी दशकों में प्राकृतिक खतरों के बढ़ने की संभावना है और स्थिति और खराब होगी.

.उपचारात्मक उपायः वित्तीय समावेशन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा जाल और भेजा हुआ धन विभिन्न प्रकार के झटकों के खिलाफ अलग- अलग प्रकार की आबादी का बचाव करने में एक दूसरे की मदद करते हैं.

- अल्पावधि में त्वरित, समावेशी और जलवायु- सूचित विकास गरीबी पर जलवायु परिवर्तन के अधिकांश प्रभावों (लेकिन सभी नहीं) को रोकने में मदद कर सकते हैं.
- त्वरित, समावेशी और जलवायु- सूचित विकास अधिकांश अल्पकालिक प्रभावों से बचा सकते हैं जबकि तत्काल गरीबी- समर्थक, उत्सर्जन- कम करने संबंधी नीतियां दीर्घकालिक प्रभावों को सीमित कर सकती हैं.
- जलवायु परिवर्तन शमन के उपाय अल्पकालिक गरीबी उन्मूलन कार्यों के लिए खतरा नहीं हैं क्योंकि नीतियों का डिजाइन अच्छी तरह से तैयार किया गया है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त है.

भारत के संबंध में रिपोर्ट

- यह दिखाने के लिए प्रत्येक वर्ष लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं या वापस गरीबी रेखा में आ जाते हैं, इसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि बीते 25 वर्षों से अधिक की अवधि में आंध्र प्रदेश में 36 समुदायों में औसतन प्रत्येक वर्ष 14 फीसदी परिवार गरीबी से बाहर निकलते हैं और 12 फीसदी गैर गरीब परिवार गरीब परिवारों की श्रेणी में चला जाता है- जिससे गरीबी में सालाना 2 फीसदी की गिरावट हो रही है.
- प्राकृतिक खतरों के प्रति गरीबों की कमजोरी को दर्शाने के लिए रिपोर्ट में कम कीमत वाली जमीन के कारण मुंबई के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की बात की गई है.
- भारत में उच्च - प्रभाव वाले जलवायु परिवर्तन परिदृश्य लगभग 50 मिलियन वाले गरीबी परिदृश्य (अगर लोग गरीब हैं) की तुलना में समृद्धि परिदृश्य (अगर लोगों की आमदनी अच्छी है) में 20 लाख लोगों को गरीबी के दायरे में ले आता है.
- पूर्व चेतावनी प्रणाली- अवलोकन प्रणाली और निकासी तैयारियां मिलकर कम लागत में कई लोगों की जान बचा सकती है. 2013 में जब ओडीशा के गोपालपुर के पास फैलिन चक्रवात आया था तो इसने 100 से कुछ अधिक लोगों की जान ली थी. हालांकि ये क्षति कम नहीं थी फिर भी 1999 में ऐसे ही आए एक और चक्रवात में हुई 10,000 मौतों के मुकाबले बहुत कम है.
- भारत में कृषि आज भी अकुशल और वंचित लोगों का मुख्य रोजगार बना हुआ है. ये परिवार कृषि लाभ या मजदूरी में किसी भी परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होंगें.
- खाद्य कीमतों और गरीबी में संबंधः अनुमान के अनुसार अगर खाद्य कीमतों में 50 और 100 फीसदी से वृद्धि होती है तो इससे गरीबी का स्तर क्रमशः 10 और 25 फीसदी तक बढ़ेगा.
- अगर परिवारों की आमदनी अनुमानिक आमदनी से कम है, ये पर्यावरणीय संसाधनों से अधिक आमदनी प्राप्त करेंगे जो गरीबी और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट के बीच संबंध की ओर इशारा करता है. सुंदरबन का नीचला इलाका यहां रहने वाले अधिकांश गरीब आबादी के लिए रहने के लिए अधिक मुश्किल होता

जा रहा है.इस क्षेत्र में समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, मिट्टी और पानी का बढ़ता खारापन, चक्रवाती तूफान और बाढ़ की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं.

- इस रिपोर्ट में कृषि प्रणालियों के जोखिम को रोकने के लिए रिपोर्ट में जलवायु प्रतिरोधी उच्च उपज किस्मों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है. ओडीशा में यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण में हालिया अध्ययन में धान की नई, बाढ़- रोधी किस्म के उपयोग के लाभों के बारे में बतया गया है जो अभी सबसे लोकप्रिय किस्म की तुलना में 45 फीसदी अधिक उपज प्रदान करेगा.
- घरेलू सर्वेक्षण में पाया गया कि कुछ स्थानों पर अंतिम संस्कार का खर्च कभी- कभी स्वास्थ्य खर्चोंकी तुलना में गरीबी का मुख्य कारण है. एक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात के करीब 85 फीसदी परिवार ने यह माना कि स्वास्थ्य और अंतिम संस्कार के खर्च गरीबी के प्रमुख कारण हैं.
- जबकि विकसित देशों में मनोवैज्ञानिक कारक अंतर्व्यैक्तिक संघर्षों से संबंधित होते हैं, भारत जैसे कम विकसित देशों में कम आमदनी गुस्सा की वजह है जिसकी वजह से अपराध के दर में बढ़ोतरी हो सकती है.
- संयंत्र स्तर पर भारतीय विनिर्माण कामगारों की दक्षता गर्म दिनों में बहुत कम हो जाती है, माइनस 2.8 फीसदी प्रति डिग्री सेंटिग्रेट.
- सिर्फ चीन और भारत में ही रुग्णता और मृत्यु दर के मामले में परिवेशी वायु प्रदूषण की अनुमानित लागत करीब 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना है.

पेरिस जलवायु शिखर सम्मलेन एवं भारत: संक्षिप्त समीक्षा

30 नवंबर 2015 से 11 दिसंबर 2015 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु शिखर सम्मेलन (कॉप-21) संपन्न हुआ. इसमें भाग ले रहे विश्व के 195 देशों ने पेरिस में तैयार जलवायु परिवर्तन के समझौते को अपनी मंज़ूरी दी. इस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया. भारत कॉप-21 में एक महत्वपूर्ण साझीदार देश के रूप में शामिल हुआ एवं भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मेलन में शिरकत की.

'कॉप-21' सम्मलेन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के साथ मिलकर पेरिस में अन्तरराष्ट्रीय सौर गठबन्धन का शुभारम्भ किया और विकसित व विकासशील देशों को साथ लाने वाली इस पहल के लिये भारत की ओर से तीन करोड़ अमेरिकी डालर की सहायता देने की घोषणा की. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कम कार्बन छोड़ने की हर कोशिश कर रहा है, विकसित देशों को बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी. इसके साथ ही पेरिस के जलवायु सम्मेलन में भाग ले रहे कई अन्य देशों ने भी ज्यादा कार्बन

छोड़ने वाले देशों पर टैक्स लगाने की माँग की.

जलवायु सम्मेलन में सौ देशों ने मिलकर 'सोलर अलायंस' बनाया व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये 180 करोड़ रुपए की राशि देने का भी एलान किया. इसके साथ ही वर्ष 2030 तक 35 फीसदी कार्बन उत्सर्जन कटौती की बात कही.

कार्बन उत्सर्जन भारत के लिये बड़ी समस्या है. देश में ग्लेशियर पानी का बड़ा स्रोत है. इन्हें बचाने के लिये न केवल हिमालय, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास करने होंगे. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को गम्भीरता से लिये जाने पर बल देना होगा क्योंकि इस लापरवाही से समुद्र का जलस्तर बढ़ने से समुद्र तटीय क्षेत्रों के और कुछ द्वीपों के समुद्र में डूब जाने का भी खतरा पैदा हो गया है. ग्लेशियर यदि वर्ष 2050 तक खत्म हो गए, जैसा कि अन्देशा पैदा हो गया है, तो सदानीरा नदियाँ बरसाती बन कर रह जाएँगी.

कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर विश्व उत्तरी विकसित देशों और दक्षिणी विकासशील देशों के दो खेमों में बँट गया है. विकसित देश चाहते हैं कि अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर को नियंत्रित किये बिना विकासशील देशों में वनीकरण द्वारा कार्बन का स्तर कम करने के लिये आर्थिक मदद देकर अपनी ज़िम्मेदारी से छुटकारा पा लिया जाये. अमेरिका की कोशिश रहती है कि तेज गति से बढ़ रही भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को ताजा नुकसान का दोषी ठहराने पर जोर दिया जाये. विकासशील देशों का तर्क है कि हमारे यहाँ आपके मुकाबले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जिसे कार्बन पदचिह्न भी कहा जाता है, बहुत कम है. अत: अभी हमें कार्बन पदचिह्न बनाने की छूट दी जानी चाहिए, ताकि हम मानव विकास सूचकांक में बहुत जरूरी विकास की स्थिति में पहुँच सकें. इस तर्क में भी बल है, लेकिन अन्त में तो पृथ्वी की धारण क्षमता का सवाल महत्त्वपूर्ण है.

जलवायु परिवर्तन का सामना करने के दो ही तरीके हैं. पहला है निम्नीकरण यानी जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लगातार कम करते जाना और एक सीमा से आगे न बढ़ने देना. इसके तहत हमें बिजली उत्पादन के क्षेत्र में और तमाम ऊर्जा ज़रूरतों की आपूर्ति के स्वच्छ तरीकों को अपनाना पड़ेगा. इसके लिये सौर व पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं. इसके साथ ही प्राकृतिक तेल और कोयले से ऊर्जा को हतोत्साहित करना पड़ेगा. बड़े बाँधों से मीथेन गैस निकलती है. अत: जल विद्युत उत्पादन की हाइड्रोकाइनेटिक और वोरेटेक्स जैसी बेहतर तकनीकों को अपनाना पड़ेगा.

खेतीबाड़ी के कार्य में रसायनों की बढ़ती घुसपैठ से पर्यावरणीय तंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता. ऐसे में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिये भी प्रयास करने होंगे. जैविक कृषि से मिट्टी में जैविक पदार्थ जितना ज्यादा बढ़ता है, उतना ही कार्बन तत्त्व मिट्टी में समाता जाता है. इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा कम होती जाती है. रासायनिक कृषि इससे उल्टी भूमिका निभाती है. जैविक-वैज्ञानिक कृषि ने रासायनिक कृषि को पछाड़ने की क्षमता सिद्ध कर दी है. हिमालय क्षेत्र में यह वृद्धि सामान्य से कुछ ज्यादा है. यह एक विदित तथ्य है कि हिमालय क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र

है. अत: यहाँ हमें ज्यादा सावधान होने की जरूरत है. तापमान वृद्धि के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लक्षण व उससे होने वाली तबाही विश्व भर में चिन्ता का विषय बन चुकी है. इसके बावजूद इन तमाम प्रयासों के असरदार परिणाम अभी तक सामने नहीं आ सके हैं. यूरोप और अमरीका की भयानक और औसत से ज्यादा सर्दियाँ और बर्फीले तूफान, ध्रुवीय ग्लेशियरों का पिघलना, जिससे समुद्र की सतह में होने वाली बढ़ोतरी, हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना, वर्षा का ढाँचा गड़बड़ाना यानी अतिवृष्टि-अनावृष्टि से बाढ़ व सूखे का बढ़ता प्रकोप वैश्विक चिन्ता का विषय बन चुके हैं. इस परिस्थिति का सामना करने का मुख्यतः एक ही तरीका हैं. पहला निम्नीकरण यानी जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लगातार कम करते जाना और एक सीमा से आगे न बढ़ने देना. इसके तहत हमें बिजली उत्पादन के क्षेत्र में और तमाम ऊर्जा ज़रूरतों की आपूर्ति के स्वच्छ तरीकों को अपनाना पड़ेगा. इसके लिये सौर व पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं.

भारत सरकार ने भी ऊर्जा के इन सुरक्षित स्रोतों के मायने समझते हुए वर्ष 2022 तक भारत में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. पर्यावरणीय संकटों को ध्यान में रखते हुए यह केन्द्र सरकार की एक स्वागत योग्य पहल मानी जाएगी. बड़े पैमाने पर उत्पादन से सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रति यूनिट खर्च भी कम होता जाएगा. इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा कि भारत में ग्रामीण स्तर पर लगी सोलर लाइटों की देखभाल या मरम्मत पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता. इसी का परिणाम है कि उनकी आयु दो-तीन वर्ष ही रह जाती है, जो कि 12 से 16 वर्ष होनी चाहिए. इस दोष के निवारण हेतु भी हमें गम्भीरता से विचार करना होगा. पंचायतों को कुछ धनराशि देकर यह ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है. इन कार्यों के लिये रिसर्च कार्य को भी उच्च प्राथमिकता और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना जरूरी है. इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले उद्योगों को भी बेहतर तकनीक अपनाने के लिये प्रोत्साहित और बाध्य करना पड़ेगा. कृषि क्षेत्र में भी पूरी तरह से वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान पर आधारित जैविक कृषि को अपनाना होगा. तभी हम वैश्विक सुरक्षित जैव भविष्य के निर्माण में भागीदार बन सकते हैं.

यूएनडीपी ने वर्ष 2015 की मानव विकास रिपोर्ट जारी की

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने 14 दिसम्बर 2015 को वर्ष 2015 की मानव विकास रिपोर्ट इथोपिया में जारी की.

जारी की गई इस रिपोर्ट का शीर्षक 'मानव विकास के लिए कार्य' निर्धारित किया गया है.

इस वर्ष जारी की गई रिपोर्ट में सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि कार्य जनता की बेहतरी, असमानता को दूर करने, आजी वका हासिल करने और लोगों को को सशक्त बनाने में योगदान कर

सके. रिपोर्ट में शामिल किए गए मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) की 188 देशों की सूची में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है.

रिपोर्ट में कहा गया है की पछले 25 वर्षों में बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिणामों और अत्यंत निर्धनता में कमी के साथ 2 बिलियन लोगों को 'निम्न मानव वकास स्तर से ऊपर निकाला गया है.

अब, इन लाभों को उठाने और प्रगति को प्रेरित करने के क्रम में चिरस्थायी कार्य पर मजबूती से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है.

इस रिपोर्ट में विशेषकर वंचितसमूहों के लिए शिक्षा में सुधार और सामाजिक सुरक्षा के द्वारा के और सामूहिक कार्रवाई में शामिल कर और शोषणकारी व अपमानजनक कार्यों का उन्मूलन करने के लिए और सुरक्षात्मक क़ानून बना कर देशों और समाजों से समुचित कार्य और चिरस्थायित्व को बढ़ावाको बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है.

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- 830 मिलियन लोगों को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो प्रतिदिन 2 बिलियन यूएस डॉलर से कम की आमदनी पर जीवन यापन कर रहे हैं.
- 200 मिलियन लोग बेरोजगार हैं जिनमे से 74 मिलियन युवा हैं. • 21 मिलियन लोग अब भी बलातश्रम का सामना कर रहे हैं.
- वैश्विक कार्य का 52 प्रतिशत महिलाओं द्वारा संपादित किया जा रहा है, इसके बावजूद स्पष्ट असमानताएं बरकार हैं.
- महिलाओं को पुरुषों की तुलना में उनके काम के लिए भुगतान किए जाने की संभावना कम होती है. अवैतनिक काम के हर चार घंटे में से तीन महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि पुरषों में यह प्रत्येक चार में दो है.
- जब महिलाओं का भुगतान किया जाता है तब वह वैश्विक स्तर औसतन पुरषों को किए गए भुगतान से 24 प्रतिशत कम प्राप्त करती हैं.
- रिपोर्ट के अनुसार विश्वस्तर पर सात अरब मोबाइल फोन धारक हैं, जिनमे स्मार्ट फोन धारकों की संख्या 2.3 अरब है और इंटरनेट का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या 3.2 अरब है.
- वर्ष 2015 में विकसित देशों में 81 प्रतिशत घरों में इन्टरनेट सुविधा है, जबकि विकाशील और अल्पविकसित देश क्रमशः 34 और 7 प्रतिशत घरों में इन्टरनेट सुविधा है.
- रिपोर्ट में कम्प्यूटर के प्रयोग से नियमित कार्यों के प्रतिस्थापन के प्रति चेतावनी दी गई है, जिससे कई

श्रमिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं.

- रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 45 मिलियन स्वास्थ्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी.

रिपोर्ट तीन सूत्रीय कार्य एजेंडे को प्रस्तावित करती है

- समाज के सभी सदस्यों, वशेषकर जो औपचारिक क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं की आवश्यकताओं का ध्यान नीति निर्धारण के समय रखना चाहिए. और इसके लिए सरकार समाज और निजी क्षेत्र के बीच अनुबंध स्थापित होना चाहिए.
- सम्पूर्ण विश्व में कामगारों के अधिकारों के अधिकार और लाभ की गारंटी केलिए सरकार के बीच एक वैश्विक समझौता होना चाहिए.
- सभी कामगारों को शामिल करते हुए एक ऐसा एजेंडा तैयार करना चाहिए जो कार्य जीवन में जुड़ने की स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और मानव गरिमा को प्रोत्साहित करे.

भारत और रिपोर्ट

- वर्ष 2009 से वर्ष 2014 में भारत को छह स्थानों का सुधार हुआ है.
- भारत का स्कोर, मध्यम मानव विकास समूह के औसत स्कोर 0.630 से कम है.
- जबकि दक्षिण एशियाई देशों के औसत स्कोर 0.607 है.
- वर्ष 1980 की तुलना में वर्ष 2014 में जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा में और 14.1 की वृद्धि हुई.
- स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष में 3.5 साल की वृद्धि हुई.
- अपेक्षित स्कूलिंग की अवधि में 5.3 वर्ष की वृद्धि हुई.

विदित हो मान विकास का सही और गहराई तक आकलन करने के लिए हार वर्ष मान विकास रिपोर्ट में चार सूचकांको को शामिल किया जाता हियो. ये सूचकांक निम्न हैं -

1. असमानता समायोजित एचडीआई(आईएचडीआई)
2. लैंगिक विकास सूचकांक(जीडीआई)
3. लैंगिक असमानता सूचकांक(जीआईआई)
4. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक(एमपीआई)

उक्त सूचकांक और भारत

- असमानता समायोजित एचडीआई(आईएचडीआई) में भारत का स्कोर 0.435 है.
- लैंगिक विकास सूचकांक(जीडीआई) में भारत का स्कोर 0.795 है.
- लैंगिक असमानता सूचकांक(जीआईआई) में भारत का स्कोर 0.563 है.
- बहुआयामी निर्धनता सूचकांक(एमपीआई) में भारत का स्कोर 0.282 है.

भारत और अन्य देश का तुलनात्मक अध्ययन

- रिपोर्ट के तीन शीर्ष देश क्रमशः नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड हैं.
- भारत के पड़ोसी और उनका स्थान क्रमशः श्रीलंका (73 रैंक), चीन (90), भूटान (132), बांग्लादेश (142), नेपाल (145), पाकिस्तान (147) और अफगानिस्तान (171).
- ब्रिक्स देश और उनका स्थान क्रमशः रूस (50 रैंक), ब्राजील (75), चीन (90), दक्षिण अफ्रीका (116) और भारत (130).
- अंतिम पाँच देश और उनका स्थान बुरुंडी (184), चाड (185), इरिट्रिया (186), मध्य अफ्रीकी गणराज्य (187), नाइजर (188) है.
- सार्क देश और उनका स्थान मालदीव (104), भारत (130), भूटान (132), बांग्लादेश (142), नेपाल (145), पाकिस्तान (147)
- रिपोर्ट में लीबिया और सीरिया को क्रमशः 27 और 15 स्थानों का घाटा हुआ.

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

- मानव विकास के लिए कार्य नामक यह रिपोर्ट सरकार को नौकरी से आगे बढ़ कर अवैतनिक देखभाल, स्वैछिक देखभाल या सृजनात्मक कार्य जैसे विभिन्न प्रकार के मानव वकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार करने को प्रोत्साहित करती है.
- रिपोर्ट में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को कम करने का आग्रह किया गया है.
- समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए, उत्पीड़न से निपटने के लिए और सामाजिक मानदंडों में आवश्यक परिवर्तन किया जाए.
- रिपोर्ट में सरकार से राष्ट्रीय रोजगार रणनीति तैयार करने का आग्रह किया गया है.

राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 को मंजूरी दी

राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 बिना संशोधन के 22 दिसम्बर 2015 को ध्वनिमत से पारित हो गया है. बिल के अनुसार जघन्य अपराधों में नाबालिग अपराधियों की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है. संसद में 07 मई 20125 को बिल पहजे ही मंजूर किया जा चुका है. अब बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. इसके बाद इसे क़ानूनी रूप से अम्ल में लाया जाएगा.

इस बिल के जरिये जघन्य अपराध में नाबालिग को पुन: परिभाषित किया गया है और ऐसे अपराधियों की सजा के लिए उम्र घटा दी गई है. अब जघन्य अपराधों के मामलों में 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के अपराधी को वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा.

जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 के मुख्य तथ्य-

- इंग्लैंड, चीन, अमेरिका के कई राज्यों में भी हत्या एवं बलात्कार के मामलों में 16 साल के अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है.
- बिल जिस स्वरुप में लोकसभा में पास हुआ उसी स्वरुप में राज्यसभा ने भी पास किया है.
- इस बिल के तहत अधिकतम सजा का प्रावधान 10 साल रखा गया है.
- बिल में सजा ए मौत और उम्र कैद का प्रावधान नहीं हैं.
- बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग हुई जिसमें बिल पास हो गया.
- गंभीर अपराध की श्रेणी में उन अपराधों को परिभाषित किया गया है जिनमें सजा 7 साल या उससे अधिक समय तक सजा का प्रावधान है.
- जूवेनाइल पुलिस का प्रावधान है और हर थाने में एक अधिकारी चाइल्ड पुलिस अधिकारी का दर्जा प्राप्त होता है.
- यहाँ एक विसंगति भी देखने को मिलती है, किसी बच्चे की खरीद फरोक्त की सजा पांच साल है वहीँ बच्चों को ड्रग्स बेचने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है.
- बिल पर चर्चा के समय दिल्ली गैंगरेप पीड़िता निर्भया के माता-पिता भी मौजूद थे.

जिम्बॉब्वे ने चीनी मुद्रा युआन को आधिकारिक तौर पर अपनाने की घोषणा की

जिम्बॉब्वे के वित्त मंत्री पैट्रिक चिनामसा ने 21 दिसम्बर 2015 को चीन की मुद्रा युआन को आधिकारिक तौर पर अपनाने की घोषणा की. इससे पहले चीन ने दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में जिम्बॉब्वे का करीब 40 मिलियन डॉलर (करीब 264 करोड़ रुपये) का ऋण माफ करने का वायदा किया.

- निर्णय के अनुसार चीन और जिम्बॉब्वे के बीच युआन व्यापार जारी रखने में भूमिका निभाएगा.
- जिम्बाब्वे में ग्राहकों के बीच युआन की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी.
- मानवाधिकार के नियमों की अनदेखी के चलते पश्चिमी देशों ने जिम्बॉब्वे में निवेश करने से दूरो बना ली थी. तभी से इसकी अर्थव्यवस्था संकट से उबरने की कोशिश कर रही है.
- 1999-2008 के बीच आई आर्थिक मंदी ने इसे और गहरा कर दिया.
- इससे महंगाई का स्तर और बढ़ गया, यहाँ तक कि हफ्ते भर का बस का किराया भी करीब 100 ट्रिलियन डॉलर हो गया.
- साल 2009 में हाइपर इनफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए अपनी मुद्रा को छोड़कर अमेरिकी 'डॉलर' और दक्षिण अफ्रीकी 'रैंड' को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाना पड़ा.
- जिम्बॉब्वे पिछले पांच सालों के दौरान 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम चीन से ऋण के तौर पर ले चुका है.
- चीन, साउथ अफ्रीका के बाद जिम्बॉब्वे का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है.
- स्थानीय लोगों के खर्च पर चीन पर महाद्वीप की विशाल खनिज सम्पदा और ऊर्जा संसाधनों के दोहन करने का आरोप है.
- विशेषज्ञों का कहना है कि जिम्बॉब्वे की आधिकारिक मुद्रा के तौर पर युआन पिछले दो सालों से ही बना हुआ है.
- चीन-जिम्बॉब्वे के बीच संबन्धों में तब और प्रगाढ़ता देखी गई जब चीन ने जिम्बॉब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार के तौर पर पेश किया.

मेक्सिको ने विश्व के पहले डेंगू टीके को मंजूरी प्रदान की

उत्तरी अमेरिकी देश, मेक्सिको ने 9 दिसम्बर 2015 को विश्व के पहले डेंगू के टीके को मंजूरी प्रदान कर दी.

इस टीके को फ्रांस के दवा निर्माता समूह सनोफी के टीका निर्माण विभाग 'सनोफी पाश्चर'ने विकसित किया है. कम्पनी द्वारा विकसित यह टीका सिर्फ 9 से 45 वर्ष के आयु समूह के लिए ही है.

देश की चिकित्सा सुरक्षा एजेंसी ने इस टीके के विश्व के 29000 लोगों पर किए गए सफल परीक्षण की पुष्टि की है.

यह टीका साधारण डेंगू से बचाव में 60.5 प्रतिशत और डेंगू के गंभीर मामलों से बचाव में 93.2 प्रतिशत कामयाब है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2014 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार यह टीका डेंगू के इलाज में 60.8 प्रतिशत तक प्रभावी है.

मेक्सिको की चिकित्सा सुरक्षा एजेंसी ने बताया की इस टीके से प्रत्येक वर्ष लगभग 104 लोगों की मृत्यु(डेंगू से) को रोका जा सकेगा, इसके अतिरिक्त चिकत्सा पर होने वाले व्यय में भी लगभग 65 मिलियन यूएस डॉलर की कमी आएगी.

डेंगू

डेंगू एक वायरल बीमारी है जो की डेंगू विषाणु के 4 प्रकारों में से किसी एक प्रकार के डेंगू विषाणु से होता है. जब कोई रोगी डेंगू बीमारी से ठीक हो जाता है, तब उस मरीज को उस एक प्रकार के डेंगू विषाणु से लम्बे समय के लिए प्रतिरोध मिल जाती है परन्तु अन्य 3 प्रकार के डेंगू विषाणु से डेंगू दोबारा हो सकता है. दूसरी बार होने वाला डेंगू काफी गंभीर हो सकता है जिसे डेंगू हेमररेजिक ज्वर (Dengue Hemorrhagic Fever) कहते है.

इस बीमार का मुख्य एजेंट मादा जाति के 'Aedes aegypti' नामक मच्छर है. इस बिमारी के लक्षण तेज ज्वर और मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में शामिल हैं. डेंगू का अब तक कोई विशेष उपचार नहीं था.

हर वर्ष विश्व में लगभग 10 करोड़ लोग डेंगू के शिकार होते है. भारत में भी हर साल कई लोगो की डेंगू के कारण मृत्यु हो जाती है.

पीपीपी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट जारी

बुनियादी ढांचा विकास हेतु डॉ. वी. केलकर की अध्यक्षता में पीपीपी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट 28 दिसंबर 2015 को जारी की गई.

विदित हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2015-16 में घोषणा की थी कि बुनियादी ढांचे के विकास के सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर फिर से विचार किया जाएगा तथा इसे फिर से मजबूत बनाया जाएगा. इस घोषणा के अनुरूप डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल पर फिर से विचार करने तथा इसे मजबूत बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था.

केलकर समिति रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) एक निजी साझीदार द्वारा एक सार्वजनिक परिसंपत्ति एवं सेवा के प्रावधान को उद्दत करता है, जिसे बाजार निर्धारित राजस्व स्रोत के आधार पर, जो निवेश पर व्यवसायिक रिटर्न की अनुमति देता है, एक निर्धारित समय अवधि के लिए, अधिकार (रियायत) प्रदान किया गया है.
- पीपीपी भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में गति लाने के एक मूल्यवान माध्यम का प्रतिनिधित्व करती है. भारत के तेज गति से विकास करने और अपने लिए एक जन सांख्यिकीय लाभांश सृजित करने के लिए तथा विकसित देशों में बुजुर्ग हो रही आबादी से पेंशन एवं संस्थागत कोषों के बड़े हिस्से का दोहन करने के लिए भी इसकी तत्काल आवश्यकता है.
- भारत पीपीपी के लिए विश्व के सबसे बड़े बाजार की पेशकश करता है. इसने इस शीर्ष स्थिति पर पहुंचने के क्रम में अनुभव की एक बेशुमार संपत्ति संग्रहित की है. भारत में जैसे-जैसे बुनियादी ढांचे में पीपीपी बाजार परिपक्व हो रहा है, नई चुनौतियां और अवसर उभरे हैं और लगातार उभरते रहेंगे. जैसा कि वर्तमान समिति के प्रेषण में है, पीपीपी की शाब्दिक समीक्षा इन मुद्दों के समाधान मदद के लिए अनिवार्य हैं, इससे पहले कि वे देशज बन जाए और अन्वेषणों को मुख्य धारा में ले आएं तथा नये अन्वेषणों को बढ़ावा दें जो पीपीपी परियोजनाओं की सफल आपूर्ति को बेहतर बनाते हैं.
- भारत में बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए पीपीपी को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में लाने में देश की सफलता पीपीपी से संबंधित सभी अधिकारियों के बर्ताव एवं मानसिकता में बदलाव पर निर्भर करेगी. इसमें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने वाली सार्वजनिक एजेंसियां, पीपीपी का पर्यवेक्षण करने वाले सरकारी विभाग, और अंकेक्षण तथा पीपीपी की निगरानी मुहैया कराने वाले कानूनी संस्थान शामिल हैं.
- भारत भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 में संशोधन के लिए प्रारंभिक कदम उठा सकता है, जो निर्णय

निर्माण एवं कार्यों में वास्तविक गलतियों के बीच अंतर नहीं करता और बुनियादी ढांचे के पीपीपी मॉडल को फिर से मजबूत बनाने पर गठित कमिटी की रिपोर्ट पर कार्य करता है. सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले गलत कार्यों को दंड योग्य बनाने के लिए और अच्छे इरादों के साथ निर्णय लेने वाले सरकारी अधिकारियों एवं नौकरशाहों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकते हैं. सरकार सरकारी अधिकारियों पर लागू होने योग्य भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सतर्कता एवं आचार नियमों के संशोधन में तेजी ला सकती है.

- सरकार के अब तक के अनुभव ने पीपीपी संरचना के तीन प्रमुख स्तंभों प्रशासन, संस्थानों एवं क्षमता को और मजबूत बनाने की जरूरत को भी रेखांकित किया है जो कि क्रियान्वयन के अगले कदमों के लिए स्थापित नींव पर बनाया जाएगा.
- मानिसकता बदलने के अतिरिक्त भारत की पीपीपी क्षमताओं, क्रियान्वयनकारी एजेंसियों और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लिए ग्राहकोन्मुखी कार्यक्रमों एवं निजी क्षेत्र समेत विभिन्न हितधारकों के लिए संरचित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के पुनर्निमाण की तत्काल आवश्यकता है. संस्थागत क्षमता निर्माण गतिविधियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की जरूरत की भी खोज की जानी चाहिए. बिना अपवाद के सभी हितधारकों ने पीपीपी के लिए एक समर्पित संस्थान की तात्कालिक जरूरत पर जोर दिया है जैसी कि पहले के बजट में घोषणा की गई थी. समिति जोरदार तरीके से 'उपीआई' का अनुमोदन करती है जो पीपीपी में उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में काम करने के अतिरिक्त, अनुसंधान, समीक्षा , क्षमता के निर्माण के लिए गतिविधियों को शुरू करने के अतिरिक्त अनुबंधकारी और विवाद निपटान तंत्रों के अधिक बारीक और परिष्कृत मॉडलों की सहायता में सक्षम बनाते हैं.

समिति की प्रमुख सिफारिशें:

- अनुबंधों में वित्तीय लाभों की बजाय सेवा सुपुर्दगी पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है.
- हितधारकों के बीच जोखिमों की बेहतर पहचान और आबंटन.
- उन्नत वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य प्रणालियां और निष्पादन की सावधानी पूर्वक निगरानी.
- भारत की जनसांख्यिकीय परिवर्तन की तत्कालिकता और अनुभव को देखते हुए, भारत पहले से ही पीपीपी के प्रबंधन को संकलित कर चुका है, सरकार को पीपीपी प्रारूप के परिपक्व और परिष्कृत स्तर के अगले कदम की ओर बढ़ना चाहिए.
- भारत में पीपीपी मॉडल को परिपक्व बनाने और भारत के बुनियादी ढांचे की आवश्कताओं और दीर्घकालिक कोषों की उपलब्धता के इस ऐतिहासिक संयोजन से लाभ लेने की तत्काल प्राथमिक जरूरत है.
- पीपीपी में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को त्वरित और बेहतर के साथ भारत के 15 वर्ष के अनुभव को देखते हुए, अनुबंध के हर स्तर पर पीपीपी के प्रदर्शन में आने वाली समस्याओं को दूर करने की

आवश्यकता.

वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा

साहित्य अकादमी ने 17 दिसम्बर 2015 को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की.

इस बार 23 भाषाओं में पुरस्कार घोषित किए गए हैं. इस बार 6 कविता संग्रह, 6 कहानी संग्रह, चार उपन्यास, दो निबंध संग्रह, दो नाटक, दो समालोचना और एक संस्मरण के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है.

यह सभी घोषित पुरस्कार 16 फरवरी 2016 को दिए जाएंगे.

दिए गए पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है

कविता संग्रह के लिए सम्मा नित कवि

ब्रजेन्द्रर कुमार (बोडो)

ध्योन सिंह (डोगरी)

रामदरश मिश्र (हिंदी)

के.वी. तिरुमलेश (कन्ड़016)

क्षेत्री राजन (मणिपुरी)

रामशंकर अवस्थी (संस्कृषत)

कहानी संग्रह के सम्मा नित कहानीकार

कुल सेइकिया (असमिया)

मनमोहन झा (मैथिली)

गुप्तन प्रधान (नेपाली)

विभूति पट्टनायक (ओड़िया)

माया राही (सिंधी)

वोल्गा (तेलुगु)

सम्मानित उपन्यातसकार

साइरस मिस्त्रीन (अंग्रेजी)

के.आर.मीरा (मलयालम)

जसविंदर सिंह (पंजाबी)

मधु आचार्य (राजस्थानी)

निंबध के लिए सम्मिनित

रसिक शाह (गुजराती)

ए.माधवन (तमिल)

नाटक के लिए सम्मुनित

उदय भेंब्रे (कोंकणी)

रबिलाल टुडू (संताली)

समालोचना के लिए सम्मांनित

बशीर भद्रवाही (कश्मीरी)

शमीम तारिक (उर्दू)

संस्मतरण के लिए सम्मा)नित

अरुण खोपकर (मराठी)

अभी बंगला के लिए किसी पुरस्कार की घोषणा नहीं की गयी.

वर्ष 1954 में अपनी स्थापना के समय से ही साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है. पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1955 में दिए गए.

पुरस्कार के रूप में उत्कीर्ण पट्टिका, शाल और 1 लाख रुपए का चेक पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं.

जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल बनीं टाइम 'पर्सन ऑफ द ईयर'

टाइम मैगजीन ने वर्ष 2015 के दिसम्बर माह में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को 'पर्सन ऑफ द ईयर' चुना है.

उन्हें यह सम्मान यूरोप में विषम परिस्थितियों में उनके द्वारा प्रदान किए गए सराहनीय नेतृत्व के लिए दिया गया.

विदित हो वर्ष 1927 के बाद से मर्केल चौथी बार इस सम्मान से सम्मानित की गई हैं.

मर्केल से पूर्व सिर्फ तीन और महिलाएँ इस सम्मान से सम्मानित की गई हैं. यह हैं वालिस सिम्पसन (1936), महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (1952) और कोराजोन एक्विनो (1986).

आतंकी संगठन आईएसआईएस का प्रमुख अबू बक्र अल बगदादी इस सूची में दूसरे स्थान पर है.

ज्ञात हो सम्मान प्रत्येक वर्ष चर्चित पत्रिका टाइम्स द्वारा प्रदान किया जाता. इसकी शुरुआत वर्ष 1927 में की गई थी. इस सम्मान की घोषणा प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में की जाती है. यह सम्मान प्रत्येक वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जो वर्ष में अत्याधिक चर्चा(सकरात्मक और नकारात्मक) में रहें हो.

इसरो ने पीएसएलवी-सी29 द्वारा सिंगापुर के छः उपग्रहों का प्रक्षेपण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 16 दिसंबर 2015 को पीएसएलवी-सी 29 के माध्यम से सिंगापुर के छः उपग्रहों का प्रक्षेपण किया. इन उपग्रहों का प्रक्षेपण सतीक्ष धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी), शार (SHAR), श्रीहरिकोटा से किया गया.

यह पीएसएलवी की 32वीं उड़ान और 31वीं लगातार सफल उड़ान थी. गौरतलब है कि 10 अगस्त 1979 को श्री हरिकोटा से रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड के साथ उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएलवी-3 का प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण असफल रहा था.

यह पीएसएलवी के कोर-एलोन संस्करण की 11 वीं उड़ान थी. सिंगापुर के इन छः उपग्रहों समेत इसरो द्वारा अब तक 20 देशों के 57 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है.

सिंगापुर द्वारा इन उपग्रहों का उपयोग आपदा निगरानी और शहरी नियोजन के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाएगा.

सभी छः उपग्रहों को भूमध्य रेखा से 15 अंश कोण पर 549 किमी. ऊंचाई की कक्षा में स्थापित किया गया.

इन छः उपग्रहों का प्रक्षेपण एसटी इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंगापुर और इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के मध्य समझौते के तहत किया गया.

सिगापुर के छः उपग्रहों में टेलिओस-1 कैंट रिज-1, वेलॉक्स-सी 1, वेलॉक्स-II, गैलेसिया एवं एथेनॉक्सैट-1 शामिल हैं. इनमें टेलिओस-1 का वजन 400 किग्रा. है.

अंतरराष्ट्रीय

ब्रिक्स देशों के बीच ब्रिक्स संघ विश्वविद्यालय के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर का अनुमोदन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 30 दिसंबर 2015 को ब्रिक्स संघ विश्वविद्यालय पर ब्रिक्स देशों के बीच समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर को पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान की.

इस समझौता पत्र से ब्रिक्स देशों के मध्य वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, विश्लेषण एवं सर्वश्रेष्ठ तौर तरीक़ों के क्रियान्वयन, संयुक्त शोध एवं छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की अंतरणीयता पर सक्रिय साझेदारी होगी.

विदित हो कि रूस के मास्को में नवंबर 2015 के दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक में ब्रिक्स संघ विश्वविद्यालय संबंधी मामले पर सहमति बनी थी.

जापान और दक्षिण कोरिया के बीच 'कम्फर्ट वीमेन' विवाद समाप्त हुआ

जापान और दक्षिण कोरिया के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय से चल रहा 'कम्फर्ट वीमेन' विवाद 28 दिसंबर 2015 को समाप्त हो गया.

द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सैनिकों द्वारा दो लाख से अधिक महिलाओं को सेक्स स्लेव बना कर रखा गया था, जिस पर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने माफी मांगी.

उस दौर की अभी भी 46 महिलाएं कोरिया में जीवित हैं. उनके लिए जापान ने एक अरब येन (करीब 55 करोड़ रुपए) की मदद की पेशकश की है. गौरतलब है कि जापान ने 1910-45 तक कोरिया को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था.

कम्फर्ट वीमेन विवाद

- जापानी सैनिकों ने जिन महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया था, उनमें अधिकतर कोरियाई थीं.
- बाकी महिलाएं चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ताइवान की थीं.
- इस दौरान यह भी दावा किया गया कि युद्ध के समय के मानवाधिकारों के मुद्दे को पृथक रूप से सुलझाया जाना चाहिए.
- अब तक दक्षिण कोरिया की 238 पीड़ित महिलाएं इस मुद्दे के तहत पंजीकरण करा चुकी हैं.
- "कम्फर्ट वीमेन" शब्द जापानी शब्द "इयानफु" का अनुवाद है जिसका संज्ञात्मक अर्थ वेश्या है.
- इस मुद्दे को लेकर दक्षिण कोरिया और जापान के बीच तनाव था, जो अब समाप्त हो गया है.

जापान के विदेश मंत्री फुमोई किशिदा ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष युन बयुंग-से के साथ एक बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंजो आबे के बयान को पढ़ा. इसमें उन्होंने मानसिक और शारीरिक तौर पर यातना झेल चुके लोगों से माफी मांगी.

रूस ने कामोव 226टी हेलीकाप्टर बनाने के लिए एचएएल के साथ समझौता किया

रूस की कंपनी रोसटेक स्टेट कॉरपोरेशन ने कम से कम 200 कामोव 226टी हल्के हेलीकाप्टर बनाने के लिए हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 29 दिसंबर 2015 को समझौता किया.

ये हेलीकाप्टर पुराने हो रहे चीता व चेतक हेलीकाप्टर की जगह लेंगे.

सरकार की महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत यह सौदा अनुमानित 1 अरब डालर मूल्य का है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर 2015 में मॉस्को यात्रा के दौरान दोनों देशों ने हेलीकॉप्टर विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया. इस समझौते पर मोदी व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए.

इस समझौते के अनुसार रोसटेक भारत में रूसी केए-226टी हेलीकॉप्टर बनाएगी. इनकी संख्या 200 से कम नहीं होगी. समझौते में हेलीकॉप्टरों का रखरखाव, परिचालन व मरम्मत शामिल है.

कामोव 226टी हेलिकॉप्टंर

- कामोव केए-226T एक लाइट वेट मल्टीरपरपज हेलिकॉप्टर है, जिसका कामोव कंपनी द्वारा निर्माण किया जाता है. हेलिकॉप्टर केए-226T में आधुनिक नेविगेशन उपकरण लगे हुए हैं.
- इसके चलते इस हेलिकॉप्र का इस्तेमाल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है.
- हेलिकॉप्टर का पिछला हिस्सा और आकार छोटा होने से इसे छोटे हवाई अड्डों पर भी लैंड या टेक ऑफ की अनुमति मिल जाती है.
- हेलिकॉप्टर बहुत ही कम ध्वनि प्रदूषण करता है और नवीनतम आधुनिक पर्यावरण आवश्यकताओं को पूरा करता है.
- इस हेलिकॉप्टर में रीप्लेजकेबल ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल लगा हुआ है जिससे कम समय में यह अपनी कार्यक्षमता बदलने में सक्षम है.

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत एवं कनाडा के बीच समझौते का नवीनीकरण

प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैंद्रीय कैबिनेट ने 30 दिसंबर 2015 को भारत एवं कनाडा के मध्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समझौता-पत्र के नवीनीकरण को अपनी अनुमति प्रदान की. इस समझौता पत्र से भारत एवं कनाडा के बीच उच्च शिक्षा में मौजूदा साझेदारियों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी.

विदित हो कि भारत एवं कनाडा के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु पांच वर्षीय समझौता-पत्र पर जून 2010 में हस्ताक्षर हुए थे. इस समझौता-पत्र की शर्तों के अनुसार पांच वर्ष पूरे होने पर समझौता-पत्र को पांच अतिरिक्त सालों के संभावित नवीनीकरण के लिए नवीकृत किया जाना था. समझौता पत्र के नवीनीकरण के माध्यम से प्रस्तावित किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंध मज़बूत हों.

चीन ने पहला आतंकवाद रोधी कानून पारित किया

चीन की राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा ने 27 दिसंबर 2015 को देश का पहला आतंकवाद विरोधी कानून पारित किया. इसे चीन की राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की 12वीं राष्ट्रीय कमेटी के 18वें पूर्णाधिवेशन में पारित किया गया. गौरतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त शक्ति दिए जाने वाले इस कानून के प्रभाव में आने से

पहले देश में अत्यधिक प्रदर्शन हुए. चीन के 36वें राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा इस अधिनियम पर हस्ताक्षर करने पर यह कानून के रूप में प्रभाव में आया.

नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति के 159 सदस्यों ने सहमति से मसौदा कानून स्वीकार कर लिया. इसे सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने मंजूरी दी थी. नए कानून ने विदेशों में आतंकवाद रोधी अभियानों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भाग लेने को वैध बनाया है.

चीनी आतंकवाद रोधी कानून

- इसके अनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और देश के सशस्त्र पुलिस बल केंद्रीय सैन्य आयोग की मंजूरी के साथ आतंकवाद रोधी अभियान चला सकते हैं.
- यह कानून चीन सहित तिब्बत पर भी लागू होगा.
- लोक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी भी विदेशों में आतंकवाद रोधी अभियान के लिए सैनिकों को भेज सकते हैं.
- यह कानून सुरक्षा एजेंसियों को अत्यधिक शक्तियां देता है.
- चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, नया कानून चीन और दुनिया के लिए ऐसे संवेदनशील समय में आया है जब पेरिस में आतंकवादी हमले, मिस्र के ऊपर रूस के एक यात्री विमान पर बम से निशाना और इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह द्वारा बंधकों की हत्याओं के मामले दुनिया को आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बारे में चौकन्ना किया है.

चीन ने किया संशोधन नए साल से दो बच्चे पैदा करने की छूट

चीनी अभिभावक एक जनवरी के बाद से दो बच्चे पैदा कर सकेंगे.

चीन की संसद में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने 27 दिसंबर 2015 को क़ानून में उस बदलाव को मंज़ूरी दे दी, जिसके तहत चीन में सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति दी. 1 जनवरी 2016 के बाद से प्रत्येक चीनी दंपति दो बच्चे पैदा कर सकेंगे.

इस साल के अक्तूबर में सत्तारूढ़ कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने 29 अक्टूबर 2015 इन बदलावों की घोषणा की.

चीन ने क्यों किया नीति में संशोधन?

- संशोधित नीति का उद्देश्य देश की आबादी की संरचना के बीच संतुलन साधना है.
- चीन ने सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की नीति 1970 के दशक में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लागू की थी. जन्म दर को स्थिर करने के लिए 2002 में इसका संज्ञान लिया गया.
- इस नीति की चीन में आलोचना भी हुई, इससे मुख्य रूप से सामाजिक समस्याएं जैसे श्रम शक्ति का कम होना और चीन की आबादी में उम्र दराजों की संख्या अधिक होने लगी.
- वर्तमान में चीन में कुल आबादी का 15 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की है और श्रम शक्ति कामगारो की जनसंख्या में कमी होना शुरू हो गयी है.
- इस नीति से 400 मिलियन बच्चों के जन्म को रोकने का अनुमान है, इस नीति का लक्ष्य संसाधनों और पर्यावरण पर दबाव को कम करना था.
- संसद ने घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ देश के सबसे पहले क़ानून को भी मंज़ूरी दे दी.
- नया क़ानून औपचारिक रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई शारीरिक, मानसिक और दूसरी क्षति को अपराध मानता है.
- साइबरस्पेस में सुरक्षा ख़तरों से निबटने के लिए भी नया क़ानून लाया गया है.
- इसी के साथ चीनी संसद ने देश के पहले चरमपंथरोधी क़ानून को भी मंज़ूरी दी. जिसके तहत अब कंपनियां संवेदनशील जानकारी जैसे एन्क्रिप्शन कुंजियां भी सरकार के साथ साझा कर सकेंगी. यह क़ानून एक जनवरी से लागू हो जाएगा.
- चीनी अधिकारियों का कहना है कि चरमपंथी तेज़ी से साइबर स्पेस का रुख़ कर रहे हैं और इसलिए नए प्रावधानों की ज़रूरत है.

चीन को लाभ

- एक अनुमान के अनुसार चीन में 140 मिलियन महिलाएं हैं जिनके पास पहले से ही एक बच्चा है.
- नए कानून के लागू होने के बाद उनमें से लगभग 90 लाख दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती हैं. इसके अलावा 2029 में चीन की कुल आबादी 1.45 अरब के आसपास होने का अनुमान है.
- योजना के मुताबिक 2050 तक श्रम शक्ति में 30 लाख से अधिक से लोगों के जुड़ने की उम्मीद है.

ओपेक ने 2015 ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक जारी किया

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक- ओपीईसी) ने 23 दिसंबर 2015 को 2015 ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक जारी कर दिया.

सबसे पहली बार 2007 में प्रकाशित हुआ, डब्ल्यूओओ तेल उद्योग के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के मध्यम और दीर्घकालिक विकास से संबंधित विभिन्न परिदृश्यों की गहन समीक्षा और मूल्यांकन प्रदान करता है.

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2040 तक तेल एवं गैस का, संयुक्त रूप से, वैश्विक ऊर्जा की मांग का करीब 53 फीसदी आपूर्ति करने की उम्मीद है.

ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक की विशेषताएं

- साल 2040 तक ऊर्जा की वैश्विक मांग में करीब- करीब 50 फीसदी का इजाफा होना तय है. करीब 78 फीसदी के साथ, समग्र ऊर्जा मिक्स में जीवाश्म ईंधन का सबसे अधिक उपयोग जारी रहेगा.
- डब्ल्यूओओ 2014 की तुलना में, मध्यम अवधि तेल की मांग उपर की ओर बढ़ रही है, 2020 तक यह प्रति दिन 97 मिलियन बैरल प्रति दिन (एमबी/डी) से अधिक हो जाएगा.
- साल 2040 त तेल की मांग 110 एमबी/डी हो जाने का अनुमान है.
- दीर्घकालिक मांग में विकासशील एशिया क्षेत्र का प्रभुत्व है, जो साल 2040 तक होने वाली वृद्धि का 70 फीसदी होगा.
- गैर- ओपेक तरल की आपूर्ति 2014 के 56.5 एमबी/डी से बढ़कर 2020 तक करीब 60 एमबी/डी हो जाएगा, डब्ल्यूओओ 2014 की तुलना में 1एमबी/डी का डाउनवर्ड रिविजन. साल 2040 तक, गैर- ओपेक तरल की आपूर्ति 60एमबी/डी से नीचे हो जाएगी.
- ओपेक कच्चा तेल में साल 2040 तक 10 एमबी/डी का विस्तार होगा और यह 40.7 एमबी/डी हो जाएगा- 2014 के प्रकाशन की तुलना में 1एमबी/डी की बढ़ोतरी.
- ओपेक रेफरेंस बास्केट का दीर्घकालिक वैल्यू माना जाता है कि 2020 में 70 अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रति बैरल से बढ़कर 2040 तक 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो जाएगा (दोनों 2014 डॉलर में)
- वैश्विक स्तर पर पूर्वानुमान की अवधि 2015- 2040 के लिए, भविष्य के तेल की मांग को कवर करने हेतु अनुमानतः 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2014 के मूल्यों पर) की जरूरत होगी.

- मौजूदा रिफाइनर परियोजनाओं की समीक्षा इस बात का संकेत देती हैं कि, 2015- 2020 की अवधि में करीब 7 एमबी/डी की नई आसवन क्षमता वैश्विक स्तर पर जुड़ेगी.
- मध्यम- अवधि में अधिशेष रिफाइनिंग क्षमता पिछले कुछ वर्ष में कम हुई है, लेकिन आउटलुक उत्पाद बाजार के लिए प्रतियोगिता की अवधि और अतिरिक्त समापन अधिशेष की जरूरत की ओर लगातार इशारा कर रहा है.
- साल 2040 तक आवश्यक संचयी आसवन अतिरिक्त क्षमता का करीब 20 एमबी/डी होने का अनुमान है.

लीबिया एकता समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन, 30 दिनों में लागू करने का अनुरोध

23 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने सर्वसम्मति से लीबिया के प्रतिद्वंद्वी खेमों के बीच एकमत सरकार के गठन की पुष्टि के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया.

सुरक्षा परिषद ने दलों से राष्ट्रीय समझौते की सरकार बनाने के लिए हुए समझौते द्वारा 30 दिनों के भीतर अपनी शर्तों को लागू करने का आग्रह किया है. इसके साथ ही परिषद ने विश्व समुदाय से आतंकवादी समूहों को हराने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की भी अपील की.

17 दिसंबर 2015 को मोरक्को में कलह-ग्रस्त लीबिया केदो प्रतिस्पर्धी सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते को 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अपना समर्थन दिया है. सरकार को एकजुट करने हेतु हुए समझौते को एकता सरकार कहा जाएगा और इसके प्रमुख होंगे व्यापारी फाएज- अल- सर्राज.

संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए इस समझौते को मुकाम तक पहुंचाने में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि मार्टिन कोबलर ने मदद की ताकि चार वर्ष से चल रहे इस संकट का समाधान हो सके. इस संघर्ष की वजह से करीब 2.4 मिलियन लीबियाई नागरिकों को मानवीय सहायता की बहुत अधिक जरूरत है.

अंतराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को लीबिया की राजधानी त्रिपोली से अगस्त 2014 में बर्खास्त कर दिया गया था. यह देश के पूर्वी इलाके में है जबकि एक और इस्लाम सर्थक निकाय राजधानी पर कब्जा किए हुए है.

सलमा बांध के निर्माण की संशोधित लागत को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 22 दिसम्बर 2015 को मंत्रिमंडल की बैठक में सलमा बांध के निर्माण के लिए अनुमानित राशि(संशोधित) को मंजूरी प्रदान की गई.

मंत्रिमंडल के अनुसार सलमा बांध परियोजना के निर्माण के लिए 1775.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पुनर्निधारित की गई है.

यह बांध अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा. इसके अतिरिक्त इस बांध निर्माण से अफगानिस्तान में भारत के प्रति सद्भावना उत्पन्न होने की सम्भावना है.

इस परियोजना की जून 2016 तक पूरा होने की सम्भावना है.

इस परियोजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी डब्ल्यूएपीसीओएस(जल संसाधन मंत्रालय की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई) को सौंपी गई है.

इसके सफल समापन पर इस परियोजना से पश्चिमी अफगानिस्तान की ऊर्जा आवश्यकताओं और सिंचाई जरूरतों के पूरा होने की संभावना है.

सलमा बांध

- यह बांध अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ नामक जिले के हेरात नामक शहर में स्थित होगा.
- इस बांध का निर्माण वर्ष 1976 में हरि नदी पर किया गया था. परन्तु अफगानिस्तान में गृहयुद्ध में यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया.
- इस बांध का निर्माण भारतीय कम्पनी डब्ल्यूएपीसीओएस ने वर्ष 1998 में प्रारंभ किया था. परन्तु देश में अस्थिरता के चलते इसे रोकना पड़ा.
- इस परियोजना के तहत 107.5 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा. इसके अतिरिक्त इसमें 14 मेगावाट के तीन पॉवर हाउसों का निर्माण भी किया जाएगा.
- इस बांध के माध्यम सेर देश के 75000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी छोड़ने का भी प्रावधान है.

ब्रुनेई में क्रिसमिस मनाये जाने पर प्रतिबन्ध

ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल-बोलकिया द्वारा 21 दिसंबर 2015 को मुस्लिमों द्वारा देश में सार्वजनिक स्थानों पर क्रिसमस मनाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गयी.

नये आदेश के अनुसार किसी भी मुसलमान द्वारा क्रिसमिस मनाये जाने पर उसे पांच साल की जेल की सज़ा दी जाएगी. इसके अलावा 20 हजार डॉलर (लगभग 13 लाख रुपए) जुर्माना भी हो सकता है.

इसके अतिरिक्त सुल्तान ने यह भी आदेश जारी किया कि यदि कोई मुसलमान इसकी बधाई देता हुआ अथवा सांता टोपी पहने दिखा तो उसे भी सजा मिलेगी.

ब्रुनेई

- ब्रुनेई की कुल आबादी लगभग 4,20,000 है.
- इसमें 65% आबादी मुसलमानों की है.
- लगभग 20% आबादी गैर-मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन कम्युनिटी की है.
- नए आदेश के अनुसार केवल गैर मुस्लिम क्रिसमस मना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी.

डेंगू के टीके को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना फिलिपीन्स

फिलीपींस 22 दिसंबर 2015 को डेंगू टीका डेंगा वैक्सिया की बिक्री को मंजूरी प्रदान करने वाला एशिया का पहला देश बन गया.

फिलीपींस के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने डेंगा वैक्सिया की बिक्री को सुरक्षित बताया.

विदित हो इस टीके को फ्रांस के दवा निर्माता समूह सनोफी के टीका निर्माण विभाग 'सनोफी पाश्चर' ने विकसित किया है और यह टीका सिर्फ 9 से 45 वर्ष के आयु समूह के लिए ही है.

सनोफी बारे में

- सनोफी एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है.

- इसे वर्ष 1973 में एल्फ एक्वइतीन के सहायक के रूप में किया गया था.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने तालिबान पर लगे प्रतिबंधो को विस्तारित किया

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की-मून की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने 21 दिसंबर 2015 को आतंकी संगठन तालिबान पर प्रतिबंधो को आगे जारी रखने का निर्णय लिया.

इस अवसर पर सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर तालिबान तथा इससे जुड़े अफ़गानिस्तान की शांति व सुरक्षा पर धमकी देने वाले व्यक्तियों या संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात दोहरायी. साथ ही उनके धन के स्रोत को बंद करने पर भी जोर दिया.

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तालिबान व अल कायदा समेत हिंसक व उग्रवादी संगठनों, अवैध सशस्त्र संगठनों, नशीले पदार्थों की तस्करी संघों द्वारा की गयी हिंसक व आतंक गतिविधियों पर ध्यान देता रहेगा एवं इसे ख़त्म करने हेतु प्रयासरत रहेगा. इसके साथ ही इस बात पर चिंता भी व्यक्त की गई कि अफ़गानिस्तान में उग्रवादी संगठन आईएस की शाखाएं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, इसे कैसे रोका जाय? प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान में सुरक्षा स्थिति बदल रही है.

उपरोक्त प्रस्ताव में सभी देशों से लगातार प्रतिबंध की सूची में शामिल सभी व्यक्तियों व संगठनों की संपत्ति को जाम करने, उन्हें हथियार भेजने पर प्रतिबंध लगाने आदि कदम उठाने का आग्रह किया गया है.

नेपाल सरकार मधेसियों की समस्या हल करने हेतु संविधान में संशोधन के लिए सहमत

नेपाल सरकार ने अपने नए संविधान में 21 दिसंबर 2015 को संशोधन करने का फ़ैसला किया है. नेपाल की कैबिनेट ने मधेसियों के आंदोलन को समाप्त करने एवं देश में गतिरोध समाप्त करने के लिए दो मांगों को मानने की भी इच्छा जाहिर की है.

यह दो मांगें हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचनक्षेत्र परिसीमन, जिनके लिए नेपाल सरकार ने नए संविधान में संशोधन करने का फैसला किया है.

मधेसी आंदोलन

- मधेसी कई मांगों को लेकर अगस्त से आंदोलन कर रहे थे. उनकी मांग थी कि निर्वाचन क्षेत्र भूगोल की बजाय जनसंख्या के आधार पर तय हों.
- सेना और पुलिस प्रहरी में मधेशियों को समानुपाति और समावेशी अधिकार मिले.
- गैर नेपाली महिला से शादी होने पर पूर्ण नागरिकता के लिए 20 वर्ष नेपाल में रहने की अनिवार्य शर्त में संशोधन हो अथवा उसे समाप्त किया जाए.
- संघीय ढांचे के ऊपरी सदन यानी राष्ट्रीय सभा में हर राज्य से 8 सदस्य मनोनीत करने की बजाय जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या तय हो.
- साथ ही उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सभा, उप सभा प्रमुख और निकाय सभा प्रमुख जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार मिले.

इन सबके अतिरिक्त सबसे बड़ा विवाद नेपाल के नए बने राज्यों को लेकर था. आरोप है कि नेपाल में 7 नए राज्यों का बंटवारा ऐसे किया गया है जिसकी वजह से मधेसी समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने आप कम हो जाएगा. इन्हीं मुद्दों को लेकर नेपाल में मधेसी आंदोलन कर रहे हैं.

नेपाल सरकार ने जिन दो मांगों को मानने का फैसला किया है उसमें आनुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्र के फिर से सीमांकन की मांग शामिल है. नेपाल की जनसंख्या 2 करोड़ 60 लाख के करीब है जिसमें 52 लाख मधेसी हैं.

यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध की अवधि को छह महीने बढ़ाया

यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने 21 दिसंबर 2015 को रूस के खिलाफ लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्ध की अवधि को छह महीने बढ़ाया. यह प्रतिबन्ध रूस द्वारा यूक्रेन संकट में शामिल होने के कारण लगाये गये थे. 28 सदस्यों वाली सभा ने यह प्रतिबन्ध 31 जुलाई 2016 तक बढ़ा दिए हैं.

इसमें रूस के आर्थिक, उर्जा एवं रक्षा क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है. इन प्रतिबंधों को मिन्स्क शांति समझौते के बाद रूस द्वारा दिखाई गयी प्रतिबद्धता के आधार पर तैयार किया गया है. रूस द्वारा फरवरी 2015 सीज़फायर पर हस्ताक्षर के बाद भी यूक्रेन में हमले नहीं रुके हैं. इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि रूस समर्थित विद्रोही शांति समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस गोलीबारी में 8000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त, यूरोपियन यूनियन ने व्लादिमीर पुतिन एवं उनके सहयोगियों पर वीज़ा प्रतिबन्ध एवं संपत्तियों को सील कर दिया गया है.

अमेरिकी सीनेट द्वारा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने हेतु आईएमएफ के सुधारों को स्वीकृति

संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 19 दिसंबर 2015 को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने हेतु आईएमएफ के सुधारों को स्वीकृति प्रदान की गयी. अब यह अनुमोदन राष्ट्रपति बराक ओबामा की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा.

यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे भारत एवं चीन जैसे देशों को आईएमएफ में विशेष स्थान हासिल होगा.

बदलाव

- चीन के वोटिंग अधिकार 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो जायेंगे जिससे यह देश संस्था में तीसरा सबसे बड़ा शेयरहोल्डर बन जायेगा. अभी यह छठे स्थान पर है.
- इससे आईएमएफ के स्रोत बढ़कर 660 बिलियन डॉलर के हो जायेंगे.
- चीन के वोटिंग अधिकार बढ़ने से अमेरिका का वोटिंग अधिकार 16.7 प्रतिशत से 16.5 प्रतिशत पर आ जायेगा.
- नयी व्यवस्था के तहत आईएमएफ बोर्ड को पूरी तरह फिर से चुना जायेगा.
- भारत का वोटिंग अधिकार भी 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो जायेगा.
- इन सुधारों में यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं के वोटिंग अधिकार कम हो जायेंगे.
- वीटो का अधिकार अमेरिका के पास बना रहेगा.

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बनाये गये आईएमएफ एवं विश्व बैंक में यह सबसे बड़ा बदलाव है.

इस निर्णय से चीन की मुद्रा रेंबिंबी को अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन एवं ब्रिटिश पोंड के समकक्ष स्थान प्राप्त होगा.

आईएमएफ सुधारों पर 188 सदस्यों ने वर्ष 2010 में स्वीकृति जाहिर की थी.

10वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने नैरोबी पैकेज अपनाया

19 दिसंबर 2014 को केन्या के नैरोबी में पांच दिनों तक चला 10वें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हो गया. सम्मेलन का समापन नैरोबी पैकेज को अपनाने के साथ हुआ. नैरोबी पैकेज का उद्देश्य सबसे गरीब सदस्यों को लाभ पहुंचाना है.

सम्मेलन में डब्ल्यूटीओ के 162 सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों ने हिस्सा लिया. भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमन ने किया. किसी अफ्रीकी देश द्वारा ऐसी बैठक की मेजबानी पहली बार की गई थी.

नैरोबी पैकेज में कृषि, कपास और सबसे कम विकसित देशों से संबंधित मामलों पर छह मंत्रीस्तरीय फैसले किए गए. इनमें शामिल हैं-

कृषि

विकासशील देशों के सदस्यों के पास कृषि उत्पादों के लिए विशेष सुरक्षा प्रणाली (एसएसएम) अपनाने का अधिकार होगा.

खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सरकारी स्टॉकहोल्डिंग से संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने और स्थायी समाधान अपनाने के लिए सदस्यों को सकारात्मक वार्ता करनी होगी और सभी ठोस प्रयास करने होंगे.

कृषि उत्पादों के संबंध में, विकसित सदस्यों को तत्काल अपने अनुसूचित शेष निर्यात सब्सिडी अधिकारों को खत्म करना होगा जबकि विकासशील देश के सदस्यों को 2018 तक अपनी निर्यात सब्सिडी अधिकारों को समाप्त करना होगा.

कपास

कपास संबंधी फैसले में कृषि के तीन तत्व शामिल हैं- बाजार पहुंच, घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा.

बाजार पहुंच पर, कपास के लिए विकसित देशों ने विकासशील देशों के बाजारों में ड्यूटी-फ्री और कोटा- फ्री पहुंच की बात की और विकासशील देशों ने ऐसा 1 जनवरी 2016 से करने की घोषणा की.

कपास के घरेलू समर्थन पर सदस्यों ने अपने घरेलू कपास नीतियों में सुधार करने और इस दिशा में अभी भी और अधिक प्रयास किए जाने पर जोर दिया.

कपास के निर्यात प्रतिस्पर्धा पर फैसले में विकसित देशों द्वारा कपास निर्यात सब्सिडी को तत्काल बंद करने और विकासशील देशों का बाद में ऐसे करना अनिवार्य किया .

एलडीसी मामले

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने जो फैसला किया वह अल्प- विकसित देशों द्वारा विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में एलडीसी के पक्ष में एकतरफा तरजीही व्यापार व्यवस्था के तहत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए अवसर मुहैया कराएगा.

सेवा क्षेत्र में सम्मेलन में अल्प विकसित देशों में सेवा और सेवा आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में अधिमान्य व्यवहार को लागू करने का फैसला किया. साथ ही सेवा व्यापार में एलडीसी की भागीदारी को बढ़ाने की भी बात की.

विस्तारित सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए)

उपरोक्त फैसलों के साथ- साथ, सम्मेलन में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सालाना मूल्य वाले 201 सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर से शुल्क समाप्त करने के ऐतिहासिक समझौते को लागू करने हेतु समयसारिणी बनाने पर सहमति व्यक्त की. विस्तारित आईटीए पर डब्ल्यूटीओ के 53 देशों ने वार्ता का आयोजन किया था. इसमें विकसित और विकासशील दोनों ही देश शामिल थे. ये देश इन उत्पादों के विश्व व्यापार में करीब 90 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं.

विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड रेमिटेंस फैक्टबुक 2016 जारी किया

18 दिसंबर 2015 को विश्व बैंक समूह के ग्लोबल नौलेज पार्टनर्शिप ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (केएनओएमएडी) पहल ने माइग्रेशन एंड रेमिटेंस फैक्टबुक 2016 जारी किया.

रिपोर्ट में 214 देशों और क्षेत्रों के लिए आप्रवासन, विदेशगमन, कुशल विदेशगमन और प्रेषण प्रवाह पर नवीनतम आंकड़े दिए गए हैं.

इसने 2011 के संस्करण को द्विपक्षीय आप्रवासन और प्रेषण एवं द्वितीय पीढ़ी के प्रसार एवं शरणार्थियों के वर्तमान गतिविधियों पर अतिरिक्त आंकड़ों के साथ अद्यतन किया है.

रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में लोगों के आर्थिक अवसरों की खोज की वजह से अंतरराष्ट्रीय आप्रवासियों की संख्या 250 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है.

साल 2015 में प्रेषित धन के मामले में 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमान के साथ भारत सबसे बड़ा देश था, इसके बाद चीन (64 बिलियन) और फिलीपींस (30 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आते हैं.

रिपोर्ट की विशेषताएं

- तेजी से विकास करते विकासशील देश विकासशील दुनिया के अन्य हिस्सों से लोगों को बड़े पैमाने पर आकर्षित कर रहे हैं.
- दक्षिण- दक्षिण पलायन दक्षिण- उत्तर पलायन के मुकाबले बड़ा है. साल 2013 में उन्नत देशों से विकासशील देशों में जाने वाले 34 फीसदी लोगों के मुकाबले विकासशील देशों से अन्य विकासशील देशों में जाने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत 38 फीसदी था.
- शीर्ष 10 प्रवासी स्रोत देश थे- भारत, मैक्सिको, रूस, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, यूक्रेन और यूनाइटेड किंग्डम.
- शीर्ष 10 प्रवासी गंतव्य देश थे- संयुक्त राज्य अमेरिका, सउदी अरब, जर्मनी, रूस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंग्डम, फ्रांस, कनाडा, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया.
- साल 2015 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों अपने देश में रहने वाले उनके परिवारों को 601 मिलियन अमेरिकी डॉलर भेजेंगे, विकासशील देश 441 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करेंगे.
- साल 2014 में अनुमानित 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा धन प्रेषित करने वाला (रेमिटेंस) स्रोत देश था. इसके बाद सउदी अरब (37 बिलियन) और रूस (33 बिलियन) रहा.

प्रेषण और प्रवासी बचत मिलकर विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो विकासशील देशों में लोगों के जीवन और आजीविका में सुधार ला सकते हैं.

- मैक्सिको- संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी कॉरिडोर था, साल 2013 में इस कॉरिडोर में 13 मिलियन प्रवासी आए. रूस- यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा देश था, इसके बाद बांग्लादेश- भारत और यूक्रेन- रूस का स्थान था.
- साल 2014 में, 14.4 मिलियन शरणार्थी थे (5.1 मिलियन फिलीस्तीनी शरणार्थियों को छोड़कर) ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का 6 फीसदी था.
- तुर्की, पाकिस्तान, लेबनान, इरान, इथियोपिया, जॉर्डन, केन्या, चाड और यूगांडा सबसे बड़े मेजबान देश रहे. करीब 86 फीसदी शरणार्थियों की मेजबानी विकासशील देश कर रहे थे. इसके विपरीत विकसित देशों में शरणार्थियों की संख्या 1.6 मिलियन थी.

डब्ल्यूटीओ ने 163वें सदस्य के तौर पर अफगानिस्तान की सदस्यता शर्तों को मंजूरी दी

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 17 दिसंबर 2015 को केन्या की राजधानी नैरोबी में डब्ल्यूटीओ के दसवीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी10) में सर्वसम्मति से अफगानिस्तान की डब्ल्यूटीओ सदस्या को मंजूरी दे दी.

इसके साथ ही अफगानिस्तान डब्ल्यूटीओ का 163वां सदस्य बन गया. इसके साथ ही अफगानिस्तान 1995 में गठित इस संगठन का सदस्य बनने वाला नौंवा सबसे कम विकसित देश भी बना.

परिग्रहण का प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल ऑफ एक्सेशन- पीओए) पर आधिकारिक तौर पर महानिदेशक रॉबर्टो अजावेदो और अफगानिस्तान के पहले उप मुख्य कार्यकारी मोहम्मद खान रहमानी ने हस्ताक्षर किए.

डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन जाने के बाद अफगानिस्तान को अब सौदे की पुष्टि 30 जून 2016 तक करनी होगी. पुष्टि करने और डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के लिए अपने पीओए की स्वीकृति की अधिसूचना के बाद उसे अगले 30 दिनों तक इंतजार करना होगा.

अफगानिस्तान ने 2004 में इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया था और कार्यकारी पार्टी के सदस्यों ने वार्ता 11 नंवबर 2015 को पूरी की.

संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद राष्ट्रीय एकता सरकार पर लीबियाई राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ

17 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद राष्ट्रीय एकता सरकार पर लीबियाई राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हो गया. हस्ताक्षर मोरक्को के खीरत (Skhirat) शहर में किए गए.

समझौते में शांतिपूर्ण और समृद्ध लीबिया के लिए वैध संस्थाओं का एकल सेट बनाने की बात कही गई है.

समझौते में राष्ट्रीय मतौक्य की एकल सरकार और राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की बात भी है जो व्यापक प्रतिनिधि सुनिश्चित करेगा जो कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों से स्पष्ट है.

समझौते पर संयुक्त राष्ट्र- सुविधा लीबिया राजनीतिक वार्ता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने हस्ताक्षर किया. ये मुख्य रूप से दो प्रतिद्वंदी संसदों और सरकारों- त्रिपोली के जनरल नेशनल कांग्रेस और टोब्रुक में संयुक्त राष्ट्र मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि थे.

वार्ता में लीबियाई समाज के लोगों को भी शामिल किया गया था जिसमें सदस्यों के साथ- साथ लीबिया के राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, नगरपालिकाओं और महिला समूहों के महत्वपूर्ण नेता शामिल थे.

समझौते को अंतिम रूप देने में मार्टिन कोबलर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वे महासचिव के विशेष प्रतिनिधि और लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थन मिशन (यूएनएसएमआईएल) के प्रमुख थे.

समझौते का महत्व

कई समस्याओं- एक से अधिक सरकारों, आतंकवाद और भूख से जूझ रहे लीबिया में इस समझौते से स्थिरता आने की उम्मीद है.

साल 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के अपदस्थ किए जाने के बाद से यह देश हिंसा के जरिए कई हिस्सों में बांट दिया गया.

दो शक्तिशाली गुटों के बीच संघर्ष 2014 में तब बढ़ गया जब दोनों ही गुटों ने उत्तरी अफ्रीका के इस तेल-समृद्ध देश पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिद्वंदी सरकारों की स्थापना कर दी.

फिलहाल देश के पूर्वी हिस्से में अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सरकार है और इसकी राजधानी त्रिपोली में इस्लामी मिलिशिया- समर्थित सरकार है.

दो सरकारों के बीच के अंदरूनी कलह की वजह से हाल के समय में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लीवेंट या आईएसआईएल काफी मजबूत हो गया है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, 2.4 मिलियन से अधिक लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है जिसमें से 435000 लोगों के देश में ही विस्थापित होने का अनुमान है.

आईएलओ ने ग्लोबल इस्टिमेट्स ऑन माइग्रेट वर्कर्स जारी किया

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 16 दिसंबर 2015 को ग्लोबल इस्टिमेट्स ऑन माइग्रेट वर्कर्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया. यह रिपोर्ट एक सांख्यिकीय अध्ययन है जो दुनिया भर में प्रवासियों की कुल संख्या के बीच श्रम प्रवासी मजदूरों के अनुपात का अनुमान लगता है.

इसने अंतरराष्ट्रीय प्रवासी मजदूरों वाले क्षेत्रों और उद्योगों को रेखांकित किया है और नवीनतम संख्या के साथ घरेलू कामकाज में लगे प्रवासियों पर विशेष फोकस किया है.

अध्ययन की आम विशेषताएं

- 'प्रवासी मजदूर- माइग्रेंट वर्कर' शब्द उन सभी अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए है जो फिलहाल काम कर रहे हैं या जो बेरोजगार हैं और जिस देश में वे रह रहे हैं वहां नौकरी की तलाश कर रहे हैं.
- दुनिया के करीब 232 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में से प्रवासी मजदूरों की आबादी 150.3 मिलियन है.
- प्रवासी मजदूरों के बीच, 83.7 मिलियन पुरुष और 66.6 मिलियन महिलाएं हैं, जो कुल का क्रमशः 55.7 फीसदी और 44.3 फीसदी है.
- प्रवासी कुल वैश्विक आबादी का 3.9 फीसदी हैं (15 वर्ष और उससे अधिक वाले), हालांकि, सभी मजदूरों के बीच प्रवासी मजदूरों का अनुपात अधिक है (4.4 फीसदी).
- गैर- प्रवासियों के 63.9 फीसदी की तुलना में प्रवासियों का श्रम शक्ति भागीदारी दर 72.2 फीसदी है.
- प्रवासियों और गैर- प्रवासी मजदूरों के बीच उच्च श्रम शक्ति भागीदारी का अंतर प्रवासी महिलाएं गैर- प्रवासी महिलाओं की तुलना में अधिका काम करती हैं (67.0 फीसदी बनाम 50.8 फीसदी).
- प्रवासी और गैर- प्रवासी पुरुष के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर में कोई खास अंतर नहीं है (78.0 फीसदी बनाम 77.2 फीसदी).

क्षेत्रवार प्रवासन श्रम

- प्रवासी मजदूरों का करीब आधा (48.5 फीसदी) दो व्यापक उप- क्षेत्रों में मिलते हैं- उत्तरी अमेरिका और उत्तरी, दक्षिणी एवं पश्चिमी यूरोप.
- इन दो क्षेत्रों में कुल महिला प्रवासी मजदूरों का करीब 52.9 फीसदी और कुल पुरुष प्रवासी मजदूरों का 45.1 फीसदी मिलता है.
- 36.5 फीसदी के साथ सभी मजदूरों के हिस्से के तौर पर अरब देशों में प्रवासी मजदूरों का अनुपात सबसे अधिक है. हालांकि, पुरुष प्रवासी मजदूरों का प्रतिशत 17.9 फीसदी है और महिला प्रवासी मजदूरों का प्रतिशत सिर्फ 4.0.
- इन उप- क्षेत्रों के बाद पूर्वी यूरोप (9.2फीसदी) और दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत (7.8 फीसदी) का स्थान आता है.
- कई उपक्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों का अनुपात 2 फीसदी से भी कम है. सबसे कम हिस्सेदारी - 0.6 फीसदी, पूर्वी एशिया (जिसमें चीन शामिल है) में है. इसके बाद उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया (भारत आता है) और लातिन अमेरिका और कैरेबिया आता है. इन सभी इलाकों में 1.0 - 1.5 फीसदी प्रवासी मजदूर मिलते हैं.

प्रवासी मजदूरों का आर्थिक वर्गीकरण

- प्रवासी मजूदरों की काफी संख्या उच्च- आमदनी वाले देशों में है. प्रवासी मजदूरों के 150.3 मिलियन के वैश्विक कुल में अनुमान के अनुसार 112.3 मिलियन (74.7 फीसदी) उच्च आमदनी वाले देशों में वर्गीकृत हैं.
- 17.5 मिलियन (11.7 फीसदी) उच्च- मध्यम आमदनी वाले देशों और 16.9 मिलियन (11.3 फीसदी) निम्न- मध्यम आमदनी वाले देशों में हैं.
- निम्न- आमदनी वाले देशों में प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे कम है, यह मात्र 3.5 मिलियन (2.4 फीसदी) है.
- साल 2013 में प्रवासी मजदूरों का काफी संख्या सेवा क्षेत्र में लगी थी, कुल 150.3 मिलियन में से 106.8 मिलियन यानि 71.1 फीसदी.
- विनिर्माण एवं निर्माण उद्योग समेत उद्योगों में 26.7 मिलियन (17.8 फीसदी) और कृषि क्षेत्र में 16.7 मिलियन (11.1 फीसदी) थे.

घरेलू काम और प्रवासी मजदूर

- घरेलू काम 11 मिलियन से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. दुनिया में 67.1 मिलियन घरेलू कामगार हैं जिनमें से 11.5 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी हैं. दुनिया भर में सभी घरेलू मजदूरों का 17.2 फीसदी और सभी प्रवासी मजदूरों का 7.7 फीसदी अंतरराष्ट्रीय प्रवासी हैं, 2013 में दुनिया का प्रत्येक छठा घरेलू कामगार अंतरराष्ट्रीय प्रवासी था.
- दक्षिण- पूर्व एशिया और प्रशांत में सभी प्रवासी घरेलू कामगारों में करीब 73.4 फीसदी (या करीब 8.5 मिलियन) महिलाएं हैं, यह 24.0 फीसदी के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है.
- घरेलू कामकाज के लिए उल्लेखनीय क्षेत्रीय मतभेदों के साथ पुरुष प्रवासी मजदूर बहुत कम पसंद किए जाते हैं.
- दुनिया के आधे पुरुष प्रवासी घरेलू कामगार अरब देशों में हैं.
- प्रवासी घरेलू कामगारों का बहुत अधिक अनुपात उच्च- आमदनी वाले देशों में है.

रिपोर्ट के बारे में

आईएलओ के अनुसार, रिपोर्ट में अनुमानों की गणना के लिए इस्तेमाल की गई तारीख गंतव्य देश में प्रवासी मजदूरों और 2013 में प्रवासियों की संख्या की गणना के लिए किया गया है. 176 देशों और क्षेत्रों का कुल आंकड़ा दुनिया के कामकाजी लोगों की आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक) का 99.8 फीसदी का प्रतिनिधित्व

करता है, इसे भी अध्ययन में शामिल किया गया है. आईएलओ द्वारा कन्वेंशन 143 की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है. कन्वेंशन 143 अपमानजनक शर्तों में प्रवास और प्रवासी मजदूरों के लिए अवसरों एवं व्यवहार की समानता को बढ़ावा देने से संबंधित है जिसे 1975 के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अपनाया गया था.

वर्ष 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा

संयुक्त राष्ट्र ने 10 नवंबर 2015 को इटली में आधिकारिक रूप से वर्ष 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की.

वर्ष 2015 के दिसम्बर माह में यह तब चर्चा में आया जब केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने घरेलू दलहन का उत्पादन और आत्म निर्भरता की आवश्यकता विषय पर भारत नीति द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में इसकी चर्चा की.

केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि इस वर्ष के अंतर्गत किसानो को बीज की नई तकनीक एवं प्रसार के कार्यक्रम की योजना बनाई जाएगी तथा दलहन की ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों की प्रजातियों के शोध पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा.

विदित हो भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक है. भारत में दलहन का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 17.20 मिलियन टन था.

सरकार ने देश में दलहन के उत्पादन के बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) परियोजना के अंतर्गत कई कदम उठाए है जैसे एनएफएसएम के कुल आवंटन का लगभग 50% दलहन के लिए दिया जाता है.

अन्तर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के बारे में

- वर्ष 2013 में यूएन मुख्यालय में आयोजित 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई.
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), सरकारों, प्रासंगिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सभी प्रासंगिक हितधारकों को इस वर्ष के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
- एक अग्रिणी पोषक तत्व के रूप में दलहन के महत्व को देखते हुए वर्ष 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया. पोषक तत्व के रूप में विकसित और विकासशील देशों के

लिए इसका अपना ही महत्व है.

- इस वर्ष का उद्देश्य दलहन के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है.
- इस वर्ष के आयोजन से दालों के वैश्विक उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है.

दलहन

दलहन एक वार्षिक फलीदार फसल है जिसे भोजन और चारे के रूप मिंज प्रयोग में लाया जाता है.

खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दलहन को एक ऐसी फलीदार फसल के सूखे अनाज के रूप में परिभाषित किया गया है अतः यह तेल निष्कर्षण वाली फसलों और सब्जियों से भिन्न है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से आईएस की धन की आपूर्ति रोकने का फैसला किया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 17 दिसम्बर 2015 को प्रथम आतंकवाद विरोधी वित्त मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कर आईएस जैसे आतंकी संगठनों के पूंजी स्रोतों को रोकने का फैसला किया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने बैठक के दौरान आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के बाहरी आय के स्रोतों को बंद करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की.

अमेरिका और रूस द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव में सभी देशों से आईएस को होने वाली आमदनी को रोकने के अपने प्रयासों में और तेजी लाने का आग्रह किया गया.

उनसे ऐसे हर संभव प्रयास करने को कहा गया है जिससे सबसे ताकतवर और अमीर हो चुके आतंकवादी संगठन आईएस को वित्तीय मदद न मिल सके.

प्रस्ताव में आईएस की मुख्य आमदनी के स्रोतों तेल और पुरानी कलाकृतियों की ब्रिकी से होने वाली आय को रोकना प्रमुख रूप से शामिल है.

यह प्रस्ताव 1999 के उस प्रस्ताव पर आधारित है जो सबसे पहले अलकायदा को लक्ष्य करके पारित किया गया था.

प्रस्ताव की मंजूरी के बाद उचित क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया.

इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद जो राज्य आईएस की मदद करेगा उस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू होंगे.

विदित हो कि सुरक्षा परिषद ने ऐसा ही प्रस्ताव फरवरी में भी पारित किया था लेकिन बाद में इसके उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं.

भारत संयुक्त राष्ट्र के आपात प्रतिक्रिया कोष में पांच लाख डॉलर का योगदान देगा

भारत ने 18 दिसम्बर 2015 को वैश्विक मानवीय राहत अभियानों में सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र की त्वरित प्रतिक्रिया कोष प्रणाली में वर्ष 2015-16 की अवधि में पांच लाख डॉलर का योगदान देने की घोषणा की.

भारत ने वर्ष 2014 में केंद्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (सीईआरएफ) में पांच लाख डॉलर का योगदान दिया था.

इतना ही योगदान भारत ने वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए भी देने की घोषणा की है.

विदित हो वर्ष 2015 में भारत ने इबोला ट्रस्ट कोष में एक करोड़ डॉलर का योगदान दिया , इसके अतिरिक्त वर्ष 2015 में युद्धरत यमन में फंसे भारतीयों ओर कई विदेशी नागरिकों को निकालने में भी भारत ने मदद की है.

सीईआरएफ

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से तत्काल राहत लाने के लिए दिसंबर 2005 में इस कोष की स्थापना की.
- वर्ष 2014 में दक्षिण सूडान, सूडान और इथियोपिया तीन सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे.

भारत और स्पेन के बीच बंदरगाह मामलों में सहयोग हेतु समझौते पत्र को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 2015 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और स्पेन के बीच बंदरगाहों से जुड़े मामलों पर सहयोग हेतु समझौते पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई. बंदरगाहों के मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग से होने वाले लाभ को देखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर का फैसला किया गया.

भारत और स्पेन के बीच इस समझौते का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों और समुद्र से जुड़े मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और एक दूसरे की ओर से परस्पर मदद और विचार-विमर्श को बढ़ावा देना है.

उपरोक्त समझौते पत्र पर हस्ताक्षर से दोनों देशों में बंदरगाहों को बढ़ावा देने और उन्हें विकसित करने में मदद मिलेगी. इससे समुद्री यातायात को भी बढ़ावा मिलेगा. अलग-अलग समुद्री संस्थानों के कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं के बीच प्रशिक्षण और जानकारियों का आदान-प्रदान हो सकेगा. इससे बंदरगाहों से वाणिज्यक वस्तुओं का परिवहन और तेज होगा. दोनों देशों के संयुक्त उपक्रमों की वजह से बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा. उनकी क्षमता बढ़ेगी. इसके साथ ही मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण होगा. साथ ही पर्यावरण अनुकूल बंदरगाहों के विकास, बंदरगाह इंजीनियरिंग, समुद्री प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी और बंदरगाह से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

आतंकवाद के विरुद्ध सऊदी अरब ने की 34 देशों के गठबंधन की घोषणा

सऊदी अरब की सरकार ने 15 दिसम्बर 2015 को आतंकवाद से लड़ने के लिए एक सैन्य गठबंधन के गठन की घोषणा की है.

इस गठबंधन में शामिल होने वाले 34 देशों में मुख्य रूप से मुस्लिम देश शामिल हैं.

इस गठबंधन का संचालन-केंद्र सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थापित किया जाएगा.

इस गठबंधन में एशिया, अफ्रीका और अरब देश शमिल हैं परन्तु सऊदी अरब का मुख्य प्रतिद्वंदी इरान इस गठबंधन में शामिल नहीं है.

यह कदम सऊदी अरब द्वारा ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक समुदाय द्वारा खाड़ी देशों से आतंकवाद के विरूद्ध एकत्र होकर लड़ने का दबाव है.

यह गठबंधन इराक, सीरिया, लीबिया, मिस्र और अफगानिस्तान में सक्रीय तंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्य करेगा. इस गठबंधन में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देश शमिल होंगे.

इसके अतिरिक्त एशिया से मालदीव, बांग्लादेश और मलेशिया ने भी गठबंधन का हिस्सा बनने के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है.

पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन जो की एक गैर मुस्लिम बाहुल्य देश है, भी इस गठबन्धन का हिस्सा है.

विदित हो आतंकवाद से जूझ रहे देश इराक, अफगानिस्तान और सीरिया इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है.

गठबंधन के 34 सदस्यों की सूची इस प्रकार है - सऊदी अरब, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, चाड, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, गैबॉन, गिनी, आइवरी कोस्ट, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, मोरक्को, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीस्तीन, कतर, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, ट्यूनीशिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन.

इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया ने भी इस गठबंधन का सदस्य बनने की इक्षा प्रकट की है.

भारत और जापान ने 16 दस्तावेजों के आदान-प्रदान सहित असैन्य परमाणु ऊर्जा पर समझौता किया

12 दिसंबर 2015 को भारत और जापान ने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग समेत 16 द्विपक्षीय दस्तावेजों का आदान- प्रदान किया. दस्तावेजों का आदान- प्रदान जापान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में हुआ.

इसके अलावा दोनों पक्षों ने भारत- प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के लिए भारत और जापान विजन 2025: विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के विषय पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया.

आदान- प्रदान किए गए दस्तावेजों की सूची इस प्रकार हैः

असैन्य परमाणु सहयोग पर करारः परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में सहयोग पर करार संबंधी समझौता ज्ञापन

उच्च गति वाले रेलवे पर करारः मुंबई और अहमदाबाद के बीच, जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराये जाने का प्रावधान इस करार में है.

रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी सहयोग पर करारः इसके तहत संयुक्त अनुसंधान, विकास और/या उत्पादन परियोजनाओं को लागू करने के लिए अनिवार्य रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी को एक दूसरे को उपलब्ध करा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान की गयी है.

वर्गीकृत सैन्य जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के विषय में करारः यह एक- दूसरे को प्रेषित की जाने वाली वर्गीकृत सैन्य जानकारी के पारस्परिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बशर्ते सुरक्षा की शर्त प्राप्तकर्ता पक्ष के राष्ट्रीय कानून और नियमों के अनुसार हों.

दोहरे कराधान से बचाव के समझौते में संशोधन पर करारः यह करार भारत और जापान के बीच आयकर के

संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम हेतु 1989 में किए गए करार में संशोधन की बात करता है.

रेल क्षेत्र में रेलवे मंत्रालयों और एमएलआईटी पर तकनीकी सहयोग पर समझौताः इसके जरिये सूचना साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं, एक दूसरे के साथ अधिकारियों और तकनीशियनों का आदान- प्रदान करना समेत व्यापक प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए क्षेत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया है.

अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) और जापान रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (जेआरटीआरआई) के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौताः यह समझौता रेल संचालन में सुरक्षा, रखरखाव के उन्नत तकनीक, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों आदि के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव देता है.

भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं जापान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी के बीच सामरिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम पर आशय पत्रः इसके तहत सहयोगी गतिविधियों जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भौतिक विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा और सहयोग देना शामिल है.

डीएसटी, भारत और जापान सोसायटी फॉर द प्रोमोशन ऑफ साइंस के बीच युवा अनुसंधानकर्ताओं के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आशय पत्रः इसके जरिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए पारस्परिक फेलोशिप कार्यक्रम की स्थापना करने का प्रावधान है.

मेडिकल उत्पाद विनियमन वार्ता और सहयोग रूपरेखा पर एमओसीः यह समझौता केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, जापान के बीच किया गया ताकि दवा के उपयोग, जैविक उत्पादों के लिए कच्चे माल पर रचनात्मक वार्ता की सुविधा मिल सके और प्रासंगिक प्रशासनिक एवं नियामक मामलों को दोनों पक्षों के क्षेत्राधिकार में लाया जा सके.

शिक्षा के क्षेत्र में एमओसीः दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच अनुबंधों एवं सहयोग को बढ़ावा देने और भारत एवं जापान के बीच इच्छुक छात्रों के आदान- प्रदान के लिए संभव हर समर्थन प्रदान करना.

नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स, जापान (आईईईजे) के बीच आशय पत्रः यह ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित मामलो में सहयोग को बढ़ावा देने के व्यापक मिशन से संबंधित है ताकि ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच की जा सके और उसे समझा जा सके.

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और टोयामा के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनः यह आर्थिक आदान- प्रदान के क्षेत्रों, दवा उत्पादन उद्योग, सांस्कृतिक आदान- प्रदान, पर्यटन, व्यक्तिगत और अकादमिक आदान- प्रदान के क्षेत्र में आपसी सहयोग की सुविधा प्रदान करने से सम्बंधित है.

केरल सरकार और लेक नाकायूमि, लेक शिंजी और माउंट डायसेन एरिया मेयर्स एसोसिएशन के बीच समझौताः इसके तहत दोनों ही पक्ष लघु एवं मध्यम उद्यमों पर फोकस के साथ व्यापार इकाइयों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों के विकास पर सहमत हुए हैं.

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएमए) और नेशनल ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज (जीआरआईपीएस) के बीच करारः इसके तहत दोनों ही संस्थानों के बीच बौद्धिक माहौल को बेहतर बनाने की बात की गयी है.

वन एवं वानिकी के क्षेत्र में करारः यह करार मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संस्थानों, सतत वन प्रबंधन, वन संरक्षण की वृद्धि और वन आपदा रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास की बात करता है.

आईएईए ने ईरान परमाणु कार्यक्रम पर 12 वर्ष लम्बी जांच समाप्त की

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी(आईएईए) ने 15 दिसम्बर 2015 को ईरान परमाणु कार्यक्रम पर की जा रही 12 वर्ष लम्बी जांच को समाप्त करने की घोषणा की.

एजेंसी को यह आशंका थी की ईरान परमाणु कार्यक्रम का प्रयोग रणनीतिक मामलों के लिए कर रहा है.

जाँच समाप्ति के सन्दर्भ में आईएईए के गवर्नर्स बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया. इसके साथ ही एजेंसी ने अधिकृत संस्थाओं को ईरान पर लचर निगरानी के निर्देश भी दिए हैं.

विदित हो इससे पूर्व वर्ष 2015 के जुलाई माह में ईरान और पी5+1 राष्ट्रों के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके तहत इरान पर लगाए गए विभिन्न तरह के प्रतिबंधोन को समाप्त कर दिया गया था.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी(आईएईए) के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त विश्व संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है.
- यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है.
- इस संस्था का गठन 2 9 जुलाई, 1 9 57 को हुआ था.
- इसका मुख्यालय वियना, आस्ट्रिया में है.

भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर 12 दिसंबर 2015 को एक समझौता हुआ. दिल्ली

के हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.

बुलेट ट्रेन समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य:

- बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान भारत को कुल 12 अरब डॉलर यानी करीब 80,400 करोड़ रुपये का लोन देगा.
- इसमें खास बात यह है कि जापान ने भारत को यह कर्ज महज 0.1 पर्सेंट की ब्याज दर पर देने का ऐलान किया है.
- जापान, भारत को 50 साल की अवधि के लिए यह कर्ज देगा. जिस पर 15 साल तक कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा.
- जापान के साथ मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए करार किया गया है.
- रक्षा उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए भी दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए.
- इसके अलावा जापान ने भारत में अगले पांच सालों में 35 अरब डॉलर यानी करीब 2,34,500 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की.
- दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते को लेकर भी करार हुआ.

विदित हो कि कुल 98 हजार करोड़ रूपये के इस समझौते पर करार के बाद दिए गए साझा बयान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारतीय रेलवे में क्रांतिकारी कदम बताया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जापानियों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दिए जाने की भी घोषणा की.

सउदी अरब में पहली बार महिलाओं ने स्थानीय निकाय चुनावों में जीत दर्ज की

12 दिसंबर 2015 को सउदी अरब के इतिहास में सरकारी स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पहली बार महिलाओं के मतदान देने और चुनाव में खड़े होने पर 20 महिला उम्मीदवारों ने चुनावों में जीत दर्ज की.

चुनाव में विजयी रहने वाली महिलाएं सउदी अरब के दूसरे सबसे बड़े शहर जेद्दा से लेकर छोटे कस्बों एवं देश के विभिन्न हिस्सों की निवासी हैं.

नगर परिषद के चुनाव के लिए खड़े हुए करीब 7,000 उम्मीदवारों में 979 महिलाएं थीं. नगर परिषद एक मात्र सरकारी निकाय है जिसके लिए चयन देश के नागरिक करते हैं. इससे पहले इसके लिए 2005 और 2011 में चुनाव हुए थे जिनमें केवल पुरूष भाग ले सकते थे.

नगर परिषद के इन चुनावों में लगभग 2100 सीटों के लिए मतदान हुआ जिनमें महिला उम्मीदवारों द्वारा केवल एक प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की गयी. इसे देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इससे पूर्व महिलाओं को मतदान करने एवं चुनाव लड़ने तक की पाबंदी थी.

राजधानी रियाद में सर्वाधिक चार महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. ईस्टर्न प्रोविंस में दो महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की जबकि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर जेद्दा में दो और सबसे रूढीवादी इलाकों में शामिल कासिम में एक महिला उम्मीदवार का चयन हुआ.

काबा के शहर से उत्तर में करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मदरका नामक गांव से भी एक महिला का चयन किया गया. गौरतलब है कि काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थल हैं, जहां दुनियाभर के मुस्लिम इबादत के लिए जुटते हैं.

भारत एवं जापान के बीच दोहरे कराधान समझौते में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर

भारत सरकार और जापान सरकार ने दोहरे कराधान को टालने और आय पर टैक्स के संदर्भ में राजकोषीय चोरी रोकने के लिए मौजूदा समझौते में संशोधन करने हेतु 11 दिसंबर 2015 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए. भारत सरकार की ओर से राजस्व सचिव डॉ. हसमुख अधिया और जापान सरकार की ओर से जापान के राजदूत केंजी हीरामत्सुक ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये.

इस प्रोटोकॉल में कर संबंधी सूचनाओं के कारगर ढंग से आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का जिक्र है, जिनमें बैंक सूचनाओं संबंधी कर मसलों पर सूचनाएं और बगैर घरेलू कर हित वाली सूचनाएं भी शामिल हैं. इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भारत के किसी निवासी के संबंध में जापान से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उन्हें जापान के सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है. इसी तरह जापान के किसी निवासी के संबंध में भारत से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उन्हें भारत के सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है.

उपर्युक्त प्रोटोकॉल में इस बात का उल्लेख है कि भारत और जापान दोनों ही राजस्व दावों के संग्रह में एक-

दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे. इस प्रोटोकॉल में सरकार/सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थानों द्वारा बीमित ऋण-दावों के संदर्भ में स्रोत देश में ब्याज आय को टैक्स से छूट दिये जाने का भी उल्लेख है.

विदित हो कि निवर्तमान मूल समझौते पर भारत एवं जापान के बीच हस्ताक्षर वर्ष 1989 में किये गये थे.

भारत-पाकिस्तान ने 8 सूत्रीय समग्र वार्ता को 10 सूत्रीय व्यापक द्विपक्षीय वार्ता से बदलने पर सहमति जताई

भारत एवं पाकिस्तान ने 9 दिसंबर 2015 को 8 सूत्रीय समग्र वार्ता को 10 सूत्रीय व्यापक द्विपक्षीय (सीबीडी) वार्ता से बदलने पर सहमति जताई.

यह निर्णय इस्लामाबाद में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश सचिव सरताज अज़ीज़ के बीच बैठक के बाद जारी किया गया.

व्यापक द्विपक्षीय वार्ता के अंतर्गत शामिल मुद्दे

1. शांति एवं सुरक्षा, विश्वास बहाली के उपाय
2. जम्मू एवं कश्मीर
3. सियाचिन
4. सर क्रीक
5. वुल्लर बैराज/तुलबुल परियोजना
6. आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग
7. आतंकवाद का मुकाबला एवं ड्रग्स के प्रसार पर नियंत्रण
8. मानवीय मुद्दे
9. लोगों का अवागमन
10. धार्मिक पर्यटन

पिछले आठ मुद्दों में मानवीय मुद्दे एवं धार्मिक पर्यटन को जोड़ा गया है ताकि शांति बहाली एवं सौहार्द को बढ़ाया जा सके.

इनके अतिरिक्त द्विपक्षीय वार्ता में शामिल मुद्दे हैं :

- दोनों देशों के सुरक्षा सचिवों को आतंकवाद पर बातचीत करनी चाहिए, पहली बार एनएसए द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर बात की गयी.

- पाकिस्तान द्वारा मुंबई हमलों के आरोपियों पर सुनवाई तेज़ करने का आश्वासन.
- निश्चित समय सीमा में सचिव स्तर की वार्ता करना.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 में सार्क सम्मेलन हेतु पाकिस्तान यात्रा.

व्यापक द्विपक्षीय वार्ता

इसका आरंभ मई 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ द्वारा किया गया था.

इसे समझौते का नाम दिया गया तथा इसमें वर्ष 1947 में हुए विभाजन के उपरांत सभी मुद्दों को शामिल किये जाने का प्रयास किया गया.

जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे को शामिल किये जाने से इस वार्ता को बल मिला लेकिन 26 नवम्बर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान के लश्करे-तैबा समूह के 10 अतंकवादियों द्वारा हमले से यह वार्ता स्थगित हो गयी थी.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीन में प्रताड़ना के खिलाफ अपील जारी

संयुक्त राष्ट्र की उत्पीडन के खिलाफ बनी समिति ने 9 दिसंबर 2015 को चीन की जेलों में बंद राजनैतिक अपराधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने हेतु अपील जारी की. संयुक्त राष्ट्र की यह अपील चीन में बढ़ती प्रताड़ना की घटनाओं को देखते हुए जारी की गयी.

समिति ने कहा कि 200 से अधिक कार्यकर्ता एवं वकील जुलाई से अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं जबकि इनमें 25 लोगों को निगरानी में रखा गया है.

संयुक्त राष्ट्र समिति ने कहा कि चीन की जेलों में प्रताड़ना और दुर्व्यवहार बड़े पैमाने पर गहरी जड़ें जमा चुका है एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर निषिद्ध अभ्यास को देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल किया जा रहा है. वर्ष 2014 में मानवाधिकार कार्यकर्ता चाओ शुनली की जेल में लम्बे समय तक प्रताड़ना झेलने के पश्चात् अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी.

यूएन ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के लिए 'साहेल ह्यूमेनिटेरियन अपील फॉर 2016' का शुभारम्भ किया

संयुक्त राष्ट्र ने 9 दिसंबर 2015 को अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के लिए 2016 के लिए 'साहेल ह्यूमेनिटेरियन अपील फॉर 2016' का शुभारंभ किया.

साहेल ह्यूमेनिटेरियन अपील फॉर 2016 के अंतर्गत अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में आने वाले 9 देशों को 1.98 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी.

साहेल ह्यूमेनिटेरियन अपील फॉर 2016 का लक्ष्य विस्थापित लोगों को आवश्यक खाद्य, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पानी और साफ-सफाई प्रदान करना है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार

- वर्तमान में साहेल क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 150 मिलियन है.
- प्रत्येक 6 लोगों में 1 का खाद्य असुरक्षित है.
- प्रत्येक 25 में 1 को तत्काल खाद्य की आवश्यकता है.
- प्रत्येक 5 बच्चों में 1 कुपोषित है.
- लगभग 4.5 मिलियन लोग इस क्षेत्र से विवादों के चलते विस्थापित हो चुके हैं.

यूएन के मानवीय मामलों के समन्वय के लिए कार्यालय(ओसीएचए) ने अनुमान लगाया है की वर्ष 2016 तक इस क्षेत्र के 23.5 मिलियन लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी उचित मात्र में उपलब्ध नहीं होगा.

इन 23.5 मिलियन लोगों में से 6 मिलियन लोगों को तत्काल खाद्य सहायता चाहिए होगी और 5.9 मिलियन बच्चे कुपोषित होंगे.

साहेल क्षेत्र

- साहेल या सहेल पट्टी अफ़्रीका के पश्चिम से पुर्व तक फ़ैला एक क्षेत्र है.
- यह क्षेत्र सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानो से पृथक करता है.
- सहेल पट्टी की लंबाई 3862 किलोमीटर है.
- यह अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फ़ैली हुई है.

- इस पट्टी की चोड़ाई कुछ सौ किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक है.
- सहेल पट्टी गाम्बिया,सेनेगल, मॉरीतानिया, माली, बुर्किनाफासो,नाइजर, नाईजीरिया, चाड, केमरून मे फ़ैली हुई है.

विदित हो साहेल क्षेत्र में विस्थापन, गरीबी और मृत्यु के पीछे कई कारण हैं जिनमें प्राकृतिक आपदा, महामारी, आतंकवाद आदि शामिल हैं.

वर्ष 2016 को इंग्लैंड-भारत शिक्षा अनुसंधान एवं नवाचार वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया

भारत और इंग्लैंड ने 9 दिसम्बर 2015 को एक संयुक्त कार्यक्रम आरंभ किया जिसका नाम है, 2016: को इंग्लैंड-भारत शिक्षा अनुसंधान एवं नवाचार वर्ष.

इसका आरंभ इंग्लैंड के राज्य, व्यापार नवाचार और कौशल सचिव साजिद जाविद एवं भारत की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया.

मुख्य विशेषताएं

- इसके अंतर्गत इंग्लैंड के अकादमीशियन भारत में ग्लोबल इनिशिएटीव ऑफ़ अकादमिक नेटवर्क्स प्रोग्राम के तहत भारत आ सकेंगे.
- इसके द्वारा दस शोध क्षेत्रों में इंप्रिंट के तहत साझेदारी को बढ़ावा दिया जायेगा.
- इससे दोनों देशों के बीच शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी.
- इससे सस्थानों में तकनीकी प्रयोग बढ़ेगा एवं रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे. इन सभी क्षेत्रों पर इंग्लैंड के सहयोग से कार्य किया जायेगा जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करेगा.
- इसके अतिरिक्त साजिद जाविद ने चेवनिंग गुरुकुल फैलोशिप कार्यक्रम के 20वें वर्ष के आरम्भ किये जाने की भी घोषणा की.

इंग्लैंड-भारत शिक्षा एवं अनुसंधान चरण-III

जाविद ने यह भी कहा कि वे इंग्लैंड-भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के तीसरे चरण से यह आशा करते हैं कि दोनों देश इस संबंध में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करेंगे.

वार्षिक 3 मिलियन पौंड वाले इस तीसरे चरण का आरम्भ 1 अप्रैल 2016 से होगा. अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय मुद्दों के लिए आधारभूत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया जायेगा.

यह नेतृत्व और संकाय विकास, शिक्षा प्रणाली में कौशल का एकीकरण, ई-साझेदारी एवं मोबिलिटी को बढ़ावा पर केन्द्रित होगी.

पृष्ठभूमि

इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमेरून द्वारा किया गया. इसकी घोषणा नवम्बर 2015 को मोदी की इंग्लैंड यात्रा के दौरान की गयी.

अमेरिकी सदन ने वीजा वीवर प्रोग्राम इंप्रूवमेंट एक्ट ऑफ 2015 को पारित किया

8 दिसंबर 2015 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने वीजा वीवर प्रोग्राम इंप्रूवमेंट एक्ट ऑफ 2015 पारित कर दिया. इसने अमेरिका के वीजा पर्यटन प्रथाओं में संशोधन किया है.

इराक, सीरिया और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल देशों की यात्रा करने वाले लोग जो अमेरिका में बिना वीजा के यात्रा करना चाहते थे, पर प्रतिबंध लगाने की इच्छा रखने वाले सांसदों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया. विधेयक के पक्ष में 407 और विपक्ष में 19 मत पड़े.

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक 1 मार्च 2011 के बाद इराक, सीरिया, ईरान और सूडान की यात्रा करने वाले लोगों को वीजा-मुक्त कार्यक्रम का हिस्सा बनने से रोकेगा.
- बदलावों में वीजा वीवर प्रोग्राम में शामिल देशों को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ जानकारी साझा करना और बायोमेट्रिक सूचना के साथ ई- पासपोर्ट जारी करना शामिल है.
- विधेयक में यात्रियों की इंटरपोल डाटाबेस में जांच किए जाने का भी प्रावधान किया गया है.
- इसके पारित होने के बाद अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को वीजा छूट वाले देशों का लगातार मूल्यांकन करना होगा कि क्या ये देश अमेरिकी सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम वाले हैं और अगर ऐसा है तो उन्हें प्रोग्राम से निलंबित किया जा सकता है.

प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद अधिनियम को सीनेट में पारित होने और राष्ट्रपति बराक ओबामा के

अनुमोदन की जरूरत है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि करीब 5000 यूरोपीय (वीजा वीवर प्रोग्राम देशों समेत) नागरिकों ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) जैसे उग्रवादी समूहों से लड़ाई करने के लिए सीरिया और इराक का दौरा किया है और ये अमेरिका के लिए खतरा हैं.

प्रस्तावित विधेयक में कानून प्रवर्तन और खुफिया समुदाय के साथ सहयोग नहीं करने वाले देशों को अमेरिका द्वारा वीजा वीवर प्रोग्राम से हटाए जाने का भी प्रावधान है.

वीजा वीवर प्रोग्राम (वीडब्ल्यूपी) 38 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनमें अधिकतर अमेरिका के सहयोगी देश और अपेक्षाकृत स्थिर विकसित लोकतंत्र शामिल हैं. यह प्रोग्राम इन देशों के नागरिकों को अमेरिका में 90 दिनों या उससे कम के लिए आने पर दूतावास से वीजा लिए बिना आने की अनुमति देता है.

रिपोर्टों के अनुसा वीजा वीवर प्रोग्राम के तहत सालाना 20 मिलियन पर्यटक अमेरिका आते हैं.

ओप्पोसीशन डेमोक्रेटिक यूनिटी राउंड टेबल ने वेनेजुएला संसद चुनाव में जीत दर्ज की

वेनेजुएला की ओप्पोसीशन डेमोक्रेटिक यूनिटी राउंड टेबल (एमयूडी) ने 6 दिसम्बर 2015 को हुए संसद चुनावों में जीत दर्ज की.

जीसस टोरीअल्बा की अध्यक्षता वाली पार्टी को 167 सीटों वाली विधानसभा में 110 सीटें प्राप्त हुई जबकि तत्कालीन शासित यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ़ वेनेजुएला (पीएसयूवी) को 55 सीटें हासिल हुई.

निकोलस मदुरो पीएसयूवी के अध्यक्ष हैं.

पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ पीएसयूवी की स्थापना की थी, इस पार्टी को वर्ष 1999 के बाद सबसे कम मत मिले.

विभिन्न कारणों के अलावा, 100 प्रतिशत महंगाई, अर्थव्यवस्था में 10 प्रतिशत गिरावट एवं 2016 में 18.1 प्रतिशत बेरोज़गारी का अनुमान पार्टी की हार के मुख्य कारण हैं.

न्यूजीलैंड औपचारिक रूप से एआईआईबी का नया सदस्य बना

न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री बिल इंग्लिश ने 8 दिसम्बर 2015 को न्यूजीलैंड के औपचारिक रूप से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) का सदस्य बनने की घोषणा की.

न्यूजीलैंड के एआईआईबी से जुडऩे से बैंक के संचालन के लिए आवश्यक 50 प्रतिशत हिस्सेदारी पूरा करने में मददगार हो सकता है.

एआईआईबी का औपचारिक रूप से संस्थापक सदस्य बनने वाला न्यूजीलैंड नौंवा देश है.

न्यूजीलैंड एआईआईबी की स्थापना पर चर्चा में शामिल होने वाला पहला विकसित पश्चिमी देश है.

विदित हो क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एआईआईबी की शुरुआती पूंजी लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर की होगी. इस बैंक के जनवरी 2016 में परिचालन शुरू करने की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड का पेडअप कैप्टल 125 मिलियन न्यूज़ीलैंड डॉलर होगा. जो उसे पाँच वर्षों में देना होगा.

एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक (एआईआईबी) के बारे में

- एशिया के 21 देशों के प्रतिनिधियों ने बीजिंग में 24 अक्टूबर 2014 को एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक (एआईआईबी) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
- एआईआईबी एशिया में बुनियादी ढांचे के निर्माण के वित्तपोषण के लिए बनाया गया है और इसका मुख्यालय बीजिंग में होगा.

यह एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसे अन्य वित्तीय संस्थानों की तरह बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाएगा.

एआईआईबी की मुख्य विशेषताएं

- बैंक की अधिकृत पूंजी 100 अरब अमरीकी डॉलर होगी.
- एशियाई देश कुल पूंजी का 75 प्रतिशत तक योगदान देंगे.
- कुल 100 अरब अमरीकी डॉलर में चीन 29.78 अरब अमरीकी डॉलर का.

बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए परिवर्तनकारी कार्बन एसेट सुविधा शुरू की गयी

चार यूरोपियन देशों जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन एवं स्विट्ज़रलैंड ने 30 नवम्बर 2015 को पेरिस में परिवर्तनकारी कार्बन एसेट सुविधा (टीसीएएफ) कार्यक्रम आरंभ किया ताकि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन पर वृहद स्तर पर कार्यवाही की जा सके. वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन देशों के साथ इस कार्यक्रम को बढ़ाने में भूमिका निभा रहा है.

500 मिलियन के इस कार्यक्रम में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के नए उपायों की खोज की जाएगी ताकि जलवायु परिवर्तन संबंधी हो रहे नुकसान से बचा जा सके.

परिवर्तनकारी कार्बन एसेट सुविधा

- इसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपायों पर विभिन्न देशों के साथ नए उपायों की खोज की जाएगी.
- उत्सर्जन को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा, परिवहन, ऊर्जा दक्षता, ठोस कचरा प्रबंधन और कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहरों पर बल दिया जायेगा.
- इसके अंतर्गत जो देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान भी किया जायेगा.
- यह वैश्विक पहल और राष्ट्रीय जलवायु योजना की एक सीमा के साथ काम करेंगे जिससे विकसित एवं विकासशील दोनों देशों को लाभ होगा.
- यह अन्तरराष्ट्रीय मानकों के तहत उच्च पर्यावरण अखंडता को बनाये रखने हेतु अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करेगा.
- यह वर्ष 2016 से कार्य करना आरंभ करेगा जिसके तहत विभिन्न देशों द्वारा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया जायेगा.
- पूंजीगत योगदान की सीमा तब तक खुली रहेगी जब तक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता.
- एक अनुमान के अनुसार, इस नई सुविधा में विश्व बैंक समूह द्वारा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जायेगा.

भारत को कनाडा से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त

भारत को 4 दिसम्बर 2015 को कनाडा से लगभग 2730 टन यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त हुई. यह यूरेनियम भारत के परमाणु उर्जा संयंत्रों के लिए लाया गया.

यह खेप उत्तरी सस्केचेवान स्थित केमको के मेकआर्थर रिवर एवं की लेक पर तैयार हुई है.

खेप सम्बन्धी बिंदु

- यह खेप कनाडा की केमको इंक द्वारा भेजी गयी है जिसके लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2015 में ओटावा यात्रा के दौरान समझौता हुआ था.
- इससे चार दशक पहले वर्ष 1974 में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण करने पर कनाडा ने विरोध दर्ज किया था. कनाडा ने भारत को किसी भी प्रकार का यूरेनियम उपलब्ध कराने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया था.

भारत-कनाडा परमाणु समझौता

- अप्रैल 2015 में, केमको ने भारत के साथ यूरेनियम आपूर्ति हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसे सितंबर 2013 में हुए भारत-कनाडा परमाणु सहयोग समझौते के आधार पर तैयार किया गया.
- इस समझौते के अनुसार कनाडा की केमको कारपोरेशन भारत को वर्ष 2020 तक 7.1 मिलियन टन यूरेनियम उपलब्ध कराएगी.
- इस समझौते की लागत 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर है.

चीन के बिजली संचालित पहले विमान आरक्स1 ई (RX1E) के उत्पादन को मंजूरी दी

चीन में घरेलू स्तर पर विकसित बिजली चालित विमान आरक्स1 ई (RX1E) को चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन ने 4 दिसम्बर 2015 को उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी है.

आरक्स1 ई (RX1E) बिजली की रोशनी-स्पोर्ट विमान शेनयांग एयरोस्पेस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया. यह चीन का पहला मानवयुक्त बिजली चालित विमान होगा.

आरक्स1 ई (RX1E) स्पोर्ट विमान की मुख्य विशेषताएं-

- दो सीटों वाल यह विमान लिथियम बैटरी द्वारा संचालित है.
- यह 3000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है.
- 90 मिनट के रिचार्ज के बाद यह 45 से 60 मिनट तक उड़ान भरने के लिए सक्षम है.
- विमान पायलट प्रशिक्षण पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के साथ ही प्रायोगिक उड़ान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
- यह 480 किलो का अधिकतम टेकऑफ़ वजन और प्रति घंटे 160 किलोमीटर की क्रूज गति से उड़ान भर सकता हैं.

अमेरिकी सेना में सभी लड़ाकू भूमिकाएं निभाएंगी महिलाएं

मेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने 4 दिसम्बर 2015 को पेंटागन में ऐतिहासिक फैसले के तहत सेना के सभी पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की घोषणा की. इस निर्णय से सभी अग्रिम मोर्चों पर महिलाएं लड़ाकू भूमिका भी निभा सकेंगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने पेंटागन के इस कदम की सराहना की.

फैसले का प्रभाव-

- अमेरिका में महिलाएं को अब युद्ध में टैंक ड्राइव करने, मोर्टार को फायर करने और पैदल सैनिकों का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाएगी.
- महिलाएं सेना में रेंजर बन सकती हैं. ग्रीन टोपियां पहन सकती हैं, नौसेना में जवान, मरीन कोर पैदल सेना, वायु सेना, पैराजम्पिंग के अलावा वो सब कार्य जिन पर सेना में अब तक पुरूषों का अधिकार था उन सभी दायित्वों का निर्वाह कर सकेंगी.
- पेंटागन का यह फैसला अमेरिका में महिलाओं के लिए दो लाख बीस हजार (220,000) सैन्य नौकरियां उपलब्ध कराएगा.
- अमेरिका में नौसेना और वायु सेना ने पहले ही लगभग सभी मोर्चों पर महिलाओं के लिए नियुक्ति के दरवाजे खोल दिए हैं. थल सेना में भी इसे अनिवार्य किया गया है.
- अमेरिकी सेना में अभी भी कुल सैनिकों (पैदल सेना और बुनियादी प्रशिक्षुओं) की संख्या का 93 प्रतिशत पुरुष सैनिक हैं.

अमेरिकी सेना में अब तक महिलाओं की स्थिति-

- लगभग 10 प्रतिशत पदों को छोड़कर पिछले सात वर्षों से ओबामा प्रशासन धीरे-धीरे महिलाओं की सशस्त्र बलों में भर्ती कर रहा है.
- इससे पूर्व ये 10 प्रतिशत पद ऐसे थे जिन पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जा सकती. इन पदों में पैदल सेना, बख्तरबंद, टोही बल और कुछ विशेष अभियान इकाइयां शामिल थीं. अब इन सभी पदों पर महिलाओं को अपनी योग्यता दिखाने का मौका दिया जाएगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीजा सुविधा पर भारत और ईरान के बीच समझौता करने को मंजूरी दी

2 दिसंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनयिक, आधिकारिक/ सेवा और सामान्य पासपोर्ट धारकों को वीजा सुविधा दिए जाने वाले भारत और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर की अनुमति दे दी.

समझौते के अनुसार वीजा आवेदन के साथ विदेशी मामलों के स्थानीय मंत्रालय द्वारा आधिकारिक नोट दिखाए जाने पर मेजबान देश में निवासी, राजनयिक मिशन, 20 कामकाजी दिनों के भीतर, 90 दिनों के लिए वैध मुफ्त वीजा राजनयिक मिशनों या वाणिज्य दूतावास पर दीर्घ कालिक मिशन पर भेजे जाने वाले वैध राजनयिक/ आधिकारिक/ सेवा पासपोर्ट धारकों को जारी किया जायेगा.

परिवार के करीबी सदस्यों (खून संबंध जैसे माता- पिता, भाई- बहन, व्यस्क बच्चे और सास- ससुर) के लिए तीन माह का वैध उचित मुफ्त वीजा और अन्य करीबी रिश्तेदारों के लिए वीजा, वीजा शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाएगा.

समझौते की मुख्य विशेषताएं

- समझौते के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक नोट दिए जाने पर जिसमें दौरे का उद्देश्य लिखा हो, एक गैर- विस्तारणीय मुफ्त प्रवेश वीजा, पंद्रह दिनों की वैधता के साथ राजनीतिक अधिकारियों और नौकरशाहों को विशेष द्विपक्षीय उद्देश्यों या किसी सम्मेलन या सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए तीन कार्यकारी दिवस के भीतर जारी किया जाएगा.
- यह तीन माह की वैधता वाला बहु- प्रवेश मुफ्त वीजा देने की अनुमति देता है. प्रत्येक दौरे में 20 दिनों तक रह सकते हैं.ऑडिट/ वित्त और आईटी/ कंप्यूटर अधिकारियों को जो अपने संबंधित कूटनीतिक मिशनों

या वाणिज्य दूतावास पर कथित आधिकारिक व्यापार के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हों, को 15 कार्यकारी दिवसों के भीतर यह वीजा जारी किया जाएगा.

- विशेष प्रशासनिक मजबूरियों के तहत, राजनयिक मिशनों या वाणिज्य दूतावास में अस्थायी तैनाती के लिए मेजबान देश में तीन माह की वैधता वाला एकल- प्रवेश मुफ्त वीजा 15 कार्यकारी दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा.
- शिक्षकों और उनके आश्रित जीवनसाथी और बच्चों के वीजा आवेदन के साथ स्थानीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक नोट दिखाने पर बीस कार्यदिवसों के भीतर तीन माह की वैधता वाला एकल प्रवेश सेवा/ आधिकारिक मुफ्त वीजा जारी किया जाएगा.
- यह समझौता आधिकारिक नोट जो दोनों पक्षों द्वारा कानूनी औपचारिकताओं के पूरे किए जाने की बात कही गई हो, पर हस्ताक्षर और हस्तांतरण के बाद प्रभाव में आ जाएगा.
- यह समझौता अनिश्चित काल के लिए मान्य होगा. इसे प्रत्येक पक्ष कम- से- कम 60 दिन पहले राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए लिखित नोटिस देकर समझौते को समाप्त कर सकता है.
- प्रत्येक देश को अपने संबंधित कानून और नियमों के तहत दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में प्रवेश करने, उनके रुकने की अवधि को कम करने या समाप्त करने का अधिकार होगा.
- इस समझौते को किसी भी समय दोनों देशों के लिखित फैसला और आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है.इस समझौते की व्याख्या, कार्यान्वयन या लागू करने के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान दोनों देशों के बीच परामर्श या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा.

आईएमएफ ने चीन की मुद्रा युआन को विशिष्ट वर्ग आरक्षित मुद्रा के रूप में मंजूरी दी

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 30 नवंबर 2015 को चीन की मुद्रा युआन को मान्यता प्राप्त मुद्रा यानि अभिजात वर्ग की आरक्षित मुद्रा के रूप में शामिल कर लिया. युआन की मान्यता 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होगी. युआन को चीनी रॅन्मिन्बी (आरएमबी) के रूप में भी जाना जाता है. युआन को आईएमएफ परिवार में शामिल करने से पहले मौजूदा मानदंडो का परीक्षण किया गया. उस परीक्षण पर सटीक होने के बाद कार्यकारी बोर्ड विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) ने नियमित रूप से पाँच-वार्षिक समीक्षाओं के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया.

समावेशन क्या है?

युआन स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्रा होगी और अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड के साथ साथ, पांचवें मुद्रा के रूप में एसडीआर बास्केट में शामिल किया जाएगा.

1 अक्टूबर 2016 को नए एसडीआर परिवार का परिचय होगा, इन परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए कोष अन्य सदस्यों को और एसडीआर नेतृत्व उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त समय प्रदान करेगा.

आईएमएफ परिवार में विविधता लाने और दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के प्रतिनिधियों की संख्या बढाकर एसडीआर के आकर्षण में वृद्धि करने के लिए आरएमबी को आईएमएफ में शामिल किया गया है.

एसडीआर में युआन का समायोजन चीन के द्रष्टिकोण से बड़ी राजनीतिक जीत है. आरक्षित मुद्रा के रूप में युआन की वांछनीयता को निवेशकों के बीच बढ़ाना, वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर के वर्चस्व को कमजोर करेगा.

वैश्विक वित्तीय प्रणाली में चीनी अर्थव्यवस्था के एकीकरण का यह निर्णय महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा.

यह भी देखने में आया है कि चीनी अधिकारियों ने चीन की मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों में सुधार के लिए पिछले कुछ वर्षों में सराहनीय प्रगति की है.

एक एसडीआर क्या है?

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) प्रणाली को 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ब्रेटन वुड्स स्थिर विनिमय दर प्रणाली को सहयोग करने के लिए बनाया था.

आईएमएफ, एसडीआर के बजाय अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति का उपयोग अपने सदस्य देशों के मौद्रिक भंडार के पूरक रूप में करता है. एसडीआर का मूल्यांकन चार अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के परिवार पर आधारित है. "स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य" मुद्राओं के साथ एसडीआर का विनिमय किया जा सकता है.

अक्टूबर 2016 से समय-समय पर एसडीआर आईएमएफ के सदस्यों को आवंटित करता रहता है. युआन के जुड़ जाने के बाद आईएमएफ में पांच मुद्रा हो जाएगी.

इसके अलावा एसडीआर, आईएमएफ पर दावा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर संभावित दावा है.

एसडीआर को जोड़ पाने के लिए मापदंड क्या हैं?

एसडीआर बास्केट जिस पर एसडीआर का मूल्य आधारित है की आम तौर पर आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड

द्वारा हर पांच साल में समीक्षा की जाती है. समीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि एसडीआर वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है या नहीं.

1999 में पिछली बार नई मुद्रा यूरो को जोड़ा गया था, जबकि तकनीकी रूप से इसे निवर्तमान जर्मन देत्स्मार्क और फ्रेंच फ्रैंक से प्रतिस्थापित किया गया था.

एसडीआर का पात्र बनने के लिए मुख्य मानदण्ड हैं-

निर्यात मानदंड: बास्केट का एक हिस्सा बनने के लिए, किसी भी देश का निर्यात पांच साल की अवधि में सबसे अधिक मूल्य का होना चाहिए. दूसरे शब्दों में मुद्रा बास्केट में शामिल होने के लिए आईएमएफ के सदस्यों या मुद्रा यूनियनों द्वारा जारी किए गए सम्बंधित देश की मुद्रा वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हो.

स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मानदंड: बास्केट का सदस्य होने के लिए आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा "स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्रा" सुनुश्चित की जानी चाहिए. जैसा कि शाब्दिक अर्थ है, मुद्रा व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए भुगतान के लिए इस्तेमाल की जा रही हो और व्यापक रूप से बाजार में कारोबार विनिमय कर रही हो.

रॅन्मिन्बी, चीन रिपब्लिक के कम्युनिस्ट पीपुल्स द्वारा 1949 में इसकी स्थापना के समय मुद्रा को दिया गया अधिकारिक नाम है. यानी यह लोगों की मुद्रा है.

दूसरी ओर शब्द युआन रॅन्मिन्बी से पीछे रह जाता है. युआन डॉलर (ढाला चांदी का सिक्का) के लिए चीनी शब्द है.

ब्राज़ील में दीर्घ आर्थिक मंदी का दौर

ब्राजील की अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून की तुलना में जुलाई-सितंबर के दौरान 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी. इस संबंध में 1 दिसम्बर 2015 को सरकार की ओर से घोषणा की गयी.

जनवरी 2015 से अब तक यह ब्राज़ील की अर्थव्यवथा में लगातार तीसरी गिरावट है जो कि वर्ष 1930 से अब तक की सबसे अधिक दीर्घावधि मंदी है.

ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के जुड़े मुख्य बिंदु

- अक्टूबर 2015 में महंगाई की दर 10 प्रतिशत तक बढ़ गयी जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है.
- वर्ष 2014-15 में बेरोज़गारी की दर 6.8 प्रतिशत थी जो जुलाई-सितंबर 2015 में बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गयी.
- कम आय के कारण घरेलू खर्च में जुलाई-सितंबर 2015 के दौरान 4.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.

- ब्राज़ील की मुद्रा, रियल, में जनवरी-नवम्बर 2015 के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गयी.
- ब्राज़ील का शेयर बाज़ार बोवेस्पा, सितंबर 2014 से 27 प्रतिशत मंदी की मार झेल रहा है.
- घरेलू एवं विदेशी निवेश में भी पिछले नौ महीनों में बहुत गिरावट दर्ज की गयी.

आर्थिक मंदी के कारण

इसमें विभिन्न कारण शामिल हैं जैसे वैश्विक मंदी, निर्यात में कमी एवं सरकार संचालित तेल कंपनी पेट्रोब्रास का घोटाला. इस सभी कारणों से देश की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ा एवं आर्थिक मंदी को बढ़ावा मिला.

भारत और फ्रांस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारम्भ

भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया.

इस गठबंधन का शुभारम्भ पेरिस,फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन(कोप 21) के दौरान संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा किया गया.

सम्मेलन के दौरान कर्क और मकर रेखा के निकट स्थित देशों से इस गठबंधन में शामिल होने का आह्वाहन किया गया.

यह गठबंधन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुड़गांव से संचालित होगा.

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय के निर्माण के लिए 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर और जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा भी की.

गठबंधन की मुख्य विशेषताएं

- इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय देशों को सौर्य उर्जा के उचित दोहन के लिए एक मंच पर लाना है.
- यह गठबंधन सौर्य ऊर्जा के क्षेत्र में धनी देशों को प्रचुर संसाधनों के उचित उपयोग के लिए तैयार करेगा.
- इस गठबंधन के माध्मय से सौर्य ऊर्जा के उपयोग में आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकेगा.
- यह अलग-अलग देशों की जरूरतों के अनुसार उत्पादन और भंडारण प्रौद्योगिकी के अनुकूल होगा.
- जिन लक्ष्यों पर गठबंधन कार्य करेगा वह हैं प्रशिक्षण में सहयोग, संस्थाओं का निर्माण, विनियामक मुद्दे,

मानक और निवेश के क्षेत्र में सहयोग.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा हेतु भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2 नवम्बर 2015 को जर्मनी के साथ सौर ऊर्जा हेतु भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गयी.

इस मंजूरी से भारत में सौर उर्जा का उपयोग बढ़ सकेगा तथा भारत में तकनीकी एवं आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा. दोनों देशों के मध्य अक्टूबर 2015 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे.

इस समझौते के तहत जर्मनी भारत को अगले पांच वर्षों तक केएफडब्ल्यू द्वारा एक बिलियन यूरो का आसान लोन प्रदान करेगा. इस फण्ड का उपयोग सहयोगी बैंकों द्वारा उपयोगकर्ताओं को ऋण देने के लिए किया जायेगा.

इससे होने वाले लाभ:

- सौर उपकरण लगाने में सहायता
- सोलर पार्क और सोलर ज़ोन का विकास किया जायेगा (इसे संभवतः ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के नज़दीक विकसित किया जायेगा)
- स्वच्छ एवं सुचारू उर्जा के लिए सोलर ऑफ़-ग्रिड एप्लीकेशन्स का विकास करना.

भारत ने वर्ष 2022 तक 100 जीडब्ल्यू की सोलर पॉवर इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान के साथ डीटीएसी समझौते को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2 दिसम्बर 2015 को दोहरे कराधान से बचाव हेतु समझौते (डीटीएसी) को मंजूरी प्रदान की गयी. इसका उद्देश्य कर सम्बन्धी सूचना का आदान-प्रदान सुगम बनाना है.

डीटीएसी पर दोनों देशों ने वर्ष 1989 में हस्ताक्षर किये थे जिसका एक अन्य उद्देश्य प्रोटोकॉल के माध्यम

से राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम करना भी था.

प्रोटोकॉल द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा होगी जिसमें बैंक सम्बन्धी सूचनाएं एवं घरेलू ब्याज के बिना कर संबंधी जानकारी भी शामिल होगी.

इसके अतिरिक्त इसमें जापान से प्राप्त होने वाली सूचना को जापान अथवा भारत की संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेकर शेयर करने का प्रावधान भी शामिल है.

प्रोटोकॉल द्वारा भारत एवं जापान को कर संबंधी, कराधान से ब्याज आय में छूट एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को सहायता प्रदान करना भी शामिल है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग पर इजरायल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

2 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग के क्षेत्र में भारत और इजरायल के बीच समझौता (एमओयू) के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.

जल संसाधन मंत्रालय ने जल उपयोग दक्षता, सूक्ष्म सिंचाई, अपशिष्ट जल, विलवणीकरण, जलभृत पुनर्भरण के पुन: उपयोग में इसराइल की सफलता को ध्यान में रखते हुए इस देश के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठाने के उद्देश्य से इसराइल के साथ समझौता करने का निर्णय लिया है.

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं-

यह द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशो के मध्य जल का पर्याप्त प्रयोग,सूक्ष्म सिंचाई, रीसाइक्लिंग/अपशिष्ट जल, विलवणीकरण, जलभृत पुनर्भरण जल संरक्षण तकनीक के कुशल उपयोग की तकनीकी को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

समझौता ज्ञापन में वर्णित गतिविधियों की देख रेख के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जायेगा.

जर्मनी की कैबिनेट ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ सैन्य सहायता को मंजूरी दी

जर्मनी की कैबिनेट ने 1 दिसम्बर 2015 को इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के खिलाफ सैन्य सहायता देने हेतु आदेश जारी किया गया. इसका उद्देश्य फ्रांस एवं साथी देशों को आतंकवादी संगठन के खिलाफ सहयोग प्रदान करना है.

यह आदेश एक वर्ष तक लागू रहेगा जिसकी लागत 134 मिलियन यूरो (142 मिलियन डॉलर) है, इसे अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है.

इस जर्मन मिशन को संसद से मंजूरी दी जानी अभी बाकी है जिसमें टोर्नेडो जेट, रीफ्यूल एयरक्राफ्ट एवं अन्य युद्धक सामग्री शामिल होगी.

इसमें जर्मनी अन्तरराष्ट्रीय संगठन को सहयोग देने हेतु अपने 1200 सैनिक तैनात करेगा.

13 नवम्बर 2015 को हुए पेरिस आतंकवादी हमलों के पश्चात फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के आग्रह पर जर्मनी ने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए सहमति जताई. ओलांद ने नवम्बर 2015 के अंतिम सप्ताह में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी एवं रूस की यात्रा कर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने में सहायता का आग्रह किया था.

रोच मार्क क्रिस्टियन काबोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति निर्वाचित

रोच मार्क क्रिस्टियन काबोर 30 नवम्बर 2015 को पश्चिमी अफ़्रीकी देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किये गये.

काबोर ने 53.49 प्रतिशत मतों के साथ पहला राउंड जीता. दूसरे स्थान पर ज़ेफ्रिन दियाबरे रहे उन्हें 29.6 प्रतिशत वोट हासिल हुए जबकि ताहिरोऊ बैरी तीसरे स्थान पर रहे.

रोच मार्क क्रिस्टियन काबोर

- काबोर वर्ष 1994 से 1996 तक बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री रहे.
- वे वर्ष 2002 से 2012 तक बुर्किना फासो की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष रहे.

- वर्ष 2014 में, उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस (सीडीपी) से त्यागपत्र दे दिया एवं एक नई विरोधी पार्टी पीपल्स मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस की स्थापना की.

ब्रिक्स देशों का पहला मीडिया शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित

ब्रिक्स देशों का पहला मीडिया शिखर सम्मेलन 1 दिसम्बर 2015 को चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया गया.

सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के 25 मीडिया संगठनों ने भाग लिया. शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अध्यक्ष कै मिंगज़ाहो, प्रथम ब्रिक्स मीडिया शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष रहे.

इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स दशों के लिए एक वैकल्पिक मीडिया मंच प्रदान करना है.

चीन की समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' ने इस पहल की शुरुआत की.

यह सम्मेलन ब्राजील राष्ट्रीय संचार कंपनी, रशिया टुडे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी, द हिंदू और दक्षिण अफ्रीका इंडीपेंडेंट मीडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया.

सम्मेलन में निम्न व्यावहारिक मीडिया सहयोग स्थापित करने के लिए निम्न प्रस्ताव पारित किए गए

- ब्रिक्स मीडिया शिखर सम्मेलन के लिए संपर्क कार्यालय स्थापित किया जाए.
- सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स मीडिया फाउनडेशन द्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के पत्रकारों को सहयोग और संरक्षण प्रदान करना होगा.
- ब्रिक्स मीडिया पत्रकारिता पुरस्कार आरम्भ किया जाएंगे.
- ब्रिक्स संयुक्त फोटो प्रदर्शनी शुरू की जाएगी.
- ब्रिक्स पत्रकारों का प्रशिक्षण और आदान-प्रदान किया जाएगा.

प्रथम सम्मेलन के दौरान 25 मीडिया संघठनो और 5 ब्रिक्स देशों ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और अन्य वैश्विक मुद्दों पर एकजुट होनें की अपील की.

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर नयी पहल आरम्भ की

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 30 नवम्बर 2015 को विश्व के जलवायु परिवर्तन प्रभावित देशों में 'एंटीसिपेट, एब्सोर्ब, रीशेप' नामक पहल आरंभ की.

इसका आरंभ पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान किया गया. इसका आरंभ इसलिए भी किया गया क्योकि पिछले एक दशक में लगभग आधी अर्थव्यवस्था इस समस्या से प्रभावित है. इसके चलते अर्थशास्त्री, भोजन एवं पीने योग्य पानी मुहैया करवाने वाले लोगों पर अत्यधिक दबाव बन चुका है.

पहल की विशेषताएं

- इससे देश जलवायु संबंधित खतरों से निपटने, चुनौती स्वीकार करने एवं आशावादी रवैया अपनाने में सहायता प्राप्त करेंगे.
- इसका उद्देश्य 364 मिलियन लोगों की जरूरतों को पूरा करना है एवं विश्व की आबादी के दसवें भाग की जलवायु परिवर्तन संबंधित समस्याओं को हल करना है.
- इसमें सूखे एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहायता करना भी शामिल है.
- यह फाइनेंसिंग एवं नॉलेज को मोबिलाइज़ करने में भी सहायता करेगा तथा बड़े पैमाने पर अनुसंधान में मदद करने, नए अविष्कारों को उत्प्रेरित,करने एवं अगले पांच वर्षों में नए उपकरणों का विकास करने के लिए गतिविधियों का समन्वय करने में सहायक होगा.

राष्ट्रीय

केंद्र सरकार ने छतों पर सौर पैनल के लिए 5000 करोड मंजूर किए

केंद्र सरकार ने छतों पर सौर पैनल लगाने के अभियान को बढावा देने तथा इसे ग्रिड कनेक्शन से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन के लिए पांच हजार करोड रुपए मंजूर किए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की 30 दिसंबर 2015 को हुई बैठक में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत इस योजना की राशि को 600 करोड़ रुपए से बढाकर पांच हजार करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया.

योजना की विशेषताएं-

- इस राशि के इस्तेमाल से अगले 5 वर्षों में छतों पर सौर ऊर्जा पैनलों को ग्रिड सिस्टम से जोड़ने की योजना को क्रियान्वित किया जाएगा.
- इसके अलावा इस राशि का 4200 मेगावाट की सौर छत प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयोग किया जाएगा.सामान्य श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इसमें 30 प्रतिशत की पूंजी छूट दी जाएगी.
- विशेष श्रेणी के राज्यों- उत्तर पूर्व के राज्यों जिसमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, को 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
- निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इसमें कोई छूट हासिल नहीं होगी क्योंकि वे पहले से ही कई छूटों के हकदार हैं जैसे कि त्वरित मूल्यह्रास, कस्टम ड्यूटी रियायतें, उत्पाद शुल्क में छूट और कर छुट्टी आदि.
- 4200 मेगावाट पावर की यह क्षमता आवासीय, सरकारी, सामाजिक और संस्थागत क्षेत्र (अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों आदि) के माध्यम से आएगी.
- औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को बिना सब्सिडी के सौर छतों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

- यह बाजार का निर्माण और उपभोक्ताओं के विश्वास का निर्माण करेगा और वर्ष 2022 तक 40000 मेगावाट पावर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार मोड के माध्यम से संतुलन क्षमता सक्षम हो जाएगा.
- सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन (एनएसएम) के लक्ष्य में 2022 तक 20000 मेगावाट से बढ़ाकर 100000 मेगावाट पावर करने के लिए संशोधन किया. इसमें से 40000 मेगावाट पावर ग्रिड से जुड़े सौर छत प्रणालियों के माध्यम से आना है.
- इस मंजूरी से सौर छतों को लगाने को बढ़ावा मिलेगा और 40000 मेगावाट पावर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा.

राष्ट्रीय पुस्तकालय को संस्कृति मंत्रालय द्वारा 400 करोड़ रूपये की मंजूरी

संस्कृति मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत पुस्तकालयों के उन्नयन-आम लोगों को सेवाएं प्रदान करने की योजना के लिए 400 करोड़ रूपये की मंजूरी दी. राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के प्रमुख संघटक इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रय भारतीय वर्चुअल पुस्तकालय का गठन (एनवीएलआई);
2. एनएमएल मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना;
3. पुस्तकालयों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक सर्वे ; और
4. क्षमता निर्माण

इस योजना के तहत मिशन चुने हुए पुस्तकालयों के बुनियादी ढांचे के उन्ननयन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 35 राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों एवं 35 जिला पुस्तकालयों (राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए जाने वाले) और छह पुस्तकालयों में प्रौद्योगिकी उन्नयन करेगा. अभी तक 11 राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों एवं 11 जिला पुस्तकालयों की पहचान की गई.

संस्कृति मंत्रालय के तहत छह पुस्तकालय इस प्रकार है-

1. दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय
2. दिल्लीत खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक पुस्तकालय, पटना

3. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता

4. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, दिल्ली

5. रामपुर रजा पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश

6. तंजावूर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तमिलनाडु

इसके तहत 12 राज्यों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई एवं तीन राज्यों को कोष जारी कर दिए गए. एनएमएल के तहत बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी के उन्यन के लिए 12 राज्यों में मंजूरी प्राप्त राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों के विवरण निम्नलिखित हैं-

क्र	**राज्य / केंद्रशासित प्रदेश**	**पुस्तकालयों के नाम**	**मंजूरी प्राप्त परियोजना अनुमानित**
1.	उत्तर प्रदेश	राज्य केंद्र पुस्तकालय, इलाहाबाद	206.00
		सरकार जिला पुस्तकालय, इटावा	87.00
2.	ओडिशा	एचकेएम राज्य पुस्तकालय, भुवनेश्वर	223.00
		जिला पुस्तकालय, गंजम	40.36
3.	गोवा	कृष्णा दास शमा राज्य केंद्र पुस्तकालय	223.00
		डॉ. फ्रांसिस्को लुइस गोम्स जिला पुस्तकालय	87.00
4.	कर्नाटक	राज्य केंद्र पुस्तकालय, बेंगलूरू	223.00
		जिला केंद्र पुस्तकालय, शिवमोगा	87.00
5.	पश्चिम बंगाल	राज्य केंद्र पुस्तकालय, कोलकाता	222.81
		उत्तर बंगाल राज्य पुस्तकालय, कूचबेहार	86.98
6.	तेलंगाना	राज्य केंद्र पुस्तकालय अफजलगंज, हैदराबाद	112.25
		जिला पुस्तकालय, महबूब नगर	52.00
7.	छत्तीपसगढ़	जिला पुस्तकालय, रायगढ़	87.00
		जिला पुस्तकालय, दंतेवाड़ा	87.00
8.	त्रिपुरा	बीरचंद्र राज्य केंद्र पुस्तकालय, अगरतला	223.00
		उनाकोटी जिला पुस्तकालय कैलाशहर	87.00
9.	अरूणाचल प्रदेश	राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, इटानगर	223.00

		जिला लाइब्रेरी, पासीघाट	87.00
10.	मिजोरम	राज्य केंद्र पुस्तकालय, आइजोल	100.00
		जिला पुस्तकालय, कोलासिब	50.00
11.	राजस्थान	राज्य केंद्र पुस्त्कालय, जयपुर	100.83
12.	गुजरात	राज्य केंद्र पुस्तकालय, गांधीनगर	106.01

संस्कृति मंत्रालय के तहत पुस्तकालय

क्र.	**पुस्तकालयों के नाम**	**मंजूरी प्राप्त परियोजना अनुमानित**
1	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, दिल्ली	234.38
2	खुदा बख्शू ओरिएंटल पब्लिक पुस्तकालय, पटना	398.78
3	तंजावूर महाराजा सरफोजी पुस्तकालय, तंजावूर	691.22
4	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता	426.84
5	केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, दिल्ली	452.38

शहरी विकास मंत्रालय और ब्लूम्बर्ग फिलेंथ्रोपीज़ के बीच स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु समझौते को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी विकास मंत्रालय और न्यूयॉर्क स्थित ब्लूमबर्ग फिलेन्थ्रोपीज़ के मध्य स्मार्ट सिटी परियोजना के विकास के लिए समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर को अपनी अनुमति प्रदान की.

प्रस्ताव के अंतर्गत ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ बतौर ज्ञान साझीदार कार्य करेगा और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी चुनौती विषय पर मदद करेगा.

केंद्रीय कैबिनेट 29 अप्रैल 2015 को हुई अपनी बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन को पहले ही मंजूरी दे चुकी है और इसके पश्चात मिशन के उद्देश्यों एवं दिशानिर्देशों के साथ प्रधानमंत्री 25 जून 2015 को इसको लॉच कर चुके हैं.

समझौते की विशेषताएं

- स्मार्ट सिटी मिशन का प्रस्ताव उन्नत शहरी अवसंरचना को सुगम बनाएगा जिससे शहरी जीवन का स्वरूप बेहतर बनेगा.
- ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ गवर्नमेण्ट इनीशिएटिव्स मेयर एवं स्थानीय नेताओं को बड़ी चुनौतियों के समाधान एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नवाचार के विकास हेतु व्यावहारिक उपकरणों एवं दृष्टिकोणों से लैस करता है.
- बतौर ज्ञान साझीदार ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ शहरी चुनौतियों के प्रबंधन की रूपरेखा बनाने में शहरी विकास मंत्रालय की मदद करेगा.
- भारत सरकार पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मिशन की मदद के लिए चलाई जाने वाली गतिविधियों पर व्यय ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोंपीज़ की ओर से किया जाएगा.

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-2020 का शुभारम्भ

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-2020 का 30 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में केन्द्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, डॉ हर्षवर्धन द्वारा शुभारंभ किया गया. इस रणनीति का उद्देश्य भारत को एक विश्व स्तरीय जैव-विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करना है.

इसमें नए जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना तथा भारत के मानव संसाधनों को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश के साथ प्रमुख मिशन की शुरूआत की जाएगी.

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-2020

- मानवता की भलाई के लिए ज्ञान और साधनों का उपयोग करने को बढ़ावा देना.
- नए जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश के साथ एक प्रमुख और सुव्यवस्थित मिशन की शुरूआत करना.
- भारत के बेमिसाल मानव संसाधनों को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना.
- अनुसंधान एवं विकास और व्यवसायीकरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना.
- भारत को एक विश्व स्तर के जैव विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करना.

रणनीति के महत्वपूर्ण तत्व

- कुशल कार्यबल और नेतृत्व की स्थापना करना.
- बढ़ती हुई जैव अर्थव्यवस्था के अनुरूप ज्ञान के वातावरण को सशक्त बनाना.
- बुनियादी, विषयी, अंतर-विषयी विज्ञानों में अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देना.
- उपयोग से प्रोत्साहित खोज अनुसंधान को प्रोत्साहन देना. सग्रग विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना.
- नवाचार, ट्रांसनेशनल क्षमता और उद्यमशीलता को पोषित करना.
- एक पारदर्शी, कुशल और विश्व स्तरीय रूप से सर्वश्रेष्ठ नियामक प्रणाली और संचारण रणनीति को सुनिश्चित करना.
- जैव-प्रौद्योगिकी सहयोग- वैश्विक और राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना. पुनः तैयार किए गए प्रारूपों से युक्त संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।

रणनीति के लक्ष्य

- वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जित करने की चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारत को तैयार करना.
- हेल्थकेयर, खाद्य एवं पोषण, स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा नामक चार प्रमुख मिशनों का शुभारंभ करना.
- वैश्विक भागीदारी से पूरे देश में प्रौद्योगिकी विकास और ट्रांसनेशन नेटवर्क की स्थापना करना - 5 नए समूहों, 40 जैव-प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों, 150 टीटीओ, 20 बायो-कनेक्ट केन्द्रों की स्थापना करना.
- जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद की स्थापना करके मानवीय पूंजी का निर्माण करने में रणनीतिक और केंद्रित निवेश को बढ़ावा देना.

केरल सरकार के शराब बिक्री नियमन पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर 2015 को केरल सरकार के शराब बिक्री नियमन पर अपनी सहमति व्यक्त की. केरल सरकार के शराब बिक्री नियमन के तहत केरल में सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब बेचने की अनुमति है.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की शराबबंदी कानून पर अपनी रजामंदी जताते हुए बारों में शराब पर बैन को सही बताया. राज्य सरकार ने नई नीति के तहत केवल पंच सितारा होटलों के बारों में ही शराब परोसने की अनुमति दी है. राज्य की ओमन चांडी सरकार ने वर्ष 2014 में लाई गई अपनी नीति के तहत 10 साल के अंदर राज्य को शराब से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. केरल सरकार के अनुसार, सरकार 10 साल के भीतर राज्य को पूरी तरह से शराब मुक्त बना देगी. सिर्फ 5 स्टार होटलों को इस नीति के तहत शराब परोसने की अनुमति दी गई है. आमतौर पर केरल में प्रत्येक निवासी प्रति वर्ष 8.3 लीटर अल्कोहल पीता है. राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना करें तो यह दोगुनी मात्रा है.

विदित हो कि केरल सरकार की 10 वर्षों में राज्य में पूरी तरह से शराबबंदी लागू करने के तहत बनाई गई नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 दिसंबर 2015 को अपनी मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस नीति के तहत केरल के बारों में शराब बैन को जारी रखा. केवल पांच सितारा होटलों में शराब परोसी जाएगी, जबकि 2, 3 और 4 सितारा बार वालों की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए मंजूरी प्रदान की

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 28 दिसंबर 2015 को देश में चार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की. इनमें तीन हवाई अड्डे आंध्र प्रदेश एवं एक गुजरात स्थित धोलेरा में स्थित होगा.

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश स्थित नेल्लोर एवं कुरनूल जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तैयार हो रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी मंजूरी प्रदान की.

सबसे पहली क्लीयरेंस, साईट क्लीयरेंस 28 दिसंबर 2015 को आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में बन रहे हवाई अड्डे को दी गयी जो विशाखापत्तनम ने 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

गुजरात में प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की लागत 1378 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. ऐसा माना जा रहा है कि इससे अहमदाबाद में मौजूद हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक में भी कमी आयेगी. इस हवाई अड्डे को पहले ही पर्यावरण मंत्रालय से वर्ष 2014 में अनुमति प्राप्त हो चुकी है.

3525 एकड़ में बन रहे धोलेरा एयरपोर्ट पर दो रनवे होंगे एवं इसकी टर्मिनल बिल्डिंग में 1200 घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता होगी.

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

- इसका अर्थ है ऐसा एयरपोर्ट जिसका एक नए स्थान पर एकदम शुरू से निर्माण हो रहा हो.
- ग्रीनफील्ड शब्द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंध रखता है जिसका अर्थ है किसी परियोजना में पहले आई बाधाओं को दूर किया जाना.

जिन परियोजनाओं को संशोधित या उन्नत किया जा रहा हो उन परियोजनाओं को ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है.

केंद्र सरकार द्वारा दस लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर एलपीजी सब्सिडी नहीं देने का निर्णय

केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2015 को दस लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं देने का निर्णय लिया.

वर्तमान में देश में प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं जिसमें प्रति सिलेंडर लगभग 200 रुपये की सब्सिडी दी जाती है.

एलपीजी सब्सिडी पर नियंत्रण करने के लिए राजग सरकार की ओर से उठाया गया यह तीसरा कदम है. इससे पहले सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में देने का फैसला किया था एवं उसके बाद जनता से स्वैच्छिक तौर पर एलपीजी सब्सिडी लौटाने का कार्यक्रम चलाया गया.

'गिव अप' सब्सिडी योजना के तहत अभी तक 57.5 लाख लोगों ने सब्सिडी पर रसोई गैस लेने से मना किया. पिछले वर्ष सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के मद में 40,551 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

एलपीजी सब्सिडी समाप्ति का आदेश

- चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में एलपीजी सब्सिडी के तौर पर सरकार ने सिर्फ 8,814 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
- आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी की कर योग्य आय 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो उसे कोई एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जाएगी. इसके लिए जनवरी 2016 से ग्राहकों को स्वयं एक घोषणा पत्र देना होगा.
- वर्ष 2008-09 में तत्कालीन सरकार ने पांच लाख रुपये से अधिक की आय वाले ग्राहकों को एलपीजी

सब्सिडी देने से रोकने को लेकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था. बाद में सरकार ने वर्ष 2011 में एक वर्ष में दिए जाने वाले सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या घटा कर छह कर दी थी. पिछले चुनाव से ठीक पहले इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया जो अभी तक जारी है.

भारत पेट्रोलियम की नई क्रूड डिस्टीलेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित

केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नविस ने 28 दिसंबर 2015 को मुम्बई रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम की नई अत्याधुनिक क्रुड डिस्टीलेशन इकाई (सीडीयू) को राष्ट्र को समर्पित किया. नई क्रूड डिस्टीलेशन इकाई की क्षमता 6.0 एमएमटीपीए है और इस पर 1419 करोड़ रुपये की लागत आई है. नई इकाई पुरानी क्रूड तथा वैक्यूम इकाई के स्थान पर लगाई गई है.

नई सीडीयू के चालू होने से स्वच्छ पर्यावरण और कम उत्सर्जन के साथ ऊर्जा का कारगर इस्तेमाल होगा और ऊर्जा खपत में कमी आएगी. इस नई इकाई से सल्फर डाई आक्साइड उत्सर्जन 10.5 एमटी/डी से कम होगा. यह देश की सभी रिफाइनरियों में सबसे कम है. तरल ईंधन समानता के संदर्भ में ऊर्जा खपत लगभग 30 प्रतिशत होगी और इससे ईंधन खपत पर प्रतिवर्ष 128 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत होगी.

नई सीडीयू की डिजाइन श्रेष्ठ है और इसमें अनेक सुरक्षा विशेषताएं है. इसमें उपकरण भी कम हैं और बंद होने तथा रखरखाव की अवधि में बेहतर प्रबंधन सुविधा मिलती है. इसमें विस्फोट प्रूफ नियंत्रण कक्ष है और बंद ड्रेनेज प्रणाली है, जिससे यह सक्षम और सुरक्षित इकाई मानी जाती है. इस इकाई के स्थिर होने से 1955 सीडीयू इकाइयां समाप्त हो जाएंगी और इससे रिफाइनरी का आधुनिकरण हो सकेगा, ताकि भविष्य में ईंधन के तौर तरीकों को पूरा किया जा सकें और परियोजना लाभ बढ़ाया जा सके.

विदित हो कि बीपीसीएल की यह रिफाइनरी वर्ष 1995 में बर्मा शेल रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी. तब इसकी क्षमता 2.2 एमएमटीपीए थी. वर्ष 1976 में राष्ट्रीयकरण के बाद रिफाइनरी का विस्तार कम लागत से कायाकल्प करके तथा नई प्रौद्योगिकी अपनाकर किया गया. अभी इसकी स्थापित क्षमता 12.0 एमएमटीपीए है. इसमें तीन क्रूड तथा वैक्यूम डिस्टीलेशन इकाइयां प्रसंस्करण और शोधन क्षमताओं के साथ काम करती हैं.

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में 99 प्रतिशत मतदान का राष्ट्रीय रिकार्ड बना

कर्नाटक में 27 दिसंबर 2015 को संपन्न विधान परिषद चुनाव में 99 प्रतिशत मतदान का राष्ट्रीय रिकार्ड बना. कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के सभी 25 निर्वाचन क्षेत्रों में 99 प्रतिशत मतदान हुआ.

विदित हो कि राज्यभर की 25 विधान परिषदों में कुल 107,123 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. चुनाव में आठ महिलाओं सहित कुल 125 उम्मीदवार आमने-सामने हैं. राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 20 सीटों और जनता दल सेक्युलर (जेडी-एस) 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. 75 सदस्यीय विधान परिषद में कांग्रेस की 28 सीटें हैं, जबकि भाजपा की 30, जेडीएस की 12 सीटे हैं. वहीं चार निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि एक सीट खाली है.

केंद्र सरकार ने चार आईटी-आधारित स्वास्थ्य सेवा पहलों की घोषणा की

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने 25 दिसंबर 2015 को चार नई आईटी आधारित पहल की घोषणा की.

इन पहलों में किलकारी, मोबाइल एकेडमी और 'एम-नशा उन्मूलन' तीन एप्लिकेशन शामिल हैं. इसेक अलावा टीबी रोगियों को परामर्श और उपचार सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 शुरु किया.

भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की सालगिरह और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले सुशासन दिवस पर चार नई आईटी आधारित पहल की घोषणा की गई.

किलकारी की विषेषताएं

- किलकारी एक ऑडियो आधारित मोबाइल सेवा है, जो परिवारों को गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और उनकी देखभाल के बारे में साप्ताहिक संदेश भेजेगी.
- इसमें महिलाओं को गर्भावस्था अथवा शिशु की एक निश्चित आयु तक साप्ताहिक तौर पर प्रासंगिक संदेश प्राप्त होंगे.

- प्रत्येक गर्भवती महिला और शिशु की मां को मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली (एमसीटीएस) में पंजीकरण करवाना होगा. यह नाम पर आधारित एक वेब प्रणाली है. यह सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए सेवाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का वितरण सुनिश्चित करेगीऔर उन पर नजर रखेगी.
- इसमें लक्षित लाभार्थियों को चार माह की गर्भावस्था से लेकर शिशु के एक वर्ष के होने तक कुल 72 संदेश भेजे जाएंगे.
- इस तरह के संदेश महिलाओं एवं माता-पिता को सशक्त बनाएंगे और शिक्षित करेंगे ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जा सके.
- कार्यान्वयन में पहले चरण में छह राज्यों में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की माताओं को ये संदेश भेजे जाएंगे। ये राज्य हैं, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान
- पहले चरण में इन संदेशों को हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया भाषा में विकसित किया जाएगा. आगे चलकर पूरे देश तक पहुंचाने के लिए इन्हें दूसरी भाषाओं में भी तैयार किया जाएगा. इससे प्रतिवर्ष दो करोड़ गर्भवती महिलाओं और दो करोड़ शिशु लाभान्वित होंगे.

उत्तर भारत के पहले केबल पुल का जम्मू-कश्मीर के बसोहली में उद्घाटन

बसोहली: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित कस्बा

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित बसोहली कस्बा उस समय सुर्खियों में आया जब केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उत्तर भारत के पहले केबल पुल को राष्ट्र को समर्पित किया.

बसोहली केबल पुल

- 592 मीटर पुल का निर्माण रावी नदी के ऊपर बसोहली-दुनेरा-बनी-भद्रवाह रोड किया गया.
- पुल तीन उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच सम्पर्क मार्ग को सुगम बनाने में सहायक होगा.
- यह पुल भारत में अपनी तरह का चौथा और उत्तर भारत एवं जम्मू कश्मीर का पहला पुल है.
- इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा 145 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है.
- राज्य के केबल पुल का निर्माण मई 2011 में शुरू किया गया था और इसके पूरा होने से क्षेत्र में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

भारत में तीन प्रमुख केबल स्टेयड पुल

- विद्यासागर सेतु - कोलकाता में हुगली नदी के ऊपर
- बांद्रा-वर्ली सी लिंक - मुंबई
- यमुना पुल - इलाहाबाद में यमुना नदी के ऊपर

लोकसभा द्वारा बोनस भुगतान संशोधन विधेयक-2015 को मंजूरी दी गयी

लोकसभा में 22 दिसंबर 2015 को बोनस भुगतान संशोधन विधेयक-2015 को मंजूरी प्रदान की गयी. इसके तहत कर्मचारियों के लिए बोनस संबंधी वेतन की पात्रता को 10 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 21 हजार रुपए कर दिया गया.

इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है. इस विधेयक में मासिक बोनस आकलन की सीमा को वर्तमान 3500 रूपये से 7000 रूपये कर दिया गया.

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि यह श्रमिकों के लिए अप्रैल 2014 के प्रभाव से लागू होगा जिससे देश के करोड़ों कर्मचारियों को लाभ होगा.

न्यूनतम वेतन में एकरूपता लाने के बारे में सभी राज्यों के साथ चर्चा की जायेगी और जल्द ही इस बारे में एक राष्ट्रीय वेतन विधेयक लाया जायेगा. अभी देश में केवल 1.7 प्रतिशत ही कुशल कामगार हैं जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम है. सरकार स्किल इंडिया के तहत इसे बढ़ाना चाहती है.

गौरतलब है कि भारत में 90 प्रतिशत श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र से है तथा इसके कारण इनमें अधिकतर लोगों को लाभ नहीं मिल पाता.

बोनस भुगतान अधिनियम

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत फैक्ट्रियों व 20 या इससे अधिक संख्या में कर्मचारी वाले संस्थानों सहित कुछ संस्थानों के कर्मचारियों को सालाना बोनस भुगतान की पात्रता प्रदान करता है और संशोधन के तहत अब 21 हजार रुपये मासिक आय पाने वाले कर्मचारी बोनस के दायरे में आएंगे, जबकि यह पहले 10 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित था.

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों के लिए दो मोबाइल एप्प लांच किए

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने 23 दिसंबर 2015 को किसानों के लिए दो मोबाइल एप्प "क्रॉप इंश्योरेंस" और "एग्रीमार्केट मोबाइल" लांच की.

मोबाइल एप्प "क्रॉप इंश्योरेंस" से किसानों को न केवल उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे मं पूरी जानकारी मिलेगी बल्कि ऋण लेने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, कवरेज राशि तथा ऋण राशि की गणना में भी मदद मिलेगी.

मोबाइल एप्प "एग्रीमार्केट मोबाइल" का 50 किलोमीटर के दायरे इस्तेमाल करते हुए किसान 50 किलोमीटर के दायरे की मंडियों में फसलों का मूल्य तथा देश की अन्य मंडियों में मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है.

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय का प्रयास किसानों तथा अन्य हितधारकों को सभी आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराना है ताकि कृषि उत्पादकता और विश्वस्तरीय आय के लिए उचित वातावरण बनाया जा सके. इस दिशा में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना लांच की गई.

क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल एप्प

"क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल एप्प " से किसानों को न केवल उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी बल्कि ऋण लेने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, कवरेज राशि तथा ऋण राशि की गणना में भी मदद मिलेगी.

इसका इस्तेमाल सामान्य बीमा राशि, विस्तारित बीमा राशि, प्रीमियम ब्यौरा तथा अधिसूचित क्षेत्र मं5 किसी अधिसूचित फसल की सब्सिडी सूचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

एग्रीमार्केट मोबाइल एप्प

इस मोबाइल एप्प से किसान बाजार भावों के बारे में सूचना एकत्र कर अपना निर्णय ले सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि बिक्री के लिए उन्हें आस-पास की किस मंडी में उत्पाद ले जाना चाहिए.

यह एप्प किसानों को आस-पास के फसल मूल्यों से अवगत कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया.

एग्रीमार्केट मोबाइल एप्प के इस्तेमाल से 50 किलोमीटर के दायरे की मंडियों में फसलों का बाजार मूल्य प्राप्त किया जा सकता है.

यह एप्प स्वतः मोबाइल जीपीएस इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के स्थान की पहचान करता है और 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बाजारों में फसलों की कीमतों को उपलब्ध कराता है. यदि कोई व्यक्ति जीपीएस लोकेशन का उपयोग करना नहीं चाहता तो उसके लिए भी किसी अन्य बाजार या फसल का मूल्य प्राप्त करने का विकल्प है. मूल्य एगमार्कनेट पोर्टल से लिए जाते है.

यह दोनों मोबाइल एप्प कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के आईटी प्रभाग द्वारा विकसति किए गए और इन्हें गूगल स्टोर या एम किसान पोर्टल

http://mkisan.gov.in/Default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है.

यदि कोई राज्य इन मोबाइल एप्लीकेशनों को अपनी भाषा में बदलना चाहता है तो ऐसा अपनी भाषा में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के नाम उपलब्ध कराकर कर सकते है. यह एप्लीकेशन उस भाषा में तैयार हो जाएगा.

सीसीईए ने मत्स्य पालन हेतु 3000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी प्रदान की

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 22 दिसंबर 2015 को एकीकृत मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन हेतु एक वृहद योजना के लिए मंजूरी प्रदान की. इसकी लागत 3000 करोड़ रूपए है तथा इस योजना की समयावधि पांच वर्ष होगी.

इसके अंतर्गत अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, समुद्री मत्स्य पालन एवं राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा नीली क्रांति के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों में अपना योगदान दिया जायेगा. इसके अंतर्गत शामिल छह क्षेत्र हैं :

- राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एवं उसके क्रियाकलाप
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास
- समुद्री मत्स्य, बुनियादी ढांचा और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास
- डाटाबेस एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
- मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए संस्थागत व्यवस्था
- निगरानी, नियंत्रण, निगरानी एवं अन्य आवश्यकताओं के आधार पर हस्तक्षेप

योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन और मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन के लिए बेहतर व्यवस्था

सुनिश्चित करना है. इसके अंतर्गत 6 से 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल किया जायेगा. इसे उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों में लागू किया जाएगा.

पर्यावरण मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कठोर मानकों को अधिसूचित किया

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2015 को कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए संशोधित मानकों को अधिसूचित किया.

इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रदूषण में कमी लाना है जिसके लिए बनाये गये नए मानक चरणबद्ध तरीके से अमल में लाए जाएंगे. ताप विद्युत संयंत्रों को तीन श्रेणियों (i) 31 दिसंबर 2003 से पहले के स्थापित संयंत्र (ii) 2003 के बाद 31 दिसंबर 2016 तक स्थापित संयंत्र (iii) 31 दिसंबर 2016 के बाद स्थापित संयंत्र में रखा गया है.

नए मानकों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से स्थापित होने वाले उर्जा संयंत्रों को शून्य जल अपशिष्ट मानक को अपनाना होगा.

नवीन मानकों के उद्देश्य

- नए मानकों का उद्देश्य पीएम 10 (0.98 केजी/ मेगावाट), सल्फर डायऑक्साइड (7.3 केजी/ मेगावाट) तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड (4.8 केजी/मेगावाट) के उत्सर्जन को कम करना है.
- इससे ताप विद्युत् संयंत्रों के आस-पास की व्यापक वायु गुणवत्ता (एएक्यू) में सुधार लाने में मदद मिलेगी.
- सल्फरडाइऑक्साइड - एसओ2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रस्तावित सीमा को नियंत्रित करने वाली टेक्नोलॉजी से मरकरी उत्सर्जन (70-90 प्रतिशत) को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी.
- ताप विद्युत संयंत्रों में जल के उपयोग को नियंत्रित करने से जल संरक्षण (लगभग 1.5 एम3/मेगावाट) होगा क्योंकि ताप विद्युत संयंत्र जल प्रोत्साहन उद्योग है.
- इससे आवश्यक ऊर्जा में संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा.

राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 लोकसभा में पारित

लोकसभा ने राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 सर्वसम्मति से 22 दिसंबर 2015 को पारित किया. यह विधेयक केंद्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पेश किया गया.

इस विधेयक के तहत देश के कुछ जलमार्गो को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रावधान है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय राजामार्ग विधेयक में आधिकारिक संशोधन करने को मंजूरी दी थी, जिसे मई 2015 में सदन में पेश किया गया था.

इस विधेयक में 106 अतिरिक्त देसी जलमार्गो को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रावधान है. मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गो में 106 अतिरिक्त जलमार्गो के शामिल करने के बाद कुल राष्ट्रीय जलमार्गो की संख्या111 हो जाएगी.

इन राष्ट्रीय जल मार्गों की घोषणा से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को इन खंडों के लिए शिपिंग और नौवहन के लिए प्रयोग करने में सहायता मिलेगी.

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) वित्तीय संसाधनों को एकत्र कर राष्ट्रीय जलमार्गों के विभिन्न खंडों को शिपिंग और नौवहन के लिए विकसित करेगा.

प्रत्येक जल मार्ग के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर ही आर्थिक निर्णय लिए जा सकेंगे.

इस योजना के माध्यम से देश में माल ढुलाई, यात्रा आदि उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ पर्यटन के विकास में भी विशेष सहायता मिलेगी.

पृष्ठभूमि

अंतर्देशीय जल परिवहन ईंधन गुणवत्ता के बिंदु से परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है. एक हॉर्सपावर से जहां सड़क क्षेत्र से सिर्फ 150 किलो और रेलमार्ग से 500 किलो भार ढोया जा सकता है वहीं जल क्षेत्र में चार हजार किलो भार ढोया जा सकता है. विश्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जहां जलमार्ग में एक लीटर ईंधन द्वारा 105 टन-किलो मीटर ले जाया जा सकता है, वहीं रेल द्वारा 85 टन-किलो मीटर और सड़क मार्ग द्वारा सिर्फ 24 टन-किलो मीटर माल ढोया जा सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि जलमार्गों द्वारा माल ढोये जाने के दौरान जहाजों से प्रति टन-किलो मीटर 32 से 36 ग्राम कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन होता है, वहीं सड़क परिवहन (भारी वाहन) में इसकी मात्रा बढ़कर 51 से 91 ग्राम कार्बन डाइआक्साइड प्रति टन-किलो मीटर हो जाती है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर 6ठे अखिल भारतीय सर्वे का लोकार्पण किया

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जुबिन ईरानी ने 21 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा पर 6ठे अखिल भारतीय सर्वे (एआईएसएचई) का लोकार्पण किया. इस सर्वे में देश के सभी उच्च शिक्षण (एचई) संस्थान शामिल किए गए. इसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय (कॉलेज) और 2010-11 से 2014-15 के बीच स्टैंड- अलोन संस्थानों को शामिल किया गया था.

इस सर्वे ने उच्च शिक्षा प्रणाली की सटीक और पूर्ण तस्वीर सामने लाई. इससे केंद्र सरकार के साथ- साथ राज्य सरकारों को भी भविष्य के शिक्षण नीतियों को बनाने हेतु प्रासंगिक सांख्यिकीय आंकड़े मिले.

एआईएसएचई 2014-15 की मुख्य विशेषताएं हैं-

- कुल नामांकन में बढ़ोतरी हुई. साल 2010-11 के 27.5 मिलियन की तुलना में 2014-15 में 33.3 मिलियन नामांकन हुए.
- सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ. यह योग्य आयु वर्ग (18- 23) वर्ष में आबादी में उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात है. साल 2010-11 में यह 19.4 फीसदी था जबकि 2014-15 में यह बढ़कर 23.6 फीसदी हो गया.
- लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई), महिलाओं और पुरुषों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुपात, में मामूली सुधार हुआ और यह इसी अवधि में 0.86 से बढ़कर 0.93 हो गया.
- एआईएसएचई पोर्टल पर सूचीबद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई- इस अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या 621 से बढ़कर 757 हो गए और महाविद्यालयों की संख्या 32974 से बढ़कर 38056 हो गई.

एलएनजी पोत बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया

विश्व में किसी भी ग्राहक देश के लिए एलएनजी परिवहन पोत बनाने हेतु 21 दिसंबर 2015 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को प्रमाणित किया गया. यह भारत का पहला शिपयार्ड है जिसे यह लाइसेंस

दिया गया है. कोचीन शिपयार्ड ने गेज़ट्रांसपोर्ट एट टेक्नीगेज़ (जीटीटी), फ्रांस से प्रमाणित मार्क-3 फ्लेक्स मोक अप का सफलता पूर्वक निर्माण किया है. सभी सुविधायुक्त व सफलता पूर्वक निर्माण के बाद कंपनी कोल जीटीटी द्वारा लाइसेंस दिया गया.

प्रमाणीकरण के बाद सीएसएल विश्व में किसी भी ग्राहक देश के लिए एलएनजी पोत का निर्माण कर सकता है. सीएसएल मार्क-तृतीय प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग मार्क-तृतीय प्रौद्योगिकी को पेटेंट करा सकता है.

किस तरह लाइसेंस लाभकारी है सीएसएल के लिए ?

जहाजों में एलएनजी के सुरक्षित उपयोग के लिए जीटीटी फ्रांस ने विभिन्न तकनीकों का पेटेंट कराया है. लाइसेंस मिलने के बाद अब सीएसएल कोई भी तरल गैस वाहक खासतौर से एलएनजी वाहक पोत बनाने में जीटीटी की झिल्ली जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए अधिकृत है. सीएसएल अब एलएनजी वाहक बनाने के लिए गेल द्वारा जारी निविदा में भाग ले सकेगा.

- गेल ने एलएनजी के परिवहन लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से अगले 20 साल के लिए अनुबंध किया है. गेल उन प्रतिष्ठित कंपनियों को एलएनजी शिपिंग कंपनियों के साथ परिवहन ठेके को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं, जो गेल के विनिर्देशों के अनुसार जहाजों का निर्माण करते हैं. अनुबंध 20 साल की अवधि के लिए होगा और उसी के अनुरूप जहाजों को तैनात किया जाएगा.
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार नौ जहाजों में से तीन को भारत में निर्मित किए जाने के लिए उत्सुक है. सीएसएल भी निविदा में भाग लेने के लिए उत्सुक है. एलएनजी वाहक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अब उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी अनुसार यार्ड की स्थापना की जाएगी और आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) जैसे क्षेत्रों में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा.

एलएनजी वाहिकाओं के बारे में-

- एलएनजी वेसल्स बहुत जटिल पोत हैं और दुनिया में केवल कुछ ही जगहों पर इन पोतों का निर्माण करने की क्षमता है.
- एक एलएनजी जहाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी क्रायोजेनिक रोकथाम और प्रणाली का संचालन है क्योकि एलएनजी को 163 डिग्री के तापमान पर परिवहन किया जाता है. इसके लिए पूर्ण रूपेण क्रायोजेनिक रोकथाम, सुरक्षित संचालन और हस्तांतरण प्रणाली की आवश्यकता है.

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में-

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत में प्रमुख जहाज निर्माण और रखरखाव की सुविधा में से एक है.
- यह कोच्चि, केरल के बंदरगाह शहर में समुद्र से संबंधित सुविधाओं का एक हिस्सा है.

- यह भारत सरकार की कंपनी के रूप में 1972 में शामिल की गयी.
- शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण और आपूर्ति और दोहरी परत (लेयर) वाले तेल टैंकरों का निर्माण की सेवाएं प्रदान की गई हैं.
- वर्तमान में, सीएसएल भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण कर रहा है.
- शिपयार्ड भी मरीन इंजीनियरिंग में स्नातक इंजीनियरों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है.

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2014-15 जारी

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने 21 दिसम्बर 2015 को 6वीं अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण(2014-15) रिपोर्ट जारी की.

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 के 19.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014-15 में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 23.6 प्रतिशत रहा है. वर्ष 2020 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल नामांकन अनुपात 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य है.

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2014-15 की मुख्य विशेताएँ

- सर्वेक्षण में देश के पूरे उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया. संस्थानों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया. ये श्रेणिया हैं विश्वविद्यालय, कॉलेज और अकेले संस्थान.
- इस तरह से रिपोर्ट में 57 विश्वविद्यालयों, 38056 कॉलेजों और 11922 अकेले संस्थानों को शमिल किया गया. इनमे से 716 विश्वविद्यालयों, 29506 कॉलेजों और 6837 अकेले संस्थानों ने सर्वेक्षण के दौरान प्रतिक्रिया व्यक्त की.
- यह सर्वे ऑनलाइन माध्यम से किया गया. सर्वेक्षण में कोई अन्वेषक डेटा एकत्र करने के लिए संस्थान में नहीं भेजा गया.
- रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 267 विश्वविद्यालयों का प्रबन्धन निजी हाथों में है, इसके अतिरिक्त देश में 43 केंद्रीय विश्वविद्याल, 1 केन्द्रीय और 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के 69 संस्थान हैं, 316 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 5 संस्थान राज्य के अधीन विधानमंडल अधिनियम, 37 डीम्ड विश्विद्यालय और 6 अन्य विश्विद्यालय है.
- भारत में कॉलेजों की सबसे ज्यादा संख्या वाले 7 राज्य हैं , उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान,

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना.

- कालेज घनत्व(प्रत्येक लाख जनसंख्या पर कालेजों की संख्या) बिहार में 7 है जबकि पुदुचेरी में 58 है. विदित हो कालेज घनत्व का राष्ट्रीय औसत 27 है.
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई विश्वविद्यालय नहीं है.
- 76% कालेजों निजी तौर पर प्रबंधित हैं, 61 प्रतिशत प्राइवेट अनएडेड और 15 प्रतिशत प्राइवेट एडेड हैं.
- उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.33 करोड़ रहे जिसमें 17.9 लाख लड़के और 15.4 करोड़ लड़कियाँ शामिल हैं. इस तरह से लडकिय कुल नामांकन का 46% हैं.
- भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 23.6 है. जिसकी गणना 18 से 23 आयु वर्ग के लिए की गई है.
- पुरुष जनसंख्या के लिए जीईआर 24.5 है और महिलाओं के लिए यह 22.7 है. इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लिए यह 18.5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए यह 13.3 है.जबकि राष्ट्रीय जीईआर 23.6 है.
- उच्च शिक्षा में डिस्टेंस एनरोलमेंट 11.7 प्रतिशत रहा, जिसमें 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं.
- लगभग 80 प्रतिशत छात्रों को स्नातक स्तर के कार्यक्रम में नामांकित हैं. इसके अतिरिक्त 112812 छात्र पीएच.डी. में नामांकित हैं जो कि कुल छात्र नामांकन के बारे में 0.34 प्रतिशत है.
- उत्तर प्रदेश उच्चतम छात्र नामांकन के साथ पहले स्थान पर है जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर.
- अनुसूचित जाति के छात्र कुल नामांकन का 13.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति छात्र कुल नामांकन का 4.8 प्रतिशत हैं. 32.9 प्रतिशत छात्रों को अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, इसमें 4.4 प्रतिशत मुस्लिम अल्पसंख्यक और 1.9 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के हैं.
- देश में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कुल संख्या 1418389 है जिनमें 61 प्रतिशत पुरुष शिक्षक हैं और 39 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं.
- भारत में प्रत्येक 100 शिकशों पर 64 पुरष शिक्षक हैं.
- छात्र शिक्षक अनुपात(पीटीआर) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 24 है.

राज्यसभा द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक-2015 पारित

संसद के ऊपरी सदन, राज्य सभा ने 21 दिसंबर 2015 को अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2015 पारित किया. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) विधेयक, 1989 में आवश्यक बदलाव करना है.

इससे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को अगस्त 2015 में पारित कर दिया था.

विधेयक की विशेषताएं

मौजूदा अपराध में संशोधन और नए अपराध जोड़ना

- इस विधेयक में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर किये जाने वाले अत्याचारों की कुछ अन्य श्रेणियां भी जोड़ी गयी हैं.
- किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को जबरन किसी प्रत्याशी के पक्ष अथवा विपक्ष में मत डालने पर मजबूर करना अपराध की श्रेणी में गिना जायेगा.
- इस विधेयक के अंतर्गत किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करना भी अपराध माना जायेगा.
- किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की महिला के यौन शोषण की श्रेणी में निम्न अपराधों को शामिल किया गया है:

1. किसी महिला को बिना उसकी स्वीकृति के हाथ लगाना.
2. अभद्र भाषा, तरीके अथवा भाव में महिला से बात करना.
3. किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की महिला को मंदिर में देवदासी के रूप में रखना भी अपराध माना जायेगा.
4. विधेयक में सहमति का अर्थ बोलकर अथवा भाव द्वारा सहमति देना भी है.

- नए जोड़े गये अपराध हैं, i. जूतों की माला पहनाना ii. मानवीय अथवा पशुओं के अवशेष को उठाने पर मजबूर करना अथवा हाथ से मल की सफाई करवाना iii. सार्वजानिक स्थान पर जाति का नाम लेकर अपमानित करना iv. किसी व्यक्ति के प्रति बुरी इच्छा रखना एवं देहावासन के उपरांत भी व्यक्ति का

अपमान करना v. व्यक्ति का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार किये जाने की धमकी देना.

- अनसूचित जाति या जनजाति के लोगों को निम्न कार्य करने से रोकना भी अपराध होगा: i. आम अथवा सार्वजानिक संपत्ति के संसाधनों को प्रयोग करने से रोकना, ii. किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल पर जाने से रोकना, iii. किसी शिक्षण स्थल अथवा स्वास्थ्य केंद्र में जाने से रोकना.
- अपराध करने वाला व्यक्ति यदि पीड़ित के परिवार के किसी सदस्य या उससे किसी तरह संबंधित है तो अदालत ऐसी स्थिति में यह अपराध जानबूझ कर किया गया मानेगी.

लोक सेवकों का उत्तरदायित्व

- विधेयक में सरकारी प्रतिनिधियों के लिए उत्तरदायित्व तय किये गये हिं जिनका अनुपालन न होने की स्थिती में छह महीने से एक वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है.
- यह उत्तरदायित्व हैं: i. शिकायत या एफआईआर दर्ज करना, ii. दी गयी जानकारी को पढ़ना तथा उपयुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर वाली कॉपी शिकायतकर्ता को देना.

नई अदालतों का निर्माण करना

- विधेयक के अनुसार इन मामलों से निपटने के लिए जिला स्तर पर विशेष अदालतों का निर्माण किया जाना चाहिए.
- यह सुनिश्चित किया जाए कि इन अदालतों में दो महीने के भीतर इन मामलों को निपटाया जायेगा.
- इसमें की जाने वाली अपील उच्च न्यायालय में निहित होंगी तथा अधिकतम तीन महीने में निपटायी जायेंगी.
- प्रत्येक विशेष अदालत के लिए एक लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा.

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

- विधेयक में पीड़ितों और गवाहों के अधिकार पर अध्याय जोड़ा गया है.
- राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था करे.
- राज्य सरकार पीड़ितों और गवाहों के अधिकार के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना निर्दिष्ट करेगी.

गुजरात झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए पीपीपी परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना

केंद्रीय आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 21 दिसंबर 2015 में जारी एक प्रगति-सूचना के अनुसार, गुजरात झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए निजी-सार्वजानिक भागीदारी (पीपीपी) परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. केंद्रीय आवास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जारी प्रगति-सूचना के अनुसार गुजरात सरकार ने हाल ही में लॉच की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (अरबन) के अंतर्गत झुग्गी बस्तियों के मूल स्थान पर पुनर्विकास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजना को प्रारंभ किया.

इस अवसर पर आवास तथा गरीबी उपशमन सचिव डॉ. नंदिता चटर्जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की अंतर-मंत्रालय केंद्रीय जांच और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने गुजरात सरकार की ओर से प्रस्तुत अहमदाबाद, सूरत, राजकोट तथा बड़ोदरा में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए 30 पीपीपी परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी. निजी डेवलपर गुजरात के इन चार शहरों में सरकारी जमीन पर रह रहे झुग्गी वासियों के लिए 17,580 नई आवासीय ईकाइयां बनाएंगे. केंद्र सरकार एक लाख रुपए प्रति मकान की दर से 176 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगी. झुग्गी बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं की शेष लागत को पूरा करने के लिए जमीन का मुद्रीकरण किया जाएगा. इसके परिणाम स्वरूप झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को नि:शुल्क सभी सुविधाओं के साथ नए मकान मिलेंगे.

उपरोक्त के साथ ही साथ सीएसएमसी ने 8 राज्यों के 145 शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1,69,381 मकानों की मंजूरी दी. इसके लिए 2,444 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी. इसमें मूल स्थान पर झुग्गी बस्ती के पुनर्वास के अंतर्गत मकानों का निर्माण, साझेदारी में किफायती मकान तथा लाभार्थी व्यक्तिगत निर्माण शामिल है.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों की दी गई स्वीकृति का विवरण:-

पश्चिम बंगाल के 70 शहरों में 47,050 ईकाइयां, तेलंगाना के 27 शहरों में 45,217 ईकाइयां, गुजरात के 6 शहरों में 27,186 ईकाइयां, मध्य प्रदेश के 16 शहरों में 19,241 ईकाइयां, झारखंड के 14 शहरों में 16,146 ईकाइयां, तमिलनाडु के 9 शहरों में 7,621 ईकाइयां, ओडिशा में भुवनेश्वर में 5,548 तथा आयजोल और मिजोरम के लवंगतली में 1,364 ईकाइयां. इसके साथ ही आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अब तक देश के 11 राज्यों में 243 शहरों में शहरी गरीब के लिए 4,23,415 मकान बनवाने की स्वीकृति दी है. इसके लिए केंद्र सरकार 5,900 करोड़ रुपए की सहायता देगी.

विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (अरबन) के अंतर्गत केंद्र सरकार झुग्गीं बस्तियों के पुनर्वास के लिए एक लाख रूप प्रति इकाई तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए साझेदारी और लाभार्थी

व्यक्तिगत निर्माण के अंतर्गत 1.50 लाख रुपए की सहायता देती है. ऋण से जुड़ी सब्सिडी के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 2.3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी.

सरकार ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए टॉल फ्री 'आईवे नेशनल हेल्पडेस्क' आरंभ किया

नि:शक्तजन अधिकारिता विभाग के सचिव लव वर्मा द्वारा 21 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन में दृष्टिहीन तथा दृष्टिबाधित लोगों के लिए 'आईवे नेशनल हेल्पडेस्क 'आरंभ किया गया.

आईवे नेशनल हेल्पडेस्क एसेल फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन तथा हैन्स फाउंडेशन जैसे संगठनों के समर्थन से स्कोर फाउंडेशन की पहल है. अब भारत के दृष्टि बाधित नागरिक टॉल फ्री नंबर 1800-300-20469 पर आईवे नेशनल हेल्पडेस्क को कॉल करके अपनी सूचनाओं का जवाब प्राप्त कर सकते हैं. इस प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशिक्षित काउंसलर सूचना साझा करेंगे और प्रसांगिक पेशेवर समाधान के साथ कॉलर से जुड़ेंगे.

आईवे नेशनल हेल्प डेस्क

- नि:शक्तजनों संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार, शिकायतों पर नज़र तथा कौशल/रोजगार में नि:शक्तशजनों की आवश्यधकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के माध्यंम से एनआईसीएसआई के साथ मिलकर हेल्पडेस्क/हेल्प सेंटर विकसित किया जा रहा है.
- आईवे सिंगल स्टॉप नॉलेज रिसोर्स सेंटर है. यह दृष्टि बाधित लोगों के साथ सूचना साझा करके और आवश्यक परिवर्तन की बात करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाता है.
- नेशनल हेल्प् डेस्क टॉल फ्री नंबर पर भारत का कोई भी नागरिक कॉल कर सकता है और अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी समस्याओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है.
- यह सूचनाएं दृष्टि हीनता के साथ जीवन संबंधी काउंसलिंग एडवोकेसिव, निजी या कानूनी मामले, सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों, रोजगार और शिक्षा से संबंधित हो सकती हैं.

रक्षा मंत्रालय ने मेकइनइंडिया डिफेंस डॉट कॉम का शुभारम्भ किया

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 21 दिसम्बर 2015 को मेकइनइंडिया डिफेंस डॉट कॉम का शुभारम्भ किया.

इस वेबसाइट का उद्देश्य रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान एवं पारदर्शी बनाना है.

सरकार ने जनवरी तक नयी संशोधित रक्षा खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का वादा किया है.

यह वेबसाइट मेकइनइंडिया डिफेंस डॉट कॉम रक्षा उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में नवीनतम समाचार एवं अधिसूचना प्राप्त करने में बहुत सहायक होगा. यह वेबसाइट औद्योगिक संवर्धन नीतियों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यक्रमों के लिए लिंक प्रदान करेगी.

डीपीपी को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा खरीद परिषद की बैठक या तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगी या जनवरी के पहले सप्ताह में होगी.

सरकार का लक्ष्य रक्षा खरीद का 40 प्रतिशत 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत लाना है जो मौजूदा समय में 30 प्रतिशत है और अगले पांच साल में इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत पर ले जाना है.

यूएसएफ ने राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम स्नातकोत्तर फैलोशिप आरम्भ की

यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में 17 दिसम्बर 2015 को उनके नाम पर फेलोशिप का ऐलान किया. कलाम युवाओं की आवाज थे.

पूर्व राष्ट्रपति क्लीन एनर्जी के गहरे सपोर्टर थे. 2012 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा (यूएसएफ) का दौरा किया. ऐकैडमिक ईयर 2016-17 से प्रत्येक वर्ष कलाम के नाम पर सम्मान दिया जाएगा.

अवॉर्ड के बारे में-

यह अवॉर्ड ऐसे भारतीय विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में निम्न विषयों में पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं

विषय निम्न है:

- अप्लाइड एंथ्रोप्लोजी
- अप्लाइज फिजिक्स
- बिजनेस पीएचडी प्रोग्राम
- सेल बायलॉजी, माइक्रोबायलॉजी और मोलीक्यूलर बायलॉजी

- केमेस्ट्री
- कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग
- इंजीनियरिंग
- क्रिमिनॉलजी
- इंटीग्रेटिव बायलॉजी
- मरीन साइंस
- साइकॉलजी

डीएसी ने रूसी एस-400 ट्रिउम्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी

18 दिसंबर 2015 को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने रूस से रूसी एस-400 ट्रिउम्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने की मंजूरी दे दी. इस सौदे की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रूपय है. केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नई दिल्ली में डीएसी की बैठक के दौरान यह मंजूरी दी थी.

भारत पांच एस-400 ट्रिउम्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा. यह खरीद राष्ट्रीय वायु रक्षा क्षमता को काफी बढ़ा देगा और चीन के बाद इस मिसाइल प्रणाली को खरीदने वाला भारत सिर्फ दूसरा खरीदार होगा.

रक्षा सौदों के लिए डीएसी की यह मंजूरी दिसंबर 2015 के आखिर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूस दौरे से पहले दी गई है.

रूसी एस-400 ट्रिउम्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में

- यह प्रणाली 400 किमी की रेंज में आने वाले दुश्मन के मिसाइलों, विमानों और यहां तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है.
- यह वायु रक्षा प्रणाली 150 किलोमीटर के दायरे में 36 लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है.
- यह बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ले जाने में भी सक्षम है.
- रूस के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली मानी जाने वाली नई एस- 400 में एस-300 के मुकाबले फायर करने की दर 2.5 गुना अधिक है.

लोकसभा में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 पारित

लोकसभा ने 17 दिसंबर 2015 को ध्वनि मत से मध्यस्थता और सुलह (संशोधन विधेयक) 2015 को पारित कर दिया. इस विधेयक में मामलों के शीघ्रता से निपटारे के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को और अधिक सुलभ, लागत प्रभावी और उपयुक्ते बनाने के प्रावधान हैं. यह भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिसक मध्यस्थात केन्द्र बनाने की सुविधा भी प्रदान करेगा.

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने पूर्व प्रचारित अधिनियम, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित और इससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया था.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2015 को इस अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दी थी और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष भेज दी थी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरटीआई पर सूचना देने के लिए जवाबदेह: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2015 को दिये अपने एक निर्णय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के आधार पर सूचना देने के लिए जबाबदेह ठहराया. इस सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आने वाले मामलों और बकाएदारों से संबंधित सूचनाएं रोक नहीं सकता है.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि हमारा अनुमान है कि अनेक वित्तीय संस्थाएं ऐसा कृत्य कर रही हैं जो न तो साफ-सुथरा है और न ही पारदर्शी है. रिजर्व बैंक इनके साथ मिलकर उनके कृत्यों को जनता की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा है. इस सन्दर्भ में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि वह उन बैंकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे जो इस तरह के अशोभनीय कारोबारी व्यवहार कर रही हैं. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं के साथ गोपनीयता या विश्वास की 'आड़' में सूचना देने से इंकार नहीं कर सकता है और आम जनता द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वह जवाबदेह है.

उपरोक्त सन्दर्भ में पीठ ने कहा कि रिजर्व बैंक और दूसरे बैंकों ने 'विश्वास के रिश्ते' और 'आर्थिक हितों' की दुहाई देते हुए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने की जनता की मांग को दरकिनार किया है. रिजर्व बैंक का यह

रवैया उनमें और अधिक संदेह तथा अविश्वास को ही जन्म देगा. नियामक प्राधिकरण के रूप में रिजर्व बैंक को बैंकों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए. सूचना के अधिकार कानून की धारा 2(एफ) के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान है कि निरीक्षण रिपोर्ट और दस्तावेज 'सूचना' के दायरे में आते हैं, जो सार्वजनिक प्राधिकार (रिजर्व बैंक) निजी संस्था से प्राप्त करती है. विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार कानून के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदकों को अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट से स्थानांतरित की गई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के मध्य विवाद सुलझाने हेतु शाह समिति का गठन

रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के मध्य विवाद सुलझाने के लिए 16 दिसंबर 2015 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शाह समिति का गठन किया गया.

यह समिति इस मामले में हुई भूल-चूक देखेगी तथा ओएनजीसी के मुआवजे के बारे में सिफारिश करेगी. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अजीत प्रकाश शाह समिति का गठन अमरीकी सलाहकार कंपनी डीएंडएम की इस बारे में अंतिम रिपोर्ट आने के बाद किया गया.

विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में गठित समिति डीएंडएम की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सरकार से सिफारिश करेगी. इस रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 करोड़ रुपये की 11.12 अरब घनमीटर प्राकृतिक गैस ओएनजीसी के कृष्णा गोदावरी क्षेत्रों से साथ लगते रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी-डी6 ब्लाक में चली गई.

समिति डीएंडएम की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सरकार को इस बारे में सिफारिश देगी. समिति को इस मामले के कानूनी, वित्तीय तथा अनुबंध के प्रावधानों को देखने को कहा गया है. समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने में सौंपेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए संशोधित मॉडल टेक्स्ट को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कार्यरत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 दिसंबर 2015 को द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के लिए संशोधित मॉडल टेक्स्ट को मंजूरी प्रदान की.

यह संशोधित मॉडल भारतीय मॉडल बीआईटी के स्थान पर लागू किया जायेगा. संशोधित मॉडल बीआईटी मौजूदा बीआईटी के स्थान पर बेहतर और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों के लिए प्रयोग किया जायेगा.

भारतीय बीआईटी के लिए संशोधित मॉडल

- नए भारतीय बीआईटी मॉडल में विदेशी निवेशकों को भारत में तथा भारतीय निवेशकों को विदेश में उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
- इसके अतिरिक्त, इससे निवेशक के अधिकारों और सरकारी दायित्वों के बीच संतुलन बनाकर रखा जायेगा.

द्विपक्षीय निवेश संधि की प्रासंगिकता

- बीआईटी निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है तथा मध्यस्थता से विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र मंच भी प्रदान करता है.
- इससे भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बेहतर गंतव्य के रूप में चिन्हित होता है.

बीआईटी की विशेषताएं

- निवेश को उद्यम आधारित परिभाषित किया गया है.
- उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार
- राष्ट्रीय उपाय
- जब्ती के खिलाफ सुरक्षा
- परिष्कृत निवेशक राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को किसी दूसरे माध्यम को अपनाने से पहले स्थानीय तरीकों से समस्या का हल निकालने पर बल देता है.
- मौद्रिक मुआवजा प्रदान करने हेतु न्यायाधिकरण की शक्ति को सीमित किया जायेगा.
- इसमें नियामक प्राधिकरण को संरक्षित करने के लिए सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल नहीं होंगे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ब्रिक्स के साथ उर्जा संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 दिसंबर 2015 को भारत एवं ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) के बीच उर्जा संरक्षण को मजबूत बनाने हेतु एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की.

समझौता ज्ञापन की विशेषताएं

- संयुक्त वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान
- व्याख्यान और सेमिनार आयोजित कराना
- क्षमता विकास एवं तकनीक हस्तांतरण
- तकनीकी विकास, शेयरिंग पॉलिसी एवं बेहतर सेवाएं
- उर्जा बचत को बढ़ावा देने वाली तकनीक एवं कार्यों को अपनाना. इसे व्यापारिक उद्देश्यों हेतु ब्रिक्स देशों एवं उससे जुड़े देशों में अपनाया जायेगा.

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, ब्रिक्स देशों द्वारा उर्जा बचत के क्षेत्र में सहयोग के व्यापक कार्यक्रमों के विकास एवं प्रसार पर कार्य किया जायेगा. साथ ही इन कार्यक्रमों को लागू करने के तरीकों एवं अर्थव्यवस्थाओं में उर्जा दक्षता बढ़ाने के उपायों पर भी कार्य किया जायेगा.

विश्व बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

विश्व बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है. इसका मकसद 2019 तक भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सभी नागरिकों को बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा खुले में शौच को समाप्त करने के अभियान में मदद करना है.

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 2.4 अरब लोगों के पास स्वच्छ माहौल में रहने की सुविधाएं नही है और इसमें 75 करोड़ से अधिक भारत में रहते हैं. कुल 2.4 करोड़ लोगों में से 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं.

भारत में करीब 50 करोड़ ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है जिससे न केवल वे बीमार और परेशान होते हैं बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है. ऋण का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के लिए किया जाएगा.

इस परियोजना का उद्देश्य सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन को मजबूती प्रदान करना है

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2015 को दिल्ली में 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया. सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के तहत 31 मार्च 2016 तक दिल्ली में डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है.

सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 सीसी से अधिक की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के साथ ही साथ वर्ष 2005 से पहले के रजिस्ट्रेशन वाले ट्रकों की दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया. इसके अलावा, जिन ट्रकों में अब दिल्ली का सामान नहीं होगा, उनके दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई एवं साथ ही, दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर लगने वाला ग्रीन टैक्स दोगुना करने का आदेश दिया.

विदित हो कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निर्देश दिया था कि दिल्ली में तत्काल प्रभाव से डीजल से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा. अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों से कहा था कि वे डीजल गाड़ियां नहीं खरीदें. जिसके बाद यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांर्डस सम्मेलन की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिसम्बर 2015 को संयुक्त कमांर्डस सम्मेलन की अध्यक्षता की.

यह सेना की तीनों शाखाओं का वार्षिक सम्मेलन है.

यह पहली बार दिल्ली से बाहर कोच्चि तट से 50 किलोमीटर की दूरी पर आईएनएस विक्रमादित्य पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया.

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सेना, नौसेना एवं वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया.

विदित हो इस सम्मेलन के दौरान भारत की रक्षा नीति, सिद्धांत और परिचालन से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाती है.

आईएनएस विक्रमादित्य पर जाने से पहले मोदी ने यहां दक्षिणी नौसेना कमान में तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया.

ज्ञात हो इस तरह का अहम सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल दिये गये सुझाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी से बाहर आयोजित किया जा रहा है.

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का 26 वां सम्मेलन विजयवाड़ा में आयोजित

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (एसजेडसी) का 26 वां सम्मेलन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 12 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया. सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की.

केंद्रीय गृह मंत्री के साथ-साथ सम्मेलन में पांच राज्यों-तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया. पांचों राज्य और पुडुचेरी एक साथ दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद सदस्य के रूप में शामिल हुए.

सम्मेलन में परिषद के सदस्यों के बीच जन समुदाय के हित में प्रायद्वीपीय क्षेत्र औद्योगिक गलियारा, तटीय सुरक्षा, प्रायद्वीपीय पर्यटन ट्रेनों की शुरूआत और अंतर-राज्य पारस्परिक परिवहन समझौते को अंतिम रूप देने के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. केंद्र राज्य और अंतर-राज्यीय मामलों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सम्मेलन में चर्चा की गयी.

क्षेत्रीय परिषद बारे में

- क्षेत्रीय परिषद सलाहकार निकाय हैं जो जन समुदाय के हित में अवसंरचना, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, भाषाई अल्पसंख्यकों, सीमा विवाद, आदि विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ चर्चा करती है और आम हित के लिए सलाह देती है.
- क्षेत्रीय परिषद का सृजन करने का विचार 1956 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा रखा गया.
- पंडित नेहरू की दृष्टि में पाँच क्षेत्रीय परिषद उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग- III, के तहत किया गया.
- उत्तर-पूर्व परिषद की स्थापना अलग अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु विकास मंत्रालय

(स्वतंत्र प्रभार) के अधीन प्रशासनिक दायरे में किया गया.

- केंद्रीय गृह मंत्री इन परिषदों में से प्रत्येक के अध्यक्ष हैं. राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से सम्बंधित क्षेत्र के लिए एक वर्ष की अवधि तक क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं.
- क्षेत्रीय परिषद के सचिवीय कार्य 1 अप्रैल 2011 से इंटर स्टेट परिषद सचिवालय को हस्तांतरित कर दिया गए हैं.

लोकसभा ने परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया

14 दिसंबर 2015 को परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, 2015 को लोकसभा में पारित किया गया. इस विधेयक में नई परमाणु परियोजनाओं की स्थापना में कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा जिससे भारत में परमाणु उर्जा को बढ़ावा मिलेगा.

यह विधेयक कोषागार सहित विपक्ष दोनों ने ध्वनि मत से पारित किया. अब यह अन्य औपचारिकताओं के लिए राज्य सभा में भेजा जायेगा.

परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक-2015

- इस विधेयक द्वारा परमाणु उर्जा कानून, 1962 में संशोधन किया जायेगा.
- यह अधिनियम देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, नियंत्रण, विकास, और उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान प्रदान करेगा. इससे देश में परमाणु ऊर्जा इकाइयों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा जिसमें परमाणु ऊर्जा निगम इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) भी शामिल है. इससे यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सरकारी कम्पनियों के साथ गठजोड़ कर सकेगी.
- अधिनियम के अनुसार, सरकारी कंपनी वही होगी जिसमें कंपनी शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा निवेश किया गया हो.
- विधेयक कम्पनियों के शेयर में किसी एक सरकारी कम्पनी द्वारा पूर्ण निवेश किया गया हो तथा जिसके योगदान से संघ के सशक्तिकरण में सहायता मिलती हो. यह प्रावधान एनपीसीआईएल एवं अन्य सरकारी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की ओर भी इंगित करती है.
- इस विधेयक के तहत परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान अथवा किसी भी संयंत्र के अधिग्रहण, उत्पादन, उपयोग, निर्यात और आयात के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. विधेयक यह भी जानकारी देता है कि यह लाइसेंस उपयुक्त सरकारी कंपनी अथवा केंद्रीय विभाग को ही दिया जायेगा.

- विधेयक में कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन, अधिग्रहण एवं परमाणु उर्जा पैदा करने वाले पदार्थों का उपयोग का अधिकार दिए जाने के लाइसेंस को सरकारी कम्पनी न होने की स्थिति में रद्द भी किया जा सकता है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए सेवाओं के लिए पुनर्निर्मित वेबसाइट आरंभ की

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 दिसंबर 2015 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत विदेशी योगदान (विनियमन) नियम (एफसीआरए) के लिए वर्तमान सेवाओं में उल्लेखनीय बेहतरी लाने हेतु नए पुनर्निर्मित वेबसाइट का आरंभ किया.

विशेषताएं

- यह नई पहल पर्याप्त सरलता एवं सुविधा के साथ एफसीआरए की वास्तविक ऐप्लीकैंट्स सीमलेस सेवाओं को प्रस्तुत करेगी.
- इसके साथ साथ, संशोधित नियमों (विदेशी योगदान) (विनियमन) नियम, 2015) को अधिसूचित भी किया गया है.
- यह सुविधा एफसीआरए, 2010 के तहत पेश की जाने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर देगी जिससे इसमें लगने वाले समय में काफी कमी आएगी.
- सभी प्रकार के आवेदन प्रारूपों को ऑनलाइन भरा जा सकेगा, दस्तावेजों को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा और यहां तक कि फीस की अदायगी भी ऑनलाइन की जा सकेगी.
- सभी प्रकार के प्रश्न एवं आवेदकों को भेजे जाने वाले जबाव ईमेल के जरिये होंगे.
- आवेदकों को डिजिटल तरीके से हस्ताक्षर किए गए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पूर्व अनुमति मंजूरी आदि भी ईमेल के जरिये भेज दिए जाएंगे.

केंद्र सरकार ने 'ऑपरेशन स्माइल-द्वितीय' शुरू करने की घोषणा की

केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'ऑपरेशन स्माइल-द्वितीय' देश भर में शुरू करने की 14 दिसंबर 2015 को घोषणा की. इसके तहत 'ऑपरेशन स्माइल-द्वितीय' देश भर में 01 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया जाएगा. यह ऑपरेशन स्माइल' का दूसरा चरण होगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, लापता बच्चों के बचाव/पुनर्वास से जुड़े पिछले अभियान के बाद आगे की पहल के रूप में 'ऑपरेशन स्माइल-द्वितीय' का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसे देश भर में शुरू किया जाएगा.

विदित हो कि इससे पहले सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के बचाव/पुनर्वास के लिए जनवरी 2015 में 'ऑपरेशन स्माइल' के नाम से एक माह का अभियान शुरू करने की सलाह दी गई थी. इसी तरह देश भर में एक अन्य समर्पित अभियान 'ऑपरेशन मुस्कान'के नाम से जुलाई 2015 में शुरू किया गया था. राज्यों ने अब तक जो जानकारियां गृह मंत्रालय को दी हैं, उनके मुताबिक 'ऑपरेशन स्माइल' के तहत 9146 बच्चों और'ऑपरेशन मुस्कान'के तहत 19742 बच्चों का बचाव/पुनर्वास किया गया है.

इस अभियान में पूरी तन्मयता के साथ भाग लेने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रेरित करने हेतु जनवरी 2015 के दौरान 'ऑपरेशन स्माइल' में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 44 पुलिस अधिकारियों को केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पुरस्कृत किया गया था. 7 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में मानव तस्करी रोकने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इन पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया. 'ऑपरेशन स्माइल-द्वितीय' के शुभारंभ के तहत अनेक गतिविधियां शुरू किये जाने की घोषणा की गई है. इस अभियान के तहत आश्रय गृहों, प्लेटफॉर्मों, बस स्टैंड, सड़कों, धार्मिक स्थलों इत्यादि में रहने वाले बच्चों के बारे में समुचित जानकारी प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों द्वारा हासिल की जाएगी. 01 जनवरी 2016 से पहले हर राज्य के पुलिस कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों को भयभीत किये बगैर ही वे तमाम जानकारियां उनसे हासिल कर सकें.

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को स्थायी और सांविधिक निकाय बनाने की सिफारिश

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने 11 दिसंबर 2015 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को वर्ष 2014 - 2015 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी.

इस वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गयी हैं:

- आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियों सहित स्थायी और सांविधिक निकाय बनाया जाए.
- अनुबंध का सिस्टम समाप्त किया जाए एवं सभी सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए.
- सफाई कर्मचारी के आकस्मिक निधन होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 10 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाए.
- अधिकारों के संरक्षण, सुनिश्चित जोखिम भत्ता, प्रभावी वित्तपोषण योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए निश्चित योजनाएं बनायीं जाएं.
- आयोग को सशक्त बनाने के लिए इसे निश्चित बजट एवं स्टाफ दिया जाए.

सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग

इसका गठन सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग कानून, 1993 के तहत 12 अगस्त 1994 को तीन वर्ष के लिए हुआ था. इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है.

इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य शामिल हैं. इसके सदस्यों का चुनाव केंद्र सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े लोगों में से किया जाता है. इसमें कम से कम एक महिला सदस्य होना भी अनिवार्य है.

यह एक एड-हॉक बॉडी है जिसका समयकाल बढ़ाया जाता रहता है. इसके वर्तमान अध्यक्ष एम शिवन्ना हैं जो 31 मार्च 2016 तक कार्यरत रहेंगे.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 'भारत के राष्ट्रपति की वेबसाइट' पर बच्चों के खंड का आरंभ

भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 11 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति भवन में 'भारतीय राष्ट्रपति की वेबसाइट' (president of India's website) में बच्चों के खंड (http://164.100.23.71/demotemprb/RB-CS/RB-CS-Home.aspx) का आरंभ किया.

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि वेबसाइट पर बच्चों के खंड का शुरू होना राष्ट्रपति भवन को लोगों के लिए खोलने की दिशा में एक और कदम है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे बच्चे इस ऐतिहासिक इमारत

की यात्रा करने के लिए और प्रोत्साहित होंगे.

बच्चों का खंड

- बच्चों का यह खंड 7 से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बनाया गया है.
- यह बच्चों को राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बेहद साधारण भाषा और फोटो व वीडियो की मदद से शिक्षित करेगा.
- इसमें कई महत्वपूर्ण बातें होंगी जैसे - राष्ट्रपति भवन की इमारत की कहानी, राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल के मुख्य अंश, आजादी के बाद भारत के राष्ट्रपतियों से संबंधित जानकारी, राष्ट्रपति भवन में बैंक्वेट और किचन, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, गार्डन ट्रेल, राष्ट्रपति भवन में जीवन और राष्ट्रपति भवन में संग्रहालय आदि.
- इससे बच्चों को भौगोलिक, राजनैतिक एवं सामाजिक शिक्षा प्राप्त होगी.

भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट: पोषण 2015 जारी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा द्वारा 10 दिसम्बर 2015 को भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट : पोषण 2015 जारी की गयी.

इस रिपोर्ट में भारत के विभिन्न राज्यों में पोषण की उपलब्धता एवं उसकी वास्तविक स्थिती के बारे में जानकारी प्रदान की गयी है.

रिपोर्ट के अनुसार देश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जितना जल्दी हो सके कदम उठाये जाने चाहिए. देश में कुपोषण से शिकार बच्चों को बचाने के लिए यह आवश्यक है.

रिपोर्ट की विशेषताएं

- इसमें राज्यवार आंकड़े दिए गये हैं जिसमें सभी 25 राज्यों एवं दिल्ली में पोषण की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गयी है.
- यह परिणामों में असमानता और भौगोलिक क्षेत्रों में उनके कई निर्धारकों, सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों एवं जनसांख्यिकीय समूहों पर भी प्रकाश डालता है तथा राज्यवार नीति निर्माण में सहायता करता है.
- इसका उद्देश्य भारत में भारत में नीति वार्ता, बहुक्षेत्र एवं अल्पपोषण शिकायतों सम्बन्धी मुद्दों का हल

ढूंढना है.

- पिछले कुछ समय से भारत में नवजात शिशुओं के अल्पपोषण में कमी आई है. हालांकि भारत अभी भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे है.
- भारत के पोषण स्तर में सुधार भारत की आर्थिक उन्नति के अनुपात से बेहद कम है जो संतोषजनक नहीं है.

सामाजिक परिदृश्य

- भारत के कृषि एवं आर्थिक परिदृश्य में सुधार का सकारात्मक प्रभाव भारत के पोषण स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा जिसमें अनुचित भोजन और देखभाल के तरीके, बीमारियां, परम्पराएं, कन्या एवं बालक के पोषण में अंतर जैसे कारण शामिल हैं.
- भारत में बेहतर पोषण के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता जैसे मुद्दे हल करना आवश्यक है.
- भारत में पोषण के स्तर बढ़ाने एवं कुपोषण में कमी लाने के लिए राज्यों को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने होंगे जिससे उचित हल निकाला जा सके.
- भारत में ख़राब पोषण के मुख्य कारणों में स्तनपान, बच्चे का स्वास्थ्य, आय में असमानता, खाद्य असुरक्षा, जाति एवं श्रेणी, दूषित जल, स्वच्छता की कमी एवं खुले में शौच जाना शामिल है.
- भारत अल्पपोषण के खतरों को उपेक्षित करता रहा है जिसके कारण देश में आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं आ सकती हैं.
- यह बाल सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है. राज्यों को भारत में बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने हेतु ठोस कदम उठाने होंगे.

यह रिपोर्ट राज्यों से जुटाए गये आंकड़ों पर आधारित है तथा उन समस्याओं के निदान पर आधारित है.

म्यांमार ने यांगून स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन किया

म्यांमार ने 9 दिसंबर 2015 को नए स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन किया. स्टॉक एक्सचेंज नाम का यांगून स्टॉक एक्सचेंज (वाईएसएक्स) रखा गया है. इसे छह कंपनियों के लिए योजनाओं के साथ मार्च 2016 में आरंभ किया जाएगा.

मार्च 2016 तक वाईएसएक्स के साथ व्यापार शुरू करने वाली छह कंपनियां निम्न हैं-

- फर्स्ट म्यांमार इन्वेस्टमेंट कंपनी
- फर्स्ट प्राइवेट बैंक लिमिटेड
- ग्रेट होर खाम पब्लिक
- म्यांमार एग्रीबिजनेस पब्लिक कारपोरेशन
- म्यांमार सिटीजंस बैंक
- म्यांमार थिलावा एसईजेड होल्डिंग्स पब्लिक

प्रारंभ में यांगून स्टॉक एक्सचेंज केवल म्यांमार की कंपनियों और निवेशकों के लिए खोला जाएगा. और बाद में विदेशी निवेशकों और कंपनियों को म्यांमार के शेयरों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी.

स्टॉक एक्सचेंज स्थानीय कंपनियों दाइवा इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिसर्च जापान और जापान एक्सचेंज समूह जो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को चलता है, द्वारा संयुक्त उद्यम में स्थापित किया गया.

इस स्टॉक एक्सचेंज के खुलने से म्यांमार में ऐसी उम्मीद की जाती है कि इसके माध्यम से एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक म्यांमार की पूंजी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ाने में भी यह मदद करेगा. म्यांमार में जब तक सैन्य शासन रहा तब से (दशकों से) अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वहां की अर्थव्यवस्था अवरुद्ध है. वहां 2010 में लोकतांत्रिक सरकार बनी.

मानव तस्करी रोकने के लिए केंद्र बनाएगा जांच एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने 09 दिसम्बर 2015 को केंद्र सरकार को बच्चों और किशोरियों की तस्करी रोकने को 30 नवंबर, 2016 तक संगठित अपराध जांच एजेंसी (ओसीईए) गठित करने का आदेश दिया है. अदालत ने सरकार से 1 दिसंबर, 2016 से एजेंसी का कामकाज शुरू कराना भी सुनिश्चित करने को कहा है. बच्चों और लड़कियों की तस्करी के पीछे यौन शोषण एक बड़ा कारण है.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह व्यापारिक और यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास जैसे मुद्दों से निपटने के लिए एक सुगम्य कानून बनाने के मुद्दे पर छह महीने में विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरा करे और कमेटी गठित करके छह महीने के भीतर अपनी प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंपे.

इससे पहले शीर्ष अदालत ने वर्ष 2014 से 30 सितंबर 2015 के बीच अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत बालिकाओं की तस्करी के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी के डेटा एक पखवाड़े के भीतर प्रदान करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों,और गृह मंत्रालय (एमएचए) को निर्देशित किया.

न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को वेश्यावृत्ति में फंसी महिलाओं को मुक्त कराने और उनका पुनर्वास कराने के मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. इससे सम्बंधित एक जनहित याचिका वर्ष 2004 में दायर की गयी थी. जनहित याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने बुधवार को उक्त दिशा निर्देश जारी किए.

अदालत ने मंत्रालय को नए कानून पर विचार-विमर्श करने व अपने सचिव की अध्यक्षता में एक पैनल गठित करने और जल्द परामर्श शुरू करके न्यायालय को सूचित करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं.

सुनवायी के दौरान सरकार ने अपने हलफनामे में मानव तस्करी रोकने के लिए संगठित अपराध जांच एजेंसी (ओसीआइए) गठित करने की योजना की बात कही थी. इसके बाद कोर्ट ने मानव तस्करी रोकने को समग्र कानून बनाने को लेकर सरकार के प्रयासों को दर्ज करते हुए यह निर्णय दिया.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण उद्योग के लिए 4000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2015 को भारत में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 4000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

इस प्रस्ताव से जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और केंद्र सरकार के अभियान "मेक इन इंडिया" भी प्रोन्नत होगा.

प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं-

- सरकार के अभियान "मेक इन इंडिया" के द्रष्टिगत जहाज निर्माण की लागत में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जहाज की सुपुर्दगी के समय अनुबंध की कीमत का 20 प्रतिशत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, मूल्य की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में निर्माता को देगी.

सहायता प्रत्येक तीन साल बाद 3 प्रतिशत कम होती जाएगी. यह योजना सभी प्रकार के जहाजों के लिए लागू है.

- यह नीति दस साल के लिए लागू हो की गयी है. इस नीति के कार्यान्वयन के लिए दस वर्षों में 4000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी.

भारत में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग-

- जहाज निर्माण उद्योग में उच्च रोजगार क्षमता, निवेश और कारोबार गुणक प्रभाव, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक सामान है.
- जहाज निर्माण उद्योग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्योग है. ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रक्षा भूमिका में इसका महत्वपूर्ण योगदान है.
- यह भारी इंजीनियरिंग उद्योग के विकास में भी भूमिका निभाता है.

भारतीय न्यास संशोधन विधेयक-2015 लोकसभा में पारित

लोकसभा ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय न्यास संशोधन विधेयक-2015 को पारित कर दिया. इस विधेयक के माध्यम से कुछ पुराने और अप्रचलित प्रावधानों को समाप्त किया गया. भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में संशोधन करते यह विधेयक लाया गया. इसे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 7 दिसंबर 2015 को सदन में पेश किया था. भारतीय न्यास संशोधन विधेयक 1882 के औपनिवेशिक काल के भारतीय न्यास अधिनियम के पुराने पड़ चुके कानूनी प्रावधानों को हटाने और उन्हें 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार बनाने के लिए लाया गया. इसके तहत वर्तमान कानून की धारा 20 पर विशेष ध्यान दिया गया जो वित्त मंत्रालय के दायरे में आता है.

विदित हो कि नये संशोधन में ट्रस्टी के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है. वर्तमान कानून के तहत ट्रस्टी, ट्रस्ट के धन को प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए बाध्य है जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 20 में किया गया है जो ट्रस्ट की सम्पत्ति कोष के रूप में होने की स्थिति में होगी और जिसका तत्काल ट्रस्ट के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2015 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसम्बर 2015 को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2015 को मंजूरी दी.

यह विधेयक राज्य सभा की समिति द्वारा तैयार सिफारिशों पर आधारित है जिसपर ऊपरी सदन में मौजूद विधेयक की समीक्षा करने के उपरांत सिफारिशें जारी की गयीं.

अब यह विधेयक संसद में पारित होने के लिए जायेगा. यह विधेयक उपभोक्ताओं के हितों, रियल एस्टेट मामलों में पारदर्शिता एवं बिल्डर्स पर नियंत्रण हेतु लाया गया है.

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) विधेयक के प्रावधान

- यह रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एकसमान नियामक वातावरण प्रदान करता है ताकि इससे जुड़े मुद्दों का तेज़ी ने निपटान हो सके.
- इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय निवेश भी बढ़ेगा एवं केंद्र सरकार को सभी के लिए घर के कार्यक्रम को सफल बनाने में भी सहायता करेगा.
- यह रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के माध्यम से उपभोक्ताओं के समक्ष अनिवार्य प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है.
- इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करना है जिसमें रियल एस्टेट के प्रति पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना शामिल है.
- इसके द्वारा व्यवस्थित विकास के माध्यम से कुशल परियोजना निष्पादन किया जायेगा.

विधेयक की विशेषताएं

- यह विधेयक वाणिज्यिक एवं घरेलू दोनों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर लागू होगा.
- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निगरानी रखने हेतु 'रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी' की स्थापना की जाएगी.
- रियल एस्टेट परियोजनाओं एवं रियल एस्टेट एजेंटो को अथॉरिटी के समक्ष पंजीकरण कराना होगा.
- इसमें पंजीकृत परियोजनाओं जैसे प्रचारक, परियोजना, लेआउट प्लान, भूमि उपयोग, मंजूरियां, समझौते आदि की विस्तृत सूचना देनी होगी.
- परियोजना की लागत की पूँजी का ब्यौरा एक भिन्न बैंक अकाउंट द्वारा देना होगा.
- इस मुद्दे से जुड़े मामलों के निपटान हेतु फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी.
- सिविल कोर्ट न्यायधिकरण इस विधेयक में मौजूद मुद्दों को प्रतिबंधित करता है जबकि उपभोक्ता

न्यायालय द्वारा इन मुद्दों को उठाया जा सकता है.

- प्रचारक उपभोक्ता की सहमति से बिना योंजना और डिजाइन में बदलाव नहीं कर सकेंगे.
- विधेयक में सरकार के उचित नियमों को लागू करने एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने सबंधी प्रावधान भी मौजूद हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 में अधिकारिक संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की.

इस विधेयक में मौजूद सिफारिशें परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की स्थायी संसदीय समिति से संबंधित हैं.

राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 में किए गये संशोधन

- यह संशोधन 106 अतिरिक्त मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग में जोड़ने का अधिकार देता है.
- इन मार्गों के कार्यरत होने पर देश में कुल 111 जलमार्ग हो जायेंगे.
- इन प्रस्तावित जलमार्गो में फ़िलहाल किसी प्रकार का आर्थिक प्रस्ताव पेश नहीं किया गया.
- प्रत्येक जलमार्ग के लिए आर्थिक निर्णय तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पर निर्भर होगा जिसपर भारतीय जलमार्ग (आईडब्ल्यूएआई) विभाग द्वारा अध्ययन किया जा रहा है.
- आईडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय जलमार्ग का एक विस्तृत एवं सुगम मार्ग तैयार कर रहा है जिसे माल ढुलाई, यात्रा आदि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा.
- जलमार्ग में नदी एवं जल का अधिकार उस राज्य का ही रहेगा.
- इस योजना द्वारा देश में पर्यटन विकास का भी विकास होगा.

कानपुर में प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौता

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्रौद्योगिकी केन्द्र (टूल रूम) की स्थापना के लिए वस्त्र मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय और राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) ने 8 दिसम्बर 2015 को एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये.

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं

- समझौते के अंतर्गत परियोजना की निधि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जबकि एनटीसी एक बंद पड़ी अलाभप्रद मिल में भूमि उपलब्ध् कराएगी.
- प्रबंधन एक शासी परिषद के माध्यम से होगा, इस परिषद में एमएसएमई के विकास आयुक्त के अध्यक्ष एवं वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधि के सह-अध्यक्ष होंगे.
- वस्त्र मंत्रालय युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और इस प्रकार वस्त्र उद्योग को योग्य कर्मी प्रदान करेगा.
- केन्द्र एमएसएमई की उत्पादकता में सुधार करने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें गुणवत्ता वाले उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा.
- यह संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव शक्ति और परामर्श प्रदान करेगा.

लोकसभा में परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तावित

केंद्र सरकार ने 7 दिसम्बर 2015 को लोकसभा में परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 पेश किया.

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य नई परमाणु बिजली परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली समस्याओं को दूर करना और स्थापना में इस कारण होने वाली देरी को कम करना.

इस विधेयक के माध्यम से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया जाएगा.

विदित हो वर्तमान में नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संयुक्त उद्यम के गठन के लिए अतिरिक्त कोष की आवश्यकता होती है.

परन्तु परमाणु ऊर्जा अधिनियम,1962 के अंतर्गत “सार्वजिनक उपक्रम” को उस उपक्रम के रूप में पारिभाषित किया गया है जिसमे 51 प्रतिशत पेडअप कैप्टल केंद्र सरकार का हो.

उक्त परिभाषा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करने में अवरोध उत्पन्न होता है.

अतः परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 के अंतर्गत निम्न संशोधन अनुसूचित है

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खख) के तहत 'सरकारी कंपनी' की परिभाषा में संशोधन करना.
- संयंत्र स्थापित करने वाले संयुक्त उद्यम की लाइंसेंसिंग के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 14 में संशोधन.
- उक्त विधेयक के अनतर्गत लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी है.

वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा से सम्बंधित कार्य का संचालन न्यूक्लीयर पॉवर कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमटेड(एनपीसीआईएल) और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) द्वारा किया जाता है.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक-2015 राज्यसभा में पारित

राज्यसभा ने 7 दिसंबर 2015 को परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक-2015 पारित कर दिया. इसके पूर्व अगस्त 2015 में लोकसभा ने इसे पारित कर दिया था.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक- 2015 प्रॉमिस्री नोट, एक्सचेंज ऑफ़ बिल, चेक को परिभाषित करता है. इसके अतिरिक्त यह विधेयक चेक बाउंस जैसे मुद्दों के लिए दंड का निर्धारण करता है. यह विधेयक अधिनियमित होने के बाद परक्राम्य लिखित अधिनियम-1881 का स्थान लेगा.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक- 2015 से संबंधित मुख्य तथ्य:

- परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक-2015, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के पश्चात् परक्राम्य लिखित अधिनियम-1881 का स्थान लेगा.
- परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 उन परिस्थितियों को परिभाषित करता है, जिनमें चेक बाउंसिंग की स्थिति में शिकायत दर्ज की जा सकती है. लेकिन इस अधिनियम में अदालतों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट नहीं किया गया है. वर्तमान संशोधन विधेयक के तहत चेक बाउंसिंग का मामला उस अदालत में दायर किया जाएगा जिसका सम्बन्ध चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के क्षेत्र से हो.
- परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक-2015 के अनुसार, यदि चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक

से अधिक अदालतों में मुकदमा है तो उससे सम्बन्धी मामले एक ही अदालत में चलाए जाएंगे.

- परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 में इलेक्ट्रॉनिक चेक की परिभाषा का स्पष्टीकरण किया गया है. अधिनियम के तहत इलेक्ट्रानिक चेक का मतलब मूल चेक की सटीक नक़ल है, जो एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर एक सुरक्षित प्रणाली में उत्पन्न हो. जबकि परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक-2015 के तहत इलेक्ट्रानिक चेक का अर्थ कंप्यूटर रिसोर्स से प्राप्त चेक है जो डिजिटल हस्ताक्षर से सुरक्षित किया गया हो.
- परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक- 2015 चेक के साथ ही साथ प्रॉमिस्री नोट, एक्सचेंज ऑफ़ बिल को भी परिभाषित करता है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांगों की श्रेणी में रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसम्बर 2015 को राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किया कि पीड़ितों को विकलांगों की श्रेणी में रखा जाए तथा उन्हें सरकारी नौकरियों व समाज कल्याण योजनाओं में आरक्षण दिया जाए.

जस्टिस एम वाई इकबाल और जस्टिस सी नगप्पन की बेंच ने एसिड अटैक की शिकार बिहार की एक पीड़ित द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. बेंच ने बिहार सरकार से पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और उसकी सर्जरी समेत सभी इलाज निःशुल्क कराने का निर्देश दिया.

पृष्ठभूमि

इससे पहले वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी प्राइवेट अस्पतालों को एसिड अटैक के शिकार लोगों की सहायता हेतु निर्देश जारी किए थे. इसमें दवा और महंगी सर्जरी समेत मुफ्त इलाज करना शामिल है.

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एसिड की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की बात भी कही थी.
- यह भी निर्देश दिया गया था कि एसिड अटैक के पीड़ित को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए.
- भारत में प्रत्येक वर्ष 1 हज़ार मामले दर्ज किये जाते हैं जबकि पूरे विश्व में लगभग 1500 मामले सामने आते हैं.
- हमलावर ज्यादातर मामलों में चेहरे को निशाना बनाते हैं.

देश की पहली डबल डेकर गोवा-मुंबई शताब्दी रेलगाड़ी शुरू

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रविवार 6 दिसंबर 2015 को प्रथम गोवा-मुंबई डबल डेकर वातानुकूलित शताब्दी रेलगाड़ी को पणजी से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रेलगाड़ी गोवा के मडगांव स्टेशन और मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन के बीच सप्ताह में तीन फेरे लेगी.

पूरी तरह से वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन देश में अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

पहली डबल डेकर गोवा-मुंबई ट्रेन की मुख्य विशेषताएं-

- ट्रेन मडगांव और मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) के बीच सप्ताह में तीन दिन चलेगी.
- रेलगाड़ी में आठ कोच हैं. प्रत्येक कोच में 120 यात्रियों के बैठने की क्षमता है.
- डबल डेकर ट्रेन लगभग 12 घंटे में अपने की दूरी को तय करेगी.
- ट्रेन तटीय राज्य गोवा के लिए पर्यटकों को अधिक संख्या में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इससे को भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

भारतीय मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय मानक निकाय बनाने के लिए विधेयक पारित

लोकसभा ने 3 दिसम्बर 2015 को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को राष्ट्रीय मानक निकाय बनाने तथा वस्तुओं सेवाओं और प्रणालियों को इसके तहत लाने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक,2015 को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की.

इस विधेयक के तहत प्रक्रिया को तो आसान बनाया गया है, लेकिन दंड के प्रावधान को मजबूत बनाया गया है.

अब अनिवार्य उत्पादों के मामले में अगर कोई सामान मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला जाएगा. इसके अतिरिक्त जुर्माने की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए और सजा भी एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है.

बीआईएस पहले केवल प्रसंस्करण की गुणवत्ता के लिए मानक तैयार करता था, लेकिन अब इसमें सिस्टम और

सर्विसेज को भी जोड़ा गया है.

कंपनियां बीआईएस मानक को स्वप्रमाणित करेंगी और शिकायत आने पर ही जांच की जाएगी.

इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलेगी और बाहर से आने वाले घटिया सामान पर रोक लगेगी.

विदित हो मानकों को लेकर पिछला कानून 1986 में बनाया गया था.

रेल मंत्रालय एवं जल संसाधन मंत्रालय के मध्य समझौता

रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती की उपस्थिति में रेल उद्येश्यों के लिए गंगा एवं यमुना नदी में स्थित सीवेज/ उत्प्रवाही उपचार संयंत्रों से उपचार के बाद पीने के अयोग्य जल के उपयोग को लेकर रेल मंत्रालय एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच 03 दिसंबर 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

विदित हो भारतीय रेल अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए जल के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है.

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं

- गंगा एवं यमुना नदी में स्थित सीवेज/ उत्प्रवाही उपचार संयंत्रों से उपचार के बाद पीने के अयोग्य जल के विभिन्न उपयोगों को लेकर रेल मंत्रालय एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया.
- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय का लक्ष्य गंगा एवं यमुना के दोनों तटों पर सीवेज/ उत्प्रवाही उपचार संयंत्रों (एसटीपी/ ईटीपी) के लिए नेटवर्क स्थापित करने का है जिससे कि नदियों में गिरने वाले प्रदूषणों को रोका जा सके.
- एसटीपी/ ईटीपी से उपचार हो चुके जल का उपयोग विभिन्न गैर लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.
- जहां कहीं भी रेलवे स्टेपशनों समेत ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए पीने के अयोग्य पानी की जरूरत होगी, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय इसके लिए आवश्यक पाइपलाइन, पंप आदि सुलभ कराएगा. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय इसके लिए प्रारंभिक राशि का भुगतान करेगा.
- रेल मंत्रालय उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले ऐसे पानी के लिए राशि अदा करेगा जिसका फैसला दोनों मंत्रालय आपसी सहमति से करेंगे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश एन्क्लेव के लिए पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी

2 दिसंबर 2015 को केंद्रीय कैबिनेट ने बांग्लादेश एन्क्लेव और कूच बिहार जिले में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दे दी. भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के हस्तांतरण के बाद पुनर्वास किया जाएगा.पैकेज की

मुख्य बातें

- विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए कुल वित्तीय अनुमान 1005.99 करोड़ रूपये का है.
- इस पैकेज में भारत में कूच बिहार जिला और बांग्लादेश एन्क्लेव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 898.50 करोड़ रुपये की तय लागत शामिल है.
- इसके अलावा, 107.49 करोड़ रुपयों की परिवर्तनीय लागत के पुनर्वास पर खर्च किए जाने की संभावना है.
- सभी काम पश्चिम बंगाल सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा 3- 5 वर्ष की समय- सीमा में किए जाएंगे.
- धनराशि केंद्रीय गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार को अनुदान सहायता के तौर पर जारी करेगी.
- यह पुनर्वास पैकेज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए दो प्रस्तावों के मिलने के बाद आया है. पुनर्वास उपायों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास और पुनर्वास सहायता से इलाकों और लोगों के सहज एकीकरण में मदद मिलेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नए आईआईटी को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2 दिसम्बर 2015 को छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की.

ये नई आईआईटी आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में खुलेंगे.

- प्रत्येक नए आईआईटी शुरुआत में 180 छात्रों को भर्ती करेंगे और प्रत्येक आईआईटी में फेकल्टी, छात्र 1 और10 के अनुपात में होंगे.
- दूसरे वर्ष यह संख्या बढ़ाकर 450 और तीसरे वर्ष 928 (840 स्नातक, 80 स्नातकोत्तर और 8 पीएचडी)

कर दी जाएगी.

- प्रत्येक नई आईआईटी प्रारंभिक 3 वर्षों में अस्थायी परिसर में कार्य करेगी तत्पश्चात इन्हें स्थायी परिसर प्रदान किया जाएगा.

इस मंजूरी के तहत इन आईआईटी को संशोधन के जरिए आईआईटी एक्ट 1961 में शामिल किए जाने तक शुरुआत में इन्हें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसायटी का गठन कर चलाने की व्यवस्था की गयी है. इस समय देश में 16 आईआईटी हैं.

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'ज्ञान' योजना का शुभारम्भ

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने आईआईटी गांधीनगर, गुजरात में 30 नवम्बर 2015 को ज्ञान(ग्लोबल इनिशियेटिव ऑफ़ एकेडमिक नेटवर्क्स) योजना का शुभारम्भ किया.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है.

ग्लोबल इनिशियेटिव ऑफ़ एकेडमिक नेटवर्क्स (जीआईएएन)

- 'ज्ञान' योजना का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है.
- इस योजना के अंतर्गत विभिन्न देशों के शिक्षाविदों को भारत में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
- आरम्भ में विभिन्न देशों के 500 शिक्षाविद इस योजना में शमिल होंगे.
- वर्तमान में 38 देशों के शिक्षाविद अल्पकालिक पाठ्यक्रम संबोधित करने के लिए अनुसूचित हैं.
- अमरीका के 46 शिक्षाविद, ब्रिटेन के 9, जर्मनी से 6, ऑस्ट्रेलिया से 6 और इस्राइल से 2 शिक्षाविद इसमें शामिल है.

प्रारंभ में निम्न विषयों को शमिल किया जाएगा -

- सांस्कृतिक विरासत के लिए 3 डी डिजिटलीकरण - इस विषय पर व्याख्यान आईआईटी गांधी नगर में प्रोफेसर मार्को कैलरी, विजुअल कंप्यूटिंग लैब, आईएसटीआई-सीएनआर, इटली द्वरा किया जाएगा.
- ओर्थपेडीक बायोमकेनिक्स: इम्प्लांट एण्ड बायोमैटेरियल्स - इस विषय पर व्याख्यान प्रोफेसर निको

वेर्डनस्कॉट, ट्वेन्ट विश्विद्यालय, नीदरलैंड द्वारा किया जाएगा.

विषय के आधार पर पाठ्यक्रम की अवधि 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक होगी. मेजबान संस्था के छात्रों के लिए यह मुफ्त रहेगा जबकी अन्य संस्थान के छात्रों मामूली शुल्क के मध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं.

केंद्र सरकार ने आईपीवी इंजेक्शन का शुभारंभ किया

केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2015 को ग्लोबल पोलियो एंडगेम स्ट्रेटजी के लिए अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में इंजेक्शन इनएक्टिवटेड पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) का शुभारंभ किया.

इस आईपीवी इंजेक्शन का शुभारम्भ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा नई दिल्ली में किया गया.

यह देश में पोलियो के खिलाफ लड़ने के लिए भारत की सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का अगला कदम है.

मुख्य बिंदु

- इस कार्यक्रम के पहले चरण के अंतर्गत असम, गुजरात, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाएगा.
- इस आईपीवी इंजेक्शन को ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) के साथ एक वर्ष के कम उम्र के बच्चों को प्रदान किया जाएगा.
- एसा पाया गया है की आईपीवी और ओपीवी एक साथ दिए जाने पर बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और इस तरह से उन्हें दोहरी सुरक्षा प्रदान करेंगे.
- नियमित टीकाकरण में आईपीवी की शुरूआत की अनुशंशा वैश्विक पोलियो एंडगेम रणनीति द्वारा मई 2015 में विश्व स्वास्थ्य महासभा में की गई थी.

इस कार्यक्रम के तहत विश्व के 126 देशों को शामिल किया गया है जो अब भी ओरल वेक्सीन का प्रयोग कर रहे हैं.

इससे पहले 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था परन्तु भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो के मामले पाए गए हैं अतः पोलियो से प्रतिरक्षा अनिवार्य है.

अर्थव्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर दीपक मोहंती समिति की मध्यावधि पथ संबंधी रिपोर्ट जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2015 को वित्तीय समावेशन पर दीपक मोहंती समिति की मध्यावधि पथ संबंधी रिपोर्ट जारी की. इस समिति की स्थापना आरबीआई द्वारा 15 जुलाई 2015 को वित्तीय समावेशन हेतु मध्यावधि (पांच वर्ष) कार्य योजना तैयार करने के लिए की गयी.

14 सदस्यों वाली इस समिति की अध्यक्षता दीपक मोहंती ने की.

समिति की मुख्य सिफारिशें

- बैंकों को महिलाओं के लिए खाते खोलने को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे और सरकार बालिकाओं के लिए जमा योजना - सुकन्या शिक्षा - पर कल्याणकारी उपाय के रूप में विचार कर सकती है.
- व्यक्तिगत खाताधारण के प्रभाव (कुल ऋण खातों का 94 प्रतिशत) को देखते हुए, आधार जैसा विशिष्ट बायोमीट्रिक अभिज्ञापक प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण खाते और ऋण सूचना कंपनियों के साथ शेयर की गई सूचना के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि ऋण प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित हो सके और पहुंच में सुधार किया जा सके.
- 'अंतिम समय' (लास्ट माइल) की सेवा डिलीवरी में सुधार करने और बढ़ी हुई सुविधा तथा उपयोग में वित्तीय पहुंच को अंतरित करने के लिए संभावित अधिकाधिक जी2पी भुगतानों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा के उपयोग द्वारा न्यून-लागत सल्यूशन विकसित किया जाना चाहिए.
- शीघ्र चुकौती रिकार्ड वाले ऋणदाताओं के लिए उच्चतर लचीलेपन के साथ स्वर्ण किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की योजना शुरू करना जिसे सरकार प्रायोजित व्यक्तिगत बीमा से सही ढंग से मॉनिटर किया जा सकता है एवं व्यय पैटर्न का पता लगाने के लिए केसीसी का डिजीटलीकरण करना.
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए बहु-गारंटी

एजेंसियों को प्रोत्साहित करना तथा काउंटर गारंटी और पुनर्बीमा की संभावना तलाशना.

- बैंकों के कारोबारी मॉडल उचित निगरानी वाली नामित संपर्क शाखाओं के साथ व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) विशेषकर आम आदमी का विश्वास प्राप्ता करने के लिए निश्चित स्थान वाले व्यापार प्रतिनिधियों (बीसी) को समेकित करें.
- कॉरपोरेट्स द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों के भाग के रूप में स्वयं सहायता समूहों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) गैर स्मार्ट फोन का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लेनटफार्म (एनयूयूपी) के उपयोगकर्ताओं के लिए, एक बहुभाषी मोबाइल अनुप्रयोग विकसित करें.
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) नेटवर्क को मजबूत किया जाए ताकि बुनियादी स्तर पर वित्तीय साक्षरता प्रदान की जा सके.
- बैंकों द्वारा अग्रणी साक्षरता अधिकारियों की पहचान की जाए जिन्हेंत रिजर्व बैंक द्वारा अपने कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) में प्रशिक्षित किया जाएगा और जो वित्तीवय साक्षरता केंद्र चलानेवाले लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं.
- दूसरी पीढ़ी के सुधारों के एक हिस्से के रूप में, सरकार एक प्रत्यक्ष आय अंतरण योजना द्वारा मौजूदा कृषि इनपुट सब्सिडी का स्थाकन खाद, बिजली और सिंचाई के साथ बदल सकता है.

इसके अतिरिक्त समिति ने कई अन्य सिफारिशें की हैं ताकि शासन प्रणाली में सुधार हो, क्रेडिट का बुनियादी ढांचा मजबूत बने और सरकारी सामाजिक नकद हस्तांतरण बढ़ें ताकि गरीबों की व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बढ़े और अर्थव्यवस्था को मध्यावधि के लिए एक धारणीय समावेशक पथ पर स्थापपित किया जा सके.

आरबीआई ने विदेशी मुद्रा मामलों पर भारत में स्टार्ट- अप के मार्गदर्शन हेतु समर्पित हेल्पलाइन बनाई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 22 दिसंबर 2015 को विदेशी मुद्रा मामलों पर भारत में स्टार्ट- अप के मार्गदर्शन के लिए समर्पित हेल्पलाइन बनाई ताकि वे नियामक रूपरेखा के दायरे में सीमा पार से लेनदेन कर सकें.

हेल्पलाइन पर मार्गदर्शन की मांग करने के दौरान, उद्यमों से अपना पूरा विवरण रिजर्व बैंक को देने और

विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमन के संबंध से वे बैंक से जिन विशेष मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं, को बताने को कहा जाएगा.

यह हेल्पलाइन कर्मी को समय से और प्रभावपूर्ण जानकारी देने में सक्षम बनाएगा. आमतौर पर, स्टार्ट-अप उद्यम निवेश समेत कई अन्य मामलों में सीमा पार से व्यापाक लेन- देन करते हैं.

भारतीय निवासी का सीमा- पार लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 द्वारा प्रदत्त नियामक व्यवस्था के अधीन आता है.

वित्त वर्ष 2015-16 में आयकर दाताओं की संख्या में 27 लाख की वृद्धि

केंद्रीय आयकर विभाग द्वारा दिसंबर 2015 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 में देश में आयकर दाताओं (इनकम टैक्सपेयर) की संख्या में 27 लाख नए लोगों की वृद्धि दर्ज की गई. आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष (2015-16) में एक करोड़ नए लोगों को आयकर के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है.

आयकर विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा नए टैक्सपेयर पश्चिमी राज्यों मसलन गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में जोड़े गए हैं. 27 लाख से ज्यादा इन नए लोगों और इकाइयों को विभाग द्वारा वर्ष 2015 के मध्य में शुरू किए गए अभियान के बाद कर दायरे में लाया गया.

विदित हो कि वर्तमान समय में देश में 3 करोड़ 66 लाख से अधिक आयकर दाता हैं. आयकर विभाग के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (2015-16) में एक करोड़ नए लोगों को आयकर के दायरे में लाने की जगह तय समय में 60 से 70% तक ही लक्ष्य हासिल हो पाने की उम्मीद है.

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की

अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के निदेशक मंडल की अध्यक्ष जेनेट येलेन ने 16 दिसंबर 2015 को इसकी घोषणा की. फेडरल रिजर्व द्वारा करीब सात सालों की रिकॉर्ड गिरावट के बाद पहली बार ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की गई.

उपरोक्त फैसले के तहत फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख दर में 0.25 फीसदी का इजाफा कर इसे 0.5 फीसदी

कर दिया. इससे पहले करीब सात साल तक यह दर शून्य के करीब थी जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के समय हुई थी. दर में किए गये इस इजाफे से उपभोक्ताओं और व्यापारिक संस्थाओं को कुछ कर्ज पर थोड़ी ज्यादा दरें चुकानी पड़ सकती हैं.

फेडरल रिजर्व के फैसले का भारत पर प्रभाव:

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी व इसमें धीरे-धीरे और बढ़ोतरी का उल्लेख अनुमान के अनुरुप है. इसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा यह पिछले एक दशक में की गयी पहली बढ़ोतरी है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का संकेत मिलता है. इससे विश्व बाजार में अनश्चितता खत्म होने और भविष्य के लिए समावेशी परिदृश्य से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नीति निर्माताओं को मदद मिलेगी. फेडरल रिजर्व का अर्थव्यवस्था में सुधार का भरोसा भारतीय निर्यात विशेष तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है.

केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाकर 400 डॉलर प्रति टन किया

केंद्र सरकार ने 10 दिसम्बर 2015 को प्याज़ का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 700 डॉलर से घटाकर 400 डॉलर प्रति टन किया. इसका निर्णय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में की गयी बैठक के दौरान किया गया. एमईपी वह मूल्य है जिससे कम मूल्य पर कोई भी व्यापारी उक्त वस्तु को नहीं बेच सकता. इसमें बढ़ोतरी से निर्यात में कमी आती है तथा घरेलू सप्लाई भी बेहतर होती है.

इससे पहले 23 अगस्त 2015 को प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाकर 700 डॉलर प्रति टन कर दिया गया था. इसकी मुख्य वजह प्याज़ की कीमतों का असामान्य रूप से बढ़ना था.

दिसंबर 2015 के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र सरकार ने प्याज़ की खुदरा कीमतें 10 रूपए प्रति किलो के स्तर पर आने पर केंद्र सरकार से प्याज़ की कीमतों को कम करने के लिए कहा था.

सार्वजनिक ऋण में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि

केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण में वित्त वर्ष 2015-16 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

केंद्र सरकार के ऋण प्रबंधन के बारे में जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का कुल सार्वजनिक ऋण (सार्वजनिक खाते के तहत आने वाली देनदारियां शामिल नहीं) सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 54.12 लाख करोड़ रुपये हो गया जो कि जून 2015 को समाप्त तिमाही में 53.01 लाख करोड़ रुपये थी. इस रिपोर्ट के अनुसार आलोच्य तिमाही में सार्वजनिक ऋण में त्रैमासिक आधार पर 2.1 प्रतिशत की बढोतरी (अस्थाई) दर्ज की गई. आलोच्य तिमाही में सार्वजनिण ऋण में आंतरिक ऋण का हिस्सा 92.1 प्रतिशत रहा.

एमएसडीई एवं डीएचआई ने विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) एवं भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने 8 दिसम्बर 2015 को विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

समझौता ज्ञापन कैपिटल गुड्स और मोटर वाहन क्षेत्र पर केंद्रित है. इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना एवं प्रशिक्षण शिक्षा और अनुसंधान के लिए विभिन्न स्थानों पर विनिर्माण प्रौद्योगिकी के बहु स्थान राष्ट्रीय संस्थान खोलना है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एचएमटी, भेल एवं आईएल की सुविधाओं का लाभ उठाना है.
- यह केंद्र सुनिश्चित करेंगे कि इनमें निर्मित उत्पाद विश्वस्तर के हों एवं जर्मनी जैसे सक्रिय देशों की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय हो.
- इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) का 20 प्रतिशत कौशल विकास के उद्देश्य से देना होगा.
- केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, उपकरण और मशीनरी भी उपलब्ध कराएंगे जो उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होगा लेकिन इसे संस्थानों में प्रशिक्षण उद्देश्य से ही उपयोग किया जायेगा.
- यह समझौता भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे तथा आईटीआई को बढ़ावा देंगे.
- आईटीआई के अतिरिक्त उन्नत प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत होंगे.
- इस समझौते द्वारा कौशल विकास की श्रृंखला में निजी भागीदारी को सक्षम बनाया जायेगा.

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर शीर्ष पर

वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह अप्रैल से सितंबर तक (छह माह) के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मामले में सिंगापुर शीर्ष स्रोत के रूप में उभरा है. उसने मॉरीशस का स्थान लिया है. इस संबंध में औद्योगिक नीति एवं वाणिज्य मंत्रालय संवर्धन और उद्योग विभाग द्वारा घोषणा दिसंबर 2015 के पहले सप्ताह में की गयी.

आंकड़ों के अनुसार 15 अप्रैल से 15 सितंबर 2015 के बीच भारत ने सिंगापुर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में 6.69 अरब डॉलर (43,096 करोड़ रुपये) आकर्षित किया. मॉरिशस से इसी अवधि में एफडीआई में 3.66 अरब डॉलर (23,490 करोड़ रुपए)विदेशी निवेश के रूप में भारत आए.

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 16.63 अरब डॉलर का एफडीआई भारत में आया है. विदेशी निवेशकों ने सर्वाधिक एफडीआई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 3.05 अरब डॉलर, ट्रेडिंग में 2.3 अरब डॉलर,सर्विस सेक्टर में 1.46 अरब डॉलर, ऑटो सेक्टर में 1.46अरब डॉलर, टेलिकॉम में 65.9 करोड़ डॉलर का निवेश आया है.

इसी अवधि में नीदरलैंड 7017 करोड़ रुपये के निवेश के साथ तीसरे नंबर पर था. जबकि 5435 करोड़ रुपये के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे पायदान पर है.

हालांकि अप्रैल 2000 से सितंबर 2015 के बीच संचयी अंत: प्रवाह के मामले में मॉरीशस अभी भी निवेश सूची में सर्वोपरी है. कुल एफडीआई निवेश का 34 प्रतिशत योगदान मॉरीशस का है. इसी अवधि में यह केवल 15 प्रतिशत थी.

एनटीसी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता किया

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) लिमिटेड ने 3 नवम्बर 2015 को सत्यनिष्ठा पैक्ट अपनाने हेतु ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

एनटीसी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं एवं 49वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बन गया है.

सत्यनिष्ठा पैक्ट एक ऐसी ईकाई है जो यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी एवं सरकार के मध्य होने वाले सभी कार्य सुचारु, इमानदारी एवं सत्यता के साथ किये जा रहे हैं. यह किसी भी अनैतिक कार्य, घूसखोरी अथवा

अविश्वसनीय कार्यों पर भी बाहरी स्रोतों द्वारा नज़र रखती है.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) लिमिटेड

यह एक सार्वजिनक क्षेत्र उपक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कानूनों के तहत कार्यरत है. वर्ष 2013-14 में एनटीसी लिमिटेड ने 12 बिलियन रुपये का लाभ अर्जित किया.

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई)

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन का ही भाग है. यह वर्ष 2005 से सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कार्यरत है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल व्यवस्था में पारदर्शिता लाने हेतु बड़ी भूमिका निभाता है.

वर्ष 2006 में ओएनजीसी ऐसा पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था जिसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये.

ओड़िसा पॉवर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं नई दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन एकमात्र सार्वजानिक उपक्रम हैं जिन्होंने सत्यनिष्ठा पैक्ट अपनाने हेतु हस्ताक्षर किये.

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु विश्व के उद्योगपतियों ने समझौता किया

सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए 28 नवम्बर 2015 को बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और जैक मा सहित दुनिया के अन्य विशिष्ट उद्योगपतियों ने एक समझौता किया. इसे ब्रेकथ्रू एनर्जी कोऐलिशन नाम दिया गया है

ब्रेकथ्रू एनर्जी कोऐलिशन में 28 अंतरराष्ट्रीय निवेशक शामिल हैं. इस ग्रुप का मकसद अनुसंधान कक्ष से बाज़ार तक सस्ती, विश्वसनीय और कार्बन फ्री एनर्जी मुहैया करने की क्षमता प्रदान करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करना है.

ब्रेकथ्रू एनर्जी कोऐलिशन में ऐसे 100 से अधिक देश शामिल होंगे जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुरता से उपलब्ध होता है. इनका मकसद स्वच्छ, सस्ती और नवीकरणीय सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना है.

इससे विश्व भर की सरकारों को विशिष्ट अविष्कारों की सहायता से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी. यूके वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रैंसन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और हेवलेट पैकार्ड के मेग वाइटमैन भी इस कोऐलिशन के हिस्सा होंगे.

एक्सिस बैंक द्वारा देश के पहले डिस्प्ले डेबिट कार्ड का शुभारम्भ

देश के तीसरे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने 2 दिसम्बर 2015 को एनआरई खाताधारक प्रवासी भारतीय ग्राहकों के लिए डिस्पले आधारित डेबिट कार्ड जारी किया है. इसके साथ ही ग्राहकों को यह सुविधा देने वाला वह देश का पहला बैंक बन गया है.

डिस्पले आधारित डेबिट कार्ड

• बैंक द्वारा जारी किए गए इस ईएमवी समर्थित डेबिट कार्ड में एक डिस्प्ले और टच बटन है. इसके माध्यम से ग्राहक स्वयं वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जेनरेट कर सकते हैं.

• इससे इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेनदेन के दौरान ओटीपी पाने के लिए एसएमएस और ईमेल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

• इसे अंतर्राष्ट्रीय एटीएम शुल्क के साथ पेश किया गया है.

• इसके जरिए ग्राहक अंतर्राष्ट्रीय एटीएम का नि:शुल्क इस्तेमाल कर सकेंगे.

• इस पर ग्राहकों के लिए हवाई यात्रा के दौरान दुर्घटना की स्थिति में 25 लाख रुपए एवं अन्य दुर्घटना में पांच लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा.

सरकार ने पीएफ निकालने में ख़त्म किया नियोक्ता का हस्तक्षेप

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अशंधारक अब भविष्य निधि (पीएफ) की निकासी के लिए आवेदन अपने नियोक्ता (कंपनी) के सत्यापन के बिना ही जमा कर सकते हैं. 02 दिसम्बर 2015 को ईपीएफओ ने पीएफ निकासी दावों के ऑनलाइन निपटान की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आज यह मंजूरी दी.

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2015 में पीएफ कटौती के उद्देश्य से 'अंशदायी वेतन' की अवधारणा को शामिल किया गया है. ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान इस विधेयक को शीघ्र ही मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष भेजेंगे.

यह सुविधा उन अंशधारकों के लिए होगी जिनका यूनिवर्सल या पोर्टेबल पीएफ खाता संख्या (यूएएन) सक्रिय हो चुका है और जिसके लिए बैंक खाता और आधार संख्या जैसी जानकारी दी जा चुकी है<

इस नई व्यस्था से निकासी दावे सीधे ईपीएफओ के यहां दाखिल करने की सुविधा से अंतत: हमें इस तरह के

आवेदनों के ऑनलाइन निपटान की सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी. ईपीएफओ के कार्यालयी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी अपने दावे फॉर्म-19, फॉर्म -आईओसी व फॉर्म 31 में दाखिल कर सकते हैं.

फॉर्म 19, फॉर्म 1 ओसी भरने होंगे.

जिन ईपीएफ सदस्यों के यूएएन नंबर एक्टिवेट हो गए हैं, वे इस सुविधा के लाभ के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 1 ओसी और फॉर्म 31 भरकर सीधे भविष्य निधि आयुक्त को बगैर नियोक्ता के सत्यापन के आवेदन सौंप सकेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि

वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में राष्ट्रीय विकास दर में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. पहली तिमाही में यह मात्र 7 फीसद थी. वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2014-15 की समान तिमाही की 8.4 फीसद वृद्धि के मुकाबले एक फीसद कम है.

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) ने 30 नवंबर 2015 को वर्तमान जीडीपी के आंकड़े जारी किए. इसके अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में विकास दर 7.2 फीसद रही. जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 7.5 फीसद थी. सीएसओ के अनुसार दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में व्यापार, होटल, परिहवन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं की वृद्धि सर्वाधिक 10.6 फीसद हुई. दूसरी तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग की वृद्धि बढ़कर 9.3 फीसद हो गई जो कि पहली तिमाही में 7.2 फीसद तथा पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.9 फीसद थी.

दूसरी तिमाही में कृषि, वानिकी और मत्स्यन क्षेत्र की वृद्धि दर 2.2 फीसद रही. इस अवधि में पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन की वृद्धि दर 6 फीसद रही है. सीएसओ के अनुसार दूसरी तिमाही के दौरान खरीफ मौसम में अनाज के उत्पादन में -1.8 फीसद और दलहन के उत्पादन में -1.1 फीसद की नकारात्मक वृद्धि रही. निर्माण क्षेत्र में भी पिछले साल की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मात्र 2.6 फीसद है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8.7 फीसद थी.

विदित हो कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.4 फीसद वृद्धि के साथ भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया. इस अवधि में चीन की वृद्धि दर 6.9 फीसद रही.

पर्यावरण पारिस्थितिकी

12 करोड़ साल पुराने टिड्डे का जीवाश्म मिला

जीवाश्म की खोज के लिए मशहूर संस्थान चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत नानजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी एंड पेलियोंटोलॉजी के छात्र के शोध के बाद 22 दिसम्बर 2015 को स्पष्ट हुआ कि कीड़ों के केवल पंख ही जीवाश्म के रूप में बच पाते हैं. जमीन के अंदर इनके शरीर के बाकी हिस्से नष्ट हो जाते हैं या उसे कोई अन्य प्राणी खा जाता है.

शोध के अनुसार टिड्डे के पंखों को देखकर पता चलता है कि यह कीड़ा आधुनिक कैटिडिट का पूर्वज है. उसके पंखो की बनावट को देखकर अनुमान लगाया गया है कि यह कीड़ा भी आधुनिक कीड़ों की तरह ही आवाज निकालता होगा. आधुनिक कैटिडिड के पंख और जनन अंग उसके पूर्वजों की अपेक्षा कमजोर होते हैं.

संस्थान में कार्यरत पेलियोंटोलॉजी के प्रोफेसर के अनुसार यह कीड़ा चीन के किसी दूसरे हिस्से या दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाया जाता. शोध के बाद पता चला है कि ये कीड़े क्रिटासियस काल के दौरान विश्व के सबसे पुराने फूल-पत्तियों को खाकर जीवित रहते थे.

पश्चिम बंगाल के तट पर ईल की नई प्रजाति जिमनोथोरेक्स मिश्रई खोजी गई

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला में स्थित दीघा के तट पर जिमनोथोरेक्स मिश्रई (Gymnothorax mishrai) नामित ईल (Eel) की नई प्रजाति की खोज की.

ईल की नई प्रजाति की खोज डेविड जी स्मिथ और दीपांजन रे के साथ अनिल महापात्र द्वारा संयुक्त रूप से पत्रिका जूटाक्सा (Zootaxa) में प्रकाशित हुई.

जिमनोथोरेक्स मिश्रई (Gymnothorax mishrai) के बारे में

- यह प्रजाति 32.4 सेमी, लंबी भूरे रंग की है.
- यह एक समुद्री प्रजाति है और खाने योग्य भी है.
- यह जिमनोथोरेक्स समूह में वर्णित अन्य प्रजातियों से अलग है, मोरे मछली की इस प्रजाति की 134 कशेरुकी हड्डियां है.
- यह प्रजाति को विशेष रूप से 22 मीटर की गहराई से एकत्र किया गया.
- इन प्रजातियों का नमूना मछली लैंडिंग केंद्र, शकरपुर में एक मछली पकड़ने की नाव से एकत्र किया गया.

ईल के बारे में

ईल मछली या सांप के समान लम्बी पंख और गलफड़े वाली मछली होती हैं, जो सागर के उथले पानी में रेत, मिट्टी, या चट्टानों के बीच पाई जाती है. ईल अपने शरीर की लंबाई के बराबर लहरे उत्पन्न करके तैरती है. वे लहर की दिशा विपरीत भी तैर कर सकते हैं.

दुनिया भर में ईल की 800 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में 150-200 ईल की प्रजातियां है.

म्यांमार के पहले यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 'इन्ले झील' का शुभारंभ

दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़ा देश म्यांमार ने 11 दिसंबर 2015 को म्यांमार के शान राज्य में देश के पहले यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 'इन्ले झील' का शुभारंभ किया.

ज्ञात हो इन्ले झील को वर्ष 2015 के जून माह में पेरिस में 'यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व' के रूप में नामित किया गया था.

इस के साथ ही म्यांमार ने यूनेस्को की मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया.

विदित हो इससे पूर्व वर्ष 2014 में म्यांमार के 'प्यू एनशियेंट सिटी' को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था.

- इन्ले झील 489721 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है. यह म्यांमार के शान राज्य टाउनगी जिले की न्याउनश्वे बस्ती में स्थित है.

- वर्तमान में इस झील को संरक्षण और पुनर्वास परियोजना की रूपरेखा के तहत नॉर्वे की सरकार से धनप्रदान किया जाता है.
- यह पक्षियों की 267 प्रजातियों के लिए निवास स्थल है, जिसमें से 82 आर्द्रभूमि पक्षी हैं.
- इस झील में लुप्तप्राय सारस क्रेन भी पाए जाते हैं.

फिलिपींस में 'मेलर तूफान' के कारण नौवहन बंद और अलर्ट जारी

फिलिपींस में मेलर तूफान के मजबूत होकर आगे बढने़ से मध्य भाग में बढते खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने 14 दिसम्बर 2015 को स्कूलों को बंद करने और समुद्र में मछली पकडने़, नौवहन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है.

मेलर एक चक्रवाती तूफान है, जिसे स्थानीय लोग 'नोना' के नाम से जानते हैं.

मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान मध्य फिलिपींस में 2013 में आए जबरदस्त तूफान हेयान की तरह है.

हेयान जब फिलिपींस से टकराया तो वह पांचवीं श्रेणी के तूफान में बदल गया था. जिसने यहां भयानक तबाही मचायी थी और इसकी चपेट में आकर लगभग 8000 लोग या तो मारे गये थे या लापता हो गए थे.

तटरक्षक बल द्वारा मेलर तूफान के खतरे के मद्देनजर समुद्र में नौवहन और मत्सयन पर रोक लगा देने से लगभग 8000 हजार लोग बंदरगाहों पर फंस गये हैं.

तूफान के प्रभाव में इसके केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए राजधानी मनीला सहित 20 प्रांतों में चेतावनी जारी कर दी गयी है. फिलिपींस को हर साल इन तूफानों का सामना करना पड़ता है औसतन 20 तूफान हर साल फिलिपींस से गुजरते हैं.

यस बैंक द्वारा क्लाइमेट एक्शन के लिए 2020 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यवस्था की घोषणा

8 दिसंबर 2015 को यस बैंक लिमिटेड ने क्लाइमेट एक्शन के लिए 2020 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की घोषणा की. क्लाइमेट एक्शन के न्यूनीकरण, अनुकूलन और लचीलेपन हेतु बैंक ऋण देगी, निवेश करेगी और पूंजी जुटाएगी.

यह घोषणा सीओपी 21 जलवायु शिखर सम्मेलन के अवसर पर की गयी थी .

इसके अलावा समग्र प्रभाव को प्राप्त करने और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंक ने 2020 तक निम्नलिखित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई हैः

- 5000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा के वित्त पोषण का लक्ष्य
- अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में अक्षय ऊर्जा का प्रतिशत धीरे- धीरे बढ़ाना
- 20 लाख पौधे लगाकर कार्बन सिंक बनाने की दिशा में योगदान
- सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से 100 मिलियन लोगों तक पहुंचना
- बैंक के कामकाज से कार्बन उत्सर्जन का समायोजन

क्लाइमेट एक्शन की दिशा में यस बैंक की प्रतिबद्धता

2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य से यहां जलवायु वित्त पोषण की तेजी से बढ़ती जरुरतों का पता चलता है.

सबसे युवा भारतीय निजी क्षेत्र बैंक और पिछले 17 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ग्रीनफिल्ड बैंकिंग लाइसेंस से सम्मानित किया जाने वाला एकमात्र बैंक होने के नाते

जलवायु कार्रवाई के प्रति यस बैंक की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है.

सितंबर 2014 मे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में यस बैंक ने सालाना 500 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा के वित्त पोषण लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी और इसे वह पहले ही प्राप्त कर चुका है. यस बैंक ने बांग्लादेश और श्रीलंका समेत कई देशों में योग्य हरित परियोजानाओं के वित्त पोषण के लिए 1315 करोड़ रुपये मूल्य के ग्रीन बांड भी जारी किए हैं.

इन प्रतिबद्धताओं के माध्यम से बैंक ने पर्यावरण की समग्र स्थिरता को मजबूत बनाने का वादा किया है.

यस बैंक के बारे में

- यस बैंक भारत का निजी क्षेत्र का पांचवां सबसे बड़ा बैंक है. भारत के सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शाखाएं हैं.
- इसका मुख्यालय लोअर परेल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (एलपीआईडी) मुंबई में है.
- बैंकिंग के लिए इस बैंक में ज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है और अपने खुदरा, कॉरपोरेट और उभरते हुए कॉरपोरेट बैंकिंग ग्राहकों को यह बेहतरीन ग्राहक अनुभव की पेशकश करता है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में प्रस्तावित सम - विषम नंबर प्लेट योजना

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक-

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 4 दिसम्बर 2015 को सम - विषम नंबर प्लेट योजना शुरू की है. इस फैसले को 1 जनवरी 2015 से लागू करने की योजना है. यह फैसला मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गयी उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.

क्या है सम - विषम नंबर प्लेट योजना?

- इस योजना के तहत राजधानी दिल्ली में एक दिन सम तो दूसरे दिन विषम नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़कों पर चल पाएंगी. यानि एक ही फैसले में राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या आधी रह जाएगी.
- योजना के तहत सम तिथि के दिन सम संख्या की कार और विषम तिथि के दिन विषम संख्या की कार चल सकेगी.
- इस योजना का मूल उद्देश्य शहर में वाहन प्रदूषण को कम करके वायुमंडल को स्वस्थ रखना है.
- यह नियम दिन में सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक ही लागू रहेगा.
- रविवार नियम का अपवाद रहेगा.
- आपातकाल वाहन जैसे अम्बुलेंस आदि पर यह नियम लागू नहीं होगा.
- प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप से लागू करने की अंतिम घोषणा दिसम्बर 2015 के अंतिम सप्ताह में की जाएगी.

प्रस्ताव सम्बन्धी दिल्ली सरकार के अन्य फैसले-

- दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में चल रही बसों की आवृत्ति में वृद्धि करेगा. इसके अलावा वे स्कूल बस जो दिन में कुछ अवधि के लिए स्कूली बच्चों के लिए काम करती हैं, इन बसों को सार्वजनिक परिवहन प्रयोजनों के लिए किराए पर लिया जाएगा.
- दिल्ली में यूरो छः उत्सर्जन मानकों को लागू करने के लिए कट ऑफ तारीख 1 जनवरी 2019 के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर 1 जनवरी 2017 तक की जाएगी.
- देर शाम तक दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया जाएगा.

- लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) 1 अप्रैल 2016 से दिल्ली की सड़कों से धूल को वैक्यूम क्लीनर से सफाई शुरू कर देगा.
- दिल्ली सरकार स्वच्छ भारत अभियान ऐप के माध्यम से वाहन प्रदूषण, बायो-मास, कचरा, पत्ते, आदि के जलाने से रोकने के लिए आम जनता को जागरूक किया जाएगा. साथ ही एप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों का समाधान किया जाएगा.
- यह व्यवस्था सीएनजी से चलने वाली बसों, टैक्सियों और ऑटो रिक्शा पर लागू नहीं होगी.
- लोक निर्माण विभाग द्वारा खुले क्षेत्रों में व्यापक बागवानी व हरियाली कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
- दिल्ली में बाहर से प्रवेश वाले व प्रदूषण के मानदंडों का पालन न करने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को दंडित किया जाएगा.
- प्रदूषण के स्तर की जांच करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) शहर भर में 200 स्थानों पर प्रदूषण जांच के लिए सुविधा केन्द्रों की स्थापना करेगी.
- प्रदूषण के खरतनाक हो रहे स्तर के बारे में नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए स्वयं सेवको के माध्यम से पहल की जाएगी. इस जागरूकता अभियान को पूर्ण रूप से अंजाम देने के लिए स्वयं सेवको की सरकार द्वारा भर्ती की जाएगी.

दिल्ली में संचालित थर्मल पावर प्लांट बंद होंगे-

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सभी थर्मल पावर प्लांट महीने के बीच में ही बंद करने का फैसला किया है. राजधानी में कोयले से चलने वाले बिजली प्लांटों, धुंआ देने वाले मशीनों का इस्तेमाल घटाने की योजना पर सरकार काम करेगी.

दिल्ली सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया?

धूल सुनिश्चित किए बगैर निर्माण नहीं- सर्वोच्च न्यायालय

- अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कहा था कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के दो प्रमुख कारण धूल कण और वाहनों से निकलने वाला धुआं है. अदालत ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कम से कम धूल की रोकथाम किए बगैर किसी इमारत या सड़क का निर्माण नहीं किया जाए. जो 3 दिसंबर 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अवलोकन से प्रेरित था.
- कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के मुताबिक लोगों द्वारा खुले में कूड़ा और पत्तियां नहीं जलाई जाएं. इस बारे में बेंच ने शहर प्रशासन को प्रिंट, ऑडियो और विजुअल मीडिया के जरिए इस तरह के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध के बारे में जानकारी

देने का निर्देश दिया.

- 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा जारी एक अध्ययन में दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहर के रूप में दिल्ली की घोषणा की थी और प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक उपायों की जरूरत के लिए एडवाइजरी जारी की थी.
- लाइसेंस संख्या के आधार पर रोड रेशनिंग (इस तरह की योजना) एथेंस (1982), सैंटियागो, चिली (1986 और विस्तारित 2001), मेक्सिको सिटी (1989), मेट्रो मनीला (1995), साओ पाउलो (1997), बोगोटा, कोलम्बिया (1998) ला पाज़, बोलीविया (2003), सैन जोस और कोस्टा रिका (2005) जैसे शहरों में लागू की गयी है.
- 2008 और 2010 के बाद से क्रमश: होंडुरास और क्विटो और इक्वाडोर में देशव्यापी प्रतिबंध है.
- बीजिंग ने भी धुंध शमन उपायों के लिए ओलंपिक खेलों के दौरान 2008 में और दिसंबर 2015 में अस्थायी प्रतिबंध लगाया था. इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए थे.

सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मापी उपकरण-

दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता जताने के बाद कोर्ट परिसर में वायु प्रदूषण मापने का उपकरण लगाया गया. गुरुवार को हाई कोर्ट ने राजधानी दिल्ली की तुलना गैस चैंबर से की थी. अक्टूबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने भी प्रदूषण पर चिंता जाहिर की थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की कार्य योजनाओं को भी नाकाफी बताया और कहा कि इसमें प्राधिकरणों की जिम्मेदारी तय नहीं है. काम करने के लिए उन्हें कोई समय सीमा भी नहीं दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में अब 21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.

स्कूल बंद करने का प्रस्ताव-

इससे पहले राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने का प्रस्ताव भी दिया था. दिल्ली के प्रदूषण की तुलना बीजिंग से की जा रही है. दिल्ली में सहे जा सकने प्रदूषण से 10 से 16 गुणा ज्यादा प्रदूषण है. मंगलवार को यूएस एम्बेसी मॉनिटरिंग सिस्टम से एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया पांच इलाकों में से दो इलाके ऐसे हैं जिनके प्रदूषण का लेवल लोगों के लिए जोखिम भरा हुआ है.

चीन ने अपनाई थी पहले यह व्यवस्था-

चीन की राजधानी बीजिंग में भी 2013 में इस तरह की व्यवस्था लागू की गई थी. यह फैसला दिल्ली में पंजीकृत करीब 90 लाख वाहनों पर लागू होगा. शहर में हर रोज करीब डेढ़ हजार नए वाहन पंजीकृत होते हैं.

क्या है पैमाना!

वायु प्रदूषण से जुड़ी कोई भी रीडिंग अगर 150 के पार जाती है तो वह लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती. अगर यह 351 और 500 के बीच रहे तो इसे मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा कहा जाता है.

दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण-

दिल्ली के आनंद विहार में यह लेवल 919 पहुंच चुका है. पंजाबी बाग, मंदिर मार्ग और आरके पुरम में 261, 269 और 308 है.

क्या है प्रदूषण का कारण?

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती भागती लाखों गाड़ियों से निकलता धुआं. राजधानी में मौजूद फैक्ट्रियों से निकलता काला जहर. बिजलीघरों की चिमनी से निकलता धुआं और मौसम में बढ़ने जा रही धुंध मिलकर प्रदूषण का एक ऐसा कॉकटेल तैयार कर रही हैं जिसमे दिल्ली का दम घुट रहा है. एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में करीब 87 लाख वाहन प्रतिदिन बाहर से प्रवेश कृते हैं.

भारत ने 8 विभिन्न बायोम्स को मॉनिटर करने हेतु आईएलटीईओ कार्यक्रम आरंभ किया

भारत ने 7 दिसम्बर 2015 को दीर्घावधि पारिस्थितिक वेधशाला (आईएलटीईओ) कार्यक्रम आरम्भ किया ताकि आठ बायोम्स (प्राकृतिक परिदृश्य) को मॉनिटर किया जा सके. यह कार्यक्रम कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़-21 (सीओपी) के दौरान पेरिस में आरंभ किया गया.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक-पारिस्थितिक चुनौतियों पर नज़र रखना है तथा भारत में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इस कार्यक्रम के तहत होने वाले अध्ययन में पर्यावरण अनुकूलन के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में बताया जायेगा.

एलटीईओ कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम के तहत छात्र एवं युवा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा.
- इस पहल द्वारा देश को अपना स्वयं का वैज्ञानिक डाटा-बेस प्राप्त होगा जिसके लिए किसी विदेशी संस्थान पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा.
- इस पहल में देश के सभी प्राकृतिक परिदृश्य शामिल होंगे जिसमें पश्चिमी हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य भारत से सुंदरबन एवं जम्मू कश्मीर से लेकर

राजस्थान एवं गुजरात भी शामिल हैं.

- इसके अतिरिक्त जल स्रोतों, हरित प्रदेश, स्तनधारी, पक्षी, मछलियां और कीड़े भी शामिल होंगे.
- अध्ययन में इस बात पर फोकस रखा जायेगा कि जलवायु परिवर्तन से इन प्राकृतिक संपदाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है.
- यह वैज्ञानिकों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ प्रदान करेगा तथा विभिन्न पारिस्थितिक संरचनाओं का वास्तविक ब्यौरा तैयार करेगा.

इस विषय पर विभिन्न विकसित एवं विकासशील देश कार्य कर रहे हैं. इससे पहले भारत में भी इस विषय पर मदुमलाई स्थित 50 हेक्टेयर के एक भूखंड पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस, बंगलौर द्वारा पिछले 30 वर्षों से अध्ययन जारी था.

बीजिंग में पहली बार वायु प्रदूषण पर रेड अलर्ट जारी

चीन की राजधानी बीजिंग ने खतरनाक स्तर तक पहुंचे वायु प्रदूषण को लेकर 7 दिसंबर 2015 को वर्ष का पहला 'रेड अलर्ट' जारी किया. चेतावनी जारी होने के साथ ही अधिकारियों ने स्कूलों को बंद करने और विशेष प्रकार के वाहनों और फक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिए. प्रदूषण की एमआई 256 से ज्यादा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है. इससे हृदय और फेफड़े संबंधी बीमारियां हो सकती हैं और सामान्य लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं.

बीजिंग के आसमान में दिसंबर 2015 में दूसरी बार धुंध की मोटी चादर फैलने के बाद यह आदेश जारी किए गए.

स्थानीय समय के अनुसार आदेश 8 दिसंबर 2015 की सुबह 7:00 से 10 दिसंबर 2015 को दोपहर तक मौसम बदलने और धुंध हटने तक जारी रहेंगे.

2013 में आपातकालीन वायु प्रदूषण रिस्पांस सिस्टम (चार स्तरीय प्रणाली) के बाद रेड अलर्ट की पहली बार घोषणा की गयी.

घोषणा का प्रभाव-

- बीजिंग ने वायु प्रदूषण संबंधी अलर्ट को 'नारंगी' रंग से बदल कर सर्वाधिक स्तर वाले लाल रंग का कर दिया है.

- 'रेड अलर्ट के दौरान किंडर गार्डन, प्राइमरी और हाई स्कूलों को कक्षाएं निलंबित करने का निर्देश दिया गया है.
- विशेष वाहनों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है
- विनिर्माण स्थलों पर बाहरी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
- कुछ औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन नियंत्रित करने या बंद करने को कहा गया है.
- इस दौरान कारों का उपयोग भी कम किया जाएगा. कारों को एक दिन के अंतर पर, उनके सम-विषम नंबर प्लेटों के आधार पर सड़क पर आने की अनुमति होगी. सम-विषम के आधार पर 30 फीसदी सरकारी कारों के सड़कों पर आने पर प्रतिबंध होगा.
- बीजिंग की जनसंख्या फिलहाल 2.2 करोड़ से ज्यादा है और यह शहर धुंध की मोटी चादर की तह में छुपा हुआ है. आने वाले महीनों में स्थिति और खराब होने की आशंका है.

100 मिलियन हेक्टेयर वन की पुनर्स्थापना के लिए अफ्रीकन रेस्टॉरेशन इनिशिएटिव का शुभारम्भ

6 दिसंबर 2015 को अफ्रीकी देशों और दाताओं के गठबंधन ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में हुए 195 देशों के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एक सम्मेलन के मौके पर अफ्रीकन रेस्टॉरेशन इनिशिएटिव (एएफआर 100) का शुभारम्भ किया.

इस महत्वाकांक्षी पहल की योजना साल 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर (250 मिलियन एकड़) पर पुनः जंगल लगाने की है. एएफआर 100 इनिशिएटिव का उद्देश्य वनों के पुनर्विकास को पोषित करना है ताकि वह शक्तिशाली कार्बन सिंक बन सके, जलवायु परिवर्तन की वजह से बन रहे कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर सके और गांव के गरीबों को आजीविका प्रदान कर सके.

दस अफ्रीकी देश, नौ वित्तीय भागीदार और दस तकनीकी समर्थन भागीदारों ने समर्थन देने का वादा किया है. एएफआर 100 इनिशिएटिव से जुड़ने वाले दस अफ्रीकी देश हैं- कांगो, इथियोपिया, केन्या, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, टोगो और युगांडा.

समर्थकों में अफ्रीकी संघ, जर्मन आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय और अमेरिका का गैर- लाभकारी समूह वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) शामिल है.

एएफआर 100 इनिशिएटिव ने 2011 के बून घोषणा में 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि के पुनरुद्धार का भी समर्थन किया है. साथ ही इसने 2014 के वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा का भी समर्थन किया है जो इसके उद्देश्य को 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ा देगा.

उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुआ राज्य का पहला 'बर्ड फेस्टिवल'

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 4 से 6 दिसम्बर 2015 के मध्य चम्बल सफारी लॉज (जरार, बाह), आगरा में देश के सबसे बड़े ''बर्ड फेस्टिबल'' का आयोजन किया गया.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बर्ड फेस्टिबल में 5 दिसम्बर को शामिल हुए.

फेस्टिवल में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पक्षी विशेषज्ञों ने भाग लिया और प्रदेश में पाये जाने वाले पक्षियों पर मन्थन किया. सम्मेलन के दौरान देश विदेश के पक्षी विशेषज्ञ सहित दुनिया के प्रख्यात पक्षी विशेषज्ञ डा0 पामेला रेसमुसेन, डा0 परअल्स्ट्राम, डा0 मार्टिन केल्से, क्रेग जोन्स, डा0 धनन्जय मोहन, डा0 असद रहमानी, बिक्रम ग्रेवाल, निखिल देवसार आदि ने भाग लिया.

फेस्टिवल के दौरान 25 से 40 विदेशी डेलीगेट्स तथा 50 से 200 भारतीय पक्षी प्रेंमी चम्बल सफारी पहुंचें और इच्छुक पर्यटकों को भी इस बर्ड फेस्टिवल का भ्रमण कराने की व्यवस्था की गई.

विदित हो पृथ्वी पर कुछ ही जगह ऐसी हैं जहां बहुत सारी विचित्र एवं आकर्षक पक्षियों की प्रजातियॉ पाई जाती हैं इनमें उत्तर प्रदेश सबसे खास है. इस क्रम में चम्बल सफारी लॉज एक विशिष्ट स्थान है.

इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 14 देशों के 25 विदेशी एवं 50 भारतीय पक्षियों का अवलोकन, (बर्ड वाचिंग) करने हेतु राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार का भ्रमण किया गया. बर्ड फेस्टिवल में प्रदेश सरकार तथा बर्ड लाइफ़ इंटरनेशल के पक्षी वौज्ञानिक टीम अपिल्न एवं जिम लॉरेन्स के बीच प्रदेश में पक्षी संरक्षण हेतु सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु विश्व के उद्योगपतियों ने समझौता किया

सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए 28 नवम्बर 2015 को बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और जैक मा सहित दुनिया के अन्य विशिष्ट उद्योगपतियों ने एक समझौता किया. इसे ब्रेकथ्रू एनर्जी कोऐलिशन नाम दिया गया है

ब्रेकथ्रू एनर्जी कोऐलिशन में 28 अंतरराष्ट्रीय निवेशक शामिल हैं. इस ग्रुप का मकसद अनुसंधान कक्ष से बाज़ार तक सस्ती, विश्वसनीय और कार्बन फ्री एनर्जी मुहैया करने की क्षमता प्रदान करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करना है.

ब्रेकथ्रू एनर्जी कोऐलिशन में ऐसे 100 से अधिक देश शामिल होंगे जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुरता से उपलब्ध होता है. इनका मकसद स्वच्छ, सस्ती और नवीकरणीय सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना है.

इससे विश्व भर की सरकारों को विशिष्ट अविष्कारों की सहायता से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी. यूके वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रैंसन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और हेवलेट पैकार्ड के मेग वाइटमैन भी इस कोऐलिशन के हिस्सा होंगे.

स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को गति देने के लिए मिशन इनोवेशन का शुभारंभ

विश्व में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को गति देने के लिए 30 नवंबर 2015 को "मिशन इनोवेशन" का शुभारंभ किया गया. मिशन का शुभारंभ पेरिस ले बर्जत, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 सीओपी 21 (COP21) के मंच से भारत सहित 20 प्रतिभागी देशों द्वारा शुरू किया गया.

इस घोषणा के साथ ही सम्मेलन 2015 सीओपी 21 में भाग लेने वाले देश 2020 तक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास के वित्तपोषण को दोगुना करेंगे.

मिशन इनोवेशन का शुभारंभ बिल गेट्स के नेतृत्व में शुरू किए गए ब्रेकथ्रू एनेर्जी कोएलिशन से अलग किया गया है. यह जीवाश्म ईंधन के लिए मांग को कम करने के लिए किया गया.

मिशन इनोवेशन की मुख्य विशेषताएं-

- मिशन इनोवेशन का उद्देश्य साथ वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा को गति देना,पुनर्जीवित करना और स्वच्छ ऊर्जा के लिए व्यापक रूप से किफायती बनाने का उद्देश्य के है.
- मिशन इनोवेशन का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों में वृद्धि करना है.
- काम करने का ढंग: मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम करते हुए, सम्मेलन में भाग लेने वाले देश अन्य देशों के साथ व उनकी सरकारों के साथ सहयोग और निजी निवेशकों और प्रौद्योगिकी के नवीन आविष्कारों में मदद करने के लिए सहयोग करेंगे.

- सहयोग से आशय स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और प्रसार को बढ़ावा देने के क्रम में विशेषज्ञ प्रौद्योगिकी और विश्लेषण क्षेत्र में डेटा का आदान प्रदान करेंगे.
- यह जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक वैश्विक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया.
- सम्मेलन में भाग लेने वाले देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, नॉर्वे, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि

विज्ञान तकनीक

ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सांप की प्रजातियां एपिसुरुस फोलियोस्क्वामा और एपीसुरुस एप्रीएफ्रॉन्टालिस की पुनः खोज

ऑस्ट्रेलिया के स्थानिक समुद्री सांप की दो प्रजातियां- एपिसुरुस फोलियोस्क्वामा और एपीसुरुस एप्रीएफ्रॉन्टालिस को वैज्ञानिकों की एक टीम ने फिर से खोज निकाला है. ये वैज्ञानिक जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के हैं.

साल 2010 में सांप की इन दोनों प्रजातियों को तिमोर सागर के ऐशमोर और हिबर्निया रीफ्स के सीमित भौगोलिक सीमाओं में पाए जाने की वजह से विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूचि में डाल दिया गया था. इन इलाकों से ये 1998 और 2002 के बीच गायब हो गए थे.

यह खोज, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन नाम की पत्रिका में 21 दिसंबर 2015 को न्यू रेंज एंड हैबिटेट रिकॉर्ड्स फॉर थ्रेटेंड ऑस्ट्रेलियन सी स्नेक्स रेज चैलेंजेज फॉर कंजर्वेशन शीर्षक वाले शोधपत्र में प्रकाशित हुआ था. अध्ययन के प्रमुख लेखक हैं ब्लांच डी अनास्तासी.

एपीसुरुस एप्रीएफ्रॉन्टालिस सांप

- एपीसुरुस एप्रीएफ्रॉन्टालिस सांप, छोटी नाक वाला समुद्री सांप है, पहले लगा था कि यह विलुप्त हो चुका है लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई निन्गलू रीफ के पानी में पाया गया.
- मनुष्यों ने 15 वर्षों में जीवित छोटी- नाक वाले समुद्री सांप को नहीं देखा है.
- तिमोर सागर के ऐशमोर रीफ के एकमात्र ज्ञात निवास स्थान से गायब होने के बाद यह जीवित और स्वस्थ देखा गया था.
- इसके गायब होने के बाद से इस प्रजाति को विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में डाल दिया गया था.
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के अनुसार 1990 के दशक में दर्ज किए जाने वाले समुद्री सांपों की तीसरे सबसे आम प्रजाति थी, लेकिन 2000 के बाद गहन सर्वेक्षण में किसी ने भी इसे नहीं दर्ज किया. इससे पता चलता है कि बीते 15 वर्षों में इसकी संख्या में 90 फीसदी की कमी आई है.

विलुप्तप्राय छोटी नाक वाले सांप की तस्वीर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पार्कों और वन्यजीव अधिकारी ग्रांट ग्रिफिन ने ली थी. उन्होंने बाद में निंगलू रीफ में लिए गए सांपों के जोड़ों की यह तस्वीर डी अनास्तासी को पहचान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के एआरसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोरल रीफ स्टडीज, को भेजी.

एपिसुरुस फोलियोस्क्वामा सांप

- एपिसुरुस फोलियोस्क्वामा सांप शार्क की खाड़ी के रसीले समुद्री घास में पत्ति- के समान पपड़ीवाले समुद्री सांप के तौर पर जाना जाता है.
- अनुसंधानकर्ताओं ने इसे इसके एकमात्र निवास स्थान ऐशमोर रीफ से 1000 मील से भी दूर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया.
- 1990 के दशक में इन सांपों की संख्या दर्ज समुद्री सांपों की संख्या की आधी थी लेकिन 2001 के बाद किसी ने भी इन्हें नहीं देखा था.

पत्ती जैसी पपड़ी वाली और छोटी नाक वाले, दोनों ही प्रकार के सांप, ऑस्ट्रेलिया के संकटग्रस्त प्रजातियों का कानून के तहत विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में सूचीबद्ध थे जिसका अर्थ है कि उन्हें विशेष सुरक्षा मिलती है.

पेंडोरम टेक्नोलॉजी ने 3 डी प्रिंटिंग का उपयोग करते हुए भारत का पहला कृत्रिम वृक्क ऊतक विकसित किया

पेंडोरम टेक्नोलॉजी प्रॉइवेट लिमेटिड ने दिसंबर 2015 के तीसरे सप्ताह में भारत का पहला कृत्रिम वृक्क ऊतक विकसित किया.

यह 3 डी मानव अंगों के विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा कदम है. कृत्रिम वृक्क ऊतक मानव वृक्क के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है जिसमें मेटाबाल्जिम, जैव रसायनों के स्राव जैसे कोलेस्ट्रॉल और एल्बुमिन और डिटोक्सिफिकेशन शामिल है.

कृत्रिम वृक्क ऊतक की विशेषताएं

- इन टिश्यू का जीवनचक्र 8 सप्ताह का होता है.
- इस तकनीक से लिवर फेल होने की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की जान बचाई जा सकेगी.

- इस तकनीक के दुष्प्रभाव कम है और इसे कम लागत पर बनाया जा सकता है.

यह कैसे बनाया गया?

5 मिलिमीटर लंबे एक टिश्यू को बनाने के लिए एक करोड़ लिवर सेल्स की जरूरत पड़ती है. इसकी आवश्यकता को बायोमटेरियल ग्लूनकोस, प्रोटीन, जीवित सेल और 3डी आर्किटेक्चीर से पूरा किया जाता है. लेजर से नियंत्रित होने वाले प्रिंटर में विशेष इंसेक्ट को बतौर स्याही उपयोग किया जाता है.

विश्व में 3डी तकनीक के उपयोग से कृत्रिम वृक्क का विकास

इसस पहले 3डी बॉयोप्रिटिंग कंपनी ऑर्गेनोवो (Organovo) ने वर्ष 2013 में पूर्ण रुप से सेलुलर 3डी मानव कृत्रिम वृक्क ऊतक विकसित किया था.

पैंडोरम टेक्नोमलॉजी के बारे में

हैदराबाद स्थित पैंडोरम टेक्नोलॉजी एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है. कंपनी के सह-संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टीर अरुण चंद्रू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएस) के तुहिन भौमिक के साथ मिलकर यह शोध किया. दोनों ने वर्ष 2011 में मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी. पैंडोरम टेक्नोलॉजी का उद्देश्य ह्यूमन अंगो (ऑर्गन) की मांग को पूरा करना है.

पैंडोरम ने बायो-बैंक में करोड़ों लिवर सेल्स को एकत्रित किया है, जिन्हें प्रयोगशाला में मल्टीप्लान किया जाता है. इस तकनीक से लिवर फेल होने की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की जान बचाई जा सकेगी.

चीन ने डीएएमपीई उपग्रह का प्रक्षेपण किया

चीन ने रहस्यमय काले पदार्थ पर प्रकाश डालने वाले डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर (डीएएमपीई) उपग्रह का 17 दिसंबर, 2015 को प्रक्षेपण किया.

यह देश का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप था और इसका प्रक्षेपण जीक्वान (Jiuquan) उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से एक लांग मार्च 2-डी रॉकेट द्वारा किया गया.

उपग्रह का उद्देश्य अदृश्य कण डार्क मैटर के स्मोकिंग गन के संकेत प्राप्त करना है. वैज्ञानिकों को कहना है कि ब्रह्मांड का अधिकांश द्रव्यमान इन्हीं कणों से बना हैं.

यह उपग्रह 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की समकालिक कक्षा में स्थापित होगा, जो अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा कणों की दिशा, ऊर्जा और इलैक्ट्रिक चार्ज का निरीक्षण करेगा.

इस उपग्रह को वुकोंग (Wukong) उपनाम दिया गया.

स्पेस एक्स ने फेल्कन 9 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण और अवतरण किया

अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा प्रदाता स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ कारपोरेशन(स्पेस एक्स) ने 21 दिसम्बर 2015 को फेल्कन 9 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर इतिहास रच दिया.

फेल्कन 9 नामक इस रॉकेट का प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केप कार्निवल से किया गया. इस प्रक्षेपण में रॉकेट ने 11 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया. इन 11 उपग्रहों का सम्बन्ध मशीन टू मशीन वैश्विक संचार के ओआरबीकॉम(ORBCOMM) मिशन से था.

इस प्रक्षेपण के बाद पृथ्वी की निम्न कक्षा में ओआरबीकॉम मिशन के अंतर्गत भेजे के उपग्रहों की संख्या 17 हो गई.

विदित हो यह पहली बार है जब कोई रॉकेट उपग्रहों को स्थापित करने के बाद पुनः धरती पर वापस लौटने में सफल रहा है.

इस तकनीक के माध्यम से भविष्य में इस तरह के मिशन में आने वालों को खर्च में कमी लाना संभव होगा, क्योंकि इसके मध्यम से एक बार प्रयोग हो चुके रॉकेट को पुनः प्रयोग में लाया जा सकेगा.

इससे पूर्व कम्पनी ने ऐसा ही एक प्रयास वर्ष 2015 के जून माह में किया था जो विफल रहा जिससे नासा के 2 टन माल का नुक्सान हुआ था.

क्यों है यह मिशन महत्वपूर्ण

किसी अन्तरिक्ष मिशन में लगभग आधा ज्यादा खर्च मिशन के लिए बनाए गए रॉकेट में आता है. यह रॉकेट सिर्फ एक मिशन के लिए ही प्रयोग में आते थे और उसके बाद व्यर्थ हो जाते हैं.

परन्तु इस मिशन ने एक आम हवाईजहाज की तर्ज पर इस तकनीक को विकसित किया है जिसके तहत रॉकेट उपग्रह को स्थापित करने के बाद पुनः लॉन्च पैड परा आ कर स्थापित हो सकेगा और अन्य मिशन के प्रयोग में लाया जा सकेगा.

भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर को अमेरिकी सेना से सौर पैनल पर अनुसंधान और विकास हेतु अनुबंध प्राप्त

9 दिसंबर 2015 को प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर को अमेरिका सेना से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले माइक्रो- ग्रिड पर अनुसंधान करने और उसके विकास का अनुबंध मिल गया.

यह मामला किसी भारतीय वैज्ञानिक संस्थान को अमेरिकी सेना द्वारा संघीय अनुबंध से सम्मानित किए जाने के दुर्लभ मामलों में से एक है.

अनुबंध की मुख्य विशेषताएं

- 52900 अमेरिकी डॉलर मूल्य का ये अनुबंध जापान स्थित अमेरिकी प्रशांत वायुसेना, यकोटा एयर बेस द्वारा दिया गया है.
- अनुबंध सौर उर्जा से चलने वाली बैट्री और सुपरकैपिसिटर ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था वाली माइक्रो- ग्रिड के विकास के लिए दिया गया है.

भारतीय विज्ञान संस्थान के बारे में

- भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा का सरकारी विश्वविद्यालय है.
- इस संस्थान की स्थापना 1909 में जमशेदजी टाटा ने की थी.
- साल 1958 में इसने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया .
- साल 2015-16 में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया जाने वाला यह पहला भारतीय संस्थान था. रैंकिंग में इसका स्थान 99वां था.

एंटी-कैंसर अणुओं की खोज

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी),भोपाल मध्यप्रदेश ने 7 दिसम्बर 2015 को एंटी-कैंसर मॉलीक्यूल की खोज की घोषणा की.

संस्थान की ओर इस खोज की पुष्टि विश्विद्यालय के कुलपति प्रो. पीयूष त्रिवेदी और विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर डॉ. सी. कार्तिकेयन ने की.

डॉ. सी. कार्तिकेयन ने कनाडा के तीन अन्य रिसर्च स्कॉलर्स के साथ मिलकर 10 वर्षों में इस खोज को पूरा किया.

खोजे गए इस नए मॉलीक्यूल का संक्षिप्त नाम सीटीआर-17 और सीटीआर-20 है.

उक्त अणु ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन को बढ़ने से रोकता है. विदित हो यह प्रोटीन कोशिका विभाजन की क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. इसको नियंत्रित करके कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है.

- यह अणु केवल कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है.
- यह अणु शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है.
- इस खोज में 22 अतिरिक्त मॉलीक्यूल खोजे गए है जो आगे चलकर कैंसर के उपचार में मददगार साबित होंगे.
- इस अणु का पूर्व नैदानिक परीक्षण कनाडा में आयोजित किया गया.
- यह परीक्षण कनाडा में जानवरों (चूहों) पर किया गया.
- उक्त मॉलीक्यूल ने कैंसर के उपचार के प्रयोग की जाने वाली दवा 'पैक्लीटेक्सल' भी और अच्छे परिणाम दिए हैं.

विदित हो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैंसर से लगभग 500000 लोगों की मृत्यु होती है.

एटलस वी रॉकेट सिग्नस कार्गो अंतरिक्ष यान आईएसएस के लिए लांच

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी "नासा" के कार्यक्रम के तहत 6 दिसंबर 2015 को रविवार को ऑर्बिटल एटीके सिग्नस कार्गो (मालवाहक) अंतरिक्ष यान (401 विन्यास) आवश्यक आपूर्ति OA-4 के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए लांच किया गया किया गया.

इस मिशन से अंतरिक्ष प्रोयगशाला और उसमें रह रहे छह अंतरिक्ष यात्रियों को प्रयोगों, उपकरणों सहित अधिकाधिक विज्ञान संबंधित सुविधाएं और कई शोध जांचों व अन्य चीजें उपलब्ध कराई जाएगी.

रॉकेट युनाइटेड लांच एलायंस एटलस वी रविवार को फ्लोरिडा के केप कार्निवल एयरफोर्स स्टेशन परिसर 41 से कार्गो अभियान को लांच किया गया.

वर्तमान सिग्नस मिशन अप्रैल के बाद अमेरिका का पहला कार्गो (मालवाहक) अंतरिक्ष यान भेजा गया है. इससे पहले स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था, पिछले साल जुलाई 2014 में सिग्नस स्टेशन पर पहुंच गया.

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आपूर्ति के लिए किए गए प्रक्षेपण बोच्ड रोकेट के कारण असफल रहे, कैप्सूल में 3500 किलोग्राम से अधिक भोजन, कपड़े सामग्री, कंप्यूटर गियर, चहलकदमी उपकरण, विज्ञान के प्रयोगों के सामान और अन्य सामग्री भेजी गयी है. स्टेशन पर मौजूद वर्तमान वैज्ञानिक दल "एक्सपीडीशन 45 और 46" अपने अभियान के दौरान 250 से अधिक प्रयोग करेंगे.

ईंधन के रूप में इथेनॉल से बेहतर बुटेनॉल: शोध

विश्व के कई देशों में इथेनॉल का प्रयोग वाहनों में ईंधन के तौर पर किया जाता है, लेकिन अब न्यूयॉर्क की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नई विधि खोज निकाली है, जिसकी मदद से इथेनॉल को एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन बुटेनॉल में परिवर्तित किया जा सकेगा.

इथेनॉल और बुटेनॉल दोनों का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में होता रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इथेनॉल की अपेक्षा बुटेनॉल ज्यादा बेहतर है. इथेनॉल का उत्पादन मक्के से किया जाता है. इसका इस्तेमाल इंजन में अतिरिक्त ईंधन के तौर पर होता है. लेकिन यह ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और कम उर्जा उत्पादन करता है. इसकी वजह से इंजन को क्षति होने की भी संभावना बनी रहती है.

न्यूयॉर्क की रोचेस्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और इस अध्ययन के मुख्य शोधार्थी विलियम जोन्स के अनुसार, बुटेनॉल इथेनॉल से ज्यादा बेहतर है. यह पेट्रोल के विकल्प के रूप में इथेनॉल की तुलना में काफी अच्छा है. यह अधिक ऊर्जा पैदा करता है और इससे इंजन को नुकसान पहुंचने का खतरा भी नहीं होता. शोधकर्ताओं ने इथेनोल को बुटेनॉल में परिवर्तित करने के लिए कई प्रतिक्रियाओं की श्रंखलाओं को बनाया है.

इस नई विधि में सबसे पहले इरीडियम उसके बाद कैटलिस्ट, निकिल और कॉपर हाइड्रॉक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को अंत में रखा गया है. यह अध्ययन पत्रिका अमरीकन केमिकल सोसायटी में प्रकाशित हुआ.

क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए संसद में जैव प्रौद्योगिकी विधेयक 2015 पारित

क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए 2 दिसम्बर 2015 को संसद में जैव प्रौद्योगिकी विधेयक 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी.

बिल का उद्देश्य नवंबर 2008 में एक कार्यकारी आदेश के तहत स्थापित किए गए कि केन्द्रों को कानूनी दर्जा

प्रदान करना है. इस तरह का केंद्र वर्तमान में एनसीआर बायोटेक विज्ञान क्लस्टर, फरीदाबाद में कार्यरत है.

क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए जैव प्रौद्योगिकी विधेयक 2015 मुख्य विशेषताएं-

केंद्र स्वायत्त निकाय के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम होगा.

- जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप इन केन्द्रों को मान्यता मिल जाएगी.
- ऐसे केंद्र उद्योग के लिए प्रासंगिक आदर्श शिक्षा कार्यक्रमों पर जोर देने हेतु जैव प्रौद्योगिकी में अंतःविषय शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक क्षेत्रीय हब का काम करेंगे.
- ये केंद्र जैविक दवाओं की खोज विज्ञान, नैनो विज्ञान और चिकित्सा, इमेजिंग तकनीक, डिजाइनर फसलों, जैव प्रौद्योगिकी और बायोमेटेरियल और बौद्धिक संपदा के साथ अन्य क्षेत्रों में मुख्य रूप से ध्यान देंगे.
- भारत में इन केन्द्रों से इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की कमी कोल कम किया जा सकेगा.
- यह एशिया और सार्क क्षेत्र के देशों के बीच जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के केंद्र बन सकते हैं.

खेल खिलाड़ी

ब्योर्न इज़बर्ग 2016 की हॉकी इंडिया लीग के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर नियुक्त

स्वीडन के ब्योर्न इज़बर्ग 30 दिसंबर 2015 को कोल इंडिया हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के टूर्नामेंट डायरेक्टर नियुक्त किये गये.

इसके अतिरिक्त मलेशिया के मुथुकुमार बालाकृष्णन को चौथे कोल इंडिया हॉकी इंडिया लीग में असिस्टेंट टूर्नामेंट डायरेक्टर का कार्यभार दिया गया है.

स्कॉटलैंड के एंडी मीर को लीग का अंपायर मैनेजर नियुक्त किया गया है.

ब्योर्न इज़बर्ग

- 50 वर्षीय इज़बर्ग को टूर्नामेंट डायरेक्टर का वृहद अनुभव प्राप्त है जिसमें वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स, तीन एफआईएच ट्रॉफी टूर्नामेंट्स (लाहौर-2004, कुआलालंपुर-2007, ऑकलैंड-2011, पोलैंड-2011) शामिल हैं.
- उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में असिस्टेंट टूर्नामेंट डायरेक्टर के पद पर कार्य किया एवं एफआईच जर्मनी-2006 तथा भारत-2010 में भी इसी पद पर कार्यरत रहे.

कोल इंडिया एचआईएल 10 जनवरी 2016 से 21 फरवरी 2016 के मध्य छह स्थानों पर आयोजित किया जायेगा.

इसमें मौजूद छह फ्रेंचाइजी हैं:

- जेपी पंजाब वॉरियर्स
- डेल्ही वेवराइडर्स
- कलिंग लांसर्स

- उत्तर प्रदेश विज़ार्ड्स
- दबंग मुंबई
- रांची रेज़

वर्ष 2016 की कोल इंडिया हॉकी इंडिया लीग की विस्तृत सूची निम्नलिखित है:

नाम	**पद**
ब्योर्न इज़बर्ग	टूर्नामेंट डायरेक्टर
क्रेग ग्रिब्ल	मुख्य अंपायर मैनेजर
एंडी मीर	अंपायर मैनेजर
मुथुकुमार बालाकृष्णन	असिस्टेंट टूर्नामेंट डायरेक्टर
गविन हॉक	
क्लौडियस डी सेल्स	तकनीकी अधिकारी
दविंदर भाटिया	
आशुतोष वर्मा	
मिलिंद नार्वेकर	निर्णयकर्ता
अंजलि शर्मा	
सोनिया बटला	
जर्मन मोंटेस डी ओका	अन्तरराष्ट्रीय अंपायर
मार्सिन ग्रोचल	
मार्टिन मैडेन	

डेविड टोम्लिंसन

जाकुब मेज्जिलक

बेन गोंतेन

आर वी रघुप्रसाद भारतीय अंपायर

जी एस संघा

रिपुदमन शर्मा

दीपक जोशी

धवल प्रजापति

अनिल कुमार

हॉकी इंडिया लीग

- • हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) भारत में हॉकी की एक पेशेवर लीग है.
- इसका आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा होता है.
- इसके पहले सत्र में पांच फ्रैंचाइज़ी टीमों के बीच मैच हुआ था.
- इस आयोजन को अन्तरराष्ट्रीय हॉकी संघ की मान्यता प्राप्त है.

लक्ष्मी रतन शुक्ला का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल के ऑलराउंडर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 30 दिसंबर, 2015 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की.

शुक्ला को दो दिन पहले ही 2 जनवरी 2016 से प्रारंभ हो रहे सैयद मुश्ताक टी-20 टूर्नामेंट के लिए बंगाल की टीम में शामिल किया गया था.

करियरः

प्रारूप	मैच	रन	बेस्ट	औसत	विकेट	100	50
एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय	3	18	13	9.00	1	0	0
प्रथम श्रेणी	137	6217	250	35.93	172	9	37
लिस्ट ए	141	2997	151	30.27	143	4	13
टी20	81	994	76	20.70	47	0	3

लक्ष्मी रतन शुक्ला के बारे में

- शुक्ला ने 137 प्रथम श्रेणी मैचों की 194 पारियों में 35.93 की औसत से 6217 रन बनाए हैं. इसमें नौ शतक व 37 अर्धशतक शामिल हैं.
- उन्होंने भारत की ओर से तीन अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं, जिसमें 18 रन बनाए हैं.
- शुक्ला को 2011-12 सत्र में घरेलू सीमित ओवरों के प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ आलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार से सम्मनित किया गया था.
- वह 2013-14 सत्र में बंगाल की तरफ से 100 रणजी ट्राफी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे.
- वह आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रह चुके हैं.

ग्लोब फ़ुटबॉल पुरस्कार 2015

ग्लोब फ़ुटबॉल ने 27 दिसंबर 2015 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक समारोह में विजेताओं को ग्लोब फ़ुटबॉल पुरस्कार प्रदान किए गए. यह ग्लोब फ़ुटबॉल पुरस्कार का छठा संस्करण था.

ग्लोब सॉकर पुरस्कार पहला और एकमात्र पुरस्कार हैं जो सर्वश्रेष्ठ फ़ुटबॉल क्लब के निदेशक और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एजेंट को फुटबॉल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है.

यह पुरस्कार वर्ष 2015 में खिलाड़ियों और फुटबॉल क्लबों के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए गए.

- सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर: लियोनेल मेसी (बार्सिलोना)

- सर्वश्रेष्ठ क्लब : एफसी बार्सिलोना (स्पेन)
- सर्वश्रेष्ठ एजेंट: जॉर्ज मेंडेस (पुर्तगाल)
- सर्वश्रेष्ठ कोच: मार्क विल्मोट्सि (बेल्जियम)
- सर्वश्रेष्ठ एकेडमी: बेनफिका (पुर्तगाल)
- सर्वश्रेष्ठ मीडिया अट्रेक्शन: एफसी बार्सिलोना
- प्लेयर करियर अवॉर्ड: फ्रेंक लेम्पार्ड, आंद्रे पिर्लो, बेस्ट
- सर्वश्रेष्ठ रैफरी: रावशान इर्मातोव
- सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष: जोसफ मारिया (बार्सिलोना)

गुजरात ने दिल्ली को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता

गुजरात ने दिल्ली को 139 रन से से पराजित कर वर्ष 2015 की विजय हजारे ट्रॉफी जीती. फाइनल मैच बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी मैदान पर 28 दिसंबर 2015 को खेला गया. गुजरात ने पहली बार यह क्रिकेट ट्रॉफी जीती है.

गुजरात की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में पार्थिव पटेल के शतक की मदद से 273 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली की पूरी टीम 33 ओवर में 134 रन के स्कोर पर आलआउट हो गई.

गुजरात की ओर से आर पी सिंह ने 42 रन देकर 4 और जसप्रीत बुमराह ने 28 रन देकर 5 विकेट लिये. गुजरात की ओर से कप्तान पार्थिव पटेल ने सर्वाधिक 105 रन बनाए.

दिल्ली की ओर से पवन नेगी ने सर्वाधिक 57 रन की पारी खेली.

कप्तान

गुजरात: पार्थिव पटेल

दिल्ली: गौतम गंभीर

विजय हजारे ट्रॉफी

विजय हजारे ट्रॉफी को एकदिवसीय रणजी ट्रॉफी भी कहा जाता है. इसकी शुरुआत वर्ष 2002-03 की गई थी. यह सीमित ओवरों की ट्रॉफी है. इसमें राज्य की टीमें भाग लेती हैं. यह क्रिकेट की घरेलू खेल प्रतिस्पर्धा है. इस ट्रॉफी का नाम क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे के नाम पर रखा गया था.

गोल्फर एस चिक्कारंगाप्पा ने मैक्लोरॉड रासेल टूर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता

भारतीय गोल्फर एस चिक्कारंगाप्पा ने 27 दिसंबर 2015 को मैक्लोरॉड रासेल टूर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता. बेंगलुरु के 22 वर्षीय गोल्फर चिक्कारंगाप्पा ने मैक्लोरॉड रासेल टूर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीतने के साथ ही पीजीटीआइ ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए अपने पहले रोलेक्स प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब पर भी कब्ज़ा जमाया.

विदित हो कि उपरोक्त जीत के साथ ही चिक्कारंगाप्पा रोलेक्स रैंकिंग (ऑर्डर ऑफ मेरिट) जीतने वाले सबसे युवा गोल्फर बन गए. उन्होंने चैंपियनशिप के अंतिम दौर में तीन अंडर 69 के साथ कुल 12 अंडर 276 के स्कोर के साथ खिताब जीता.

भारत के ल्यूज खिलाड़ी शिवा केशवन ने एशियाई लूज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता

भारत के ल्यूज खिलाड़ी शिवा केशवन ने नागनो, जापान में रविवार को संपन्न 18 वीं एशियाई लूज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया.

स्पर्धा की दो हीटों में 2/10 के स्कोर के साथ केशवन जापानी के खिलाड़ी हिदेनरी कानायामा से पिछड़ गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

जापानी के हिदेनरी कानायामा को स्वर्ण पदक मिला जबकि कोरिया के डोंग हियोन किम तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक हासिल किया.

उल्लेखनीय है कि पांच बार के ओलंपियन और दो बार के एशियाई चैंपियन केशवन दो बार विश्वकप टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले चुके हैं और न्यूयार्क के लेक प्लेसिड में वह नेशंस कप में 15वें स्थान पर रहे थे.

मुंबई गरूड़ ने हरियाणा हैमर्स को हराकर प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्केरण का खिताब जीता

मुंबई गरूड़ ने 27 दिसंबर 2015 को केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम, दिल्ली में आयोजित फाइनल में हरियाणा हैमर्स को 7-2 से हराकर प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया.

मुंबई गरुण ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए यह खिताब अपने नाम किया.

मुंबई के अमित धनकर ने पुरूषों के 65 किलो वर्ग में हरियाणा के विशाल राणा को 12-0 से हराया. मुंबई के लिए कप्तान एडेलिन ग्रे, जियोर्जी एस, ओडुनायो एडेकुओरोये और ओडिकाजे एलिजबार ने मुकाबले जीते.

विश्व चैपिंयनशिप स्वर्ण पदक विजेता ओकसाना हरहेल ने महिलाओं के 58 किलो वर्ग में मुंबई की साक्षी मलिक को हराया. पुरूषों के 74 किलोवर्ग में हरियाणा के लिवान लोपेज एजकुइ ने मुंबई के प्रदीप को 11-6 से मात दी.

मुंबई की आइकन खिलाड़ी एडेलिन ग्रे ने महिलाओं के प्लस 69 किलोवर्ग में हरियाणा की गीतिका जाखड़ को हराया. तीन बार की विश्व चैपिंयन ने यह मुकाबला 10-0 से जीता.

मुंबई के जियोर्जी ने पुरूषों के 125 किलोवर्ग में हरियाणा के हितेंदर को 10-0 से मात दी.

विश्व चैपिंयनशिप कांस्य पदक विजेता हरियाणा की ततियाना किट और मुंबई की ओडुनायो एडेकुओरोये के बीच महिलाओं के 53 किलोवर्ग के मुकाबले में ओडुनायो ने 9-0 से जीत दर्ज की.

पुरूषों के 97 किलोवर्ग में मुंबई के ओडिकाजे एलिजबार ने आंद्रितेसे वालेरी को 6-4 से हराया. रितु फोगट ने निर्मल देवी को मात दी और राहुल अवारे ने नितिन को 6-3 से हराया.

मुंबई को विजेता के रुप में तीन करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई.

टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (पुरुष) : विनेश फोगट

टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (महिला) : ओडुनायो एडेकुओरोये (मुंबई गरूड़)

आइकन मेंटर : योगेश्वर दत्त

प्रो कुश्ती लीग के बारे में

प्रो कुश्ती लीग (PWL), कार्तिकेय शर्मा के स्वामित्व प्रोस्पोर्टीफाई और भारत के कुश्ती महासंघ की पहल है.

यह लीग 10-27 दिसम्बर 2015 के बीच भारत के 6 शहरो में आयोजित की गई. इसमें दुनियाभर के 66 पहलवानों ने हिस्सा लिया.

फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का ख़िताब जीता

बार्सिलोना के सुपर स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी को दुबई में 27 दिसंबर 2015 को आयोजित ग्लोब सॉकर अवॉर्ड्सब समारोह में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया. इसके साथ ही मैसी के क्लब बार्सिलोना ने सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार हासिल किया.

बार्सिलोना के अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेयू ने सर्वश्रेष्ठ क्लब और सर्वश्रेष्ठ प्रेसीडेंट की ट्रॉफी ग्रहण की. बेल्जियम के कोच मार्क विल्मोट्स् को सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया.

विदित हो कि बार्सिलोना ने वर्ष 2015 में पांच खिताब हासिल किए. क्लब ने स्पेनिश लीग, कोपा डेल रे (किंग्स कप), चैंपियंस लीग, यूरोपियन सुपर कप और वर्ल्ड क्लब कप पर अधिकार जमाया. क्लब इस वर्ष प्रमुख खिताबों में सिर्फ स्पेनिश सुपर कप नहीं जीत पाया, क्योंकि उसे एटलेटिको बिलबाओ के हाथों शिकस्त मिली.

अन्य पुरस्कार:

बेस्ट एजेंट : जॉर्ज मेंडेस,

बेस्ट कोच : मार्क विल्मोट्सि,

बेस्ट एकेडमी : बेनफिका,

बेस्ट मीडिया अट्रेक्शन: बार्सिलोना,

प्लेयर करियर अवॉर्ड: फ्रेंक लेम्पार्ड, आंद्रे पिर्लो, बेस्ट

रैफरी: रावशान इर्मातोव.

ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 शतक बनाने वाली पहली टीम बनीं

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारुपों में 1000 शतक बनाने वाली पहली टीम बन गई.

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के मेलबर्न में वेस्टइंडीज के विरूद्ध दूसरे टेस्ट के पहले दिन 26 दिसंबर 2015 को शतकीय पारी खेलने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने एक हजार शतक पूरे किए.

ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है, जिसके 964 शतक हैं.ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 71 अंतर्राष्ट्रीय शतक रिकी पोंटिंग ने बनाए हैं. टी20 में में ऑस्ट्रेलिया की ओर से केवल आरोन फिंच ने शतक बनाया है. इंग्लैंड की ओर से टेस्ट में कप्तान एलिस्टेयर कुक ने सबसे ज्यादा 28 शतक बनाए है. वहीँ मार्कस ट्रेस्कोथिक ने सबसे ज्यादा 12 एकदिवसीय शतक बना चुके हैं.

तीसरे स्थान पर भारत है जिसके 688 शतक हैं. इनमें सबसे ज्यादा 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं. टी20 में सुरेश रैना और रोहित शर्मा 1-1 शतक बना चुके है.

टीमों की सूचीं

टीम	कुल अंतर्राष्ट्रीय शतक
ऑस्ट्रेलिया	1002
इग्लैंड	964
भारत	688
वेस्टइंडीज	629
पाकिस्तान	543
दक्षिण अफ्रीका	501
श्रीलंका	393
न्यूजीलैंड	377
ज़िम्बाब्वे	107

बांग्लादेश	77
आयरलैंड	20
स्कॉटलैंड	14

एंटी-डोपिंग टेस्ट में पॉज़ीटिव पाए जाने के बाद पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह निलंबित

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह को डोपिंग टेस्ट में पॉज़ीटिव पाए जाने के बाद 27 दिसम्बर 2015 को निलंबित कर दिया है. किकेटर शाह के 13 नवंबर को इन-कॉम्पटीशन टेस्ट में वाडा ने नमूने लिए थे. आईसीसी डोपिंग मामले की जांच कर रही है.

उनके नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ क्लोरटालिडोन पाया गया जो कि वाडा की प्रतिबंधित सूची के तत्वों में सेक्शन पांच में शामिल है. जिस दिन परीक्षण किया गया पाकिस्तान ने उस दिन अबुधाबी में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच खेला था. पाकिस्तान जनवरी में सीमित ओवरों की श्रंखला के दौरे पर न्यूजीलैंड जाएगा.

'आईसीसी डोपिंग रोधी संहिता के अनुरूप अनुशासनात्मक प्रक्रिया का परिणाम लंबित रहने तक यासिर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है.' अब इस पर निर्णय संहिता की प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा.

यासिर शाह के बारे में-

- 29 वर्षीय यासिर शाह ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से टेस्ट डेब्यू किया था.
- यासिर अपनी गेंदबाज़ी के दम पर पाकिस्तान को कई मैच जिता चुके हैं.
- यासिर ने पाकिस्तान के लिए 12 टेस्ट मैचों में 24 के बेहद शानदार औसत से 74 टेस्ट हासिल किए हैं.
- उन्होनें 4 बार 5 विकेट भी झटके हैं. वहीं वनडे में उन्होनें 18 विकेट लिए हैं.
- यासिर टेस्ट मैचों में सबसे तेजी से 50 विकेट हासिल करने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज हैं.
- इस साल जून में यासिर ने श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए यह कीर्तिमान बनाया.
- साल 2015 में जारी आईसीसी टेस्ट टीम में भी यासिर शाह को सदस्य बनाया गया.

यासिर कर सकते हैं अपील-

- यासिर लिखित आवेदन के माध्यम से एक डोपिंग रोधी न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए अपने 'बी' नमूने के परीक्षण की अपील कर सकते हैं.
- इस परीक्षण के परिणाम नकारात्मक आए, तो ही सारे पिछले परिणामों को गलत माना जाएगा और तुरंत प्रभाव के साथ निलंबन को रद्द कर दिया जाएगा.
- अपील डोपिंग रोधी प्रबंधक द्वारा 14 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाना अनिवार्य है.

विकास ठाकुर ने भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

सेना खेल नियंत्रण बोर्ड की 68वीं पुरुष और 31वीं महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में 27 दिसंबर 2015 को विकास ठाकुर ने 341 किलोग्राम भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया.

विकास ने तीनों स्पर्धाओं, स्नैच, क्लीन एवं जर्क में रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने स्नैच में 154 किलोग्राम तथा क्लीन एवं जर्क में 187 किलोग्राम (कुल 341 किलोग्राम) भार उठाया.

विकास ने इससे पहले बनाये गये अपने ही 339 किलोग्राम के रेकॉर्ड को तोड़ा जो उन्होंने केरल के त्रिचूर में 35वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान बनाया था.

महाराष्ट्र के हर्षद वास्देकर दूसरे और हरियाणा के शुभम तीसरे स्थान पर रहे जिन्होंने क्रमश: 305 और 302 किलोग्राम भार उठाया. दूसरे स्थान पर रहे हर्षद और विकास ठाकुर के बीच काफी बड़ा अंतर रहा.

संजीता, रमन्ना को राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल

संजीता चानू और कोरादा रमन्ना ने 25 दिसम्बर 2015 को सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में क्रमश: महिलाओं के 48 किग्रा और पुरूषों के 56 किग्रा में स्वर्ण पदक जीते.

- महिलाओं के 48 किग्रा में संजीता ने स्नैच में 78 और क्लीन एवं जर्क में 95 किग्रा भार उठाया.
- उन्होंने कुल 173 किग्रा भार उठाकर सोने का तमगा जीता.
- मीराबाई चानू को रजत और चंद्रिका तरफदार को कांस्य पदक मिला.
- पुरूषों के 56 किग्रा में रमन्ना ने स्नैच में 109 किग्रा और क्लीन एवं जर्क में 142 किग्रा भार उठाया.

- उन्होंने कुल 251 किग्रा भार उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया.
- जमजांग देरू (246 किग्रा) को रजत और गुरू राजा (242 किग्रा) को कांस्य पदक मिला.

पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी कर्नल सी के नायडू पुरस्कार के लिए चयनित

वर्ष 1983 की विश्वकप विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी को वर्ष 2015 के कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया.

बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर और सचिव अनुराग ठाकुर और द हिंदू के प्रकाशक एन राम की सदस्यता वाली समिति ने 23 दिसंबर 2015 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किरमानी का चयन किया.

सैयद किरमानी के बारे में

- सैयद किरमानी की जन्म 29 दिसंबर 1949 को मद्रास (अब चेन्नई) में हुआ था.
- किरमानी ने अपना टेस्ट करियर 24 जनवरी 1976 को न्यूजीलैंड के खिलाफ और एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय करियर 21 फरवरी 1976 को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू किया.
- भारत सरकार ने किरमानी को वर्ष 1982 में पदमश्री से सम्मानित किया था.
- इसके बाद वह अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं.
- किरमानी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष भी रह चुके है.
- किरमानी ने वर्ष 1976 से 1986 के बीच भारत की ओर से 88 टेस्ट मैच और 49 अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच खेले.

कर्नल सी के नायडू पुरस्कार

बीसीसीआई यह पुरस्कार भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सी के नायडू की जयंती के शताब्दी वर्ष के अवसर पर क्रिकेट में अभूतपूर्व योगदान देने वाले खिलाड़ियों को प्रदान करती है. इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और पहला पुरस्कार लाला अमरनाथ को मिला था.

कर्नल सी के नायडू पुरस्कार के अंतर्गत खिलाड़ी को एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति-पत्र और 25 लाख रुपए का चेक

प्रदान प्रदान किया जाता है.

कर्नल सी के नायडू पुरस्कार से सम्मानित भारतीय क्रिकेटर

- सैयद मुश्ताक अली (1995)
- कैप्टन विजय हजारे (1996)
- के एन प्रभु (1997)
- पीआर उमरीगर (1998)
- कर्नल हेमचंद्र अधिकारी (1999)
- सुभाष गुप्ते (2000)
- मंसूर अली खॉ पटौदी (2001)
- भाऊ साहेब निबालकर (2002)
- चंद्रकांत बोर्डे (2003)
- बिशन सिंह बेदी (2004)
- भागवत चंद्रशेखर (2004)
- इरापल्ली प्रसन्ना (2004)
- एस वेंकटराघवन (2004)
- नारीमन कांट्रेक्टर (2007)
- गुंडप्पा विश्वनाथ (2008)
- मोहिन्दर अमरनाथ (2009)
- सलीम दुर्रानी (2010)
- अजीत वाडेकर (2011)
- सुनील गावस्कर (2012)
- कपिल देव (2013)
- दिलीप वेंगसरकर (2014)

योनेक्स ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न

योनेक्स ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 7-12 दिसंबर, 2015 के बीच कैलीफोर्निया, अमेरिका में संपन्न हुआ. पुरुष एकल वर्ग में दक्षिण कोरिया के ली ह्युन इल ने इंग्लैंड के राजीव ओउसेफ को 21-19 21-12 से पराजित किया.

महिला एकल वर्ग में चीनी ताइपे की पाई यु-पो ने स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमौर को 18-21 21-15 21-15 से हराया.

प्रतियोगिता के अन्य परिणाम

पुरुष युगल-

विजेता- गोह वी शेम एवं वी कोइंग तान (मलेशिया)

उपविजेता-ब्लादिमिर इवानोव एवं इवान सोजोनोव (रूस)

महिला युगल-

विजेता- जुंग क्युंग इउन एवं शिन सिउंग चान (दक्षिण कोरिया)

उपविजेता- चांग ये ना एवं ली सो ही (दक्षिण कोरिया)

मिश्रित युगल-विजेता- चोई सोलग्यु एवं एओम ह्यूवॉन (दक्षिण कोरिया)

उपविजेता- माइकल फुच्स एवं बिर्गिट मिचेल्स (जर्मनी)

माइकल ब्रैडली अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबाल खिलाड़ी घोषित

अमेरिका की राष्ट्रीय फुटबाल टीम और टोरंटो एफसी के कप्तान माइकल ब्रैडली को वर्ष 2015 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 23 दिसंबर 2015 को अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबाल खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

कॉनकैफ गोल्ड कप में अमरीकी फुटबाल टीम की कप्तानी करने वाले 28 वर्षीय मिडफील्डर माइकल ने टूर्नामेंट के दौरान ही अपना 100 वां मैच खेला था. वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुने जाने वाले माइकल को

43 प्रतिशत समर्थन मिला, जबकि फैबियन जॉनसन को 33 लोगों का प्रतिशत समर्थन प्राप्त हुआ.

दूसरी ओर अमेरिका की राष्ट्रीय महिला फुटबाल टीम और ह्यूस्टन डेस क्लब की सदस्य कार्ली लॉयड को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबाल खिलाड़ी घोषित किया गया, जबकि मैथ्यू मियाज्गा को अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबाल खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

स्टीव स्मिथ वर्ष 2015 के आईसीसी क्रिकेटर ऑफ़ द इयर चुने गए

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को वर्ष 2015 के दिसम्बर माह में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ़ द इयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ़ द इयर चुना गया.

स्टीव स्मिथ को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ़ द इयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया.

इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका के ए.बी.डिविलियर्स को वर्ष 2015 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ़ दद इयर(सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी) पुरस्कार सम्मानित किया गया.

ज्ञात जो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के चौथे और विश्व के 11वें खिलाड़ी हैं जिन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया. इससे पूर्व पोंटिंग, मिशेल जॉनसन और माइकल क्लार्क को भी इस सम्मान से सम्मानित किया चुका है.

इसके अतिरिक्त स्मिथ सातवें ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ़ द इयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ़ द इयर दोनों के लिए चुना गया है. ईसे पूर्व मिशेल जॉनसन को वर्ष 2014 में और माइकल क्लार्क को वर्ष 2013 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

विदित हो इस पुरस्कार के लिए वोटिंग 18 सितम्बर 2014 से 13 सितम्बर 2015 के मध्य आयोजित कराई गई थी.

ऑस्ट्रेलिया महिलाओं के कप्तान मेग लैनिंग को आईसीसी वेमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ़ द इयर से सम्मानित किया गया. जबकि वेस्ट इंडीज महिला कप्तान स्टेफनी टेलर को आईसीसी वेमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ़ द इयर चुना गया.

संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व कप्तान खुर्रम खान को आईसीसी एसोसिएट एण्ड एफिलियेट क्रिकेटर ऑफ़ द इयर चुना गया.

न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम को आईसीसी स्प्रिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार के लिए चुना गया.

अम्पायर रिचर्ड केटलबोरो को आईसीसी अम्पायर ऑफ़ द इयर चुना गया.

सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी महिला युगल विश्व चैम्पियन घोषित

अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) ने सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी को वर्ष 2015 सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 22 दिसंबर 2015 को महिला युगल विश्व चैम्पियन घोषित किया.

वर्ष 2000 में एकल में विश्व चैम्पियन बनी हिंगिस को 15 वर्ष बाद दोबारा आईटीएफ विश्व चैम्पियन चुना गया.

सानिया और हिंगिस ने मार्च 2015 में जोड़ी बनाने के बाद दो ग्रैंडस्लैम विंबलडन और अमेरिकी ओपन खिताब जीतने के अलावा 7 अन्य टूर्नामेंट में भी जीत दर्ज की, जिसमें ग्वांग्झू, वुहान, बीजिंग, चार्ल्सटन के अलावा डब्ल्यूटीए फाइनल्स का खिताब भी शामिल है. सानिया और हिंगिस ने वर्ष 2015 में 55 मैच जीते, जबकि सिर्फ 7 मैच हारे हैं.

इसके अलावा आईटीएफ ने अमेरिका की सेरेना विलियम्स और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को वर्ष 2015 का आईटीएफ विश्व चैम्पियन घोषित किया. सेरेना को छठी बार महिला विश्व चैम्पियन चुना गया, जबकि जोकोविच पांचवीं बार पुरुष चैंपियन बने.

वर्ष 2015 में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी द्वारा जीते गए खिताब

- 21 मार्च 2015: इंडियन वेल्स ओपन
- 5 अप्रैल 2015: मियामी ओपन
- 12 अप्रैल 2015: फैमिली सर्किल कप
- 11 जुलाई 2015: विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट
- 13 सितंबर 2015: अमेरिकी ओपन
- 26 सितंबर 2015: ग्वांग्झू ओपन
- 3 अक्तूबर 2015: वुहान ओपन
- 10 अक्तूबर 2015: चीन ओपन

- 1 नवंबर 2015: डब्ल्यूटीए फाइनल्स

सेरेना विलियम्स और जोकोविच 2015 आईटीएफ विश्व चैंपियन बनें

आईटीएफ ने 22 दिसम्बर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेरेना विलियम्स और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को वर्ष 2015 का आईटीएफ विश्व चैंपियन घोषित किया.

विलियम्स को छठी बार महिला विश्व चैंपियन का यह खिताब मिला ही जबकि जोकोविच का यह सम्मान प्राप्त करने का पांचवां अवसर है.

इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस और भारत की सानिया मिर्जा महिला डबल्स विश्व चैंपियन चुना गया. जबकि नीदरलैंड के जीन जूलियन रोजेर और रोमानिया के होरिया टेकाउ को पुरुषों का डबल्स विश्व चैंपियन चना गया.

विदित हो स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस को इससे पूर्व वर्ष 2000 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा टेकाउ को वर्ष 2002 में डबल्स चैम्पियन चुना गया था.

हंगरी के डालमा गाल्फी और संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को आईटीएफ जूनियर विश्व चैंपियन चुना गया.

नीदरलैंड के जिसके ग्रिफायन और जापान के शिंगो कुनिदा को आईटीएफ व्हीलचेयर विश्व चैंपियन चुना गया है. शिंगो कुनिदा को यह खिताब सातवीं बार प्राप्त हुआ है.

आईटीएफ विश्व चैंपियंस को 31 मई 2016 को यह पुरस्कार रोलैंड गैरोस के दौरान पेरिस में प्रदान किया जाएगा.

ज्ञात हो सेरेना विलियमस ने इस वर्ष पाँच खिताब जीते हैं और वर्ष के अंत में नम्बर 1 रैंकिंग प्राप्त की है. जोकोविच ने इस वर्ष 11 खिताब जीते हैं. उन्होंने लगातार में चार बार विश्व रैंकिंग पहला स्थान बनाए रखा.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने की सन्यास की घोषणा

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ब्रैडन मैकुलम ने वर्ष 2015 के दिसम्बर माह में घोषणा की कि वह अगले साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

ले लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया के साथ 20 फरवरी को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान में खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के बाद वह अंतराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे.

मैकुलम ने अब तक 99 टेस्ट मैचों में 38.48 की औसत से 11 शतकों के साथ 6273 रन बनाए हैं.

न्यूजीलैंड की तरफ से अंतराष्ट्रीय मैच में तिहरा शतक लगाने वाले इकलौता बल्लेबाज है.

वह 2013 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बनने बने. अब तक मैकुलम की कप्तानी में कीवी टीम ने कुल 28 मैच खेले हैं जिसमें 11 में टीम को जीत मिली हैं.

मैकुलम की कप्तानी में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इस साल हुए विश्व कप में उपविजेता रहीं. उन्होंने 254 एकदिवसीय मैचों में 30.30 की औसत से पांच शतक के साथ 5909 रन बनाएं है.

श्रीलंका पर आसान जीत के साथ ट्राई सीरीज पर भारतीय अंडर-19 का कब्जा

अंडर-19 टीम इंडिया ने 21 दिसम्बर 2015 को मेजबान श्रीलंका को फाइनल में 97 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने ट्राई सीरीज भी जीत ली.

इस जीत में बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज खालिद अहमद की अनुशासित गेंदबाजी और सलामी बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर के अर्धशतक की मदद भूमिका महत्वपूर्ण रही.

टीम इंडिया के सामने जीत के लिये 159 रन का लक्ष्य था. सुंदर (56) और ऋषभ पंत (35) ने पहले विकेट के लिये 89 रन जोड़कर भारत को अच्छी शुरूआत दिलायी. टीम इंडिया ने 33.5 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

इससे पहले श्रीलंका अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. श्रीलंकाई टीम सात विकेट 81 रन पर आउट हुई. विशाद रंदिका डिसिल्वा (56) ने ऐसे समय में अर्धशतकीय पारी खेली. श्रीलंका ने 47.2 ओवर में 158 रन बनाए.

टूर्नामेंट की तीसरी टीम इंग्लैंड थी जो एक भी मैच में जीत दर्ज नहीं कर पायी.

फेड कप में भारत का नेतृत्व करेंगी सानिया मिर्ज़ा

अखिल भारतीय टेनिस संघ की एस पी मिश्रा की अगुवाई वाली चयन समिति ने 21 दिसम्बर 2015 को तीन से पांच फरवरी के बीच थाईलैंड के हुआ हिन में आयोजित होने वाले फेड कप के एशिया ओसियाना ग्रुप एक मैचों के लिये चार सदस्यीय टीम का चयन किया.

विश्व की नंबर एक युगल खिलाड़ी और देश की शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा अगले वर्ष तीन फरवरी से शुरू होने वाले फेड कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी.सानिया के अतिरिक्त टीम में शीर्ष एकल खिलाड़ी अंकिता रैना, प्रेरणा भांबरी और प्रार्थना थोंबरे शामिल हैं.

कर्मन कौर थांडी को रिजर्व खिलाड़ी रखा गया है.

सानिया के नेतृत्व में में भारत ग्रुप-1 में आ गया है.

इसके अतिरिक्त चयनकर्ताओं ने फरवरी में गुवाहाटी में होने वाले साउथ एशियन गेम्स के लिए छह सदस्यीय पुरुष टीम का भी चयन किया है.

इसमें साकेत मायनेनी, रामकुमार रामनाथन, सनम सिंह, विजय सुंदर प्रशांत, पूरव राजा और दिविज शरण शामिल हैं.

जीवन नेदुनचेझियान रिजर्व खिलाड़ी हैं.

इस टूर्नामेंट की महिला टीम में अंकिता, प्रेरणा, रिषिका सुंकारा, नताशा पाल्हा, प्रार्थना और शर्मदा बालू शामिल हैं. जीशान अली पुरुष टीम के और शालिनी ठाकुर महिला टीम की कोच होंगी.

फेड कप के बारे में

- यह महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में की गई थी.
- वर्ष 1995 तक इसे फेडेरेशन कप के नाम से जाना जाता था.
- पुरषों की एसी ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को डेविस कप कहते हैं.

अंडर-19 विश्वकप में इशान किशन बने भारत के कप्तान

वर्ष 2016 के जनवरी माह में बंगलादेश में आयोजित होने वाले अंडर-19 विश्वकप की भारतीय टीम की घोषणा 22 दिसम्बर 2015 को की गई.

अंडर-19 विश्वकप के लिए भारत की ओर से इशान किशन को अंडर-19 टीम का कप्तान चुना गया है.

जबकि बाएँ हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम का उपकप्तान चुना गया है.

इशान किशन के नेतृत्व में भारत श्रीलंका और इंग्लैंड की त्रीपक्षीय श्रृंखला में भारत की अंडर 19 टीम ने विजय प्राप्त की.

इससे पूर्व कोलकता में आयोजित भारत बांग्लादेश और अफगानिस्तान त्रिपक्षीय श्रृंखला में भारत ने जीत प्राप्त की.

चुनी गई टीम में इशान किशन और ऋषभ पंत के अलावा वाशिंगटन सुंदर, सरफराज खान, अमनदीप खरे, अनमोल प्रीत सिंह, अरमान जाफर और रिकी भुई, बल्लेबाज हैं.

जबकि आवेश खान, शुभम मावी, खलील अहमद और राहुल बाथम टीम के चार गेंदबाज हैं. इनके अतिरिक्त मयंक डागर, जीशान अंसारी और महिपाल लोमरोर तीन अन्य लेग स्पिनर खिलाड़ी हैं.

विदित हो भारत को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल के साथ ग्रुप डी में रखा गया है. भारत का पहला मैच मीरपुर में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध 28 जनवरी को है.

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने सेप ब्लेटर और माइकल प्लातिनी पर आठ वर्ष का प्रतिबंध लगाया

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा (FIFA) के नैतिक पंचाट ने विवादों से घिरे सेप ब्लेटर और माइकल प्लातिनी पर 21 दिसंबर 2015 को आठ वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया. फीफा ने यह प्रतिबंध सेप ब्लेटर द्वारा प्लातिनी को 20 लाख स्विस फ्रेंक्स के भुगतान के मामले में अपने पदों का दुरूपयोग के आरोप में लगाया.

फीफा द्वारा लगाये गए प्रतिबंध के द्वारा ब्लेटर और प्लातिनी को हर तरह की फुटबॉल गतिविधि से तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया. इसके साथ ही फीफा की वर्ष 1998 से कमान संभाल रहे ब्लेटर पर 50,000 स्विस फ्रेंक्स और युएफा के निलंबित प्रमुख तथा फीफा उपाध्यक्ष प्लातिनी पर 80,000 फ्रेंक्स का

जुर्माना लगाया गया. अदालत द्वारा जारी बयान में कहा गया कि दोनों ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया.

विदित हो कि फीफा वर्ष 2011 में प्लातिनी को ब्लेटर द्वारा अधिकत 20 लाख स्विस फ्रेंक्स के भुगतान की जांच कर रहा था. उन्होंने कहा कि यह बतौर सलाहकार वर्ष 1999 से 2002 तक उनके काम की एवज में दिए गए थे. फीफा की अदालत ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप खारिज कर दिया लेकिन उन्हें हितों के टकराव का दोषी पाया.

इसके पूर्व ब्लेटर और प्लातिनी को अक्तूबर 2015 में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था जब स्विस अभियोजकों ने वर्ष 2011 में धन के हस्तांतरण की आपराधिक जांच शुरू की थी.

दारियास चेनाई ने 59वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरूषों की ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता

जयपुर स्थित जेडीए शूटिंग रेंज में आयोजित 59वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के संयुक्त महासचिव दारियास चेनाई ने पुरूषों की ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता. इसके साथ ही एनआरएआई के अध्यक्ष रानिंदर सिंह और पूर्व ट्रैप विश्व चैंपियन मानवजीत सिंह संधू ने क्रमश रजत और कांस्य पदक जीते.

विदित हो कि राष्ट्रीय महासंघ के पदाधिकारी दारियास चेनाई और रानिंदर सिंह के बीच पुरूष ट्रैप के स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला हुआ. तेलंगाना की तरफ से भाग ले रहे दारियास 116 के क्वालीफिकेशन स्कोर के साथ फाइनल में पहुंचने वाले अंतिम निशानेबाज थे. उन्होंने दिल्ली के किस्मत चोपड़ा के खिलाफ शूट ऑफ में जीत दर्ज की.

रानिंदर ने 118 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई. भारत के अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज तमिलनाडु के पृथ्वीराज टोंडाईमैन और एयर इंडिया के जोरावर सिंह संधू ने क्रमश 121 और 119 के स्कोर के साथ शीर्ष दो स्थान पर रहकर क्वालीफाई किया था. मानवजीत संधू ने क्वालीफाईंग में 117 का स्कोर बनाया और वह पांचवें स्थान पर थे.

फाइनल में दारियास और रानिंदर दोनों ने 14 सही शाट लगाए जिससे स्वर्ण पदक के लिए उनका मुकाबला टाई हो गया. मानवजीत 13 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे. दारियास ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में 13 शाट सही लगाए जबकि रानिंदर 11 शाट ही सही लगा पाए. इस तरह से दारियास राष्ट्रीय पुरूष ट्रैप चैंपियन बने. मानवजीत ने कांस्य पदक के मुकाबले में पृथ्वीराज को हराया.

हरियाणा के विश्व कुंडु ने जूनियर पुरूष ट्रैप का स्वर्ण पदक जीता जबकि किस्मत चोपड़ा ने रजत और

राजस्थान के अधिराज सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता. मानवजीत ने अनुभवी मनसेर सिंह और विश्वदेव सिंह संधू के साथ मिलकर पंजाब के लिए पुरूष ट्रैप टीम का स्वर्ण पदक जीता. दारियास की अगुवाई में तेलंगाना ने रजत और उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक हासिल किया.

अभय सिंह ने जीता सिंगापुर ओपन का खिताब

शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी अभय सिंह ने 20 दिसम्बर 2015 को पुरूष अंडर-19 के फाइनल में मलेशिया के एल्विन चाइ को 11-8 ,11-3, 11-8 से हराकर ओल्ड चांग की सिंगापुर स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया.

अभय इस साल अब तक कुल सात जूनियर खिताब जीत चुके हैं. जिसमें दो अंतरराष्ट्रीय खिताब हैं.

अभय ने पहले दौर में सिंगापुर के विवेक पालनियप्पन को 11-2, 11-2, 11-1 से हराया जबकि इसके बाद जापान के युसुके ओगाता के खिलाफ 13- 15, 11-3, 11-8, 10-12, 11-6 से संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की.

सेमीफाइनल में उन्होंने सिंगापुर के कोजिरो तान को 7-11, 11-5, 11-7, 11-7 से पराजित किया था.

युजेंसन लिंगदोह और बाला देवी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में सम्मानित

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने पुरुष वर्ग में युजेंसन लिंगदोह एवं महिला वर्ग में बाला देवी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाडियों के रूप में सम्मानित किया. एआईएफएफ के प्रमुख प्रफुल्ल पटेल ने 20 दिसंबर 2015 को वार्षिक आम बैठक में इसकी घोषणा की.

लिंगदोह को आई-लीग क्लबों के कोचों के मतों के आधार पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. उन्हें पुरस्कार के तौर पर दो लाख रुपये नकद और ट्रॉफी दी जाएगी. प्रीतम कोटाल को 2015 का इमर्जिंग प्लेअर ऑफ द ईयर (उभरता खिलाड़ी) चुना गया.

महिला वर्ग में यह पुरस्कार पहली बार दिया गया और इस वर्ष इसे प्यारी जाजा ने हासिल किया. ओडिशा फुटबाल संघ को 2015 के लिए 'बेस्ट ग्रासरूट प्रोग्राम' पुरस्कार दिया गया. सी. आर. श्रीकृष्णा को 2015 का सर्वश्रेष्ठ रेफरी और सापम केनेडी को सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी घोषित किया गया.

युजेंसन लिंगदोह

- वर्ष 1986 में मेघालय स्थित शिलोंग में जन्में युजेंसन लिंगदोह बेंगलुरु एफ सी के लिए मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं.
- अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 2018 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफाई मैच में नेपाल के खिलाफ खेलते हुए भारत को 2-0 से जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
- इसके अतिरिक्त वे शिलोंग लाजोंग, रंग्दाजिद यूनाइटेड, पुणे सिटी नामक क्लबों से भी जुड़े हैं.

बाला देवी

- वर्ष 1990 में मणिपुर में जन्मीं बाला देवी भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए फॉरवर्ड खेलती हैं.
- उन्हें असम में खेले गये वर्ष 2002 में अंडर-19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया.
- वर्ष 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय टीम में खेलना आरंभ किया.
- वर्ष 2015 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बाला देवी ने अपने राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व किया एवं उनकी टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ.

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले पहले कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन बने

25 वर्षीय केन विलियमसन 21 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले न्यूजीलैंड के पहले क्रिकेटर बन गए. उन्होंने हैमिल्टन में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पांच विकेट लेकर यह स्थान हासिल किया.

इस के साथ ही विलियमसन ने 889 अंकों के साथ शीर्ष पर मौजूद इंग्लैंड के खिलाडी जॉय रूट (886 अंक) का स्थान ले लिया. दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स 881 के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं.

इसके अलावा कैलेंडर वर्ष 2015 न्यूजीलैंड के क्रिकेटर विलियमसन के लिए सुनहरा रहा उसने इस वर्ष उच्चतम कुल 1172 रन बनाए.

एक कैलेंडर वर्ष में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए सबसे अधिक टेस्ट रन

1. केन विलियमसन 1172 (2015)
2. ब्रैंडन मैकुलम 1164 (2014)
3. विलियमसन 929 (2014)
4. जॉन आर रीड 871 (1965)
5. रॉस टेलर 866 (2013)

फुटबॉल क्लब बार्सीलोना ने फीफा क्लब विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट का खिताब जीता

स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सीलोना ने 20 दिसंबर 2015 को अर्जेंटीना के क्लब रिवर प्लेट को 3-0 से हराकर रिकार्ड तीसरी बार फीफा क्लब विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट का खिताब जीता.

बार्सीलोना की ओर से लियोनेल मेसी ने 36वें मिनट में गोल किया. इसके अलावा लुई सुआरेज ने भी 49वें और 68वें मिनट में दो गोल किए.

जापान के फुटबॉल क्लब सैनफ्रीस हिरोशिमा ने टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया. टूर्नामेंट में पांच गोल करके लुई सुआरेज ने गोल्टन बूट पुरस्कार हासिल किया. इससे पहले स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने वर्ष 2014 में फीफा क्लब विश्व कप फुटबाल का खिताब जीता था.

फीफा क्लब विश्व कप 2015 का आयोजन जापना में 10 दिसम्बर 2015 से 20 दिसम्बर 2015 तक किया गया. इस प्रतियोगिता में कुल सात टीमों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता का आयोजना जापन के दो शहर ओसका और योकोहामा के स्टेडियम क्रमशः नागाई और इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ़ योकोहामा में किया गया.

फीफा क्लब विश्व कप 2015.

फीफा क्लब विश्व कप फीफा द्वारा आयोजित पुरुषों की एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है. वर्ष 2000 में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्राजील में किया गया था.

सिंगापुर स्लैमर्स ने अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग 2015 का खिताब जीता

सिंगापुर स्लैमर्स ने 20 दिसंबर 2015 को अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग (आईपीटीएल) का खिताब जीता. . सिंगापुर में आयोजित फाइनल में सिंगापुर स्लैमर्स ने इंडियन एसेस को 26-21 से हराकर यह खिताब जीता.

सिंगापुर स्लैमर्स को खिताब जीतने पर दस लाख डॉलर और इंडियन एसेस को पांच लाख डॉलर की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई.

फाइनल मैच का विवरण

- लेजेंड एकल: सिंगापुर स्लैमर्स के कार्लोस मोया ने इंडियन एसेस के फैब्रिस सांतोरो को 6-4 से हराया.
- महिला एकल: सिंगापुर स्लैमर्स के बेलिंडा बेनसिच ने इंडियन एसेस की स्वेतलाना कुजनेत्सोवा को 6-4 से हराया
- मिश्रित युगल: इंडियन एसेस के सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने डस्टिन ब्राउन और सिंगापुर स्लैमर्स के कारोलिना पिलिसकोवा को 6-2 से पराजित किया
- पुरुष एकल: सिंगापुर स्लैमर्स के स्टैन वावरिंका ने इंडियन एसेस के बर्नार्ड टोमिच को 6-3 से हराया
- पुरुष युगल: पुरुषों के युगल वर्ग में सिंगापुर स्लैमर्स के वावरिंका और मार्सेलो मेलो की जोडी ने इंडियन एसेस के बोपन्ना और इवान डोडिग को 6-3 से हराया.

आईपीटीएल से संबंधित मुख्य तथ्य:

इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग (आईपीटीएल) आईपीएल की ही तरह टीम प्रतियोगिता है. इसके संस्थापक इंडियन टेनिस स्टार महेश भूपति हैं. इसका पहला संस्करण 2014 में एशिया के चार देशों में खेला गया. पहले संस्करण का खिताब इंडियन एसेस ने जीता था.

चेन्नईयन एफसी ने एफसी गोवा को हराकर इंडियन सुपर लीग खिताब जीता

इंडियन सुपर लीग (आईएसएल-2) के फाइनल मुकाबले में 20 दिसंबर 2015 को फुटबॉल टीम चेन्नईयन एफसी ने एफसी गोवा को हराकर ख़िताब जीता. चेन्नईयन एफसी 3-2 से विजयी रही.

चेन्नईयन ने 90वें मिनट में बराबरी करने के बाद इंजरी टाइम में विनिंग गोल दागा. चेन्नईयन टीम के लिए

इस मैच में रूनो पेलिस्सरी और जॉन स्टीवन मेंदोजा वेलेंशिया ने गोल किए.

गोवा के लिए थोंगखोसिएम हाओकिप और ज्यॉफ्रे माटेऊ गोंजालेज ने गोल दागे. कट्टीमनी का सेल्फ गोल गोवा पर भारी पड़ गया. मैच के आखिरी तीन गोल आखिरी पांच मिनट में हुए.

सेल्फ गोल के बाद चेन्नई को 2-2 से बराबरी मिल गई. इसके बाद मेंदोजा वेलेंशिया ने इंजरी समय में गोल दागकर चेन्नईयन को ख़िताब दिलाया. आईएसएल का फाइनल मैच नेहरू स्टेडियम में खेला गया.

आईएसएल-2

- चेन्नईयन टीम को 8 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिली. एफसी गोवा की टीम को 4 करोड़ रुपए मिले.
- आईएसएल-2 में कुल 60 मुकाबले हुए. इस दौरान 186 गोल हुए.
- वेलेंशिया को सबसे ज्यादा गोल (12) करने के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया.
- चेन्नईयन के मैनेजर इटली के मशहूर फुटबॉलर मार्को मेतराजी हैं. मेतराजी वही खिलाड़ी हैं जिन्हें 2006 के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस के जिनेदिन जिदाने ने हेडबट किया था. जिदाने को इसके बाद मैच से बाहर कर दिया गया था और इटली ने खिताब जीता था.

सुनील जोशी ओमान टीम के गेंदबाजी कोच नियुक्त

पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज सुनील बन्दाचार्य जोशी को 18 दिसम्बर 2015 को अगले वर्ष मार्च 2016 होने वाले ट्वंटी 20 विश्वकप के लिए ओमान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है.

सुनील जोशी हेड कोच दिलीप मेंडिस से जुड़ेंगे.

सुनील जोशी के बारे में

- पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील जोशी का जन्म 6 जून 1970 को कर्नाटक में हुआ.
- जोशी ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1996 में की.
- उन्होंने जम्मू कश्मीर और हैदराबाद क्रिकेट टीम को कोचिंग दी है.
- उन्होंने अपने कैरियर के 15 मैचों में 132 रन बनाए.
- इसके अतिरिक्त जोशी ने अपने कैरियर में 41 विकेट लिए.

डैन कार्टर वर्ष 2015 के 'बीबीसी ओवरसीज़ स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी ऑफ़ द इयर' चुने गए

न्यूज़ीलैंड के रग्बी खिलाड़ी डेनियल विलियम कार्टर को 18 दिसम्बर 2015 को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी ऑफ़ द इयर पुरस्कार के लिए चुना गया.

इस वर्ष पहली बार विजेता को सार्वजनिक वोट के मध्यम से चुना गया है.

इस क्रम उन्होंने नोवाक जोकोविच, केटी लेडेकी, उसैन बोल्ट, जॉर्डन स्पेथ और सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया.

कार्टर वर्ष 2015 में आयोजित रग्बी वर्ल्ड कप विजेता टीम न्यूज़ीलैंड का हिस्सा भी थे.

सर्वाधिक टेस्ट रग्बी अंक अर्जित करने वाले 33 वर्षीय कार्टर ने तीसरी बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है.

यह पुरस्कार 20 दिसम्बर को उन्हें उत्तरी आयरलैंड की राजधानी, बेलफास्ट के एसएसई अरीना में प्रदान किया जाएगा. यह आयोजन पहली बार यहाँ आयोजित किया जा रहा है.

विदित हो कार्टर ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद वर्ष 2015 में संन्यास ले लिया. अपने पूरे कैरियर में कार्टर ने 112 कैप्स जीती और 1598 अंक अर्जित किए. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में की.

भारतीय पुरुष टीम ने 20वीं अवध राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण

सूरत, गुजरात के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 18 दिसम्बर 2015 को आयोजित 20वीं अवध राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 3-1 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया. जबकि महिला टीम को सिंगापुर के हाथों 1-3 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

भारतीय पुरुष टीम ने दूसरी बार स्वर्ण अपने नाम किया है इससे पूर्व वर्ष 2004 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 16वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अचंता शरत कमल ने पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता था.

महिलाओं के लिए यह चौथा अवसर था जब महिलाओं ने रजत पदक जीता. इससे पूर्व महिलाओं ने वर्ष 1975,

1983 और 1991 में रजत पदक जीता था.

भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के बारे में

- भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी.
- यह अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का संस्थापक सदस्य है.
- टीटीएफआई में 32 राज्य इकाइयों और 37 संस्थानों की संबद्धता है.
- यह देश के सबसे अधिक सक्रिय महासंघों में से एक है.
- भारत ओलंपिक, विश्व, राष्ट्रमंडल, एशियाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ(टीटीएफआई) के मध्यम से ही भाग लेता है.

ग्रीक टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर जेकुपोविक पर लगा आजीवन प्रतिबंध

टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट ने 18 दिसम्बर 2015 को ग्रीक टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर जेकुपोविक पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए.

टेनिस खिलाडी जेकुपोविक को भ्रष्टाचार रोधी कार्यक्रम के तहत दोषी पाया गया है.

जेकोपोविक पर भ्रष्टाचार के पाँच आरोप हैं.

इस निर्देश के बाद 33 वर्षीय जेकुपोविक तत्काल प्रभाव से शासी निकाय द्वरा आयोजित किए जाने वाले किसी भी खेल के लिए अयोग्य हो गए हैं.

जेकोपोविक की वर्ष 2008 में कैरियर की उच्च रैंकिंग 267 थी.

इस सत्र में उन्होंने दो एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट में भाग लिया है.

टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट के बारे में

- टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट को वर्ष 2008 के सितम्बर माह में स्थापित किया गया था.
- टेनिस इंटेग्रिटी यूनिट(आईटीयू), अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ), एटीपी, डब्ल्यूटीए और ग्रैंड स्लैम बोर्ड की संयुक्त पहल है.
- इस इकाई का उद्देश्य टेनिस में भ्रष्टाचार को रोकना है.

मनोज प्रभाकर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त

भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का गेंदबाज़ी कोच नियुक्त किया.

पूर्व भारतीय ऑल-राउंडर मनोज वर्ष 2016 में भारत में आयोजित होने वाले टी-20 विश्व कप तक अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाज़ी कोच रहेंगे.

इसके साथ ही मनोज प्रभाकर ऑफगानिस्तान के प्रमुख कोच और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंज़माम उल हक के साथ सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा होंगे. इंज़माम अफगानिस्तान टीम के प्रमुख कोच हैं.

मनोज प्रभाकर के बारे में

- प्रभाकर ने भारत के लिए 39 टेस्ट मैचों में 1300 रन (1 शतक और 9 अर्धशतक) और 96 विकेट हासिल किए.
- प्रभाकर ने 130 एकदिवसीय मैचों में 1858 रन (2 शतक और 11 अर्धशतक) और 157 विकेट भी हासिल किए.
- प्रभाकर ने वर्ष 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और उसी वर्ष शारजहां में श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था.
- वह दिल्ली रणजी टीम के कोच भी रह चुके हैं.

हॉकी इंडिया लीग का प्रायोजक होगा कोल इंडिया लिमिटेड

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमटेड 17 दिसम्बर 2015 को तीन वर्षों के लिए हाकी इंडिया लीग का नया टाइटिल प्रायोजक बनाया गया.

सीआईएल टाइटिल प्रायोजक के रूप में हीरो मोटोकार्प की जगह लेगा.

इस क्रम में सीआईएल के बोर्ड ने हाकी इंडिया लीग के 2016 के सत्र के प्रायोजन के लिये 14 करोड़ 73 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की.

इस धनराशि में 13 करोड़ रूपये की प्रायोजन राशि के अलावा प्रत्येक मैच के कोल इंडिया मैच का सर्वश्रेष्ठ

गोल, सत्र का सबसे उपयोगी खिलाड़ी के लिये नकद पुरस्कार और अन्य खर्चे भी शामिल हैं.

इस टूर्नामेंट को कोल इंडिया हाकी इंडिया लीग के नाम से जाना जाएगा.

टूर्नामेंट अगले वर्ष 18 जनवरी से 21 फरवरी तक खेला जाएगा.

इस दौरान छह फ्रेंचाइजी टीमें देश के छह शहरों में कुल 34 मैच खेलेंगी.

इस संबंध में यहां कोल इंडिया के कारपोरेट कार्यालय में दोनों पक्षों के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये. सीआईएल की ओर से निदेशक : पर्सोनल एवं इंडस्ट्रियल रिलेशंस: आर मोहन दास और हाकी इंडिया की ओर से सीईओ एलेना नोर्मन से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए.

विदित हो एचआईएल के साथ हीरो का तीन वर्षों का अनुबंध 2015 सत्र के बाद खत्म हो जाएगा.

रोरी मैक्लराय ने यूरोपियन टूर गोल्फर आफ द ईयर का खिताब जीता

रोरी मैक्लराय ने 15 दिसंबर 2015 को यूरोपियन टूर गोल्फर आफ द ईयर का खिताब जीता. पिछले 4 वर्षों में यह उनका तीसरा यूरोपियन टूर गोल्फर आफ द ईयर का खिताब है.

रोरी मैक्लराय को गोल्फ मीडिया के पैनल में शामिल सदस्यों ने सर्वसम्मति से वर्ष 2015 के यूरोपीय टूर गोल्फर आफ द ईयर के लिए नामित किया. इससे पहले मैक्लराय को वर्ष 2012 और 2014 में यूरोपीय टूर गोल्फर आफ द ईयर के लिए चुना गया था.

4 मई 1989 को जन्मे, उत्तरी आयरलैंड के पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी रोरी मैक्लराय यूरोपीय और पीजीए टूर के सदस्य हैं. मैक्लराय चार प्रमुख खिताब जीत चुके हैं. उनके द्वारा जीते गये मुख्य चैम्पियनशिप में शामिल हैं: वर्ष 2011 में यूएस ओपन, वर्ष 2012 में यूएसपीजीए चैम्पियनशिप और वर्ष 2014 में ब्रिटिश ओपन और पीजीए चैंपियनशिप.

शिवा, मंदीप एवं अन्य चार भारतीय मुक्केबाज आईओसी छात्रवृत्ति हेतु चयनित

चार भारतीय मुक्केबाज शिवा थापा, मंदीप जांगड़ा, गौरव बिधूड़ी एवं सुमित सांगवान को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक

समिति (आईओसी) ने 15 दिसंबर 2015 को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया.

इस छात्रवृत्ति के तहत मुक्केबाजों को अगस्त 2016 तक प्रतिमाह 800 अमेरिकी डॉलर (लगभग 53 हज़ार रुपये) प्रदान किये जायेंगे. इसके अतिरिक्त उन्हें ओलंपिक खेलों में शामिल होने एवं अवागमन शुल्क के रूप में 5000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3 लाख 34 हज़ार रुपये) भी दिए जायेंगे.

शिवा थापा 56 किलोग्राम श्रेणी में विश्व कांस्य पदक विजेता हैं जबकि मंदीप जांगड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में 69 किलोग्राम श्रेणी के रजत पदक विजेता हैं.

बिधूड़ी ने विश्व मुक्केबाजी मुकाबले के लिए लगातार दूसरी बार स्थान हासिल किया है जिसे यूएसए नॉकआउट द्वारा आयोजित किया जाता है. दूसरी ओर, सुमित ने वर्ष 2010 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया. उन्होंने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स से पहले एशियन ओलंपिक्स क्वालीफाई गेम में स्वर्ण पदक भी अर्जित किया था.

गौरव बिधूड़ी (52 किलोग्राम) एवं सुमित सांगवान (69 किलोग्राम) को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मनोनीत किये जाने के बाद चयनित किया गया.

अपूर्वी चंदेला और चैन सिंह ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

अपूर्वी चंदेला और चैन सिंह ने नई दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 59वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन 15 दिसंबर 2015 को क्रमश: महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते.

रियो ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी अपूर्वी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह पदक जीता. राजस्थान की अपूर्वी ने कुल 207.8 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता.

राजस्थान की ही जूनियर निशानेबाज गीताक्षी दीक्षित ने 206.8 अंक के साथ रजत जीता. हरियाणा की अंजुम मुदगिल (185.7) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में भारतीय सेना के चैन सिंह ने एयर इंडिया के गगन नारंग के कड़ी चुनौती पर काबू पाते हुए स्वर्ण जीता. चैन ने फाइनल में 452.8 का स्कोर अर्जित किया जबकि ओलिंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग ने 451.1 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता.

खेल पत्रिका स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने सेरेना विलियम्स को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना

अमेरिका की प्रतिष्ठित खेल पत्रिका स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड (एसआइ) ने दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को दिसंबर 2015 में 'स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर' चुना. इसके साथ ही सेरेना, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका द्वारा इस पुरस्कार से नवाजे जा चुके मुक्केबाज मुहम्मद अली, ऑर्थर एश, लेब्रॉन जेम्स, माइकल जॉर्डन, बिली जीन किंग और जैक निकलस जैसे दिग्गजों के समूह में शामिल हो गई.

अमेरिका महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना वर्ष 1983 के बाद पहली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित पत्रिका ने यह सम्मान दिया है. इससे पहले एसआइ ने मेरी डेकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था. अमेरिका की इस शीर्ष टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2015 में लगातार तीन ग्रैंडस्लैम जीते. इसके साथ ही हर सप्ताह जारी होने वाली विश्व रैंकिंग में लगातार दो साल तक शीर्ष पर रहना उनकी श्रेष्ठता को साबित करता है.

लाहिड़ी बने एशियन टूर जीतने वाले चौथे भारतीय गोल्फर

अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय गोल्फर अर्निबान लाहिड़ी ने सेनटोसा में एक टूर्नामेंट शेष रहते 15 दिसम्बर 2015 को एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट खिताब अपने नाम कर लिया.

मौजूदा वर्ष में लगभग 7.6 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले लाहिड़ी ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरे स्थान पर चल रहे ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट हेंड से काफी आगे हैं इसलिए उन्हें सत्र समाप्त होने से पहले ही विजेता घोषित कर दिया गया. स्कॉट के पास अब तक 3.3 करोड़ रुपए के करीब ही हैं. एशियन टूर का मौजूदा सत्र समापन फिलीपींस में 17 से 20 दिसंबर तक फिलीपीन ओपन के साथ होगा.

लाहिड़ी के बारे में-

- दुनिया में 41वें नंबर के गोल्फर लाहिड़ी चौथे भारतीय हैं, जिन्होंने एशियन टूर अपने नाम किया.
- लाहिड़ी से पहले यह खिताब जीतने वाले भारतीयों में ज्योति रंधावा (2002), अर्जुन अटवाल (2003) और जीव मिल्खा सिंह (2006 और 2008) शामिल है.
- एशियन टूर के दो चैंपियनशिप (मेबैंक मलेशिया ओपन और हीरो इंडियन ओपन) जीत कर अपने नाम करने के साथ लाहिड़ी दुनिया के शीर्ष 50 गोल्फरों में जगह बनाने में सफल रहे.
- वे मेजर पीजीए चैंपियनशिप के टॉप-5 में रहे और पहली बार प्रेसिडेंट्स कप के लिए क्वालीफाई किया.
- एशियन टूर में लाहिड़ी 2008 से लगातार हिस्सा ले रहे हैं.

- लाहिड़ी का अगला लक्ष्य मेजर खिताब जीतना है.
- लाहिड़ी एशियन टूर मेरिट 2013 में तीसरे और 2014 में दूसरे स्थान पर रहे.

जापान की नोजोमी ओकुहरा, केंटो मोमोता ने वर्ल्ड दुबई सुपर सीरीज फाइनल का एकल खिताब जीता

जापानी बैडमिंटन खिलाडी केंटो मोमोता और नोजोमी ओकुहरा ने 13 दिसंबर 2015 को हमदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दुबई में आयोजित बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल मुकाबले में क्रमश: पुरुष एकल और महिला एकल खिताब जीत लिया.

ओकुहरा ने चीन की वांग यिहान को 22-20, 21-18 से हराकर महिला एकल खिताब पर कब्जा किया और कुछ ही देर बाद, केंटो मोमोता ने 21-15 21-12 से डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को मात देकर पुरुषों का एकल खिताब जीत लिया.

केंटो मोमोता बारे में-

- 1 सितंबर 1994 को जन्मे केंटो मोमोता कोर्ट पर अपने विस्फोटक अंदाज और खेलने की अप्रत्याशित शैली के लिए जाना जाता है.
- 2014 में जापान में आयोजित मेडेन थॉमस कप के सभी मैचों में उसने भाग लिया और जीते.
- सिंगापुर ओपन जीतने वाले वह पहले जापानी खिलाड़ी थे.
- जकार्ता में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2015 में पदक जीतने वाले वह पहले जापानी खिलाड़ी थे.

नोजोमी ओकुहरा बारे में-

- 13 मार्च 1995 को जन्मी नोजोमी ओकुहरा जापानी की एकल विशेषज्ञ महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है.
- 2011 में वह सबसे कम उम्र में एकल बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली जापानी महिला खिलाड़ी बनी.
- 2012 में उसने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स खिताब कनाडा 2012 ओपन ग्रां प्री जीता.
- 2015 में उसने जापान सुपर सीरीज में पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर सीरीज खिताब जीता.

विजय कुमार ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

ओलंपिक पदक विजेता विजय कुमार ने 59वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 12वें दिन 13 दिसंबर 2015 को पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता.

यह आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया. भारतीय सेना के गुरप्रीत सिंह ने रजत जबकि राष्ट्रीय रैपिड फायर पिस्टल चैंपियन पेम्बा तमांग ने कांस्य पदक जीता.

विजय ने 588 अंकों का स्कोर बनाकर गुरप्रीत (586 अंक) और पेम्बा (582 अंक) को पीछे छोड़ा. इससे पहले ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने पुरुषों के दस मीटर एयर रायफल में रजत पदक जीता. इसी श्रेणी में सेना के इमरान हसन खान ने स्वर्ण और चैन सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया.

12वें दक्षिण एशियाई खेल-2016 का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर गुवाहाटी में जारी किया गया

12वें दक्षिण एशियाई खेल-2016 (ओसी-एसएजी) की आयोजन समिति ने 13 दिसंबर 2016 को आईटीए सांस्कृतिक केन्द्र माचखोआ, गुवाहाटी, असम में आयोजित एक समारोह में प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का अनावरण किया. यह खेल 6 से 16 फरवरी, 2016 तक गुवाहाटी और शिलांग में संयुक्त रूप से आयोजित किए जाएंगे.

12वें दक्षिण एशियाई खेलों में 23 विधाओं में 8 देशों के करीब 4500 खिलाड़ियों और अधिकारियों के शामिल होने की आशा है. इससे पहले जुलाई 2015 में ओसी-एसएजी ने 12वें एशियाई खेल के प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का डिजाइन तैयार करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की थी.

यह वर्ष में दो बार होने वाला बहु-खेल कार्यक्रम है. प्रत्येक श्रेणी की करीब 450 प्रविष्टियों में से प्रतीक चिन्ह और शुभंकर का चयन किया गया. कोल्हापुर के अनंत खसबरदार और एनआईएफटी पटना के अभिजीत कृष्णा ने क्रमशः शुभंकर और प्रतीक चिन्ह डिजाइन प्रतियोगिता जीती.

प्रतीक चिन्ह

प्रतीक चिन्ह में 8 पंखुड़िया हैं, जो 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में प्रतिभागी देशों को दर्शाते हैं. यह पंखुड़ियां घड़ी की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, जिससे खेल की सकारात्मक भावना प्रदर्शित होती है. प्रतीक चिन्ह यूरोप में प्राचीन समय के दौरान खेल विजेताओं को सिर पर पहनाए जाने वाले मुकुट के समान दिखती है.

शुभंकर

खेलों के शुभंकर का नाम तिखोर रखा गया है, जो 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 का ब्रांड एम्बेसडर है. तिखोर को खेल प्रेमी और आधुनिक दर्शाया गया है. वह सब क्षेत्रों में दक्ष, सक्रिय, ऊर्जावान और बच्चों के

बीच लोकप्रिय बताया गया है. ऐसा दर्शाया गया है कि वह क्षेत्र के खेल प्रेमियों के लिए प्रेरक, मित्र और पारिवारिक है.

आईसीसी ने वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी मलरेन सैमुअल्स को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 13 दिसंबर 2015 को वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी मलरेन सैमुअल्स को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया. इसके तहत आलराउंडर मलरेन सैमुअल्स को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने से 12 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

दिसंबर 2015 के शुरू में ब्रिस्बेन में उनके एक्शन की स्वतंत्र जांच के बाद यह फैसला किया गया. मलरेन सैमुअल्स के गेंदबाजी एक्शन को लेकर वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच गाले में 14 से 17 अक्टूबर 2015 के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान सवाल उठाए गए थे.

आईसीसी के अनुसार, मैच अधिकारियों ने सैमुअल्स के एक्शन की रिपोर्ट की जिसके बाद आईसीसी नियमों के अनुसार ब्रिस्बेन में आईसीसी से मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में उनकी स्वतंत्र जांच की गई. जांच से पता चला कि गेंदबाजी करते समय उनकी कोहनी 15 डिग्री के तय मानक से अधिक मुड़ती है. सैमुअल्स पर इससे पहले दिसंबर 2013 में तेज गेंदबाजी करने से रोक दिया गया था.

देबोरा हेरल्ड विश्व रैंकिंग में भारत की पहली और विश्व की चौथी साइकिल चालक बनीं

10 दिसंबर 2015 को यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल द्वारा जारी वर्ल्ड एलीट वीमेन रैंकिंग में देबोरा हेरल्ड को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है. वे भारत की पहली साइकिलिस्ट हैं जिन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ.

20 वर्षीय देबोरा हेरल्ड को 500 मीटर टाइम ट्रायल में 211 अंक अर्जित करने पर यह स्थान हासिल हुआ. इससे पहले नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित ट्रैक एशिया कप में भी देबोरा का बेहतर प्रदर्शन रहा था.

उन्होंने 10वें स्थान पर रहते हुए 3 पदक (एक स्वर्ण और दो रजत) जीते. इस प्रतियोगिता में भारत कुल 11

पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

गौरतलब है कि वे मूल रूप से अंडमान स्थित कार निकोबार द्वीप की रहने वाली हैं तथा सूनामी प्रभावित उन लोगों में से हैं जिनके परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था.

एलिज़ाबेथ कोशी ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

केरल की खिलाड़ी एलिज़ाबेथ सुसान कोशी ने 11 दिसम्बर 2015 को नई दिल्ली स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 59 वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता.

कोशी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता. इसी प्रतिस्पर्धा में हरियाणा की अंजुम मोदगिल ने रजत पदक प्राप्त किया तथा तमिलनाडु की गायत्री एन ने कांस्य पदक जीता.

तेजस्विनी सावंत चौथे स्थान पर रही. हालांकि तेजस्विनी ने प्रियाल और केनी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता.

महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के परिणाम

एलिज़ाबेथ सुसान कोशी - 459.3 अंक (राष्ट्रीय रिकॉर्ड), अंजुम मोदगिल - 448.8 अंक, एन गायत्री 435.6 अंक, जूनियर श्रेणी: एन गायत्री - 575.2 अंक, अदिति सिंह - 570.3 अंक, श्रेया - 567 अंक.

आईसीसी टी-20 विश्वकप 2016 का कार्यक्रम घोषित

आईसीसी ने 11 दिसम्बर 2015 को वर्ष 2016 में भारत के 8 विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले टी-20 विश्वकप के कार्यक्रम की घोषणा की.

विदित हो वर्ष 2016 का टी-20 विश्वकप 8 मार्च 2016 से 3 अप्रैल 2016 के मध्य आयोजित की जाएगी.

प्रतियोगिता के दौरान कुल 58 मैच खेले जाएंगे जिनमे से 35 पुरषों के और 23 महिलाओं के होंगे.

यह 27 दिवसीय प्रतियोगिता बेंगलुरू, चेन्नई, धर्मशाला, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी.

प्रतियोगिता का सेमीफाइनल 30 और 31 मार्च को दिल्ली और मुंबई में आयोजित किए जाएंगे.

जबकि 3 अप्रैल को होने वाला फाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में आयोजित किया जाएगा.

पुरुषों वर्ग के विजेता को पुरस्कार के 5.6 मिलियन यूएस डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी. विदित हो यह राशि वर्ष 2014 की पुरस्कार राशि से 86 प्रतिशत अधिक है.

जबकि महिला वर्ग के लिए कुल पुरस्कार राशि 400000 डॉलर है. जो बांग्लादेश में आयोजित किए गए वर्ष 2014 के टी-20 विश्वकप की तुलना में 122 प्रतिशत अधिक है.

आईसीसी टी-20 विश्वकप 2016 का कार्यक्रम निम्न प्रकार है

पुरुष वर्ग :

पहला दौर : इस वर्ग के विजेता दूसरे दौर में पहुंचेंगे

ग्रुप ए : बांग्लादेश, नीदरलैंड, आयरलैंड और ओमा

ग्रुप बी : जिम्बाब्वे, स्काटलैंड, हांगकांग और अफगानिस्तान

दूसरे दौर के ग्रुप :

सुपर 10 ग्रुप 1 : श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ग्रुप बी की विजेता टीम

सुपर 10 ग्रुप 2 : भारत, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ग्रुप ए की विजेता

महिला वर्ग :

ग्रुप ए : आस्ट्रेलिया (ए वन) , दक्षिण अफ्रीका (ए टू), न्यूजीलैंड (ए थ्री) , श्रीलंका (ए फोर), आयरलैंड (ए फाइव).

ग्रुप बी : इंग्लैंड (बी वन), वेस्टइंडीज (बी टू), भारत (बी थ्री) , पाकिस्तान (बी फोर), बांग्लादेश (बी फाइव).

क्रूगर वैन वाइक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की

न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट विकेटकीपर क्रूगर वैन वाइक ने 10 दिसम्बर 2015 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की.

क्रूगर वैन वाइक के बारे में

- क्रूगर वैन वाइक का जन्म 7 फ़रवरी 1980 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था.
- क्रूगर ने न्यूजीलैंड की ओर से नौ टेस्ट मैच खेले हैं जिसकी 17 पारियों में उन्होंने 341 रन बनाये.

- क्रूगर को 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया.
- बेंगलुरु में भारत के खिलाफ 71 रन की शानदार पारी उनके कॅरियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा.
- उन्होंने 21.31 के औसत से नौ टेस्ट मुकाबलों में 341 रन बनाए.
- अपने कॅरियर में 138 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेलने वाले क्रूगर ने 39.61 के औसत से 6734 रन बनाये.
- क्रूगर ने दक्षिण अफ्रीका के घरेलू क्रिकेट के दौरान नॉर्थंस और टाइटंस टीमों का प्रतिनिधित्व किया.
- इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड घरेलू क्रिकेट में वह कैंटरबरी और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ओर से खेले.

चेन लॉन्ग एवं कैरोलिना मरीन ने वर्ष 2015 का बीडब्ल्यूएफ प्लेयर अवार्ड जीता

चीन के चेन लॉन्ग एवं इंग्लैंड की विश्व चैंपियन कैरोलिना मरीन ने दुबई में 7 दिसंबर 2015 को वर्ष 2015 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) प्लेयर ऑफ़ द इयर अवार्ड जीता.

कैरोलीन मरीन ने चीन की जाओ युन्लेंद, भारत की सायना नेहवाल और चीन की बाओ यिजिन को मात दी. चेन लॉन्ग पिछले वर्ष भी मेल प्लेयर ऑफ़ द इयर थे.

चीन के उभरते खिलाड़ी एवं मिक्स्ड डबल्स के विश्व जूनियर चैंपियन ज्हेंग सी वी ने मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ़ द इयर के रूप में एडी चूंग अवार्ड प्राप्त किया.

बीडब्ल्यूएफ ने पहली बार पारा बैडमिंटन खिलाडियों को भी सम्मानित किया. कोरिया के ली सैम सॉप को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष पारालम्पिक खिलाड़ी घोषित किया गया. इसी प्रकार सोफी सगोय को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पारालम्पिक खिलाड़ी घोषित किया गया.

कैरोलिना मरीन

- स्पेन की नागरिक कैरोलिना मरीन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के महिला एकल 2015 मुकाबले की विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं.
- उन्होंने वर्ष 2014 और 2015 में महिला विश्व चैंपियन ख़िताब जीता था.
- वर्ष 2009 में वे यूरोपियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली स्पैनिश महिला

खिलाड़ी बनीं.

- वर्ष 2009 में यू-17 बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतर्गत वे स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली स्पेनिश बैडमिंटन महिला खिलाड़ी बनीं.
- उन्होंने वर्ष 2013 में लंदन ग्रां प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता.

चेन लॉन्ग

- चीन के चेन लॉन्ग ने ओलिंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था. वे दो बार विश्व चैंपियन एवं दो बार ऑल-इंग्लैंड चैंपियन भी रह चुके हैं.
- वे वर्ष 2007 में विश्व जूनियर चैंपियन ख़िताब भी प्राप्त कर चुके हैं.
- उन्होंने वर्ष 2007 में एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी ख़िताब प्राप्त किया था.

महेला जयवर्धने एमसीसी के मानद आजीवन सदस्य के रूप में चयनित

मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने 9 दिसम्बर 2015 को श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी महेला जयवर्धने को मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया.

महेला जयवर्धने इस क्लब में शामिल होने वाले श्रीलंका के 14वें खिलाड़ी हैं. विदित हो इस सूची में कुमार संगकारा, मुथैया मुरलीधरन और चमिंडा वास जैसे श्रीलंकाई खिलाडी पहले से शामिल हैं.

अपने 18 वर्षों के कैरियर में जयवर्धने ने 49.84 की औसत से 149 टेस्ट मैच खेले और 11814 रन स्कोर किए.

उन्होंने वर्ष 2014 में इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स में अन्तिम मैच खेला था. यह मैच ड्रा हुआ था.

ज्ञात हो वर्तमान में जयवर्धने इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजी के सलाहकार हैं.

मेरिलबोन क्रिकेट क्लब और क्लब की सदस्यता

मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) लन्दन में एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में की गयी थी. काफी प्रभावी और पुराना होने के कारण क्लब के निजी सदस्य क्रिकेट के विकास के लिए समर्पित हैं. यह लन्दन एन डब्ल्यू 8 के सेंट जॉनस वुड में लोर्डस क्रिकेट ग्राउंड में स्थित है. एमसीसी पहले इंग्लैण्ड और वेल्स तथा पूरी दुनिया में क्रिकेट का नियंत्रण करने वाली इकाई थी. 1993 में इसके कई विश्वस्तरीय कार्यों को

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को स्थानांतरित कर दिया गया और इसके अंग्रेजी प्रशासन को उसी समय टेस्ट एंड कंट्री क्रिकेट बोर्ड (टीसीसीबी) को स्थानांतरित कर दिया गया.

मेरिलबोन क्रिकेट क्लब में दो तरह की सदस्यता का प्रावधान है पहली आजीवन सदस्य और दूसरी सहयोगी सदस्य.

आजीवन सदस्यों को निम्न सुविधाएँ प्रदान की जाती है

- आजीवन सदस्य लॉर्ड्स में आयोजित सभी मैचों में उपस्थित रह सकता है.
- एमसीसी की वार्षिक आम बैठक में वोट डाल सकता है.
- क्लब के भविष्य सदस्यता के लिए उम्मीदवार मनोनीत कर सकता है.

रोहित शर्मा प्रो रेस्लिंग लीग में यूपी वरियर्स के सह-मालिक बनें

9 दिसंबर 2015 को भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा प्रो रेस्लिंग लीग की टीम यूपी वारियर्स के सह-मालिक बन गए. इस टीम में सुशील कुमार और जोगिन्दर कुमार जैसे भारतीय पहलवान शामिल हैं.

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के बाद शर्मा प्रो रेस्लिंग लीग में किसी टीम के सह- मालिक बनने वाले दूसरे सबसे बड़ा नाम हैं.

इसके साथ ही शर्मा फ्रेंचाइजी- आधारित लीग से जुड़ने वाले सचिन तेंदुलकर, महेन्द्र सिंह धौनी और विराट कोहली जैसे क्रिकेटरों की कतार में शामिल हो गए.

प्रो रेस्लिंग लीग

प्रो रेस्लिंग लीग (पीडब्ल्यूएल) प्रोस्पोर्टिफाई और भारतीय कुश्ती महासंघ की पहल है. यह अब तक की सबसे अमीर कुश्ती प्रतियोगिता है.

छह- शहरों की फ्रेंचाइजी प्रतियोगिता 10 दिसंबर 2015 से नई दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में शुरु होगी. प्रतियोगिता का सेमीफाइनल 25 और 26 दिसंबर 2015 को और फाइनल 27 दिसंबर 2015 को खेला जाएगा. प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे- 5 भारतीय और 4 विदेशी (5 पुरुष, 4 महिलाएं). लीग की छह टीमें इस प्रकार हैं-

- मंगलायतन यूनिवर्सिटी दिल्ली वीर
- यूपी वरियर्स

- हरियाणा हैमर्स
- पंजाब रॉयल्स
- रेवांता मुंबई गरुड़
- बेंगलुरु योद्धा

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने टायसन फ्यूरी से विश्व आईबीफ खिताब वापस लिया

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ (आईबीफ) ने ब्रिटिश हैवीवेट मुक्केबाजी चैम्पियन टायसन फ्यूरी से विश्व आईबीफ खिताब वापस लेने की 9 दिसंबर 2015 को घोषणा की. आईबीफ ने टायसन फ्यूरी से विश्व खिताब जीतने के दो हफ्ते से भी कम समय में इसे वापिस लेने की घोषणा की. फ्यूरी ने 28 नवंबर 2015 को व्लादीमिर क्लिश्को को अंकों के आधार पर हरा कर यह ख़िताब हासिल किया था.

संबंधित रिपोर्ट के अनुसार, टायसन फ्यूरी 8 दिसंबर 2015 को को व्याचेस्लाव के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के अनिवार्य मुकाबले में उतरना था लेकिन उसने क्लिश्को के खिलाफ दोबारा मैच खेलना पसंद किया. जिसपर आईबीएफ चैम्पियनशिप्स के चेयरमैन लिंडसे टकर ने उनसे आईबीएफ खिताब वापस लेने की घोषणा की.

स्पेन की कैरोलीन बनीं साल की सर्वश्रेष्ठ महिला बैडमिंटन खिलाड़ी

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल 07 दिसम्बर 2015 को इतिहास रचने से चूक गईं. उन्हें ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप के महिला एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में स्पेन की कैरोलीन मरीन से हार का सामना करना पड़ा. हालाँकि मुकाबले के आरम्भ में उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी.

कैरोलीन मरीन ने इस वर्ष पांच सुपर सिरीज हिताब जीते हैं. इस खिताबी दौड़ में उन्होंने चीन की जाओ युन्लेंद, भारत की सायना नेहवाल और चीन की बाओ यिजिन को मात दी.

मरीन ने सायना को एक घंटे दो मिनट में 16-21, 21-14, 21-7 से हराकर महिला एकल खिताब जीता. किसी वर्ल्ड सुपरसीरीज प्रीमियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहली बार पहुंची विश्व की तीसरी खिलाडी सायना ने

मैच में शानदार आगाज किया और पहले गेम में 11-6 की बढ़त बनाई और अंत मैच से उनकी पकड़ ढीली होती गयी. कैरोलीन मरीन इसे जीतने में सफल रहीं.

मरीन ने अपने करियर में पहली बार सायना को हराया है. इससे पूर्व तीन मौकों पर उन्हें सायना से हार का सामना करना पड़ा. पूर्व में केवल दो भारतीय खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद (2011) और प्रकाश पादुकोण (1980) ही ऑल इंग्लैंड ओपन का खिताब जीतने में सफल रहे हैं.

क्रिसन इल्युमज़िनोव ने विश्व शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया

क्रिसन इल्युमज़िनोव ने 7 दिसम्बर 2015 को विश्व शतरंज फेडरेशन (फिडे) के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया.

उन्होंने यह इस्तीफ़ा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी सीरिया शासन को सहायता पहुँचाने वाले लोगों की सूची में नाम आने पर दिया.

संयुक्त राज्य द्वारा इल्युमज़िनोव का नाम नवम्बर 2015 में जारी किया गया जिसमें कथित रूप से उन्हें सीरिया की सेंट्रल बैंक में हिस्सेदारी रखने का आरोपी बताया गया है. वे वर्ष 2012 में सीरिया गये थे जहां उन्होंने राष्ट्रपति असद के साथ शतरंज खेली थी.

इल्युमज़िनोव इससे पहले इराक एवं लीबिया के शासकों सद्दाम हुसैन एवं मुअम्मार गद्दाफी के साथ भी शतरंज खेलने एवं आपसी संबंधों को लेकर चर्चा में रहे हैं.

53 वर्षीय इल्युमज़िनोव वर्ष 1995 से फीडे के अध्यक्ष हैं. इसके अतिरिक्त वे वर्ष 1993 से 2010 तक रिपब्लिक ऑफ़ कलमीकिया के राष्ट्राध्यक्ष भी थे.

भारत के शीर्ष टेस्टक बल्ले बाज बने अजिंक्यं रहाणे

हाल में 08 दिसम्बर 2015 को हुई साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं. रैंकिंग में वे अब तक 14वें पायदान पर थे. विश्व रैंकिंग में वह 12वें स्थान पर हैं, जो उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

रहाणे श्रृंखला से पहले 26वें स्थान पर थे लेकिन चौथे टेस्ट में 127 और नाबाद 100 रन बनाने के बाद वह

12वें स्थान पर आ गए. कप्तान विराट कोहली दो पायदान चढ़कर 14वें स्थान पर हैं. टेस्टे बल्लेरबाजों की ताजा रैंकिंग में अजिंक्य़ रहाणे भारत के शीर्ष पर विराजमान हैं. उन्होंने यह स्थान विराट कोहली को पीछे छोड़ कर हासिल किया है.

गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के बायें हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में पहली बार शीर्ष दस में शामिल हो गए हैं. वे चार पायदान चढ़कर सातवें स्थान पर हैं जबकि, आर अश्विन आल राउंडर की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए. जडेजा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला से पहले 30वें स्थान पर थे, लेकिन श्रृंखला में लगातार अच्छे प्रदर्शन से स्थान क्रम ऊपर आ गया है.

तेज गेंदबाज उमेश यादव 13 पायदान चढ़कर कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 32वीं रैंकिंग पर हैं जिन्होंने आखिरी टेस्ट में पांच विकेट लिए. गेंदबाजों की रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन शीर्ष पर बने हुए हैं। भारतीय बल्लेबाजों में मुरली विजय चार पायदान गिरकर 16वें और चेतेश्वर पुजारा दो पायदान गिरकर 17वें स्थान पर पहुँच गए है.

आखिरी टेस्ट में 56 रन बनाने और सात विकेट लेने वाले आर अश्विन पांच पायदान चढ़कर बल्लेबाजों की सूची में 46वें स्थान पर आ गए. वह हरफनमौलाओं की सूची में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को पछाड़कर शीर्ष पर आए हैं.

फीफा रेफरी एसके भट्टाचार्य का निधन

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) के पूर्व रेफरी एसके भट्टाचार्य का पश्चिम बंगाल के चंदनपुर में 8 दिसम्बर 2015 को निधन हो गया.

वह 87 वर्ष के थे.

देश के मशहूर फुटबॉल रेफरी रहे भट्टाचार्य ने तेहरान में हुये 1972 एशिया कप फाइनल्स में टूर्नामेंट की निगरानी की थी.

वह भारत में आयोजित देश के शीर्ष फुटबॉल टूर्नामेंटों के फाइनल मुकाबलों में रेफरी रहे थे जिसमें डुरंड कप, डीसीएम ट्राफी और आईएएफ शील्ड टूर्नामेंट शामिल हैं.

पुणे और राजकोट सीएसके एवं आरआर के स्थान पर आईपीएल की अंतरिम फ्रैंचाइज़ी चयनित

8 दिसम्बर 2015 को वर्ष 2017 तक के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सेशन के लिए पुणे एवं राजकोट को सीएसके एवं आरआर टीमों के स्थान पर अंतरिम फ्रैंचाइज़ी चयनित किया गया. यह टीमें निलंबित की गयी चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) एवं राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के स्थान पर चयनित की गयी हैं.

सीएसके एवं आरआर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2013 के भ्रष्टाचार मामले में लिप्त पाए जाने पर वर्ष 2017

तक निलंबित कर दिया गया था. जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर दो साल का बैन लगाया था.

पुणे टीम कोलकाता के उद्योगपति संजीव गोयनका ने 20 करोड़ में खरीदी है जबकि वहीं मोबाइल कंपनी इंटेक्स राजकोट की मालिक बनी है.

वर्ष 2016 का आईपीएल सीज़न 9 अप्रैल से 29 मई 2016 तक आयोजित किया जायेगा. इसका पहला और आखिरी मैच मुंबई में खेला जायेगा जबकि नए खिलाडियों का चयन बेगलुरु में 6 फरवरी 2016 में किया जायेगा.

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने टायसन फ्यूरी से विश्व आईबीफ खिताब वापस लिया

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ (आईबीफ) ने ब्रिटिश हैवीवेट मुक्केबाजी चैम्पियन टायसन फ्यूरी से विश्व आईबीफ खिताब वापस लेने की 9 दिसंबर 2015 को घोषणा की. आईबीफ ने टायसन फ्यूरी से विश्व खिताब जीतने के दो हफ्ते से भी कम समय में इसे वापिस लेने की घोषणा की. फ्यूरी ने 28 नवंबर 2015 को व्लादीमिर क्लिश्को को अंकों के आधार पर हरा कर यह ख़िताब हासिल किया था.

संबंधित रिपोर्ट के अनुसार, टायसन फ्यूरी 8 दिसंबर 2015 को को व्याचेस्लाव के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के अनिवार्य मुकाबले में उतरना था लेकिन उसने क्लिश्को के खिलाफ दोबारा मैच खेलना पसंद किया. जिसपर आईबीएफ चैम्पियनशिप्स के चेयरमैन लिंडसे टकर ने उनसे आईबीएफ खिताब वापस लेने की घोषणा की.

पंजाब मार्शल टीम ने चैपियंस टेनिस लीग-2015 का ख़िताब जीता

पंजाब मार्शल टीम ने 6 दिसंबर 2015 को संपन्न चैपियंस टेनिस लीग-2015 का ख़िताब जीता. 23 नवंबर 2015 से 6 दिसंबर 2015 तक देश भर के विभिन्न हिस्सों में हुई टेनिस लीग के फाइनल में पंजाब ने हैदराबाद एसेस को हराकर खिताब अपने नाम किया.

देशी और विदेशी खिलाडियों से सजी पंजाब मार्शल ने फाइनल मैच में 22 और हैदराबाद ने 21 अंक हासिल किए. सी.टी.एल.-2 में विजेता टीम को एक करोड़ रुपए जबकि उप विजेता टीम को 50 लाख रुपए ईनामी

राशि मिली. पंजाब टीम के सदस्य साकेत मिनानी लगातार दूसरे वर्ष श्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी बने.

विदित हो कि विपक्षी हैदराबाद टीम में दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस थी, जिनकी मौजूदगी के बाद भी मार्शल ख़िताब जीतने में सफल हुए. मार्टिना ने टूर्नामेंट में 70 प्रतिशत जीत दर्ज की. उन्हें सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी घोषित किया गया.

प्रीमियर बैडमिंटन लीग हेतु खिलाडियों की नीलामी में साइना और ली चोंग वेई सबसे महंगे खिलाड़ी बनें

भारत में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ प्रीमियर बैडमिंटन लीग हेतु खिलाडियों की नीलामी में साइना और ली चोंग वेई सबसे महंगे खिलाड़ी बनें. प्रीमियर बैडमिंटन लीग में खिलाडियों की नीलामी के तहत विश्व की नंबर दो बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और ली चोंग वेई को 8 दिसंबर 2015 को हुई नीलामी में सबसे अधिक एक लाख डॉलर की बोली लगी जबकि पीवी सिंधू और किदांबी श्रीकांत को क्रमश: 95000 और 80000 डॉलर में खरीदा गया.

विश्व की नंबर दो महिला खिलाड़ी साइना और पूर्व नंबर एक पुरुष खिलाड़ी ली चोंग वेई को क्रमश: लखनऊ के अवध वारियर्स और हैदराबाद हंटर्स ने लगभग 66 लाख 70 हजार 745 रुपये में खरीदा. वहीं पूर्व विश्व चैम्पियनशिप की दो बार की कांस्य पदक विजेता सिंधू के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की टीमों ने आक्रामक बोली लगाई, लेकिन अंतत: उन्हें चेन्नई स्मैशर्स ने लगभग 63,37,207 रूपये में खरीदा.

विदित हो कि भारतीय बैडमिंटन संघ ने वर्ष 2013 में पहली बार इंडियन बैडमिंटन लीग का आयोजन किया था. इसके बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में यह लीग नहीं हुई. इस टूर्नामेंट की शुरुआत अब पीबीएल के रूप में दोबारा हो रही है. इसकी शुरुआत 2 जनवरी 2015 को मुंबई में होगी.

आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने गैरी कर्स्टन को मुख्य प्रशिक्षक पद से हटाया

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने 7 दिसंबर 2015 को गैरी कर्स्टन को मुख्य प्रशिक्षक पद से हटाने की घोषणा की. कर्स्टन को आईपीएल के आगामी नौवें संस्करण के पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के मुख्य कोच के पद से हटा दिया गया. दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ अपने वे आईपीएल के

पिछले दो सीजन से साथ थे. जिसमें वह खास कुछ नहीं कर सके एवं आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम सबसे निचले दो पायदानों पर रही.

विदित हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोच के रूप में बेहद सफल रहे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज गैरी कर्स्टन ने टीम इंडिया को वर्ष 2011 का विश्व कप जिताने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी.

भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया

भारत ने दिसंबर 2015 के प्रथम सप्ताह में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया. भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराने के कारण आईसीसी रैंकिंग में नंबर दो का स्थान प्राप्त किया.

भारत ने पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए यह जगह हासिल की. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गयी श्रृंखला जीतने के बाद भारतीय टीम को 10 अंक मिले जिसके कारण वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंची.

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग सूची:

क्रम	**संख्या- टीम**	**कुल अंक**
1.	दक्षिण अफ्रीका-	114
2.	भारत-	110
3.	आस्ट्रेलिया-	109
4.	पाकिस्तान-	106
5.	इंग्लैंड-	99
6.	न्यूजीलैंड-	95
7.	श्रीलंका-	93
8.	वेस्ट इंडीज-	76
9.	बांग्लादेश-	47
10.	जिम्बाब्वे-	5

ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी विश्व लीग फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराया

सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में 6 दिसंबर 2015 को आयोजित 2014 - 2015 पुरुषों के हॉकी विश्व लीग फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर ख़िताब पर कब्जा किया. पिछले टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चौथा स्थान हासिल कर पाया था.

भारत ने दुनिया की नंबर दो और गत चैम्पियन नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से पराजित किया और टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा. भारत को इस जीत के लिए कांस्य पदक दिया गया है.

भारत ने किसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 33 साल बाद पदक का सूखा भी खत्म किया है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में आखिरी बार पदक 1982 में एम्सटर्डम में खेली गई चैंपियन्स ट्राफी में जीता था.

पुरुषों 2014-15 की एफआईएच हॉकी विश्व लीग के बारे में<

- पुरुषों की 2014-15 अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) हॉकी विश्व लीग पुरुषों के लिए एफआईएच हॉकी विश्व लीग फील्ड हॉकी चैम्पियनशिप का दूसरा संस्करण है.
- यह रायपुर भारत में दिसंबर 27 नवंबर 2015 से से 6 दिसंबर 2015 तक आयोजित किया गया.
- प्रतियोगिता के सेमीफाइनल को भी 2016 के ग्रीष्मकालीन में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालीफायर के रूप में प्रस्तुत किया गया.
- एफआईएच नेशनल एसोसिएशन का प्रत्येक सदस्य को टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने का अधिकारी था. भाग लेने के लिए प्रविष्टियों के बाद प्रतिस्पर्धा के लिए 56 टीमों की घोषणा की गयी.
- हॉकी विश्व लीग के फाइनल के लिए कुल 8 टीम मुकाबले में रहीं. इन टीमों में भारत, जर्मनी, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन हैं.

भारत ने जीता इंडो-पाक निःशक्त क्रिकेट सीरीज

शारीरिक रूप से नि:शक्त खिलाड़ियों की टी-20 इंडो-पाक दोस्ताना क्रिकेट सीरीज के दूसरे मैच में 6 दिसम्बर 2015 को भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया.

दिल्ली के रोशनआरा क्लब स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित ओवरों में 131 रन बनाएं. भारतीय टीम की तरफ से रवि पाटिल और इकबाल खान ने दो-दो विकेट लिए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने केवल दो विकेट खोकर 10 गेंदे शेष रहते आठ विकेट से आसान जीत दर्ज की.

भारतीय टीम की ओर विक्रांत केनी ने 42 रन और उत्पल मजूमदार ने 30 रन बनाए.

अपना पदार्पण मैच खेल रहे ओमवीर ने 27 रनों का योगदान दिया.

पाकिस्तान टीम की ओर से 33 गेंदों पर 47 रनों की जोरदारी पारी खेलने वाले उमर कमाल को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

बुब्बा वाटसन हीरो वर्ल्ड चैलेंज चैम्पियन बने

दो बार के मास्टर्स विजेता बुब्बा वाटसन ने 7 दिसम्बर 2015 को आखिरी दौर में छह अंडर 66 का स्कोर करके हीरो वर्ल्ड चैलेंज गोल्फ खिताब जीत लिया.

इस दौरान भारत के अनिर्बान लाहिड़ी संयुक्त 17वें और आखिरी स्थान पर रहे .

वाटसन ने कुल 25 अंडर 263 का स्कोर किया. वह पिछले साल के विजेता जोर्डन स्पियेथ को हराया जो चौथे स्थान पर रहे. पैट्रिक रीड दूसरे और रिकी फोलेर तीसरे स्थान पर रहे.

पीजीए टूर पर बायें हाथ के चुनिंदा गोल्फरों में शुमार वाटसन पिछले 10 टूर्नामेंटों में छठी बार शीर्ष पांच में रहे.

लाहिड़ी चौथे दौर में इवन पार 72 के स्कोर के साथ दो पायदान खिसक गए . वह और एशिया के ही हिदेकी मत्सुयामा आखिरी स्थान पर रहे.

वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल: भारत ब्रिटेन को 2-1 से हराकर, सेमीफाइनल में पहुंचा

भारतीय हॉकी टीम ने 3 दिसम्बर 2015, गुरुवार को हॉकी वर्ल्ड लीग (एचडब्ल्यूएल) के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टूर्नामेंट में अविजित रहे ब्रिटेन को 2-1 से हरा दिया. भारतीय टीम पूरे 35 वर्षों बाद ब्रिटिश टीम

को हराने में सफल हुई. जीत के साथ ही टीम इंडिया एचडब्ल्यूएल फाइनल के सेमीफाइनल में पहुँच गई.

सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम में भारत की ओर से दोनों गोल वीआर रघुनाथ और तलविंदर सिंह ने किए. ब्रिटेन मात्र एक गोल कर सका. भारतीय टीम का सेमीफाइनल में बेल्जियम और अर्जेंटीना में से विजेता टीम से मुकाबला होगा.

जीत में गोलकीपर की भूमिका

भारतीय टीम की जीत में स्टार गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कई शानदार बचाव कर जीत में अहम योगदान किया. भारत की ओर से पेनाल्टी कॉर्नर से किए गए गोल से 1-0 की बढ़त मिली.

अमिताभ बच्चन बने आईपीटीएल की सिंगापुर स्लैमर्स के सह-मालिक

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 3 दिसम्बर 2015 को इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग (आईपीटीएल) की फ्रेंचाइजी ओयूई सिंगापुर स्लैमर्स की साझेदारी में स्वामित्व हासिल करने की घोषणा की.

मौजूदा सत्र के आखिरी दिन सिंगुपार स्टेडियम में 20 दिसंबर को होने वाले मैच के दौरान अमिताभ स्टेडियम में मौजूद भी रहेंगे.

यूडी ग्रुप और अमिताभ के पास अब संयुक्त रूप से स्लैमर्स का स्वामित्व होगा और आईपीटीएल के दूसरे संस्करण में हिस्सा लेने वाली आठ टीमों में यह टीम शामिल होगी. विदित हो सिंगापुर 18 से 20 दिसंबर के बीच आईपीटीएल-2 के अंतिम चरण की मेजबानी करेगा.

ज्ञात हो दूसरी विश्व वरीयता प्राप्त शीर्ष ब्रिटिश खिलाड़ी एंडी मरे, स्विट्जरलैंड के अग्रणी खिलाड़ी स्टानिस्लास वावरिंका, निक किर्जियोस, डस्टिन ब्राउन, कार्लोस मोया, मार्सेलो मेलो, कैरोलीना प्लिस्कोवा और बेलिंडा बेंसिक स्लैमर्स का टीम का हिस्सा हैं.

रॉबर्ट लेवांडोवस्की को नौ मिनट में पांच गोल करने पर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया

पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोवस्की ने नौ मिनट में पांच गोल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया. इस प्रदर्शन द्वारा बायर्न म्यूनिख ने वूल्फसबर्ग टीम को 5-1 से हरा दिया. इस रिकॉर्ड को 30 नवम्बर 2015 को

अधिकारिक रूप से गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया.

लेवांडोवस्की को बायर्न म्यूनिख मैदान पर आयोजित एक विशेष प्रेस कांफ्रेस के दौरान चार अधिकारिक गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया.

रिकॉर्ड

- 22 सितंबर 2015 को पोलैंड के इस खिलाड़ी ने वूल्फसबर्ग के खिलाफ खेलते हुए नौ मिनट में पांच गोल किये, यह यूरोपियन फुटबॉल लीग के इतिहास में सबसे तेज़ गोल हैं.
- बुंदेसलीगा के इतिहास में उन्होंने सबसे तेज़ हैट्रिक तोड़ने (3 मिनट 22 सेकेंड), सबसे तेज़ चार गोल (पांच मिनट 42 सेकेंड), सबसे तेज़ पांच गोल (8 मिनट 59 सेकेंड) एवं सबसे अधिक गोल (5 गोल) करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

लेवांडोवस्की ने वर्सोविया से अपने करियर की शुरुआत की जहां उन्होंने सात वर्ष तक खेला. इसके बाद वे डेल्टा वॉरसॉ टीम के साथ खेले जहां उन्होंने चार गोल किये.

3 जनवरी 2015 को उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ पांच वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किये. वे 9 जुलाई 2014 से बायर्न म्यूनिख के अधिकारिक खिलाड़ी के रूप में मौजूद हैं.

डोपिंग रोधी एजेंसी में सुधार हेतु रूस और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) सहमत हुए

रूस और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा मास्को घोटाले में फंसी रूस डोपिंग रोधी एजेंसी (RUSADA) में सुधार के लिए सहमति व्यक्त की गयी है.

रूस के खेल मंत्री विटाली मुतकों ने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में वाडा के महानिदेशक डेविड हाउमैन के साथ मुलाकात के तीन दिन बाद 1 दिसम्बर 2015 को रूस डोपिंग रोधी एजेंसी (RUSADA) में सुधार करने की घोषणा की.

विटाली मुतकों ने योजना के विवरण का खुलासा नहीं किया तथा इसकी विस्तृत जानकारी रोडमैप के कार्यान्वयन के उपरांत सार्वजनिक किए जाने की सूचना दी.

उन्होंने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी सेवा में सुधार के लिए विदेशी भागीदारों के साथ सक्रिय सहयोग देने की भी बात की.

पृष्ठभूमि

द इन्टरनेशनल एसोसिएसन ऑफ़ एथलेटिक्स फेडरेशन(आईएएएफ) ने नवंबर 2015 के तीसरे सप्ताह में वाडा स्वतंत्र आयोग द्वारा 9 नवंबर 2015 को रूस की डोपिंग रोधी कार्यक्रम के विषय में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद रूस डोपिंग रोधी एजेंसी को निलंबित कर दिया था.

रूस की डोपिंग रोधी एजेंसी ने इस सम्बन्ध में यह स्वीकार किया कि वह कमियों को दूर कर रही है और डोपिंग से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है.

अनिल कुंबले का मुंबई इंडियंस के 'चीफ मेंटर' पद से इस्तीफा

पूर्व भारतीय लेग स्पिनर खिलाड़ी अनिल कुंबले ने 30 नवम्बर 2015 को तत्काल प्रभाव से मुंबई इंडियंस के 'चीफ मेंटर' पद से त्यागपत्र दे दिया.

इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) की इस फ्रेंचाइजी के साथ वह जनवरी 2013 से जुड़े थे. उनका यह फैसला बीसीसीआई के हितों के टकराव पर कड़े रवैये के बाद आया है.

विदित हो मेंटर के रूप में कार्य करते हुए वर्ष 2013 में उनकी टीम मुंबई इंडियंस ने आईपीएल और चैंपियन्स लीग जीती. मुंबई इंडियंस ने इसके बाद वर्ष 2015 में भी आईपीएल जीता.

ज्ञात हो कुम्बले वर्तमान में कमेंट्री के लिए स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं.

कार्पोरेट

मांग पर किराना सेवा देने वाले पेपरटैप ने जिफ्फस्टोर का अधिग्रहण किया

गुड़गांव की मांग पर किराना सेवा देने वाले पेपरटैप ने 21 दिसंबर 2015 को बेंगलुरु की स्थानीय किराना वितरण स्टार्टअप जिफ्फस्टोर का अधिग्रहण कैश- एंड- स्टॉक डील में कर लिया. हालांकि सौदे के विवरण का खुलासा नहीं किया गया है.

सौदे की शर्तों के अनुसार जिफ्फस्टोर अपने सभी काम का विलय पेपरटैप में करेगा. इसके अलावा, इसके 40 सदस्यों की टीम पेपरटैप के गुड़गांव और बेंगलुरु कार्यालय में शामिल किए जाएंगे.

जिफ्फस्टोर के बारे में

- जिफ्फस्टोर की स्थापना इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के ड्रॉप- आउट शमील अब्दुल्ला ने अपने दोस्तों अस्विन राम, सतीश बसवराज और संदीप श्रीनाथ के साथ मिलकर 2013 में की थी.
- यह टीलैब्स इन्क्यूबेटर का भी हिस्सा था और 2014 में इसने यूनिटस सीड फंड और टाइम्स इंटरनेस से कुल 500000 अमेरिकी डॉलर का अनुदान लिया था.

पेपरटैप के बारे में

- पेपरटैप की स्थापना नवनीत सिंह और मिलिंद शर्मा ने नवंबर 2014 में की थी.
- यह 18 शहरों में काम करता है और एक दिन में 20000 ऑर्डर पूरा करता है.
- इसने 97-98 फीसदी की दर से पूर्ति का दावा किया है.

अमेरिकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी अरिसेंट ने नैसकॉम फाउंडेशन के साथ समझौता किया

अमेरिकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी अरिसेंट ने नैसकॉम फाउंडेशन के साथ 1 दिसंबर 2015 को एक समझौता किया. यह समझौता अरिसेंट रोजगार कार्यक्रम (Aricent Employability Programme) हेतु किया गया. इस सीएसआर समर्थित प्रोग्राम के तहत 2500 इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार के अवसर उपलब्द होंगे.

विदित हो कि अरिसेंट रोजगार कार्यक्रम के तहत कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के स्नातक छात्रों को इसके हेतु पेशकश की जाएगी. चयनित छात्रों को साफ्टवेयर विषय विशेष में प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे संबंधित क्षेत्र में रोजगार पा सकें.

बायोकॉन लिमिटेड ने भारत में हेपेटाइटिस-सी दवा का जेनेरिक संस्करण लांच किया

बायोकॉन लिमिटेड ने 24 दिसम्बर 2015 को भारतीय बाजार में हेपेटाइटिस-सी दवा का जेनेरिक संस्करण लांच किया. हरवनी दवा का जेनेरिक संस्करण सीआईएमआईवीआईआर-एल (CIMIVIR-L) ब्रांड के तहत बेचा जाएगा.

इसका दिन में एक बार उपयोग करना होगा. कंपनी का दावा है कि यह हेपेटाइटिस-सी से संक्रमित लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प होगा. सीआईएमआईवीआईआर-एल यह लेडीपेसविर 90 एमजी का सोफोसबुविर 400 एमजी मिश्रण है, जो एक अमेरिकी मेडिकल कंपनी जिलेड के उत्पाद का विकल्प है.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा भारत में इस कांबिनेशन को जिलेड के लाइसेंस के तहत बेचने की अनुमति दी गयी.

हेपेटाइटिस- सी

हेपेटाइटिस सी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस सी वायरस एचसीवी (HCV) की वजह से होता है और यकृत को प्रभावित करता है. हेपेटाइटिस सी वायरस रक्त से रक्त के संपर्क द्वारा फैलता है. शुरुआती संक्रमण के बाद अधिकांश लोगों में यदि कोई हों, तो बहुत कम लक्षण होते हैं, हालांकि पीड़ितों में से 85% के यकृत में वायरस रह जाता है.

हेपेटाइटिस सी वायरस फैलने का कारण

- सौंदर्य चिकित्सा जहां मृत त्वचा की कोशिकाएं गिरी होती हैं उसकी सतह पर कई दिनों तक हेपेटाइटिस सी का वायरस पनपता रहता है.
- दवा इंजेक्ट करने वाले उपकरणों (सुई, हीटिंग चम्मच आदि) को शेयर करने से. यह उप-सहाराई अफ्रीका के बाहर एचसीवी के संचरण का प्राथमिक स्रोत है.
- किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित सेक्स से.
- कभी-कभार प्रसव के दौरान संक्रमित माता से उसके बच्चे में हो सकता है. यह खतरा तब और भी बढ़ सकता है जब माता एचआईवी से भी संक्रमित हो.
- संक्रमित रक्त से.
- नाक से कोकीन का इस्तेमाल करने वाले उपकरणों को शेयर करने से.
- हाथ पर टैटू गुदवाने, संक्रमित खून चढ़वाने, दूसरे का रेजर उपयोग करने आदि की वजह से हेपेटाइटिस सी होने की संभावना अधिक रहती है.

लक्षण

- लोगों में हेपेटाइटिस सी से संक्रमित होने पर भी कोई लक्षण नहीं दिखाई देते.
- अमूमन इसके लक्षण 15 से 150 दिन में विकसित होते हैं.
- जिन लोगों में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, ऐसे संक्रमित लोग ही वायरस को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
- इसके कुछ लक्षणों में भूख में कमी, पीलिया, उल्टी, अनिद्रा और अवसाद शामिल हो सकते हैं.

टेक महिंद्रा ने एनएफसी आधारित मोबोमनी की शुरुआत की

टेक महिंद्रा लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2015 को भारत का पहला कांटेक्टलेस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, मोबोमनी आरंभ किया.

कंपनी का दावा है कि यह देश की पहली सेवा है जिसमें नीयर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) निहित होगी, इसके द्वारा दो एनएफसी सक्षम उपकरणों के बीच रेडियो संपर्क स्थापित किया जायेगा.

मोबोमनी

- मोबोमनी एक प्रीपेड वॉलेट है जिसे एनएफसी कांटेक्टलेस टैग के तहत जारी किया गया है.
- इसे टैप एंड पे द्वारा एनएफसी सक्षम व्यापारिक प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोग किया जायेगा जिससे वस्तु विनिमय एवं खरीददारी करना और भी आसान हो सकता है.
- इसके अंतर्गत उपभोक्ता रिटेल नेटवर्क पर 1000 रुपये का भुगतान करके ई-कैश सेवा का लाभ उठा सकते हैं.
- •डिजिटल वॉलेट में पूंजी ट्रान्सफर होने पर उपभोक्ता टैप एंड पे सेवा द्वारा रिचार्ज, बिलों के भुगतान तथा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं.
- उपभोक्ता की सुरक्षा हेतु सभी हस्तांतरण एवं डाटा सुरक्षित रखे जायेंगे.

सत्यवती बरेरा बिग फोर समूह की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त

सत्यवती बरेरा को 27 दिसंबर 2015 को भारत में बिग फोर एकाउंटिंग फर्म की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया. वे यह स्थान प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं.

वे 1 जनवरी 2016 से यह पद ग्रहण करेंगी. उन्हें नील विल्सन के स्थान पर नियुक्त किया गया है जो पीडब्ल्यूसी के वैश्विक कार्यक्रम के तहत लंदन जा रहे हैं. वे दीपक कपूर के बाद संस्था में दूसरे स्थान पर होंगी.

सत्यवती बरेरा

- अभी वे पीडब्ल्यूसी में उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रबंधन सहायक हैं.
- वे पीडब्ल्यूसी के साथ 35 वर्षों से कार्यरत हैं.
- उन्होंने वर्ष 1980 में ऑडिट प्रैक्टिस से पीडब्ल्यूसी में करियर आरंभ किया.
- वे वर्ष 1995 से फर्म की पार्टनर हैं.
- वे संस्था के लिए भारत में कंसल्टेंसी सेवा भी देती रही हैं.

बिग फोर

यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा सेवा प्रदाता है जो ऑडिट, एश्योरेन्स, टैक्स, कंसल्टिंग, एडवाइजरी, कॉरपोरेट फाइनेंस एवं लीगल सेवाओं के लिए जाना जाता है. वे विभिन्न पब्लिक कंपनियों के लिए ऑडिट करते हैं.

वे विश्व भर में अकाउंटेंट सेवाओं की सैंकड़ों रोज़गार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तथा इस क्षेत्र में विकास कार्यों में भी भागीदार बनते हैं.

निम्नलिखित कम्पनियां इस अन्तरराष्ट्रीय समूह की सदस्य हैं:

1. डिलॉयट टच तोमस्तु लिमिटेड
2. प्राइसवाटरहाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी)
3. अर्नस्ट एंड यंग (ई एंड वाई)
4. लायनवेल्ड पीट मर्विक जिओर्डलर (केपीएमजी)

बीडीओ एवं ग्रांट थोर्नटन क्रमशः पांचवें एवं छठे भागीदार हैं.

रिलांयस डिफेन्स लिमिटेड और रूस अलमाजआंते के बीच एयर डिफेन्स मिसाइल प्रणाली विकसित करने हेतु समझौता

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलांयस डिफेन्स लिमिटेड और एयर डिफेन्स मिसाइल प्रणाली विकसित करने वाली रूस की अग्रणी कंपनी अलमाजआंते ने 24 दिसंबर, 2015 को भारतीय रक्षा बलों के लिए आवश्यक हवाई रक्षा मिसाइल व राडार प्रणालियों की संपूर्ण श्रृंखला पर पर मिलकर काम करने का निर्णय किया.

इस संबंध में एक कंपनी के समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के मौके पर हस्ताक्षर किए गए.

भागीदारी का विवरण :

रिलायंस और अलमाजआंते ने एयर डिफेन्स मिसाइल प्रणालियों की पहचान की है जिसमें टीओआर-1एम मिसाइल प्रोग्राम, राडार व ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम्स शामिल है.

रूस की कंपनी अलमाजआंते ने एस-400 ट्रायंफ हवाई रक्षा प्रणाली विकसित की है जिसे भारत ने करीब 40,000 करोड़ रुपये में खरीदने की योजना बनाई है.

रिलायंस और अलमाजआंते की साझेदारी से सहयोग गहरी उन्नयन आधुनिकीकरण, मरम्मत, ऑफसेट के निष्पादन, पुर्जों की आपूर्ति के साथ-साथ अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का विस्तार होगा.

यह साझेदारी भारत पहल में केन्द्र सरकार के मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगी.

प्रस्तावित साझीदारी दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.

रिलांयस डिफेन्स लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.

विप्रो ने अमेरिकी कंपनी विटिओस का अधिग्रहण करने की घोषणा की

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने 13 करोड़ डॉलर में अमेरिकी कंपनी विटिओस के अधिग्रहण करने की घोषणा की.

इस अधिग्रहण से देश की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो को पूंजी बाजार के आउटसोर्सिंग दायरे में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी. यह अधिग्रहण मार्च 2016 के अंत तक पूरा होने की संभावना है.

अधिग्रहण के बाद भी विटोस अपनी ब्रांड आईडी को रिटेन करेगी और साथ ही इसकी मैनेजमेंट टीम द्वारा किए जा रहे बिजनेस में भी कोई बदलाव नहीं होगा. कंपनी विप्रो के साथ मिलकर के अपने असैट मैनेजमेंट बिजनेस का भी विस्तार करेगी.

विटिओस कंपनी की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूजर्सी के सॉमरसेट में स्थित है, जो वैकल्पिक निवेश प्रबंधन (एआईएम) के क्षेत्र को अपनी बिजनेस प्रोसेस ऐज ए सर्विस (बीपीएएएस) सेवाएँ उपलब्ध कराती है.

विटोस पोस्ट ट्रेड ऑपरेशन के बाद कस्टमर्स को असेट, करेंसी, कॉर्डर अथवा स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को प्रोसेस आउटसोर्स करती है. विटोस शैडो अकाउंटिंग प्रोसेस में प्रमुख कंपनी है जो कि पूरे एशिया, यूरोप और यूएस में अपने 400 कर्मचारीयों के जरिए सर्विस देने का काम करती है. टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूरशन में विटोस एक प्रमुख कंपनी है.

आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग हेतु आईआरसीटीसी के साथ गठबंधन किया

आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी वेबसाइट के जरिए रेल टिकटों की बिक्री करने के लिए 23 दिसंबर 2015 को रेलवे के ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी के साथ गठबंधन किया.

इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है, जिसने अपनी वेबसाइट पर ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई.

निजी क्षेत्र के सबसे बड़ा बैंक की अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और प्रीपेड डिजिटल वॉलेट पर रेल टिकटों की बुकिंग की सुविधा शुरू करने की भी योजना है.

इस सेवा का लाभ लेने के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल नंबर से बैंक की वेबसाइट पर वन-टाईम पंजीकरण करना होता है और आईआरसीटीसी के साथ उपयोगकर्ता आईडी पंजीकृत करानी होती है. इसके पश्चात वे बैंक की वेबसाइट से सीधे टिकट खरीद सकते है.

किसी भी बैंक के ग्राहक आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट से इस सेवा का उपयोग कर ऑनलाइन रेल टिकट बुक कर सकते हैं.

उपयोगकर्ता किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग खाता, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रेल टिकट के लिए भुगतान कर सकते हैं.

इस सेवा के जरिए उपयोगकर्ता ट्रेन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, ई-टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन रद्द कर सकते हैं और अपनी पीएनआर स्थिति देख सकते हैं.

इस वेबसाइट पर विभिन्न सेवाओं से संबंधित नवीनतम जानकारियां उपलब्ध होंगी.

इस वेबसाइट को भारतीय रेलवे की रिजर्वेशन प्रणाली से रियल टाईम आधार पर सीधे जोड़कर ट्रेन विकल्प व टिकट उपलब्धता व अन्य सेवाएं हासिल की जा सकती है.

पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने पांच ब्रांड्स का अधिग्रहण किया

पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पीईएल) कंज्यूमर प्राडक्ट्स डिविजन ने 23 दिसंबर 2015 को 92 करोड़ रुपये में ऑर्गेनॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एमएसडी बी. वी. के पांच ब्रांड्स के अधिग्रहण की घोषणा की.

इसका उद्देश्य ओवर-द-काउंटर स्वास्थ्य सेवा खंड की पेशकशें बढ़ाना है. पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अनुसार इस अधिग्रहण में मुख्य तौर पर पांच ब्रांड शामिल जिनमें नेचरोलैक्स, लैक्टोबेसिल और फारिजीम शमिल हैं. इन ब्रांड की भारतीय उपभोक्ताओं के बीच खासी मांग है. इन पांचों ब्रांडों के ट्रेडमार्क अधिकार भारत के लिए हासिल किए गए हैं.

पीरामल एंटरप्राइजेज के कार्यकारी निदेशक नंदिनी पीरामल के अनुसार कंपनी अपनी रणनीति के तहत ओवर द काउंटर बाजार में वर्ष 2020 तक तीन शीर्ष कंपनियों में शामिल होना चाहती है.

भारतीय रेल आईआईटी के साथ शोध केंद्र स्थापित करेगा

भारतीय रेल ने शोध केंद्र स्थापित करने के लिए 22 दिसम्बर 2015 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की विभिन्न शाखाओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. भारतीय रेल ने चयनित विश्वविद्यालयों में चार शोध केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी रूडकी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं.

- भारतीय रेल ने इससे पहले अप्रैल 2015 में मुंबई विश्वविद्यालय के साथ भी एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे.
- इन समझौतों से कम-से-कम खर्च में रेलवे संपत्ति के सदुपयोग के लिए समाधान हासिल किया जा सकेगा.
- भारतीय रेल को प्रौद्योगिकी का शुद्ध निर्यातक के रूप में तैयार करने की ओर यह कदम उठाया गया है.

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में पांच हजार करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) को अपनी विदेशी इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में पांच हजार करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी दी.

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने अपनी विदेश निवेश इकाई को अधिग्रहण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया था. इसके साथ ओवीएल का इक्विटी आधार बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो जाएगा. ओएनजीसी ने ओवीएल को यह कर्ज ऋण ब्याज पर दिया था.

गौरतलब है कि इस मंजूरी से ओएनजीसी विदेश का पूंजी आधार मजबूत होगा. इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा और विदेशों में अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएनटी) व्यवसाय शुरू करने के लिए ओएनजीसी की क्षमता में वृद्धि होगी.

मेक इन इंडिया: विवो ने ग्रेटर नोएडा में पहला प्रोडक्शीन प्लां ट लगाया

भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत चीन की मोबाइल हैंडसेट कंपनी विवो ने 22 दिसंबर 2015 को भारत में मैन्युीफैक्चसरिंग और एसेंबलिंग फैसिलिटी बनाने पर 125 करोड़ (12.5 करोड़ युआन) का इन्वेमटमेंट किया है. विवो ने ग्रेटर नोएडा में कंपनी प्रोडक्शऔन प्लां ट लगाया है, जिसकी क्षमता एक माह में 10 डिवाइज बनाने की है.

- यह यूनिट विवो स्मामर्टफोन की मैन्युसफैक्चहरिंग और एसेंबलिंग करने के साथ-साथ ज्याोदा रोजगार और इंपोर्ट पर विवो की निर्भरता को कम करेगी.
- विवो मोबाइल इंडिया की यह भारत में हमारी पहली यूनिट है. वर्तमान में यहं औपचारिक कर्मचारियों की संख्या दो सौ से अधिक है जो लगभग 2,200 तक बढाई जाएगी.
- विवो भारत में एक साल से बिजनेस कर रही है.
- कंपनी ने 30,000 वर्ग मीटर के प्लोंट में पहले चरण में करीब 125 करोड़ रुपए का इन्वेंस्ट0मेंट किया है.
- प्रोजेक्टे के पहले चरण में कई एसेंबलिंग लाइंस, क्वाणलिटी कंट्रोल लैब और वेयरहाउस शुरू किए गए है.
- इस यूनिट में कई मॉडल्सई जैसे Y11, Y21 और Y15S आदि की मैन्युसफैक्च रिंग की जाएगी.
- सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत माइक्रोमैक्स , लावा, जियोनी, वनप्ल्स और शाओमी ने भी देश में एसेंबलिंग शुरू कर दी है.

भारत में स्मार्टफ़ोन-

- भारत में मोबाइल फोन यूज़र्स की संख्या 90 करोड़ से अधिक है.
- लेकिन स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या सिर्फ 20 करोड़ है.
- हाल में भारतीय बाजार में स्मार्टफोन की मांग बढ़ी है जो भारत को विश्व में स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा बाजार बनाने को तैयार है.

ग्रॉसरी शॉपिंग सेवा पेपरटेप ने बेंगलुरु की डिलीवरी स्टार्टअप जिफसौर का अधिग्रहण किया

गुड़गांव स्थित ग्रॉसरी शॉपिंग (किराने की डिलीवरी) सेवा पेपरटेप ने 21 दिसंबर 2015 को बेंगलुरु की डिलीवरी

स्टार्टअप जिफसौर (Jiffstore) का अधिग्रहण किया. इस सौदे के विवरण का खुलासा नहीं किया गया.

सौदे की शर्तों के अनुसार जिफसौर का पूरी तरह से पेपरटेप में विलय हो जाएगा. इसके अलावा, जिफसौर की 40 सदस्यीय टीम पेपरटेप के गुड़गांव और बेंगलुरु कार्यालयों में शामिल हो जाएगी.

जिफसौर

- जिफसौर की स्थापना इंडियन बिजनेस स्कूल (आईएसबी) के ड्रॉप आउट शमील अब्दुल्ला, और उनके दोस्त अश्विन राम, सतीश बासवराज और संदीप श्रीनाथ द्वारा वर्ष 2013 में स्थापित किया गया था.
- यह टीलैब्स (TLabs) इनक्यूबेटर का हिस्सा भी था. वर्तनाम में पेपरटेप 100 मिलियन डॉलर कम्पनी बन चुकी है.

पेपरटेप

- पेपरटेप (PepperTap) नवंबर 2014 में नवनीत सिंह और मिलिंद शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था.
- यह 18 शहरों में कार्यरत है और पूरे दिन में करीब 20000 आर्डर को पूरा करता है.

आरकॉम और एयरसेल वायरलेस बिजनेस का विलय करेंगी

रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल ने 22 दिसम्बर 2015 को अपने वायरलेस बिजनेस का विलय करने की घोषणा की. दोनों कम्पनियाँ इस विलय को 90 दिन के अन्दर अंजाम देंगी. यह सौदा 35,000 करोड़ रुपये की इकाई के रूप में सामने आएगा.

- विलय के बाद टेलीकॉम मार्केट में वायरलेस सेवा प्रदाता आइडिया सेलुलर के बाद यह चौथी बड़ी कंपनी होगी.
- समझौते के बाद इकाई की आमदनी करीब 25,000 करोड़ रुपये सालाना और एबिट्डा यानी इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन और एमॉर्टाइजेशन से पहले मुनाफा 6,000-7,000 करोड़ रुपये का होगा.
- विलय के बाद दोनों कम्पनियाँ इकाई बोर्ड में सामान प्रतिनिधित्व और एकसमान होल्डिंग्स के मसौदे पर बातचीत कर रहे हैं.
- एयरसेल की प्रमोटर्स कंपनी मलेशिया की मैक्सिस कम्युनिकेशंस और सिंड्या सिक्योरिटीज एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट हैं.

- वायरलेस की तीसरी कम्पनी बनने के बाद आरकॉम, सिस्टेमा और एयरसेल की प्रासंगिक संपत्तियों को ट्रांसफर किया जाएगा.
- इस कंपनी के साथ करीब 15 करोड़ डॉलर के सब्सक्राइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, विभिन्न बैंड्स में स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स और इसके साथ जुड़ा कर्ज होगा.
- नयी इकाई के पास कंबाइंड स्पेक्ट्रम का करीब 19 पर्सेंट हिस्सा रहेगा.
- आरकॉम और सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने नवंबर में ऑल-स्टॉक डील में भी मर्जर का ऐलान किया था.
- विलय का मकसद 'देश में कंसॉलिडेशन और ऑपरेशनल और कैपेक्स संबंधी तालमेल से फायदा लेना और रेवेन्यू बढ़ाना है.'

रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में-

- रिलायंस समूह की प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड स्वर्गीय श्री धीरूभाई एच अंबानी द्वारा (1932-2002) स्थापित की गयी.
- रिलायंस समूह के पास वर्तमान में रुपये 91,500 करोड़ रुपये (15.3 बिलियन डॉलर) से अधिक मूल्य की संपत्ति है.
- रुपये 10,200 करोड़ रुपये (1.7 डॉलर) नकदी प्रवाह है और 4700 करोड़ रुपये (0.80 डॉलर) का शुद्ध लाभ है.
- कंपनी के 118 मिलियन से अधिक ग्राहक है.
- कंपनी की संचार श्रृंखला 21,000 शहरों और कस्बों और 400,000 से अधिक गांवों में है.

रॉनी स्क्रूवाला की कम्पनी एर्री ने अपाल्या टेक्नोलॉजीज़ का अधिग्रहण किया

उद्यमी रॉनी स्क्रूवाला एवं पूर्व मीडिया एग्जिक्यूटिव्स बी साईकुमार तथा अजय चाको की डिजिटल मीडिया कंपनी एर्री (Arre) ने 22 दिसंबर 2015 को हैदराबाद की वीडियो डिलीवरी कंपनी अपाल्या टेक्नोलॉजीज़ का एक कैश समझौते में अधिग्रहण किया.

इसके साथ ही आईडीजी वेंचर्स, सिस्को, कलारी कैपिटल सहित अपाल्या के मौजूदा इनवेस्टर्स फर्म से बाहर निकल गए हैं. समझौते के तहत अपाल्या के को-फाउंडर्स वामशी रेड्डी और शिवा को एर्री की पैरेंट कंपनी यू-डिजिटल में दो पर्सेंट स्वेट इक्विटी प्राप्त होगी.

एर्री को एक 'ओरिजिनल' डिजिटल कंटेंट कंपनी के तौर पर पेश किया जा रहा है जो वीडियो सीरीज, पॉडकास्ट और डॉक्युमेंट्री जैसी कई फॉर्मेट में कंटेंट प्रस्तुत करेगी.

अपाल्या के एक्विजिशन से एर्री को अपने डिजिटल कंटेंट बिजनेस में प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी को जोड़ने में मदद मिलेगी.

अपाल्या टेक्नोलॉजिज़

- अपाल्या चार देशों में 10 टेलीकॉम कंपनियों के साथ काम करती है. रेवेन्यू के लिहाज से मॉडल ब्रांडेड कंटेंट एंड सॉल्यूशंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांजैक्शंस/सब्सक्रिप्शंस के आधार पर बनाया जाएगा.
- कंपनी 16-30 आयु वर्ग के लोगों को टारगेट करने की योजना बना रही है. पिछले कुछ महीनों में इसने अपने साथ प्रॉडक्शन हाउसेज़, लेखक और स्ट्रिंगर्स को कंटेंट तैयार करने के लिए जोड़ा है.
- अपाल्या का रेवेन्यू 40 करोड़ रुपये का था और यह ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफे में थी. एर्री की योजना फरवरी 2016 में लॉन्च के समय सात वीडियो कार्यक्रम प्रसारित करने की है. इनमें देश का पहला डिजिटल रियल्टी शो शामिल होगा जो इंटरनेशनल शो री-जेंडर पर आधारित है.

टाटा मोटर्स शोध एवं विकास में निवेश के मामले में दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों की सूची में शामिल

भारत की प्रसिद्ध वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स को शोध एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश के मामले में दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों की सूची में शामिल किया गया. दिसंबर 2015 में यूरोपीय आयोग द्वारा जारी वर्ष 2015 के लिए वार्षिक औद्योगिक आरएंडडी निवेश सूची में टाटा मोटर्स को शामिल किया गया. टाटा मोटर्स इस सूची में 49 वें स्थान पर है.

शोध एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश के लिहाज से दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों की सूची में टाटा मोटर्स एकमात्र भारतीय कंपनी है. इस सूची में जर्मनी की फॉक्सवैगन शीर्ष पर है. वर्ष 2015 के लिए तैयार वार्षिक औद्योगिक आरएंडडी निवेश सूची में फॉक्सवैगन के बाद सैमसंग दूसरे स्थान पर है. उसके बाद क्रमश: माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और नोवार्टिस शीर्ष पांच में शामिल हैं.

वर्ष 2014 में टाटा मोटर्स इस सूची में 104 वें स्थान पर थी. इसके साथ ही सूची में वह शोध एवं विकास पर सबसे अधिक निवेश बढ़ाने वाली कंपनी रही है. उसका ज्यादातर शोध एवं विकास निवेश उसकी ब्रिटेन की अनुषंगी जगुआर लैंड रोवर में हुआ.

विदित हो कि यूरोपीय आयोग द्वारा जारी वर्ष 2015 के लिए जारी आरएंडडी निवेश के लिहाज से दुनिया की 2500 कंपनियों की विस्तारित सूची में कुल 26 भारतीय कंपनियां शामिल हैं. इस सूची में सबसे अधिक 829 कंपनियां अमेरिका से हैं. उसके बाद जापान से 360, चीन से 301, ताइवान से 114, स्विट्जरलैंड से 80 तथा कनाडा और इस्राइल से 27-27 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं.

सीआईआई औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2015

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 15 दिसंबर 2015 को 35 कंपनियों को औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया. इनमें 10 स्टार्ट-अप और 25 बड़ी और छोटी कंपनियां थी.

औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2015 की स्थापना सीआईआई द्वारा वर्ष 2014 में उद्योग क्षेत्रों में अभिनव भारतीय उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई.

शीर्ष 10 स्टार्टअप पुरस्कार

- कैपिटल नंबर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
- आडियो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
- राइट ट्रैक एडमिजन्ज प्राइवेट लिमिटेड
- फिनमार्ट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
- जीटी सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड
- अनन्या सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
- योमा मल्टीनेशनल सॉल्यूशंस
- कासा ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- साइबोर्ग साइबर फोरेंसिक एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
- फील गुड डिजाइन

विशेष श्रेणी के पुरस्कार

- विनिर्माण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप (अनन्या सीड्स प्राइवेट लिमिटेड)
- सेवा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप (राइट ट्रैक एडमिजन्ज प्राइवेट लिमिटेड)
- विनिर्माण क्षेत्र में पुरस्कार - बड़े उद्यम (जाइडस कैडिला)
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए पुरस्कार - बड़े उद्यम (यूफ्लेक्स लिमिटेड)
- विनिर्माण क्षेत्र लिए पुरस्कार- माइक्रो एवं लघु उद्यमों के (कोरेल टेक्नोलॉजी (आई) प्राइवेट लिमिटेड)
- सेवा क्षेत्र में बड़े उद्यम के लिए पुरस्कार (रॉबर्ट बॉश इंजीनियरिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड)

हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इंदुलेखा का अधिग्रहण करने हेतु मोसंस समूह के साथ समझौते किया

हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) ने 17 दिसंबर 2015 को मोसंस समूह के साथ समझौते की घोषणा की.

यह समझौता 330 करोड़ रुपए के ब्रांड इंदुलेखा का अधिग्रहण करने हेतु किया गया.

प्रस्तावित अधिग्रहण का उद्देश्य एचयूएल का पर्सनल केयर बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है.

इंदुलेखा के बारे में

इंदुलेखा आयुर्वेदिक तेल को वर्ष 2009 में शुरू किया गया था.

कुछ ही वर्षों में इन वर्षों में इंदुलेखा तेल ने विज्ञापन और ब्रांड निर्माण में निरंतर निवेश करके बाजार में अपनी जगह बना ली है

इंदुलेखा आयुर्वेदिक तेल को वर्ष 2014 में फिर से रीलांच किया गया.

इंदुलेखा ब्रांड की केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में एक मजबूत उपस्थिति है. इसको हाल ही में महाराष्ट्र में लांच किया गया.

इंदुलेखा ब्रांड ने 100 करोड़ रुपए का कारोबार किया और मार्च 2015 के अंत तक इसका लगभग 30 प्रतिशत का एबिटा मार्जिन था.

सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2015

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2015 स्थायी व्यवसाय में नई दिल्ली में 15 दिसंबर, 2015 को प्रदान किए गए.

यह पुरस्कार 26 विजेताओं को 4 मुख्य श्रेणियों और 9 उप श्रेणियों में प्रदान किए गए. यह पुरस्कार सीआईआई-आईटीसी उत्कृष्ट केंद्र के सतत विकास के प्रयासों का एक हिस्सा हैं.

रेल मंत्री सुरेश प्रभु पुरस्कार समारोह में विशेष अतिथि थे.

रिलायंस एंटरटेनमेंट और स्टीवेन स्पिलबर्ग के मध्य करार

अनिल अम्बानी की रिलायंस एंटरटेनमेंट और स्टीवेन स्पिलबर्ग की ड्रीमवर्क्स ने 17 दिसम्बर 2015 को एक नई फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल सामग्री निर्माण कंपनी 'अंबलिन पार्टनर्स' के गठन की घोषणा की.

जेफ स्कोल की कंपनी पार्टिसिपेंट मीडिया और प्रमुख अमेरिकी मनोरंजन कंपनी एंटरटेनमेंट वन (ईवन) भी संयुक्त उपक्रम कंपनी की हिस्सेदार होगी और ये कंपनियां विशेष सामग्रियों के लिए मिलकर काम करेगी तथा सह-निर्माण के अवसरों पर भी विचार करेगी. रिलायंस एंटरटेनमेंट और ड्रीमवक्र्स सात वर्षों से साथ काम कर रहे हैं और नई परियोजना ने उनकी कंपनियों को साथ काम करने का एक और अवसर दिया है. वर्ष 2009 में रिलायंस वैश्विक दर्शकों के लिए छह फिल्मे एक वर्ष में बनाने के लिए स्पीलबर्ग के साथ एक साझेदारी की घोषणा की थी.

ड्रीमवर्क्स स्टूडियोज और पार्टिसिपेंट मीडिया द्वारा निर्मित 'लिन्कन' और 'द हेल्प' जैसी फिल्मों को एकेडमी एवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया.

फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2015 में व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची जारी की

फोर्ब्स पत्रिका ने 16 दिसम्बर 2015 को वर्ष 2015 में व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची जारी की.

सूची में 144 देशों को शमिल किया गया है. इस सूची में भारत को 97वां स्थान प्राप्त हुआ है.

जारी की गई सूची में डेनमार्क को वर्ष 2015 का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है.

इस सूची में भारत की स्थित घाना और कजाखिस्तान जैसों से देशों से भी खराब है.

फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई सूची निम्न शीर्ष 10 देश शामिल हैं

रैंक	देश
1.	डेनमार्क
2.	न्यूजीलैंड
3.	नॉर्वे
4.	आयरलैंड
5.	स्वीडन
6.	फिनलैंड
7.	कनाडा
8.	सिंगापुर
9.	नीदरलैंड
10.	यूनाइटेड किंगडम

जारी की गई सूची में निम्न चार देश

रैंक	देश
141.	हैती
142.	लीबिया
143.	गिनी
144.	चाड

- विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पिछले वर्ष की तुलन में चार स्थान नीचे आया है.
- ब्रिटेन और जापान दोनों तीन स्थान ऊपर आए हैं और क्रमशः 10 और 23 प्राप्त किया है.
- चीन पिछले वर्ष 97 की तुलना में इस वर्ष 94 स्थान प्राप्त किया है.
- जर्मनी के दो स्थानों का सुधार हुआ है.

भारत निवेशक संरक्षण, नवाचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपदा अधिकारों पर क्रमशः 8, 41 , 57 और 61 स्थान पर है.

खाद्य भुगतान के लिए आईआरसीटीसी और पेटीएम के मध्य समझौता

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने 16 दिसम्बर 2015 को अपनी ई-खानपान की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त भुगतान गेटवे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेटीएम के साथ करार किया.

विदित हो वर्तमान में आईआरसीटीसी ट्रेन प्रस्थान से एक दिन पहले उपभोगता को खाद्य आर्डर करने के लिए एक मेल भेजता है. इसके अतिरिक्त उपभोगता आरक्षण के समय भी खाद्य ऑर्डर कर सकते हैं.

विदित हो वर्तमान में आईआरसीटीसी प्रत्येक दिन 5.5 लाख से 6 लाख तक ई खानपान सम्बन्धी बुकिंग ले रहा है.

ऑर्डर करते समय उपभोगता के पास ऑनलाइन भुगतान के अलावा कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प भी उपलब्ध होगा. वर्ष 2015 के अक्टूबर माह में आईआरसीटीसी ने ई-केटरिंग की सुविधा का और प्रसार करने के लिए इसका नाम फ़ूड ओं ट्रैक रख दिया था.

स्नैपडील ने हिंदी एवं तेलगु में मोबाइल वेबसाइट आरंभ की

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील डॉटकॉम ने 15 दिसंबर 2015 को हिंदी एवं तेलगु भाषाओं में अपनी मोबाइल वेबसाइट आरंभ की. स्नैपडील भारत में 270 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ कार्यरत है.

बहुभाषा का यह प्लेटफ़ॉर्म केवल मोबाइल वेबसाइट पर मौजूद होगा. यह सुविधा स्नैपलाइट प्लेटफ़ॉर्म के साथ मौजूद होगा जिसमें वे उपभोक्ता भी इसका उपयोग कर सकेंगे जहां इंटरनेट की क्वालिटी बेहतर नहीं है.

स्नैपलाइट मोबाइल वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के लिए स्नैपडील द्वारा तैयार वेबसाइट है.

कम्पनी के अनुभवों एवं उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित बहुभाषा प्लेटफ़ॉर्म को मोबाइल एप्प एवं डेस्कटॉप वेबसाइट के लिए भी आरंभ किया जायेगा.

भारत में अन्य 130 मिलियन स्मार्टफ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए स्नैपडील 11 क्षेत्रीय भाषाओं - हिंदी, तेलगु, गुजरती, तमिल, मराठी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमी एवं पंजाबी में भी 26 जनवरी 2016 से सेवाएं आरंभ करेगा.

नैटको, हेटेरो को हेपेटाइटिस सी की जेनेरिक दवा बाजार में लाने की मंजूरी दी

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने 14 दिसम्बर 2015 को दवा कंपनियों नैटको फार्मा और हेटेरो को क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की दवा डैक्लाट्सविर का जेनेरिक वर्जन भारत में बेचने की इजाजत दे दी है. सितंबर 2014 में हेटेरो ड्रग्स लि ने क्रोनिक हेपेटाइटिस सी दवाओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित गिलाद विज्ञान के साथ एक गैर अनन्य लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह निश्चित दवा संयोजन गिलाद के ब्रांड हार्वोनी का जेनेरिक संस्करण है.

- नैटको के अनुसार वह भारत की पहली कंपनी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी दर्ज है, जिसे डीसीजीआई से यह दवा बनाने की इजाजत मिली है.
- कंपनी को 30 और 60 एमजी की डोज के लिए यह मंजूरी दी गयी है.
- हेटेरो दवा कंपनी को हेपेटाइटिस की दवा का जेनेरिक वर्जन बेचने के लिए डीसीजीआई से अनुमति मिली है.
- हेटेरो भी 30 और 60 एमजी की डोज की दवा की बिक्री कर सकती है.
- डैक्लाट्सविर को सोफोसबुविर के साथ यूज करके क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी का इलाज किया जाता है.
- नैटको दवा का जेनेरिक वर्जन एनएटीडीएसी ('NATDAC') नाम से बाजार में उतारेगी.
- नैटको दवा को खुद और अपने पार्टनर्स के जरिये बिक्री करेगी.
- नैटको 60 एमजी की 18 टैबलेट को 6,000 रुपये और 30 एमजी की 28 टैबलेट को 4,000 रुपये में लॉन्च करेगी.
- हेटेरो की दवा ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के डाकलिंजा टैबलेट्स का जेनेरिक वर्जन होगी.

हेटेरो के बारे में

- हैदराबाद स्थित भारतीय दवा कंपनी हेटेरो ड्रग्स लि डॉ बी पार्थ सरधि रेड्डी पीएचडी द्वारा वर्ष 1993 में स्थापित की गयी.
- 12000 कर्मचारियों वाली कंपनी का 1 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व है और पिछले वित्त वर्ष में $ 100 मिलियन का लाभ कमाया है.
- 100 से अधिक देशों में इसका विपणन है.

नैटको के बारे में

- 33 लाख रूपए के शुरुआती निवेश के साथ वर्ष 1981 में हैदराबाद में नैटको फार्मा की शुरुआत की गयी. नैटको विनिर्माण और वैश्विक मानकों के अनुरूप सस्ती दवाए बनाती है.
- 20 कर्मचारियों के साथ शुरू की गयी इकाई में वर्तमान में 3200 से अधिक कर्मचारी हैं. न्यू ड्रग डेवलपमेंट सहित पांच विनिर्माण समर्पित आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ कंपनी का कारोबार भारत भर में फैला है.

हेपेटाइटिस सी वायरस फैलने का कारण

- सौंदर्य चिकित्सा जहां मृत त्वचा की कोशिकाएं गिरी होती हैं उसकी सतह पर कई दिनों तक हेपेटाइटिस सी का वायरस पनपता रहता है.
- दवा इंजेक्ट करने वाले उपकरणों (सुई, हीटिंग चम्मच आदि) को शेयर करने से. यह उप-सहाराई अफ्रीका के बाहर एचसीवी के संचरण का प्राथमिक स्रोत है.
- किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित सेक्स से.
- कभी-कभार प्रसव के दौरान संक्रमित माता से उसके बच्चे में हो सकता है. यह खतरा तब और भी बढ़ सकता है जब माता एचआईवी से भी संक्रमित हो.
- संक्रमित रक्त से.
- नाक से कोकीन का इस्तेमाल करने वाले उपकरणों को शेयर करने से.
- हाथ पर टैटू गुदवाने, संक्रमित खून चढ़वाने, दूसरे का रेजर उपयोग करने आदि की वजह से हेपेटाइटिस सी होने की संभावना अधिक रहती है.

लक्षण-

- लोगों में हेपेटाइटिस सी से संक्रमित होने पर भी कोई लक्षण नहीं दिखाई देते.
- अमूमन इसके लक्षण 15 से 150 दिन में विकसित होते हैं.
- जिन लोगों में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, ऐसे संक्रमित लोग ही वायरस को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
- इसके कुछ लक्षणों में भूख में कमी, पीलिया, उल्टी, अनिद्रा और अवसाद शामिल हो सकते हैं.

जगुआर लैंडरोवर, स्लोवाकिया में एक अरब पाउंड निवेश करेगी

टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली लक्जरी कार इकाई ब्रितानी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंडरोवर (जेएलआर) ने 11 दिसंबर 2015 को ब्रैटिसलावा, स्लोवाकिया में घोषणा की कि वह एक अरब पाउंड के निवेश से नया विनिर्माण संयंत्र लगायेगी. ब्रितानी कंपनी का यह नया संयंत्र स्लोवाकिया के पश्चिमी इलाके में स्थित शहर नित्रा में लगाया जायेगा. जिसके लिए वहाँ की सरकार के साथ करार किया जा चुका है.

- इसके साथ स्लोवाकिया में संयंत्र लगाने वाली वह ब्रिटेन की पहली कार निर्माता कंपनी बन जायेगी.
- नित्रा में जगुआर लैंडरोवर की इस नयी फैक्ट्री (संयंत्र) की स्थापना के साथ ही ब्रिटेन, चीन, भारत और ब्राजील में पहले से मौजूद संयंत्रों के साथ वास्तविक वैश्विक कंपनी बनने की रणनीति में मददगार होगी.

नए संयंत्र के बारे मे-

- स्लोवाकिया के संयंत्र में 2800 लोगों को रोजगार मिलेगा.
- इसकी शुरुआती उत्पादन क्षमता डेढ़ लाख वाहनों की होगी और उत्पादन 2018 के उत्तरार्द्ध में शुरू होने की उम्मीद है.
- संयंत्र के निर्माण का काम 2016 में शुरू होगा.

क्या है जैगुआर?

- जैगुआर की स्थापना सर विलियम लॉयन्स द्वारा 1922 में, स्वालो साइडकार कंपनी के रूप में की गई.
- इसका मुख्यालय कॉवेंट्री, इंग्लैंड में है.

- टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांडों का 2008 में अधिग्रहण किया था.
- जगुआर लैंड रोवर ने 2009 में देश में अपने पहले शोरूम का उद्घाटन किया.
- जगुआर लैंड रोवर का पहला संयंत्र भारत में मई 2011 में शुरु किया गया.

टेक महिंद्रा एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिनिनफेरिना का अधिग्रहण किया

टेक महिंद्रा एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 14 दिसंबर 2015 को इटली की ऑटोमोबाइल डिज़ाइन कंपनी पिनिनफेरिना के 76 प्रतिशत शेयर का अधिग्रहण किया.

महिंद्रा ग्रुप कंपनी ने पिनिनफेरिना का लगभग 165 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया. इस अधिग्रहण का उद्देश्य स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (एसपीवी) का निर्माण करना है. इस डील में टेक महिंद्रा का 60 प्रतिशत जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

इस अधिग्रहण के पश्चात् भी पिनिनफेरिना स्वायत्त रूप से कार्य करती रहेगी. मिलान स्टॉक एक्सचेंज में पाओलो पिनिनफेरिना कंपनी के चेयरमैन के रूप में दर्ज हैं. इस समझौते से महिंद्रा विश्व की टॉप 50 ऑटोमोबाइल कम्पनियों में शामिल हो जायेगी.

पिनिनफेरिना

- फेरारी के तमाम मॉडलों की डिजाइनिंग पिनिनफेरिना कर चुकी है.
- इसके अतिरिक्त पिनिनफेरिना ने फ़िएट, एल्फा रोमियो, बेंटली, बीएमडब्ल्यू एवं मसेरती को भी डिज़ाइन किया है.
- इसकी स्थापना बतिस्ता पिनिनफेरिना ने गाड़ियों को डिज़ाइन करने के लिए 1930 में की थी.
- वर्ष 1966 में उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके बेटे सर्जियो एवं दामाद रेंजों कार्ली को इसका नियंत्रण प्राप्त हुआ.

महिंद्रा ग्रुप कम्पनी ने इससे पहले अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण कोरिया की एसयूवी निर्माता कम्पनी सैंगयोंग एवं फ़्रांस की स्कूटर निर्माता कम्पनी प्यूजियो का अधिग्रहण किया है.

इनफ़ोसिस ने “स्टार्टअप” में 20 करोड़ रुपए निवेश किया

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी इन्फोसिस ने 14 दिसम्बर 2015 को खेल से सम्बंधित उपकरण बनाने वाली कंपनी स्टार्टअप व्हूप में अल्पांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु 30 लाख डालर का निवेश किया है.

इन्फोसिस कम्पनी के कर्ता- धर्ताओं ने एक नियामकीय जानकारी में घोषणा की कि कम्पनी ने व्हूप में 30 लाख डालर (करीब 20 करोड़ रुपए) का निवेश किया है. इन्फोसिस इस सौदे के जरिए कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. यह हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. यह निवेश प्रक्रिया 16 दिसंबर 2015 तक पूरी की जाएगी.

इन्फोसिस के बारे में-

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख इंफोसिस लिमिटेड (पूर्व में इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) व्यापार परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है.

सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घरेलू बहुराष्ट्रीय कंपनी इन्फोसिस का मुख्यालय बंगलौर, कर्नाटक में है.

इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी, एन एस राघवन, एस गोपालकृष्णन, एसडी शिबूलाल, लालकृष्ण दिनेश और अशोक अरोड़ा के साथ 1981 में सह-स्थापना की थी.

राजस्व के मामले में इंफोसिस 2014 से दूसरी सबसे बडी भारत स्थित आईटी सेवा कंपनी है. और एच -1 बी वीजा का पांचवां सबसे बड़ा नियोक्ता है.

व्हूप स्टार्टअप के बारे में -

बोस्टन, अमेरिका की व्हूप स्टार्टअप विशिष्ट पेशेवर खेल टीमों के लिए परफॉर्मेंस ऑप्टीमाइजेशन सिस्टम मुहैया कराती है.

परफॉर्मेंस ऑप्टीमाइजेशन सिस्टम एक डिवाइस है जो स्पोवर्ट्स एथेलीट्स की कलाई पर बांधा जाता है.

इस डिवाइस की मदद से खिलाड़ियों और उनके कोच को अपना परफॉर्मेंस जांचने, ट्रेनिंग और गेम के लिए योजना तैयार करने में मदद मिलती है.

हैवेल्स ने सिल्वेनिया को बेचा 80 फीसदी हिस्सा

विश्व स्तरीय उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल्स कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने 10 दिसम्बर 2015 को यूरोपीय लाइटिंग कंपनी सिल्वेनिया में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी 14.88 करोड़ यूरो यानी करीब 1,090 करोड़ रुपये में शांघाई फीलो अकॉस्टिक्स को बेचने की घोषणा की.

कंपनी हैवेल्स माल्टा बीवी में 80 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. जबकि शेष 20 फीसदी हिस्सेदारी वह बाहर होने के विकल्प के साथ अगले 3 से 5 साल तक अपने पास रखेगी.

हैवेल्स और उसके व्यापारिक लक्ष्य

- हैवेल्स ने फ्रैंकफर्ट की कंपनी सिल्वेनिया का अधिग्रहण हॉलैंड की अपनी सहायक इकाई हैवेल्स नीदरलैंड्स के जरिये 2007 में 30 करोड़ डॉलर के एक सौदे के तहत किया था.
- हैवेल्स इंडिया हॉन्ग कॉन्ग की अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई हैवेल्स एग्जिम लिमिटेड में भी 80 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी.
- कंपनी ने कहा है कि दोनों कंपनियों के लिए 100 फीसदी हिस्सेदारी के लिए एकीकृत इक्विटी मूल्य 18.6 करोड़ यूरो यानी करीब 1,340 करोड़ यूरो होगा जो समायोजन पर निर्भर करेगा.
- इन दोनों कंपनियों के लिए एकीकृत निवेश का आकार 980 करोड़ रुपये है.
- कंपनी जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए उत्पाद खंड और बाजार में विस्तार पर किया जाएगा.
- हैवेल्स इंडिया 'मुख्य तौर पर हम भारत में बरकरार रहने पर ध्यान केंद्रित करेगी.
- कंपनी पश्चिम एशिया और दक्षिण एशियाई देशों में व्यापारिक विस्तार की संभावनाएं तलाशेगी.
- कंपनी भारत सहित अपने वैश्विक उत्पाद पोर्टफोलियो का भी विस्तार करेगी.
- कंपनी मुनाफे में चल रही अमेरिका, ब्राजील, चिली और थाइलैंड में हैवेल्स सिल्वेनिया की सहायक इकाइयों में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रखेगी.
- मौजूदा पोर्टफोलियो के तहत कंपनी का इरादा स्मार्ट सिटी परियोजना जैसे अन्य वेंचरों में विलय-अधिग्रहण के जरिये कारोबार बढ़ाने का है.

सिल्वेनिया के बारे में-

सिल्वेनिया लाइटिंग के सामान बनाने वाली प्रमुख कंपनी है जो करीब 48 देशों में कारोबार करती है.

इस कंपनी की हैसियत करीब 44.3 करोड़ यूरो है.

भारत फोर्ज रॉल्स रायस को इंजन के कलपुर्जे की आपूर्ति करेगी

आटो कलपुर्जे बनाने वाली घरेलू कंपनी भारत फोर्ज ने 10 दिसंबर 2015 को एरो इंजन के कलपुर्जों की आपूर्ति के लिये रॉल्स रायस के साथ दीर्घकालिक समझौता किया.

- समझौते के तहत ट्रेंट इंजन सहित, एरो इंजन के कई अहम हिस्सों की आपूर्ति की जाएगी.
- इसमें फोर्जड और मशीनी मुख्य कलपुर्जों की आपूर्ति पर जोर होगा''
- राल्स रॉयस के साथ कलपुर्जों की आपूर्ति की भागीदारी से एयरोस्पेस क्षेत्र से 10 करोड़ डालर का राजस्व लक्ष्य हासिल करने उद्देश्य है.
- वैश्विक एयरोस्पेस क्षेत्र में फोर्जड और मशीनों उत्पादों के साथ अहम् भूमिका निभाएगी.

भारत फोर्ज के बारे में -

भारत फोर्ज तीन अरब डालर के कल्याणी समूह की अग्रणी कंपनी है. कल्याणी समूह आटोमोटिव, तेल और गैस, बिजली और एयरोस्पेस सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन वाले नवोन्मेषी, सुरक्षित और अहम कलपुर्जे और निदान उपलब्ध कराने वाली कंपनी है.

मोबाइल कंपनी ओप्पो आईसीसी की ग्लोबल पार्टनर बनी

मोबाइल टेलीफोन कंपनी ओप्पो 2016 से 2020 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ग्लोबल पार्टनर होगी. यह समझौता 10 दिसम्बर 2015 को दोनों के बीच दुबई में किया गया.

ओप्पो के बारे में-

चीन में 2004 में लॉन्च हुए ओप्पो मोबाइल का बाजार 20 देशों में है. जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है.

ओप्पो वैश्विक बाजार में अग्रणी है और क्रिकेट खेलने वाले देशों में इसका काफी दबदबा है.

फीफा क्लब विश्व कप और अलीबाबा ई-ऑटो के मध्य समझौता

फीफा क्लब विश्व कप और अलीबाबा ई-ऑटो के मध्य 9 दिसम्बर 2015 को 8 वर्षों का समझौता हुआ है.

यह समझौता वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के लिए हुआ है.

विदित हो अलीबाबा ई-ऑटो, विश्व की सबसे बड़े ऑनलाइन और मोबाइल कॉमर्स समूह अलीबाबा का एक ब्रांड है जिसने वर्ष 2016 से शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन (एसएआईसी) के साथ एक इन्टरनेट कार को शुरू करने की योजना बनाई है.

इस समझौते का उद्देश्य फीफा क्लब विश्व कप को वैश्विक मंच पर पहचान प्रदान करना है.

फीफा क्लब विश्व कप 2015

- फीफा क्लब विश्व कप 2015 का आयोजन जापना में 10 दिसम्बर 2015 से 20 दिसम्बर 2015 तक किया जाएगा.
- प्रतियोगिता में कुल सात टीमें हिस्सा लेंगी.
- प्रतियोगिता का आयोजना जापन के दो शहर ओसका और योकोहामा के स्टेडियम क्रमशः नागाई और इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ़ योकोहामा में किया जाएगा.

फेसबुक ने भारत में स्थापित की लघु एवं मध्यम उपक्रम परिषद

सोशल मीडिया क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फेसबुक ने वर्ष 2015 के दिसम्बर माह में एक लघु एवं मध्यम उपक्रम परिषद का गठन किया है.

इस परिषद के गठन का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के छोटे उद्यमों को जानकारी साझा करना और अपने उपक्रम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने में मदद करना है.

विदित हो भारत के 20 लाख भारतीय लघु एवं मध्यम कारोबार (एसएमपी) फेसबुक के मंच पर हैं.

वैश्विक स्तर पर यह फेसबुक द्वारा गठित दूसरी लघु एवं मध्यम उपक्रम (एसएमई) परिषद है. पहली परिषद अमेरिका में बनी थी.

वर्तमान में 4.5 करोड़ छोटे कारोबार ग्राहकों से जुड़ने के लिए फेसबुक पेज का सक्रियता से उपयोग करते हैं.

आज किराने की दुकान से लेकर रेस्तरां और आनलाईन वस्त्र साइट तक ये कारोबार आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और देश भर में लोगों के जीवन को समृद्ध करते हैं.

छोटे एवं मध्यम उपक्रम भारत के 40 प्रतिशत निर्यात का परिचालन करते हैं.

टेक महिंद्रा, फोर्ब्स पुरस्कार से सम्मानित

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनी टेक महिंद्रा को 7 दिसम्बर 2015 को दुबई में फोर्ब्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

महिंद्रा समूह की बहुराष्ट्रीय कम्पनी टेक महिंद्रा को 'फोर्ब्स टॉप 100 मिडिल ईस्ट - ग्लोबल मीट्स लोकल 2015' पुरस्कार दिया गया.

यह पुरस्कार फ़ोर्ब्स मिडिल ईस्ट द्वारा आयोजित किया गया था.

विदित हो इस पुरस्कार के लिए उन बड़ी कंपनियों का चयन किया जाता है, जिनकी वैश्विक कंपनी होने के साथ-साथ पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय भी है.

चयन का आधार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी की छवि, क्षेत्र में उसका अनुभव, भौगोलिक पहुंच, रोजगार पर उसका प्रभाव तथा पश्चिम एशिया में उसकी स्थिति है.

कम्पनी की ओर से कंपनी के महाप्रबंधक तथा पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा तुर्की में कारोबार के प्रमुख राम रामचंद्रन ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया.

यह कंपनी 12 वर्षों से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन और तुर्की में कार्य कर रही है.

ऑनलाइन नि: शुल्क शिक्षा के लिए टाटा ट्रस्ट ने खान अकादमी के साथ समझौता किया

विश्व के दूसरे देशों में ऑनलाइन शिक्षा देने वाली खान अकादमी ने 6 दिसम्बर 2015 को भारतीय बाजार के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ नि: शुल्क ऑनलाइन शिक्षा देने हेतु पांच साल के लिए समझौता किया. समझौता के

तहत कंटेंट तैयार करने से लेकर शिक्षकों की टीम सहित शिक्षा के लिए मूल ढांचा टाटा ट्रस्ट उपलब्ध कराएगा.

टाटा ट्रस्ट, खान अकादमी को पांच साल के दरम्यान भारतीय शिक्षार्थीयों के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु मौजूदा संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराएगी.

टाई-अप की मुख्य विशेषताएं-

- टाटा ट्रस्ट के चेयर मैन रतन टाटा और खान अकादमी के सीईओ और संस्थापक सलीम खान ने इसकी घोषणा की.
- पांच साल की साझेदारी दो चरणों में विभाजित करके पूरी की जाएगी.
- पहले दो वर्ष शहरों में मध्यम और कम आय वर्ग वाले छात्रों की जरूरतों के द्रष्टिगत टेक्नोलोजी के प्रयोग के साथ शैक्षिक संसाधनों का मजबूत सेट डिजाइन किया जाएगा.
- प्रथम चरण में हिंदी और अंग्रेजी के बाद अगले चरण में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं मराठी, तमिल और बांग्ला में कक्षाओं की पेशकश सहित अन्य क्षेत्रों में विविध सामग्री पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा. इस कार्य को अंजाम देने के लिए हिंदी का पोर्टल भी तैयार भी कर लिया गया है.
- टीम का आकार भारत में भी अमेरिका के बराबर होगा, अकादमी ऑन लाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीकों से शिक्षा उपलब्ध कराएगी.

खान अकादमी के बारे में-

- खान अकादमी 2006 में स्थापित, अमेरिका आधारित गैर लाभ शैक्षिक संगठन है.
- इसे शिक्षक सलमान खान द्वारा कहीं भी, किसी के लिए भी विश्व स्तरीय नि: शुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया.
- अकादमी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से छोटे व्याख्यान देता है.
- खान अकादमी व्यापक रूप से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बोर्ड फाउंडेशन, गूगल, और कई अन्य परोपकारी संगठनों द्वारा समर्थित है.

जॉय बांदेकर ओला के कॉरपोरेट अध्यक्ष नियुक्त

एप्प आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कम्पनी ओला ने 7 दिसम्बर 2015 को जॉय बांदेकर को कॉरपोरेट अध्यक्ष

के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की.

बांदेकर को 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है और अब वह ओला की मुख्य लीडरशिप टीम का हिस्सा होंगे.

इससे पूर्व जॉय बांदेकर फ्लिपकार्ट में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे.

बांदेकर ने इससे पूर्व ईबे, किर्लोस्कर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मक्स्वर्थ बागों और एटकॉम टेक्नोलॉजीज जैसे संगठनों के साथ काम किया है.

विदित हो ओला की भारत में उबेर और मेरु टैक्सी सेवा प्रदाता से प्रतिस्पर्धा है.

ओला ने किया दुनिया की चार दिग्गज कंपनियों के साथ करार

टैक्सी सेवा प्रदाता ऐप आधारित दुनिया की चार दिग्गज कंपनियों ओला, दीदी क्वैड, लिफ्ट और ग्रैब ने 05 दिसम्बर 2015 को दक्षिण-पूर्वी एशिया, भारत, चीन और अमेरिकी बाजार में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से शुक्रवार को वैश्विक साझेदारी की घोषणा की.

इस साझेदारी से यात्रियों को लाभ-

- चारों कंपनियां एक-दूसरे के नवाचारों को साझा कर सकेंगी.
- दूसरे देशों के लोगों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने में मदद मिलेगी.
- इससे एक-दूसरे की प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता को भी जानने का मौका मिलेगा.
- इन चारों कंपनियों के बीच एस साझेदारी के बाद दुनिया भर के शहरों में परिवहन क्षेत्र में क्रांति आएगी.
- इन कंपनियों की साझेदारी से लाखों उपभोक्ताओं को सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी.

इससे परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के साथ ही यात्रियों एवं चालकों के जीवन स्तर में भी सुधार की संभावना बढ़ी हैं. इसके मद्देनजर एक-दूसरे के प्रोडक्ट इनोवेशन, ड्राइवर सपोर्ट, प्रौद्योगिकी विकास एवं स्थानीय गतिविधियों के प्रबंधन के माध्यम से उपभोक्तओं को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करेंगे.

टाटा समूह ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चायना लिमिटेड (आईसीबीसी) के साथ समझौता किया

टाटा समूह की कारोबारी कंपनियों की प्रवर्तक इकाई, टाटा सन्स और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चायना लिमिटेड (आईसीबीसी) के बीच दीर्घकालिक भागीदारी का 2 दिसंबर 2015 को एक समझौता हुआ. इसके तहत चीनी बैंक भारत के इस प्रमुख औद्योगिक घराने का रणनीतिक बैंकिंग भागीदार बनेगा.

टाटा संस के अनुसार, आईसीबीसी टाटा समूह को वित्तपोषण-उत्पाद, वैश्विक नकदी प्रबंधन, परामर्श, अंतरराष्ट्रीय व्यापार-रिण, निवेश बैंकिंग, विदेशी विनिमय, वायदा एवं विकल्प कारोबार और अन्य वैश्विक वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा. टाटा संस के अनुसार, आईसीबीसी टाटा समूह के लिए संबंधित सेवाओं के लिए अधिकारियों की एक वैश्विक टोली बनांएगा जो टाटा समूह की रणनीतिक विकास योजनाओं में मदद करेगी. कंपनी के अनुसार, यह समझौता वैश्विक होगा और इसके दायरे में भारत, चीन, सिंगापुर, यूरोप, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी बाजार आएंगे.

फ्लिप्कार्ट ने मैपमायइंडिया में हिस्सेदारी खरीदी

ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने 3 दिसम्बर 2015 को नेविगेशन और ट्रैकिंग सॉल्यूकशन प्रोवाइडर मैपमायइंडिया में हिस्से्दारी खरीदी. इसका उद्देश्य डिलवरी चेन को मजबूत बनाना है.

इस समझौते द्वारा टेक्नोलॉजी की सहायता से फ्लिपकार्ट को सप्लाई चेन मजबूत करने में आसानी होगी क्योंकि मैपमायइंडिया मानचित्र डाटा और लोकेशन टेक्नोललॉजी की सेवाएं प्रदान करती है.

फ्लिपकार्ट ने जारी बयान में कहा कि मैपमायइंडिया सभी इंडस्ट्रीज़ के कंज्यूमर्स और इंटरप्राइजेज को स्वतंत्र रूप से प्रोडक्ट्स और सॉल्यूंशन की सर्विस देती रहेगी.

मैपमायइंडिया

- मैपमायइंडिया की स्थापना राकेश वर्मा एवं रश्मि वर्मा द्वारा की गयी थी.
- इन्होंने इससे पहले लाइटबॉक्स वेंचर्स, नेक्सस वेंचर एवं क्वालकॉम वेंचर द्वारा 30 मिलियन डॉलर का लाभ अर्जित किया था.
- मोबाइल ऐप बेस्टल कैब सर्विस कंपनी ओला ने भी बेहतर नेविगेशन के लिए मैपमायइंडिया के साथ

पार्टनरशिप करने का ऐलान किया था.

- इसके अंतर्गत ओला को मैपमायइंडिया के पूरे मैपिंग डाटा का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त हुआ.

अमेरिकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी अरिसेंट ने नैसकॉम फाउंडेशन के साथ समझौता किया

अमेरिकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी अरिसेंट ने नैसकॉम फाउंडेशन के साथ 1 दिसंबर 2015 को एक समझौता किया. यह समझौता अरिसेंट रोजगार कार्यक्रम (Aricent Employability Programme) हेतु किया गया. इस सीएसआर समर्थित प्रोग्राम के तहत 2500 इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार के अवसर उपलब्द होंगे.

विदित हो कि अरिसेंट रोजगार कार्यक्रम के तहत कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के स्नातक छात्रों को इसके हेतु पेशकश की जाएगी. चयनित छात्रों को साफ्टवेयर विषय विशेष में प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि वे संबंधित क्षेत्र में रोजगार पा सकें.

उबेर ने विकलांगों के लिए उबेरअसिस्ट सेवा शुरु की

ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कम्पनी उबेर ने 2 दिसम्बर 2015 को देने वाली कंपनी उबेर ने विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शारीरिक रूप से अक्षम एवं वृद्ध लोगों के लिए उबेरअसिस्ट नामक विशेष सेवा शुरु की है.

उबेरअसिस्ट सेवा

- इस सेवा के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किफायती, सुरक्षित एवं भरोसेमंद माध्यम उपलब्ध कराया जाएगा.
- इस सेवा का लाभ लेने के लिए लोगों को उबेर ऐप के प्रमोशन टैब में 'असिस्टडेल' कोड लिखना होगा.
- सेवा के अनलॉक हो जाने के बाद स्लाइडर के ऊपर उबेरअसिस्ट विकल्प चुनने पर यह सेवा उपलब्ध हो जाएगी.

इस सेवा को अभी दिल्ली में शुरु किया गया है और इसे जल्द ही देश के सभी प्रमुख शहरों में शुरु किया

जाएगा.

इसके अतिरिकित चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए आईकेयर लाइफ के साथ करार भी किया गया है. इसमें चालकों को व्हीलचेयर एवं वॉकर को मोडऩे तथा उचित तरीके से रखने के अलावा लोगों को सहुलियत से गाड़ी में सवार करना तथा उतारना सिखाया जाएगा.

इसके साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार की अक्षमता के बारे में भी जानकारी दी जाएगी तथा आवश्यक एहतियात भी बताये जाएंगे.

जहाज निर्माण सामग्री सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जहाज निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त करने की घोषणा की. इसके तहत जहाज निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को 24 नवंबर 2015 से सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया.

उपरोक्त आशय की छूट से पहले जहां एक ओर जहाजों को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की लगभग नगण्य दरों और शून्य प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) पर आयात किया जा सकता था, वहीं जहाज निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल (इनपुट) पर बीसीडी एवं काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) की सामान्य दरें अदा करनी पड़ती थीं. ऐसे में घरेलू बाजार के लिए जहाजों का निर्माण करने वाले भारतीय शिपयार्ड लागत के मामले में नुकसान में रहते थे.

भारतीय शिपयार्डों को लागत के मामले में हो रहे नुकसान को खत्म करने और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय ने इस मसले को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के समक्ष उठाया था.

आईसीबीसी बना टाटा समूह का रणनीतिक सहयोगी

टाटा समूह की कारोबारी कंपनियों की प्रवर्तक, टाटा सन्स और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चायना लिमिटेड :आईसीबीसी: के मध्य 2 दिसम्बर 2015 को समझौता हुआ.

इस दीर्घकालिक भागीदारी का समझौता के तहत चीनी बैंक भारत के इस प्रमुख औद्योगिक घराने का रणनीतिक बैंकिंग भागीदार बनेगा.

आईसीबीसी टाटा समूह को वित्तपोषण-उत्पाद, वैश्विक नकदी प्रबंधन, परामर्श, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऋण, निवेश बैंकिंग, विदेशी विनिमय, वायदा एवं विकल्प कारोबार और अन्य वैश्विक वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा.

टाटा समूह के लिए आईसीबीसी इन सेवाओं के लिए अधिकारियों का एक वैश्विक समूह बनाएगा जो टाटा समूह की रणनीतिक विकास योजनाओं में मदद करेगी.

यह गठजोड़ वैश्विक होगा और इसके दायरे में भारत, चीन, सिंगापुर, यूरोप, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी बाजार आएंगे.

राज्य

आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रौद्योगिकी पहल हेतु माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

आंध्र प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर, 2015 को प्रौद्योगिकी पहल के तहत माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. समझौता ज्ञापन पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के बीच एक बैठक के बाद हस्ताक्षर किए गए.

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुधार डिजिटल समावेशन ड्राइव और आईटी आधारित विकेन्द्रीकृत नागरिक सेवाएं प्रदान करना है.

प्रौद्योगिकी पहल से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के बारे में जानकारी, कृषि उत्पादकता में सुधार और बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी.

समझौता ज्ञापन की विशेषताएं

- माइक्रोसॉफ्ट एजयुर मशीन लर्निंग और एडवांस्ड विजुएलाइजेशन मेथड लागू करके कंपनी एपी सरकार को तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगी. और तीन अवधारणाओं (पीओसी) के समाधान का करेगी.
- तीन पीओसी समाधान शिक्षा, कृषि और ई सिटिजन सेवाओं के क्षेत्र से संबंधित हैं.
- पीओसी समाधान राज्य में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने व प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बनाया गया है.
- माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा डेटा एकत्र करने, विश्लेषण, भविष्य की योजनाओं के विश्लेषण और नीति नियोजन के लिए, प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा.
- राज्य सरकार के प्रमुख आईटी अधिकारियों को माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकियों क्लाउड, मोबिलिटी और उचित माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाएगा.
- कंपनी विशाखापत्तनम में उत्कृष्टता के लिए केन्द्र (सीओई) की स्थापना की करेगी.

राज्यपर्यटकों का पसंदीदा राज्य बना उत्तरप्रदेश: एसोचैम

भारत में वर्षान्त पर्यटन रुझान-2015 पर एसोचैम सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा 'इयर एंड टूरिज्म ट्रेंड्स इन इंडिया (2015) के 26 दिसम्बर 2015 के ताजा अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश विश्व पर्यटन मानचित्र पर विदेशी सैलानियों का पसंदीदा राज्य बन गया है.

- उत्तर प्रदेश विश्व धरोहरों की मौजूदगी के साथ-साथ सुरक्षा के लिहाज से बेहतर और किफायती होने से नये साल की छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले सैलानियों की पसंदीदा जगह है.
- अध्ययन के मुताबिक देश की उत्तरी, मध्य तथा तटीय पट्टी में नये साल की छुट्टियां मनाने के लिए करीब 15 लाख घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की आमद की संभावना है.
- रपट के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब तीन लाख सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है.
- यह आंकड़ा सम्भावित पर्यटक संख्या का लगभग 20 फीसदी है.
- इन पर्यटकों ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, अयोध्या, ब्रजमण्डल, सारनाथ, वाराणसी तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने की इच्छा जाहिर की है.
- एसोचैम की रिपोर्ट में विमानन सेवाओं को बेहतर करने, पर्यटन स्थलों का विकास करने, तीर्थस्थलों के बेहतर प्रबंधन तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने के लिए उठाये गये अन्य कदमों की वजह से उत्तर प्रदेश घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए दिलचस्पी का केंद्र बना है.
- पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद वैश्विक पर्यटन केंद्रों पर जाने की पर्यटकों की अनिच्छा के कारण नये साल के छुट्टी सीजन में घरेलू पर्यटन कारोबार में भी 10 प्रतिशत का उछाल आने का अनुमान है.
- उद्योग मण्डल के अध्ययन के अनुसार अंडमान और निकोबार तथा पर्यटन केंद्रों के लिहाज से सम्पन्न गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, राजस्थान, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बडी संख्या में पर्यटकों की आमद की सम्भावना के मद्देनजर कारोबार में खासे इजाफे की उम्मीद है.
- विदेशों में हाल ही में आतंकवादी हमलों का उन जगहों के पर्यटन कारोबार पर खासा नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है.
- पर्यटक विदेशों में हुए आतंकी हमलों से भारत की ओर आकर्षित हो सकते हैं.
- बढती महंगाई, महंगे हो रहे हवाई किराये और होटल, रुपये की विनिमय दर में अनिश्चित उतार-चढाव तथा सम्बन्धित अन्य कारकों की वजह से सुस्त पड़े घरेलू पर्यटन उद्योग को इससे बल मिलेगा.

- एसोचैम कि रिपोर्ट का आधार पिछले एक महीने के दौरान लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इन्दौर, जयपुर, कोलकाता, मुम्बई तथा पुणे में घूमने-फिरने के शौकीन करीब 500 लोगों से बातचीत है.
- उन पर्यटकों में से करीब 60 फीसदी लोगों ने कहा कि वे नये साल की छुट्टियों पर जाने की योजना बना रहे हैं.
- अध्ययन के मुताबिक आधे से ज्यादा उत्तरदाताओं ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी पर्यटन केंद्रों पर जाने का मन बना चुके हैं.
- वे दक्षिण भारत के उन पर्यटन स्थलों पर नहीं जाना चाहते, जहां हाल में जबरदस्त बारिश हुई थी.
- रिपोर्ट के अनुसार मात्र आठ से 10 प्रतिशत लोगों ने ही कहा कि वे दुबई, हांगकांग, मलेशिया, मालदीव, मारीशस, श्रीलंका, सिंगापुर तथा अन्य 'सुरक्षित' स्थानों पर छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं.
- एसोचैम के प्रतिनिधियों ने उपरोक्त शहरों में काम कर रहे अनेक टूर आपरेटरों से भी बात की. ज्यादा संख्या में घरेलू पर्यटन स्थलों की बुकिंग की रही हैं.

एसोचैम के बारे में-

- भारतीय वाणिज्य एंव उद्योग मंडल (The Associated Chambers of Commerce and Industry/ ASSOCHAM) या एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है.
- इसकी स्थापना १९२० में हुई थी.
- वर्तमान में भारत की एक लाख से अधिक कंपनियाँ इसकी सदस्य हैं.
- एसोचैम भारत की वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की रक्षा के लिये काम करता है.
- इसके अध्यक्ष सुनील कनोरिया हैं.

डिजिटल सेवाएं: देश में छत्तीसगढ़ प्रथम, 28 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार

देश भर में एक जुलाई से 7 जुलाई, 2015 तक आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यो के लिए 26 दिसम्बर 2015 को देश

भर में पहला स्थान दिया गया है. डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन जिलों को भी भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है.

नई दिल्ली में 28 दिसंबर को केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ राज्य को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे. जिलों की श्रेणी में कोंडागांव जिले को प्रथम, कोरिया को दूसरा और गरियाबंद जिले को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है. इन जिलों को भी 28 दिसंबर को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा.

- डिजिटल सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को दूसरा और मेघालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है.
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इस पुरुस्कार को ग्रहण करेंगे.
- एक जुलाई से 7 जुलाई, 2015 तक आयोजित डिजिटल भारत सप्ताह के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोलह प्रमुख डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया था. इनमें मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पोर्टल भी शामिल है.
- वाईफाई हॉटस्पॉट के अंतर्गत नागरिकों विशेषकर छात्र छात्राओं को सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए वाई-फाई सिटी परियोजना का शुभारंभ किया गया.
- राजस्व विभाग की छह तथा समाज कल्याण विभाग की पांच पेंशन सेवाओं, ई-जिला सेवाओं के लिए आईओएस मोबाइल एप्प, ई-जिला सेवाओं के डैशबोर्ड मोबाइल एप्प का शुभारंभ किया.
- एकीकृत डिजिटल छत्तीसगढ़ के मोबाइल एप्प, छत्तीसगढ़ कैंपस कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले 16 ग्रामों में सामान्य सेवा केंद्र के उद्यमी को डिजिटल छत्तीसगढ़ एप, टेबलेट का वितरण सहित विभिन्न ई-सेवाओं का शुभारंभ किया गया. इसी के लिए छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्राप्त हुआ है.
- तेज इंटरनेट स्पीड के लिए वाईफाई, मोबाइल ऐप, पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा, राजस्व विभाग से संबंधित 6 सेवाएं, लोकसेवा केंद्र, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर, जैसी ऑनलाइन सेवाएं भी लांच की गयी थीं.

मानव मूत्र से पैदा की जा सकेगी बिजली

आगरा में इंजीनियरिंग के छात्रों ने 23 दिसम्बर 2015 को मानव मूत्र का इस्तेमाल कर बिजली तैयार करने का शोध किया है. आविष्कार करने वाले छात्र कैमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. छात्रों का ये अनूठा

आविष्कार इलेक्ट्रोलिसिस विधि पर आधारित है.

क्या है शोध मॉडल-

- शोध माडल में तांबे और जस्ते की प्लेटों को एनोड और कैथोड के रूप में प्रयोग किया गया है. मूत्र में उपस्थित यूरिया एनोड और कैथोड के विभिन्न आयामों में विभक्त
- होकर विद्युत का संचार करता है.
- छात्रों ने प्रयोग के लिए कांच के पात्र को डिजाइन किया. जिसे दो अतिरिक्त भागों में विभक्त किया.
- एक भाग में तांबे की प्लेट और दूसरे भाग में जस्ते की प्लेट को समायोजित किया. दोनों प्लेटो को तार के माध्यम से तीन वॉट की एलईडी से जोड़ा.
- छात्रों ने दोनों भागों में एक बार स्वच्छ मानव मूत्र और अगली बार गौ मूत्र डालकर प्रयोग किया. दोनों ही बार पांच मिनट के बाद वोल्टोमीटर में रीडिंग आने लगी.
- सबसे ज्यादा सफल प्रयोग मानव मूत्र से हुआ जिससे एक लीटर मानव मूत्र से लगभग 6 घंटे से ज्यादा 3 वाट का बल्ब जला.

प्रदूषण नियंत्रण हेतु पटना में प्रतिबंधित की जाएंगी 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसम्बर 2015 को राजधानी पटना में 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. निरंतर प्रदूषित हो रहे वायुमंडल से जनजीवन को बचाने के लिए यह फैसला किया गया है.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिहार ने 14 दिसम्बर 2015 को प्रदूषण के आंकड़े भेजे थे जो नवम्बर में 400 के पार थे.

राज्य में प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी चिंताजनक है.

रोकने के उपाय -

- सरकार का प्रयास इसे रोकने के लिए यह पहला कदम है.
- ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया जाएगा.

- सायरन, हूटर तथा हॉर्न बजाने पर रोक के साथ प्लास्टिक को जलाने पर रोक लगाई जाएगी.
- नीतीश सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को प्राधिकृत करने के निर्देश दिए.
- यह फैसला अक्टूबर 2013 से लंबित था.
- आम जन मानस को शुद्ध वायु मिल सके इसलिए बरगद, पीपल, पाकड़ के साथ-साथ फलदार पौधे लगाए जाएंगे. वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गंगा किनारे के भट्ठों व पटना के पास चल रहे भट्ठों पर कार्रवाई का आदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया.

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना लागू करने का निर्णय लिया

बिहार सरकार ने 22 दिसंबर 2015 को मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना लागू करने का निर्णय लिया. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई समीक्षा बैठक में राज्य में शहरों की सफाई को ठीक रखने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना लागू करने का निर्णय लिया गया.

उपरोक्त निर्णय के साथ ही साथ बिहार सरकार की ओर से वर्ष 2015-16 में कार्य के आधार पर सबसे उत्कृष्ट काम करनेवाले एक नगर निगम को पांच करोड़, दो नगर परिषद को तीन-तीन करोड और दो नगर पंचायत को एक-एक करोड़ रुपये स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए दिये जाने की घोषणा की गई.

मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

- मुख्यमंत्री ने 11 नगर निगम की शहरों के लिए सिटी मोबिलिटी प्लान बनाने का निर्णय लिया गया.
- सभी शहरों में एक-एक बस स्टैंड, पार्क, ड्रेनेज व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया गया.
- बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वह अनावंटित 5118 संपत्तियों को तत्काल आवंटित करे.
- अतिक्रमित संपत्तियों को मुक्त किया जाये.
- राज्य में कम आय वाले लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया.
- शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्र में वासभूमि के साथ व्यापक पैमाने पर मल्टी

स्टोरी फ्लैट बनाने को गति दी जाये. अगल पांच वर्षों में चार लाख परिवारों को घर बनाकर देने का निर्णय लिया गया. शहरी विकास को गति देने के लिए लैंड पुलिंग योजना को लागू करने को विभाग को निर्देश दिया गया.

- शहरी क्षेत्र के गराबों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नेटवर्क से तीन वर्षों में जोड़ने का निर्णय लिया गया.
- शहरी स्थानीय निकायों से सुगमतापूर्वक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक साल के अंदर ई-म्युनिसप्लिटी लागू करने का निर्णय लिया गया.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण-1ए को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण-1 ए को मंजूरी दे दी. 6928 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 22.878 किलोमीटर लंबाई की परियोजना में 22 स्टेशन बनाए जाएंगे.

22.878 किलोमीटर लंबाई की परियोजना में तीन भूमिगत मेट्रो स्टेशनों के साथ 3.440 किलोमीटर भूमिगत मार्ग होगा और 19 स्टेशनों के साथ 19.438 किलोमीटर ऊपरगामी मार्ग होगा. मेट्रो ट्रेन चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे और मुंशी पुलिया के बीच चलायी जाएगी.

परियोजना पर 6928 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है. केन्द्र सरकार इक्विटी और सहयोग ऋण के रूप में 1300 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देगी.

परियोजना को केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की संयुक्त कंपनी के रूप में 50:50 के स्वामित्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एलएम्आरसी) द्वारा बनाया जाएगा.

परियोजना निम्न कानूनी ढांचे के दायरे में कार्यरत रहेगी-

- मेट्रो रेल (वर्क्स निर्माण) अधिनियम, 1978
- मेट्रो रेल (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002
- रेल अधिनियम, 1989, समय-समय पर यथासंशोधित

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुप्रतिक्षित पटना मेट्रो रेल परियोजना को 22 दिसंबर 2015 को स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही उन्होंने योजना को अमली रूप देने के लिये मेट्रो परियोजना को भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश भी विभाग को दिया.

मुख्यमंत्री के उपरोक्त स्वीकृति के साथ ही राज्य की बहुप्रतिक्षित परियोजना को आगे पटरी पर दौड़ने का रास्ता साफ हो गया है. इसके तहत मेट्रो रेल का निर्माण पहले चरण में दो रूटों पर किया जाना है. इसमें सगुना मोड़ से मीठापुर इस्ट-वेस्ट कोरिडोर व पटना जंक्शन से नया अतर्राज्यीय बस पड़ाव, नार्थ-साउथ कारिडोर है. इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पटना मास्टर प्लान को तीन माह में स्वीकृत कराने का निर्देश दिया. साथ ही विभाग को नया पाटलिपुत्रा बसाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति का भी निर्देश दिया.

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और सांसद हेमामालिनी हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एंबेसडर नियुक्त

हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और सांसद हेमामालिनी को पर्यटन विभाग का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया. इसकी घोषणा हरियाणा के पर्यटन मंत्री राम बिलास शर्मा ने 22 दिसंबर 2015 को की.

राज्य में पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और सांसद हेमामालिनी को 1 फरवरी 2015 से सूरजकुंड में शुरू हो रहे क्राफ्ट मेले में भी आमंत्रित किया जाएगा.

सूरजकुंड मेले इस बार थीम राज्य के रूप में तेलंगाना तथा थीम देश के रूप में चीन हिस्सा लेगा.

इससे पहले हरियाणा सरकार ने योग गुरू बाबा रामदेव को हरियाणा में योग एवं आयुर्वेद का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया था.

पर्यावरण नियंत्रण हेतु नोएडा-एनसीआर सात जोन में विभाजित

अब नोएडा-एनसीआर में केवल रविवार को ही अवकाश नही रहेगा, अपितु सप्ताह में अवकाश की विभागवार वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है. जिलाधिकारी नोएडा ने 22 दिसम्बर 2015 को यह फैसला पर्यावरण से आम जनता के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के द्रष्टिगत किया है.

निरंतर बढ़ते वाहनों की वजह से नोएडा मे पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है. इससे जनता के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड रहा है.

हर रोज लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं, जिससे जाम लगता है. वाहनो के धुंए से आम लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हो रहे हैं.

क्या है योजना-

- नोएडा में अब एक ही दिन अवकाश नही रहेगा.
- प्रत्येक दिन शहर का कोई ना कोई हिस्सा अब वैकल्पिक रूप से बंद रहेगा.
- आम तौर पर रविवार के दिन कंपनिया और इन्डस्ट्रीज बंद रहती हैं. इस व्यस्था को परिवर्तित कर दिया गया है.
- इसके तहत अब सभी विभगों में से कोई एक विभाग सप्ताह के किसी भी दिन बंद रहेगा. यानि रविवार के अवकाश की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.
- शहर की सभी कंपनियों, इन्डस्ट्रीयों और बाजारों को 7 जोन मे बांटा गया है.
- प्रत्येक दिन किसी एक जोन में अवकाश रहेगा.
- यह कदम प्रदूषण और जाम की वजह से उठाया गया है.
- वाहनो से निकलते धुंए की वजह से पर्यावरण की हवा जहरीली हो चुकी है.

डीडीसीए घोटाले पर दिल्ली सरकार ने गोपाल सुब्रह्मण्यिम आयोग बनाया

21 दिसंबर 2015 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) घोटाले की जांच के लिए एक सदस्यी आयोग का गठन किया.

इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया.

आयोग की अध्यक्षता भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यिम करेंगें. आयोग डीडीसीए के प्रशासकों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा.

आयोग का गठन चेतन सांघी की अध्यक्षता में तीन सदस्ययी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय को डीडीसीए के कामकाज के बारे में गंभीर शिकायतें मिलने के बाद डीडीसीए में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया.

समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ने दिल्ली सरकार को पूछताछ आयोग अधिनियम 1952 के तहत क्रिकेट प्रशासकों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए आयोग के गठन का सुझाव दिया था.

यूपी के विकास के लिए रतन टाटा और सीएम अखिलेश के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए 21 दिसम्बर 2015 को राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. टाटा समूह शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ शिशु स्वास्थ्य, ऊर्जा और विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आय में बढ़ोतरी तथा अवस्थापना विकास में सहयोग के लिए प्रदेश के विकास को गति देगा.

राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव आलोक रंजन और टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से एक्ज़ीक्यूटिव ट्रस्टी आर वेंकट रमन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

विकास कार्यों की निगरानी के लिए संयुक्त राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी. जिसमें प्रदेश सरकार और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि नियुक्त होंगे.

निर्धन और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में राज्य सरकार के प्रयासों को टाटा ट्रस्ट गति देगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक विकास से जुड़े कार्यों में प्रदेश सरकार और टाटा ट्रस्ट दीर्घकालिक भागीदारी निभाएंगे.

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य-

- माताओं एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण कार्यक्रम तैयार कर उसे लागू किया जाएगा. महिलाओं

में खून की कमी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे.

कैंसर-

- प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र की मदद से शुरूआती चरण में ही कैंसर का पता लगाने के लिए एक प्रणाली विकसित कर लागू की जाएगी. साथ ही, कैंसर रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी.

जीवन स्तर-

- जनता के रहन-सहन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट्स गुणवत्तापरक शिक्षा तथा रोजगारपरक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में भी मिलकर कार्य करेंगे.

किसानों के लिए-

- राज्य सरकार और टाटा के बीच होने वाले करार में आफ ग्रिड सौर ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली का विकास तथा सोलर वाटर लिफ्टिंग पम्प्स की स्थापना के काम को प्राथमिकता दी जाएगी.
- हाईटेक प्लाण्ट नर्सरी, हार्टीकल्चर के क्षेत्र में उन्नत तकनीक एवं प्रजातियों का समावेश, एग्रो फारेस्ट्री, जैविक खेती तथा कृषि उपज में बढ़ोत्तरी के लिए भी सम्मिलित रूप से प्रयास किए जाएंगे.
- फसलों का सुरक्षित भण्डारण, कृषि विपणन, लघु सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन, उन्नत प्रजातियों के बीजों के विकास सहित दूध, मैंथा, लहसुन, प्याज मक्का, दालों, केला, आलू आदि के लिए वैल्यू चेन का विकास भी किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उदय योजना में शामिल हुआ

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 19 दिसंबर 2015 को केंद्र सरकार की उदय योजना (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) में राज्य की भागीदारी को अपनी मंजूरी प्रदान की.

विद्युत, कोयला एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक जनता के लिए यह एक नए सूर्योदय के समान है.

11 राज्य - आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पहले ही उदय में शामिल हो चुके हैं.

उदय योजना

उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया. इस योजना में ब्याज-भार, विद्युत की लागत और एटी एण्ड सी की हानियों को कम करने का प्रावधान है. इसके परिणामस्वयरूप डिस्काम्स् लगातार 24 घंटे पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हो जाएंगी. योजना में यह भी प्रावधान है कि राज्य 30 सितंबर 2015 के अनुसार डिस्कॉम के 75 प्रतिशत से अधिक कर्ज को दो वर्षों में अपने ऊपर ले लेंगे. इस योजना में राज्य सरकार को अपने ऋणों का स्वैच्छिक रूप से पुनर्गठन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान देने का प्रावधान है. इस योजना में ऐसे उपायों का प्रावधान है जिनसे विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आयेगी और इससे अंतत उपभोक्ताओं को लाभ होगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग पर लगाया प्रतिबन्ध

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने 18 दिसम्बर 2015 को राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया.

मुख्य तथ्य

- मंत्रीमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, बिक्री, भंडारण और ढुलाई इत्यादि को प्रतिबंधित किया जाएगा.
- अब कोई भी दुकानदार, थोक या खुदरा विक्रेता, फेरी या ठेले वाला किसी भी खाद्य या अखाद्य सामान को पॉलीथीन बैग में नहीं दे सकेगा.
- अब कोई भी व्यक्ति किसी किताब, निमंत्रण पत्र इत्यादि को रखने या ढकने के लिए किसी भी तरह के प्लास्टिक आवरण का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.
- इस प्रतिबंध के तहत ऐसी प्लास्टिक थैलियां शामिल नहीं होंगी जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है, या इसका अभिन्न अंग हैं, जिसमें प्रयोग से पहले चीजें सीलबंद की जाती हैं.
- इसके अतिरिक्त जैव चिकित्सीय कूड़ा-करकट (प्रबंधन एवं संभाल) नियमावली 1998 के तहत निर्दिष्टि प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर यह पाबंदी नहीं लागू होगी.

विदित हो इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने 18 नवंबर को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि पूरे प्रदेश में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए 31 दिसंबर तक अध्यादेश जारी करे.

मुख्यमंत्री ने लगभग 585 करोड़ की 148 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया

उप्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 17 दिसम्बर 2015 को गोरखपुर जनपद के बहुमुखी विकास हेतु लगभग 585 करोड़ रुपए की 148 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. देश के सबसे लम्बे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का पूर्वांचल में बलिया तक विस्तार किया जाएगा.

- मुख्यमंत्री ने 379.70 करोड़ रुपए की 79 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 205.14 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं का लोकार्पण किया.
- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न योजनाओं के तहत 10 हजार 151 लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र भी वितरित किए.
- गोरखपुर शहर की सड़कों के चौड़ीकरण तथा बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा.
- गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए 2.5 एकड़ जमीन खुटहन के पास दी जाएगी.इस सम्बन्ध में केन्द्र से अनुरोध किया गया है.
- शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त किया जाएगा.
- शहर वासियों को पीने के लिए आरओ का पानी उपलब्ध करारा‍या जाएगा.

छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 47.1 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत हुई

महिला एवं बाल विकास विभाग के 16 दिसम्बर 2015 को जारी आकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में भारी कमी दर्ज की गई है. वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुपोषण दर अब 30 प्रतिशत है. पिछले दस वर्षों में कुपोषण दर में 17 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2005-06 (वजन आधारित) के अनुसार प्रदेश में कुपोषण दर 47.1 प्रतिशत थी. कुपोषण दर में यह गिरावट निरंतर जारी है.

कुपोषण व इसके कारण-

- कुपोषण एक चक्र है.
- प्रदेश में कुपोषण की दृष्टि से राज्य के 17 हाई बर्डन जिले हैं.
- खान-पान के गलत तरीकों, भोजन में पौष्टिकता की कमी जैसे कई कारणों से होती है.
- शून्य से छह वर्ष की बालक- बालिकाएं का उचित पालन पोषण न होने के कारण वे इसके शिकार हो जाते हैं.
- कुपोषण से बचने के लिए गर्भवती तथा शिशुवती माताओं की देखभाल अति आवश्यक है.

ललित मोदी पुन: आरसीए अध्यक्ष नियुक्त

आईपीएल के पूर्व विवादित कमिश्नर ललित मोदी 16 दिसम्बर 2015 को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के पद पर पुन: अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं.

उनके विरुद्ध आमीन पठान अविश्वास प्रस्ताव लाए थे. अविश्वास प्रस्ताव की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्रा को चैयरमेन नियुक्त किया था. इससे पहले ही इसे वापस ले लिया गया. मोदी लंदन से ही आरसीए की कमान संभालेंगे.

नियुक्ति के प्रभाव-

मोदी के आरसीए अध्यक्ष बनते ही बीसीसीआई ने संघ की मान्यता रद्द कर दी थी.

क्या था विवाद?

- आरसीए के कामकाज से नाराज कई जिला संघों ने मोदी के खिलाफ बगावत कर दी थी.
- इसी कारण अध्यक्ष मोदी, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया.
- मोदी गुट न्यायालय पहुंचा और करीब एक वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद ज्ञानसुधा मिश्रा को दोबारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया.
- इससे पूर्व क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौजूदगी में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव परित हो गया था.

ललित मोदी के बारे में-

- पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी पर बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगाया है.
- ललित मोदी के खिलाफ 2009 में आईपीएल के टेलिकास्ट राइट्स से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है.

जारी हो चुका है गैर जमानती वॉरंट-

- इस साल अगस्त में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने ईडी की तरफ से दर्ज केस में मोदी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया.
- इसके बाद ईडी ने इंटरपोल से संपर्क करके मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कहा.
- रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद इंटरपोल अपने सदस्य देशों में छुपे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है.

अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित

अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 16 दिसंबर 2015 को विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया.

प्रस्ताव पारित करने वाले 33 सदस्यों में 20 कांग्रेस विरोधी विधायक, 11 बीजेपी विधायक और दो निर्दलीय शामिल हैं.

मुख्यमंत्री नबाम तुकी और उनके मंत्री परिषद के सदस्यों सहित 27 विधायकों ने इस पूरी कार्यवाही का बहिष्कार किया.

महाभियोग प्रस्ताव की पूरी कार्यवाही एक सामुदायिक सभागार के अस्थाई स्थल पर हुई, क्योंकि कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होने की आशंका के कारण जिला प्रशासन ने विधानसभा सचिवालय परिसर को सील कर दिया गया था.

गौरतलब है कि 60 सदस्सीय अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी विधायकों और निर्दलीयों ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ 19 नवंबर को विधानसभा सचिव को महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था.

ऊर्जा संरक्षण के तहत उप्र सरकार ने नया पोर्टल शुरू किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 दिसम्बर 2015 को ऊर्जा संरक्षण के तहत यूपीसेवएनर्जी डॉट कॉम (upsavesen-ergy.com) नाम से पोर्टल शुरू किया है. सरकार का प्रयास गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है.

- इसके लिए 02 करोड़ रुपये के ऊर्जा संरक्षण फण्ड की स्थापना की गयी है.
- वर्ष 2017 तक 500 मेगावाट से अधिक सोलर ग्रिड पावर प्लाण्ट के पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
- निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्लाण्ट स्थापित करने को बढ़ावा दिया जा रहा है.Hindi eBook November 2015
- मै. अदानी ग्रीन एनर्जी लि गुजरात, एसल इन्फ्रा प्रोजेक्ट मुम्बई, सुखबीर एग्रो एनर्जी नई दिल्ली, राधे-राधे इस्पात प्रालि, कानपुर तथा टेक्निकल एसोसिएट लखनऊ के साथ-साथ 05 मेगावाट की 08 परियोजनाओं के पीपीए एमओयू, यूपीपीसीएल के साथ एक दूसरे को सौंपे गए.
- सम्बन्धित अभिलेखों का उप्र पावर कारपोरेशन एवं सम्बन्धित निजी निवेशकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान किया गया.
- ऊर्जा संरक्षण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित लोहिया आवासों में सोलर पावर पैक स्थापित किए जा रहे हैं.
- जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के 10 गरीब परिवारों को सोलर पावर पैक देने के साथ लोहिया एवं जनेश्वर मिश्र ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जा रही है.
- इस पोर्टल के माध्यम से एक व्यापक अभियान चलाकर प्रदेश की जनता को ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा.

राज्यपाल ने उप्र राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2015 को मंजूरी दी

राज्यपाल राम नाईक ने 16 दिसम्बर 2015 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2015 को मंजूरी दे दी. ब्रिटिशकाल से पूर्व के राजस्व कानून को संशोधित करने के उद्देश्य से यह अध्यादेश लाया गया. सरकार ने रेवेन्यू कोड आर्डिनेंस के तहत इसे पारित कराया है. कानून का रूप देने के लिए इसे छह माह में सदन में पास करवाया जाएगा.

- नए अध्यादेश के तहत अब उत्तर प्रदेश के दलितों को अपनी भूमि गैर-दलितों को बेचने का अधिकार मिल गया.
- भले ही विक्रेता के पास साढे तीन एकड से भी कम भूमि क्यों ना हो.
- इस अध्यादेश के बाद पट्टे पर खेती को भी वैधानिक मंजूरी मिल गई है. इसमें जमीन से जुड़े अन्य प्रावधान भी किए गए हैं.

रेवेन्यू कोड ऑर्डिनेंस में मुख्य तथ्य-

- सरकारी जमीन पर दिए जाने वाले पट्टे में अब पट्टा धारक की पत्नी भी सह खातेदार होगी. दोनों के बीच विवाद की स्थिति में वह बराबर की हिस्सेदार होगी. पट्टा हासिल करने के बाद पति की मौत पर भी पत्नी हकदार होगी.
- कोई भी व्यक्ति 5.0586 हेक्टेअर से ज्यादा जमीन सरकार की अनुमति के बिना नहीं खरीद सकेगा. यदि उसके पास पहले से जमीन है तो उसको जोड़कर कुल सीमा इतनी होनी चाहिए. इससे व्यावसायिक उपयोग के लिए किसानों से सस्ती जमीन खरीदने वालों पर लगाम लगेगी.Hindi eBook November 2015
- पैतृक जमीन की खतौनी में कई खातेदार होते हैं. उसमें यह साफ नहीं होता कि कौन सी जमीन किसकी है. यदि आठ खातेदार हैं तो 1/8 लिखा होता है. अब जमीन की खतौनी में सह-खातेदारों के नाम के साथ उनके हिस्से का उल्लेख किया जाएगा. जमीन का भी सीमांकन होगा.
- बड़ी योजनाओं के लिए अर्जित भूमि के बीच में पड़ने वाली लोक उपयोगिता की श्रेणी बदलने के लिए सरकार सक्षम होगी.
- राजस्व विवादों के निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक और अपर आयुक्त न्यायिक की नियुक्ति सरकार कर सकेगी. अभी तक तहसीलदार न्यायिक का ही प्रावधान था.
- खाली जमीन पर चहारदीवारी बनाने भर से ही यह नहीं हो जाएगा कि वह उसका मालिक है.
- जमीन संबंधी वादों के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व समिति होगी. वहां आपसी सुलह से सह खातेदारों के हिस्सों को तय किया जा सकेगा.
- किसी बकाएदार पर 50 हजार रुपए से कम बकाया है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी.
- इससे पहले इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में संशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा मंजूरी के लिए भेजा गया था. जो पारित नहीं हो सका था.

क्या था पहले-

- पहले ऐसी सूरत में जिलाधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही गैर-दलित किसी दलित की भूमि खरीद सकता था.
- इस अध्यादेश से ऐसे जरूरतमंद दलित जिन्हे किसी तरह की पूँजी की आवश्यकता हो तो वे अपनी मर्जी से अपनी भूमि को बेच सकेगा.
- प्रदेश सरकार राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संभवत संशोधन विधेयक पेश करेगी.

सीएम अखिलेश ने 45 अरब लागत की 105 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया

उत्तर प्रदेश में 15 दिसम्बर 2015 को 36 अरब 94 करोड़ रुपए की 58 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है एवं 4 अरब 55 करोड़ रुपए की लागत की 47 परियोजनाएं लोकार्पण की गयी है.

हरदुआगंज थर्मल पॉवर स्टेशन (एचटीपीएस) कासिमपुर के द्वतीय चरण के विस्तार के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएल) की 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई का शिलान्यास किया. इसके अलावा 400 के0वी0, 220 के0वी0 और 132 के0वी0 के 12 विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया.

- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएल) की 660 मेगावॉट की प्रथम सुपर-क्रिटिकल इकाई पर लगभग 4,826 .50 करोड़ रूपये की लागत आएगी.
- राज्य सरकार का यूपीआरवीयूएल इस परियोजना से वर्ष 2019 तक बिजली का उत्पादन शुरु करने का लक्ष्य है.
- इस परियोजना से अलीगढ़ क्षेत्र के साथ-साथ नोएडा व ग्रेटर नोएडा समेत पूरे प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में लाभ मिलेगा.
- परियोजना का निर्माण कार्यदायी संस्था तोशिबा जे0एस0डब्ल्यू0 पावर सिस्टम द्वारा किया जाएगा.
- प्रदेश की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 4,933 मेगावाट है, जो वर्ष 2021-22 तक बढ़कर 10,213 मेगावाट हो जायेगी.

लोकार्पण किए गए 12 विद्युत उपकेन्द्र

मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किए गए 12 विद्युत उपकेन्द्रों के चालू होने से प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाने में काफी मदद मिलेगी.

इन उपकेन्द्रों की सम्मिलित कुल लागत 657.44 करोड़ रुपये है.

ये 12 विद्युत उपकेन्द्र निम्न हैं:

- मुरादनगर-2 (गाजियाबाद, 400 के0वी0),
- अलीगढ़ (400 के0वी0),
- ललितपुर (220 के0वी0),
- डिबाई (बुलन्दशहर) 220 के0वी0,
- बोनेर (अलीगढ़) 220 के0वी0,
- यू0पी0एस0आई0डी0सी0 मसूरी गुलावटी (गाजियाबाद) 132 के0वी0,
- खैरागढ़ (आगरा) 132 के0वी0,
- कुसुमरा (मैनपुरी) 132 के0वी0,
- लहरपुर (सीतापुर) 132 के0वी),
- मुण्डाली (मेरठ) 132 के0वी0,
- चकरनगर (इटावा)132 के0वी0 तथा
- किरथल (बागपत) 132 के0वी0

प्रदेश सरकार के इस प्रयास से अक्टूबर, 2016 तक शहरों को 22 से 24 घण्टे तथा गांवों में 16 घण्टे बिजली मुहैया कराने के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी.

लाभार्थीपरक योजनाएं-

- लाभार्थीपरक योजनाओं के तहत 3,565 लाभार्थी लाभान्वित किए.
- इन योजनाओं के अन्तर्गत 3,565 लाभार्थियों मे से 50 चयनित लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप तत्काल लाभान्वित किया.

वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्त

इलाहबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह को 16 दिसम्बर 2015 को उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया.

ज्ञात हो यह देश में पहली बार हुआ है जब उच्चतम न्यायलय ने नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेते हुए किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की.

इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को दो दिन का समय देते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया था.

उच्चतम न्यायालय ने आदेश के बावजूद उत्तरप्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी. न्यायालय ने अखिलेश सरकार से उन पांच अंतिम नामों की सूची मांगी थी जिन्हें प्रदेश का लोकायुक्त बनाया जा सकता है.

विदित हो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चबतम न्यातयालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश को शामिल किया गया है.

(1) उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा, जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो.

सड़क सुरक्षा पर राधाकृष्णन पैनल की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य बना दिल्ली

शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने 15 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने शुरू कर दिया है.

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद देश में दिल्ली ऐसा पहला राज्य बन गया है.

कार्यान्वयन का प्रभाव

- शराब पीकर गाड़ी चलाना, माल वाहनों में यात्रियों को ले जाना, अधिक तेजी से वाहन चलाना, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना इनमे से कोई भी करते पपे जाने पर यायायात के नियमों का उल्लघन मन जाएगा. ऐसे मामले में तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अन्य जुर्माना का प्रावधान है.Hindi eBook November 2015
- पहली बार अपराधी पाए जाने पर 400 रुपये जुर्माना और उसके बाद पकडे जाने पर जुर्माना और 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा.

नशे में ड्राइविंग के मामले में

- कोर्ट चालान जारी किया जाएगा
- ऐसे ड्राइवरों को मजिस्ट्रेट द्वारा पहली बार 2000 तक रुपये का जुर्माना इसके अलावा 6 महीने जेल की सजा सजा दी जा सकती है.
- नशे की हालत में ड्राइविंग करते दोबारा पकडे जाने पर आरोपी 3000 रुपए का जुर्माना इसके अलावा 2 वर्ष की अवधि के लिए जेल की सजा सजा दी जा सकती है.
- ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा. दोबारा पकडे जाने पर जुर्माने की राशि दो गुनी यानि 2000 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी.
- माल वाहनों में यात्रियों को ले जाना, ड्राइविंग करते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर पहली बार अपराध करने पर 100 रुपए और दोबारा पकडे जाने पर 300 रुपए का जुर्माना किय जा सकता है.

राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 14 दिसंबर 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसने अगले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान की चार स्मार्ट सिटी पर 6457 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मंत्रालय के पास भेजा. अधिसूचना के अनुसार, अब तक कुल 7 राज्यों की ओर से 15 स्मार्ट सिटी प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को प्राप्त हुये हैं.

राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रस्ताव से संबंधित मुख्य तथ्य:

- स्मार्ट सिटी के रूप में अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर को विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 6,457 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है.
- कुल निवेश में जयपुर के लिए 2,403 करोड़ रुपये, कोटा के लिए 1,493 करोड़ रुपये, अजमेर के लिए 1,300 करोड़ रुपये और उदयपुर के लिए 1,221 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है.
- कोटा के निकट एक ग्रीनफील्ड शहर विकसित किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर शेष तीन शहर रेट्रोफिटिंग क्षेत्र (कुछ नया जोड़ना) आधारित स्मार्ट सिटी विकास योजनायें क्रियान्वित करेंगे.
- सभी चारों शहर समस्त सिटी के लिए समाधान लागू करेंगे, जो प्रौद्योगिकी आधारित होंगे.
- जयपुर से जुड़ी स्मार्ट सिटी योजना के तहत 600 एकड़ क्षेत्र में रेट्रोफिटिंग का काम किया जाएगा, जिसमें सतत गतिशीलता वाला गलियारा, स्मार्ट नागरिक बुनियादी सुविधायें और विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है, जिन पर 1583 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. 600 एकड़ के समूचे क्षेत्र में बड़ी चौपड़ एवं छोटी चौपड़ के बीच के पुराने शहर के साथ-साथ अल्बर्ट म्यूजियम भी शामिल है.
- अजमेर में, रेट्रोफिटिंग का काम अन्ना सागर झील के उत्तर और पश्चिम भागों में 1,334 एकड़ से भी ज्यादा के क्षेत्र में किया जाएगा. इसके तहत बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जाएगा और हरित इमारतों का निर्माण किया जाएगा. इस पर 925 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है.
- उदयपुर से जुड़े स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के तहत 880 करोड़ रुपये का निवेश 828 एकड़ क्षेत्र की रेट्रोफिटिंग में किया जाएगा. इसके तहत सीवरेज एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा.
- कोटा हेतु 1045 करोड़ रुपये की लागत से 395 एकड़ क्षेत्र में ग्रीनफील्ड के विस्तारीकरण का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा समस्त शहर के लिए बनाये गये प्रस्ताव के तहत कचरे का ठोस प्रबंधन करने के साथ-साथ स्मार्ट कॉरीडोर का निर्माण किया जाएगा, जिन पर कुल मिलाकर 438 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है.

पंचायत चुनाव हेतु हरियाणा सरकार के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति जताई

सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए नए नियमों पर 9 दिसंबर 2015 को अपनी सहमति व्यक्त की एवं वर्तमान खट्टर सरकार के नए नियम पर लगाए गए हरियाणा हाईकोर्ट के स्टे (रोक) को खत्म कर दिया. इस नियम के तहत अब हरियाणा में केवल

पढ़े-लिखे उम्मीवदवार ही पंचायत चुनाव में खड़े हो सकेंगे.

हरियाणा की वर्तमान मनोहर खट्टर सरकार ने राजनीति का स्तअर सुधारने के लिए नया कदम उठाते हुए 11 अगस्तन 2015 को मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके नए नियम बनाए गए थे, जिन पर हरियाण हाईकोर्ट ने स्टेा लगा दिया था. इसके बाद सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील थी.

विदित हो कि हरियाणा सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक व महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लिए 8वीं पास तय कर दी थी. अधिनियम में जो संशोधन किए गए थे उनके उनुसार पंचायती राज संस्थांओं में सभी स्त.र के निर्वाचित प्रतिनिधियों की न्यू नतम शैक्षणिक योग्यचता 10 पास होना जरूरी है वहीं महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का 8वीं पास होना आवश्य क है. इसके अलावा जिन लोगों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें अिन मामलों में 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. साथ ही जिन लोगों ने सहकारी बैंकों से लिया गया कर्ज नहीं चुकाया है वो भी अयोग्यन करार दिए गए हैं.

उपरोक्त के अलावा अधिनियम में दो और संशोधन किए गए. जिनके अनुसार उम्मी दवार घरेलू बिजली कनेक्शकन की बकाया राशी चुकाने के बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे साथ ही चुनाव में खड़ा होने के लिए उनके घर चालू शोचालय होना जरूरी है.

फ्रैंक इस्लाम को मिलेगा उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार

भारतीय मूल के एक अमेरिकी उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति फ्रैंक इस्लाम को उनकी उपलब्धियों और विदेश में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार किया जाएगा.

आजमगढ़ जिले में पैदा हुए 63 वर्षीय इस्लाम को चार जनवरी को आगरा में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सम्मानित करेंगे.

इस्लाम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है.

उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से राज्य में जन्मे प्रवासी भारतीय को उनकी उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मनित किया जाएगा.

यूपी प्रवासी दिवस

उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवासी वर्ष 2016 में 4 से 6 जनवरी के मध्य आगरा में आयोजित किया जाएगा.

यूपी प्रवासी दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में एनआरआई विभाग की स्थापना के साथ हुई. इस दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से बड़े पैमाने पर विदेशों में बसे भारतीयों और उत्तर प्रदेश एनआरआई/पीआईओ के साथ जोड़ना है.

उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार

यूपी रत्न पुरस्कार राज्य से प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान को पहचान करने के लिए स्थापित किया गया है.

राजस्थान में 126 मेगावाट की प्रतापगढ़ पवन परियोजना की शुरुआत

ऊर्जा उत्पादन कंपनी वेलस्पन रिन्यूवल एनर्जी ने 7 दिसम्बर 2015 को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 126 मेगावाट पवन परियोजना के शुरू करने की घोषणा की. यह 126 मेगावाट प्रतापगढ़ पवन परियोजना वेलस्पन रिन्यूवल एनर्जी पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी पवन परियोजना है.

यह परियोजना 290 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगी और वार्षिक 211922 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी. कंपनी ने इस परियोजना में 840 करोड़ रुपए का निवेश किया है.

विदित हो वर्ष 2015 में वेलस्पन रिन्यूवल एनर्जी ने पूरे देश में 700 मेगावाट (डीसी) ऊर्जा का उत्पादन किया है. कम्पनी का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा(सौर्य और पवन ऊर्जा के माध्यम से) का उत्पादन है. वर्तमान में वेलस्पन रिन्यूवल एनर्जी भारत के 10 राज्यों में में मौजूद है.

वेलस्पन एनर्जी लिमिटेड एक स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादनकर्ता कंपनी है. यह नई दिल्ली, भारत में स्थित है. यह भारत की सबसे बड़ी सौर्य ऊर्जा उताप्दन कम्पनी है. विदित हो इस कम्पनी के कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन(यूएनएफसीसी) में पंजीकृत है. ज्ञात हो वर्ष 2014 के 31 दिसम्बर तक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भारत में 33.8 गीगावाट थी.

महाराष्ट्र, विधानमंडल में ऑनलाइन प्रश्नों की अनुमति देने वाला देश का पहला राज्य बना

महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके विधानमंडल सदस्य प्रश्नों को ऑनलाइन माध्यम से

पूछ सकते हैं. यह घोषणा 7 दिसम्बर 2015 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान की गई.

इस कदम का उद्देश्य कागज के प्रयोग को कम करना है.

इस क्रम में एक नई वेबसाईट(http://mls.org.in/) को लॉन्च किया गया है, जिसकी एक्सेस सभी विधान सभा और विधान परिषद सदस्यों को दी गई है. जिसके माध्यम से सदस्य ऑनलाइन ही प्रश्नों को पूछ सकते हैं.

सदन के सभी सदस्यों को अलग - अलग यूजर नेम और पासवर्ड प्रदान किया गया है.

इसके अतिरिक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और आधे घंटे की परिचर्चा जैसे सदन के अन्य कार्यों के लिए अनुरोध करना भी इसके माध्यम से आसान होगा. इस वेबसाइट का प्रयोग इस वर्ष के शीतकालीन सत्र से प्रारंभ हो गया है. इस सत्र के दौरान 28 प्रतीशत प्रश्नों को ऑनलाइन माध्यम से पुछा गया.

इस वेबसाइट के सदुपयोग के लिए विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को पूर्व में ही इसका प्रशिक्षण दिया गया था. परन्तु वर्ष 2016 के बजट सत्र को ऑफलाइन माध्यम से ही आयोजित किया जाएगा.

इस कदम से अनुमान है की कुल खर्च में 20 प्रतिशत की कमी आएगी.

राजस्थान यूडीएवाई योजना में शामिल

राजस्थान सरकार ने 07 दिसम्बर 2015 को विद्युत मंत्रालय को यूडीएवाई योजना (उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना) में शामिल करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है.

यूडीएवाई के बारे मे-

यूडीएवाई योजना (उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना) बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और संचालन क्षमताओं में सुधार करने के लिए लांच की गई है. इसमें ब्याज बोझ, बिजली की लागत तथा एटी एण्ड सी घाटों को कम करने की पर्याप्त व्यवस्था है.

यूडीएवाई के लाभ-

इस व्यवस्था के बाद बिजली वितरण कंपनियां सातों दिन 24 घंटे (24x7) पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होंगी. जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी.

इस योजना के नियमानुसार 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, संबंधित राज्य दो वर्षों में डिस्कॉम का 75 प्रतिशत से अधिक का ऋण ले सकते हैं. साथ ही राज्य सरकार को यूडीएवाई के जरिए अपने ऋण का स्वैच्छा से पुनर्गठन करने व बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

यूडीएवाई में ऐसे नियमों की व्यवस्थाकी गयी है जिससे बिजली उत्पादन लागत में कमी आएगी और अंततः उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा.

आंध्र प्रदेश डिस्कॉम पुनरुद्धार योजना 'उदय' में शामिल होने वाला पहला राज्य बना

आन्ध्र प्रदेश 5 दिसम्बर 2015 को केंद्र सरकार की उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य बना. इस योजना का उद्देश्य कर्ज में डूबी उर्जा कम्पनियों का पुनरुद्धार करना है.

आन्ध्र प्रदेश ने उर्जा मंत्रालय द्वारा उदय में शामिल होने की मंजूरी देने के बाद इसमें शामिल होने का निर्णय लिया.

उदय योजना में ऋण, उर्जा की लागत, तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को कम करने हेतु प्रयास किये जायेंगे. परिणामस्वरूप उर्जा कम्पनियां 24x7 उर्जा उपलब्ध करा सकेंगी.

यह एक वैकल्पिक योजना है जिसमें राज्य सरकारें, राज्य डिस्कॉम एवं केंद्र सरकार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके शामिल हो सकते हैं.

इसके अतिरिक्त उदय योजना में शामिल होने वाले राज्य हैं झारखण्ड (दूसरा राज्य) एवं राजस्थान (तीसरा राज्य).

उदय योजना की विशेषताएं

- राज्य सरकार डिस्कॉम पर देय 30 सितंबर 2015 तक का 75 प्रतिशत ऋण चुकाएगी.
- केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे में 2015-16 एवं 2016-17 के ऋण को शामिल नहीं करेगी.
- राज्य सरकार बाज़ार में नॉन-एसएलआर बांड जारी करेगी अथवा ऋण की मार झेल रहे डिस्कॉम को प्रत्यक्ष रूप से बांड भेजेगी.
- राज्य द्वारा भविष्य में होने वाले घाटे को वहन किया जायेगा.
- जो राज्य उदय योजना में शामिल हुए हैं उन्हें अतिरिक्त फण्ड मुहैया कराया जायेगा.
- जो राज्य परिचालन व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे उन्हें आईपीडीएस एवं डीडीयूजीजेवाई अनुदान पर उनके दावे से बाहर रखा जा सकता है.

झारखंड 'यूडीएवाई' योजना में शामिल

झारखंड सरकार ने यूडीएवाई योजना (उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना) में शामिल होने के लिए बिजली मंत्रालय को 5 दिसंबर 2015 को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी.

यूडीएवाई योजना से संबंधित मुख्य तथ्य:

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय और परिचालन क्षमताओं में सुधार लाने के लिए यूडीएवाई (उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना) योजना शुरू की गई है. इसमें ब्याज के बोझ, बिजली की लागत और एटी एंड सी के नुकसान को कम करने की परिकल्पना की गई थी, ताकि डिस्कॉम सतत् 24x7 पर्याप्त और टिकाऊ बिजली आपूर्ति कर सके. इस योजना से 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, संबंधित राज्य दो वर्षों में डिस्कॉम का 75 प्रतिशत से अधिक का ऋण ले सकते हैं. इसके साथ ही यूडीएवाई के जरिए राज्य सरकारों को अपने ऋण का स्वैच्छा से पुनर्गठन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है.

हिमाचल प्रदेश रोटावायरस टीकाकरण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य

हिमाचल प्रदेश 3 दिसंबर 2015 को रोटावायरस टीकाकरण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया. टीकाकरण अगले माह जिला कांगड़ा शुरू की जाएगी.

रोटावायरस टीका से दस्त के कारण होने वाली (पांच वर्ष से कम उम्र के) बाल मृत्यु दर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

रोटावायरस टीके की तीन खुराक छह, दस और चौदह सप्ताह की उम्र में शिशुओं को पिलायी जाएगी. यह प्रशासन और यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) का हिस्सा हैं.

रोटावायरस टीकाकरण परियोजना की मुख्य विशेषताएं-

- परियोजना धर्मशाला में राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा शुरू की गयी.
- प्रशासनिक अधिकारी पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोटावायरस वेक्सिन पिलाकर कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे.

- अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक महामारी नेटवर्क टीकाकरण में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी और टीकों पर होने वाला पूरा खर्च भी वहन करेगी.
- परियोजना जल्द ही पुणे, महाराष्ट्र और वेल्लोर तमिलनाडु में शुरू की जाएगी.

रोटावायरस क्या है?

- भारत में 11 महीने की आयु से कम उम्र के शिशुओं में होने वाली गंभीर दस्त (एमएसडी) की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावशाली टीका है.
- यह रेवोरिड समूह में डबल स्टैण्डर्ड आरएनए वायरस की एक प्रजाति है.
- कीटाणुओं के कारण यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है. मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी इस बीमारी का कारक है.
- यह कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट करता है

दिल्ली विधानसभा द्वारा विधायकों के वेतन में 400 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव पारित

दिल्ली सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विधायकों की बेसिक सैलरी में 400 प्रतिशत बढ़ोतरी का विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया.

इससे विधायकों का बेसिक वेतन 12,000 प्रतिमाह से बढ़कर 50,000 रुपये हो जायेगा. अन्य सभी भत्तों आदि को मिलाकर अब दिल्ली के विधायक को करीब 2,35,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा.

विधेयक में विधायकों के लिए वेतनवृद्धि के अलावा विधानसभा में उपस्थिति के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 1,000 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर 2,000 रुपए प्रतिदिन कर कर दिया गया है.

विधायक का यात्रा भत्ता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है. मंत्री की बेसिक सैलरी 20,000 से 80,000 कर दी गयी है जबकि निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है.

आर्थिक वृद्धि के मामले में बिहार सबसे आगे : ब्रिकवर्क रेटिंग्स रिपोर्ट

ब्रिकवर्क रेटिंग्स की ओर से दिसंबर 2015 के प्रथम सप्ताह में जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मामले बिहार सबसे आगे है. इस रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 17.06 प्रतिशत रही. वहीं महाराष्ट्र 11.69 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा 16,870 अरब रुपये के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा.

उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहे हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र से काफी पीछे हैं. इन राज्यों का जीएसडीपी 9,670 अरब रुपये (प्रत्येक) है. इसके साथ ही जब जीएसडीपी में उद्योग के योगदान की बात आती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र से आगे है. गुजरात के जीएसडीपी में उसके उद्योग का योगदान 27.26 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र के मामले में यह 25.18 प्रतिशत है. वहीं जीएसडीपी की वृद्धि दर के मामले में 17.06 प्रतिशत के साथ बिहार सबसे आगे है. मध्य प्रदेश 16.86 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ दूसरे, गोवा 16.43 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा. नया बना राज्य तेलंगाना 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ काफी पीछे है.

ब्रिकवर्क रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में जुटाए गए करों पर निर्भरता के मामले में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है. उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों में करों का हिस्सा 70 प्रतिशत है. इस मामले में उसके बाद गुजरात और तमिलनाडु का स्थान आता है. व्यय के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य औसतन 43 प्रतिशत खर्च सामाजिक सेवाओं पर करते हैं. वे आर्थिक सेवाओं पर 22 प्रतिशत तथा सामान्य सेवाओं पर 23 प्रतिशत खर्च करते हैं.

झारखंड सरकार मत्स्य विकास निगम का गठन करेगी

झारखंड सरकार ने 1 दिसंबर 2015 को मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मत्स्य विकास निगम के गठन निर्णय लिया है. इसकी विधिवत स्थापना के लिए अध्ययन हेतु राज्य की एक टीम असम भेजी जायेगी. असम में हाल ही में निगम का गठन किया गया है. अध्ययन के बाद निगम की रूप-रेखा तय की जाएगी.

राज्य में मत्स्य विकास निगम के गठन का उद्देश्य

- 2017-18 तक झारखंड ने दूसरे राज्यों में मछली भेजने का लक्ष्य रखा है.

- 2016-17 तक राज्य के लिए मछली उत्पादन की जरूरत पूरा करना.
- राज्य अभी 1200 केज में मछली का उत्पादन कर रहा है. अगले साल इसकी संख्या पांच हजार करने का लक्ष्य है.
- वर्तमान में राज्य में 1.05 लाख एमटी मछली का उत्पादन किया जा रहा है जबकि जरूरत 1.40 लाख एमटी की है.

राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय

कुआं, तालाब, डोभा आदि के अतिरिक्त सीसीएल, इसीएल, बीसीसीएल की बंद पड़ी खदानों को भी मछली उत्पादन के लिए तैयार किया जाएगा. वर्तमान में राज्य में करीब 85 हजार जमाबंदी तथा 26 हजार सरकारी तालाब हैं. मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए पिकअप वैन दिया जा रहा है. एक लाख आठ हजार मत्स्य पालकों का बीमा भी कराया गया है.

गुजरात श्रम कानून संशोधन विधेयक-2015 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्रम कानून (गुजरात संशोधन) विधेयक-2015 को स्वीकृति प्रदान की, इससे गुजरात विधानसभा में फरवरी 2015 में पारित विधेयक कानून बन सकेगा.

विधानसभा द्वारा 25 फरवरी को विधेयक श्रम कानूनों को लचीला बनाने हेतु पारित किया गया. इसमें उद्योगों के दौरान मजदूरों एवं कर्मचारियों के मध्य होने वाले विवादों को अदालतों से बाहर सुलझाने पर बल दिया गया है.

कानून की विशेषताएं

- इसमें जनपयोगी सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान दिया गया है.
- इसके अनुसार मजदूर किसी उद्योग द्वारा लिए गये निर्णय पर तीन वर्ष की बजाय एक वर्ष के भीतर आपत्ति उठा सकेंगे. इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूर केवल एक वर्ष में ही किसी निर्णय के विरोध में अदालत में जा सकेंगे.
- अदालती मामलों से बचने के लिए इस विधेयक में अनावश्यक और अंतहीन मुकदमेबाजी कम की गयी है. इसके अनुसार मजदूर बिना अदालती कार्यवाही के नियोक्ता से समझौता कर सकते हैं. अदालत से बाहर किये गये समझौते में सरकार नियोक्ता से 21,000 रुपये जुर्माना वसूलेगी तथा आहत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को 75 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी.

- इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कुछ बदलाव किये गये हैं जिसमें सरकार को उद्योगों पर अधिक अधिकार दिए गये हैं.
- इसके अनुसार किये गये बदलावों में जिन उद्योगों में 20 से अधिक मजदूर कार्यरत हैं उनमें चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को भी बल प्रदान करेगा.

यह विधेयक, 'गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध में नियंत्रण विधेयक' के साथ राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया था.

'दि हिन्दू' समाचार पत्र के अनुसार दाखिल सूचना का अधिकार याचिका से पता चला कि राष्ट्रपति ने 20 सितंबर 2015 को ही इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी थी. इसके अतिरिक्त 34 अन्य विधेयकों को भी स्वीकृति प्रदान की गयी है. विभिन्न राज्यों द्वारा 65 विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गये जिसमें सिक्किम स्थानीय रोजगार संवर्धन एवं गुजरात आतंकवाद विधेयक भी शामिल हैं.

हालांकि राष्ट्रपति ने सिक्किम स्थानीय रोजगार संवर्धन विधेयक-2008 को स्वीकृति देने से मना कर दिया. इसे 26 सितंबर 2015 को इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि यह संविधान की धारा 14,15 एवं 19 का उल्लंघन करता है. इस विधेयक के अनुसार जिन लोगों के पास सिक्किम सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट है उन्हें प्राइवेट सेक्टर में 80 प्रतिशत रोज़गार का अवसर दिया जायेगा.

कारखाना अधिनियम, 1948 के संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी

भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30 नवम्बर 2015 महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कारखाना अधिनियम, 1948 के संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी. इस संशोधन के बाद महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कारखानों में कार्य करना संभव होगा.

विदित हो वर्ष 2015 के जुलाई माह में महाराष्ट्र विधानसभा ने कारखाना अधिनियम,1948 की धारा 66 में संशोधन प्रस्तावित किया था.

प्रस्तावित संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था.

इस संशोधन के साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जो महिलाओं से रात की पाली में कार्य करवाने के प्रति प्रयासरत हैं.

- उक्त संशोधन 'इंस्पेक्टर राज' की प्रथा को भी हतोत्साहित करेगा और इस क्रम में भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित करेगा. इस संशोधन के चलते एक फेक्ट्री इंस्पेक्टर को फेक्ट्री के विरुद्ध मामला दर्ज करने से

पहले चीफ फेक्ट्री इंस्पेक्टर से अनुमति लेनी होगी.

- संशोधन के पश्चात अब 90 दिन कार्य करने के बाद कर्मचारी 'पेड लीव' का हकदार होगा. पूर्व में यह सुविधा 240 दिनों के बाद मिलती थी.
- अब प्रबंधन की अनुमति से ओवर टाईम को भी 75 घंटे से बढ़ा कर 115 घंटे किया जा सकता है.
- इस संशोधन के बाद निराक्षण और प्रमाणन जैसी गतिवधि उन्ही कारखानों के लिए अनिवार्य है जहां न्यूनतम कर्मचारी 20(बिजली का प्रयोग ना करने वाले कारखाने) और 40(बिजली का प्रयोग करने वाले कारखाने) हैं.

झारखण्ड सरकार ने पूर्ण राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया

झारखण्ड सरकार ने 1 दिसम्बर 2015 को पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया. राज्य ने केंद्र सरकार से सहायता की मांग भी की. यह निर्णय मुख्यमंत्री रघुबर दास की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया गया जिसके कारणों में वर्ष 2015 में हुई बेहद कम बारिश की वजह से फसलों का बर्बाद होना शामिल है. राज्य कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया कि केंद्र सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि केंद्र सरकार की टीम सूखा प्रभावित राज्य का दौरा करने के लिए एक टीम भेज सके.

इससे पहले राज्य कृषि विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि राज्य के 64 ब्लॉक में फसल 50 प्रतिशत बर्बाद हुई है जबकि 62 ब्लॉक में 40 प्रतिशत नुकसान हुआ है.

दिल्ली विकास प्राधिकरण ई-इंडिया पुरस्कार से सम्मानित

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 1 दिसंबर 2015 को ई-इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

डीडीए को यह पुरस्कार जनसेवा में प्रौद्योगिकी और मोबाइल एप्प जैसे संसाधनों के उचित उपयोग के लिए दिया गया है.

यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित ई-भारत शिखर सम्मेलन 2015 में दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से डीडीए(सिस्टम), निदेशक वीएस तोमर को प्रदान किया गया.

यह पुरस्कार डीडीए को निम्न मोबाइल एप्प के विकास के लिए दिया गया

- डीडीए को पुरस्कार, डिजिटल इंडिया आईटी पहल की श्रेणी में भूमि संरक्षण और इंजीनियरिंग परियोजनाओं के क्षेत्र में असाधारण आईटी पहल के लिए प्रदान किया गया.
- अतिक्रमण पर नज़र रखने के लिए बनाए गए एप्प 'वेकेंट लैंड फोटो अपलोडिंग सिस्टम'
- डीडीए को दूसरा पुरस्कार 'मेज़रमेंट बुक' नामक एप्प के लिए दिया गया जिसका सम्बन्ध मानकों और परियोजना आवश्यकताओं के सटीक आकलन के लिए होता है.

दिल्ली सरकार ने ई-जिला परियोजना आरंभ की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 नवम्बर 2015 को महत्वाकांक्षी 'ई जिला परियोजना' की शुरूआत की. इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को दिल्ली सरकार की विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी.

ई-जिला परियोजना के तहत निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी:

- इस सेवा के आरंभ होने से प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा सकेगा.
- दिल्ली सरकार ने 1962 से जाति के आंकड़ों को पूरी तरह डिजिटल किया है जो उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं.
- परियोजना के प्रथम चरण में जिन प्रमाणपत्रों का चयन किया गया है वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवास, निशक्तता कार्ड, आय, जन्म, विवाह पंजीकरण, मृत्यु प्रमाणपत्र और लाल डोरा प्रमाणपत्र शामिल हैं.
- परियोजना के तहत प्रमाणपत्रों का डुप्लीकेशन भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा.

ई-जिला परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

- जिला प्रशासन द्वारा दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ एकल खिड़की के माध्यम से नागरिक सेवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करना.
- सार्वजनिक मामलों / अपील / शिकायतों /जानकारी प्रदान करने इत्यादि कार्यो का तेजी से निपटान.
- कार्य भार मे कमी के लक्ष्य के साथ कर्मचारियों की दक्षता में सुधार करना.
- पोस्ट परियोजना मूल्यांकन द्वारा आगामी सुधार के लिए फीडबैक प्रदान करने हेतु.
- नागरिकों सेवाओ को शीघ्र प्रदान करने हेतु भी इसकी शुरुआत की गयी है.

न्यूज कैप्सूल

चर्चित व्यक्ति

ज्ञानेन्द्र डी बंदग्यान नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेन्स (एनसीजीजी) के महानिदेशक नियुक्त

- अर्थशास्त्री तथा पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेन्द्र डी बंदग्यान को नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेन्स (एनसीजीजी) का 30 दिसंबर 2015 को महानिदेशक नियुक्त किया गया.
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके ज्ञानेन्द्र की नियुक्ति तीन वर्ष के लिये की गई.
- इसे 2 वर्ष के लिये या 60 वर्ष पूरा होने तक बढ़ाया जा सकता है.
- पूर्व आईएएस अधिकारी 54 वर्षीय ज्ञानेंद्र मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं.
- एनसीजीजी बेहतर राजकाज सुधार पर एक शोध संस्थान है. एनसीजीजी एक स्वायत्त संस्थान है जो डीओपीटी के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है.

याहू इंडिया के वर्ष 2015 के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व सूची में गाय (Cow) को शीर्ष स्थान

देश में सक्रिय अग्रणी इंटरनेट सर्च इंजन 'याहू' की वर्ष 2015 में भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व की सूची में 'गाय' (Cow) ने शीर्ष स्थान हासिल किया है. याहू द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा 21 दिसंबर 2015 को की गई.

याहू ने वर्ष 2015 में सर्वाधिक चर्चित रहे मुद्दों, घटनाओं और आयोजनों की वार्षिक समीक्षा के तहत यह सूची जारी की. याहू ने कहा कि इंटरनेट पर गाय सर्च की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से प्रारंभ हुई, जिस पर इंटरनेट पर विवाद छिड़ा रहा. वक्तव्य में आगे कहा गया है कि दादरी हत्याकांड, अवार्ड वापसी और बेहद चर्चित रहा असहिष्णुता का मुद्दा ऐसे कारण रहे जिसके चलते गाय इस सूची में शीर्ष पर पहुंच गई.

याहू इंडिया के अनुसार, राजनीतिक हस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाधिक सर्च किए गए राजनेता रहे. जबकि समाचारों की श्रेणी में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट को सर्वाधिक सर्च किया गया. इसमें दिवंगत हुए पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम दूसरे और आईसीसी विश्व कप-2015 तीसरे स्थान पर रहा.

गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद मुख्य अतिथि होंगे

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद भारत के 67वें गणतंत्र दिवस समारोह में 26 जनवरी 2016 को मुख्य अतिथि होंगे. उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की संभावना है. ओलांद ने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है.

- यह पांचवीं बार है जब फ्रांस का कोई नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होगा.
- इससे पहले फ्रांस्वा ओलांद फरवरी 2013 में भारत आए थे. किसी देश के लिए अब तक की यह अधिकतम संख्या है.
- इससे पहले फ्रांस के नेता जेक्सशिराक़ वर्ष 1976 और 1998 में, वलेरी गिस्कार्द 1980 में, और निकोलस सरकोजी 2008 में इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आ चुके हैं.
- भूटान के राष्ट्राध्यक्ष ने 1954, 1984, 2005 और 2013 में अब तक चार बार अध्यक्षता की है.
- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पहली अमेरिकी राष्ट्रपति थे.

भारत-फ्रांस द्विपक्षीय संबंध-

भारत द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण करने के बाद फ्रांस पहला देश था जिसने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की. फ्रांस ही वह पहला देश है जिसने 2008 में भारत के एनएसजी छूट प्राप्त करने के बाद असैन्य परमाणु ऊर्जा में प्रवेश करने में सहयोग किया.

ठाकुर अनूप सिंह ने मिस्टर वर्ल्ड-2015 का खिताब जीता

ठाकुर अनूप सिंह ने 1 दिसंबर 2015 को बैंकॉक में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में मिस्टर वर्ल्ड-2015 का खिताब जीता. इस प्रतियोगिता में अनूप सिंह ने 43 देशों से आए बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ा. यह प्रतियोगिता डब्लूबीपीएफ (WBPF) वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक चैम्पियनशिप के तहत आयोजित किया गया था.

विदित हो कि ठाकुर अनूप सिंह ने वर्ष 2015 का मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता भी जीता था. वे वर्ष 2015 के एशियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक के कास्य पदक विजेता भी रह चुके हैं.

नियुक्त

करण अडानी, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के सीईओ नियुक्त

अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेडएल) ने 28 दिसम्बर 2015 को सुदीप्ता भट्टाचार्या के स्थान पर करण अडानी को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया.

कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठक के बाद निर्णय लिया कि भट्टाचार्या का इस्तीफा 31 दिसंबर को कारोबारी घंटे समाप्त होने के बाद प्रभावी हो जाएगा.

निदेशक मंडल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए 1 जनवरी 2016 से करण अडानी को नया सीईओ नियुक्त किया है.

चार वर्ष पहले अडानी समूह से जुड़े कंपनी के पूर्ण कालिक निदेशक भट्टाचार्या अमेरिका में अडानी समूह के ग्रुप सीईओ (उत्तरी अमेरिका) का पदभार सँभालेंगे.

करण वर्ष 2009 से विभिन्न अडानी पोर्ट्स के ऑपरेशन का प्रबंधन कर रहे हैं. वह देश भर के पोर्ट्स के स्ट्रैटजिक डेवलपमेंट का काम देखेंगे.

अमिताभ कांत को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 28 दिसंबर, 2015 को अमिताभ कांत को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा. यह अतिरिक्त प्रभार 31 दिसंबर 2015 से प्रभावी होगा. कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर का स्थान लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 31 दिसंबर 2015 को खत्म हो जाएगा. केरल कैडर के 1980 बैच के आईएएस

अधिकारी कांत वर्तमान में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव के रूप में सेवा कर रहे हैं.

अमिताभ कांत का कार्यकाल 28 फ़रवरी 2016 तक निर्धारित है.

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एनआईटीआई)

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एनआईटीआई) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 65 वर्ष पुरानी संस्था योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई. भारत सरकार ने यह कदम राज्य सरकारों, विशेषज्ञों तथा प्रासंगिक संस्थानों सहित सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद उठाया.

भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के अध्याक्ष होंगे. इस संस्था में एक उपाध्यक्ष तथा एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) होगा. उपाध्यक्ष की नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष करेगा.

आयोग में संचालन परिषद होगी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यमपालों को शामिल किया जाएगा. यह संचालन परिषद राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तैयार करेगी.

राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तैयार करने के लिए आयोग में अधिकतम पांच पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होंगे जबकि चार केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे.

पवन कुमार अग्रवाल एफएसएसएआई के सीईओ नियुक्त

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल 22 दिसंबर 2015 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया.

वे युद्धवीर सिंह मलिक के स्थान पर नियुक्त किये गये हैं. युद्धवीर सिंह को सितम्बर 2015 में अपर सचिव के रूप में नीति आयोग में भेज दिया गया था. उन्होंने ही नेस्ले के प्रसिद्ध ब्रांड मैगी पर प्रतिबन्ध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

पवन कुमार अग्रवाल से पहले एफएसएसएआई के निदेशक आशीष बहुगुणा अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी के रूप में यह पद संभाल रहे थे.

पवन कुमार अग्रवाल वर्ष 1985 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी हैं. इस समय वे केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

जेट एयरवेज़ ने अमित अग्रवाल को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया

निजी विमान चालक कंपनी जेट एयरवेज़ ने 22 दिसंबर 2015 को अमित अग्रवाल को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया.

गौरतलब है कि जेट एयरवेज़ में मुख्य वित्तीय अधिकारी का पद मार्च 2014 से रविशंकर गोपालकृष्णन के जाने के पश्चात् से रिक्त था.

47 वर्षीय अग्रवाल चार्टेड अकाउंटेंट हैं तथा उन्हें 24 वर्षों का वृहद अनुभव है. वे भारत के अतिरिक्त, यूरोप में आर्सेलर मित्तल तथा उत्तरी अमेरिका में एस्सार स्टील में भी कार्यरत रहे हैं. वे कम्पनी का वित्त तथा राजकोषीय प्रबंधन देखेंगे.

इससे पहले अग्रवाल अक्षय ऊर्जा कंपनी सुजलोन में सीएफओ पद पर कार्यरत थे.

जेट एयरवेज़ के विमान भारत में 51 स्थानों एवं विश्व भर में 22 स्थानों के लिए उड़ान भरते हैं जिसमें 115 कर्मचारी कार्यरत हैं.

जेफ विलियम्स एप्पल इंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) नियुक्त

जेफ विलियम्स 18 दिसंबर 2015 को एप्पल इंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) नियुक्त किए गए. एप्पल के सीओओ का पद वर्ष 2011 में टिम कुक के सीईओ बनने के बाद से खाली था.

विलियम्स पिछले 17 वर्ष से एप्पल इंक के साथ काम कर रहे हैं.

इसके अलावा जॉनी स्रोउजी को हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और टॉर मेहेरन को मार्केटिंग कम्युनिकेशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया.

जेफ विलियम्स के बारे में

- विलियम्स वर्ष 1998 में एप्पल में शामिल हुए थे.
- वर्ष 2004 से विलियम्स कंपनी की सप्लाई चेन, सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ सोशल रेस्पान्सिबिलिटी वाले कार्यों को भी देखा करते थे.

- उन्होंने आईफोन के लांच के साथ ही मोबाइल फोन के बाजार में एप्पल की प्रविष्टि करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
- एप्पल में शामिल होने से पहले, विलियम्स ने आईबीएम में तीन साल तक इंजीनियरिंग और संचालन की भूमिका में काम किया.
- इसके अलावा सीनियर वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट फिल शिलर को ऐप स्टोर के प्रमुख का अतिरिक्त चार्ज दिया गया.

पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर नए सीआईसी नियुक्त

पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर 18 दिसम्बर 2015 को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किए गए. अब तक सेवारत सूचना आयुक्तों के बीच से ही सीआईसी की नियुक्ति की जाती रही है. यह नियुक्ति परिपाटी से हटकर की गयी है.

आर के माथुर अब तक सीआईसी रहे विजय शर्मा का स्थान लेंगे. एक दिसंबर को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद रिक्त हुआ है.

आर के माथुर की नियुक्ति तीन साल के लिए की गयी है. वह 65 साल की उम्र तक पदासीन रहेंगे.

आर के माथुर केबारे में-

- त्रिपुरा संवर्ग के सेवानिवृत आईएएस अधिकारी 62 वर्षीय माथुर 28 मई, 2013 को दो साल की निश्चित अवधि के लिए रक्षा सचिव बनाये गये थे.
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) से स्नातक और आईआईटी दिल्ली से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने वाले माथुर अपने संवर्ग राज्य और केंद्र में कई अहम पदों पर रहे हैं.
- वह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम तथा रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति दोनों ही मंत्रालय में सचिव भी रहे.
- प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली चयन समिति ने बुधवार को माथुर के नाम को अंतिम रूप दिया.
- इस समिति में वित्त मंत्री अरुण जेटली और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं.

न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल ने दिल्ली के लोकायुक्त पद की शपथ ली

दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रेवा क्षेत्रपाल ने 17 दिसंबर 2015 को दिल्ली के लोकायुक्त पद की शपथ ली. दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई.

विदित हो कि अक्टूबर 2015 में ही उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता (दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता) के साथ हुई बैठक में दिल्ली के लोकायुक्त पद हेतु न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल के नाम पर सहमति बनी थी.

न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल से संबंधित मुख्य तथ्य:

न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल दिल्ली उच्च न्यायालय से वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हुईं न्यायाधीश हैं. उनका जन्म शिमला में 23 सितंबर 1952 को हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई जीसस एंड मेरी स्कूल से हुई. उन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) से इतिहास में स्नातक किया है. उसके पश्चात उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी से कानून की पढाई की. लॉ फैकल्टी की तरफ से उन्हें बेस्ट स्टूडेंट के तौर पर चुना गया था एवं गोल्ड मेडल भी दिया गया था. दिल्ली बार काउंसिल में वर्ष 1975 में एडवोकेट के तौर पर उन्होंने अपना पंजीकरण करवाया. वर्ष 1999 में वे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सेकेट्री पद पर रहीं.

वरिष्ठ राजनयिक अखिलेश मिश्रा मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त

भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक अखिलेश मिश्रा को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया. विदेश मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2015 को यह घोषणा की. अखिलेश मिश्रा निवर्तमान में टोरंटो में भारत के महावाणिज्यदूत पद पर कार्यरत हैं. वर्ष 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी मिश्रा राजीव शाहारे की जगह लेंगे, जिन्हें डेनमार्क में भारत का राजदूत बनाया गया है.

विदित हो कि टोरंटो में भारत के महावाणिज्यदूत की जिम्मेदारी संभालने से पहले मिश्रा नेपाल और भूटान के साथ भारत के संबंधों से निपटने वाले विदेश मंत्रालय के उत्तरी प्रभाग में संयुक्त सचिव तथा बहुउद्देश्यीय आर्थिक संबंध प्रभाग में संयुक्त सचिव रह चुके हैं. इससे पहले वह काबुल में 'डिप्टी चीफ आफ मिशन' और सैन फ्रांसिस्को में उपमहावाणिज्यदूत रह चुके हैं.

अखिलेश मिश्रा मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त

विदेश मंत्रालय ने 15 दिसम्बर 2015 को अखिलेश मिश्रा को मालदीव के अगले उच्चायुक्त नियुक्त होने की घोषणा की.

वर्तमान में अखिलेश मिश्रा टोरंटो में भारत के महावाणिज्यदूत हैं.

वह राजीव शाहारे का स्थान लेंगे उन्हें अब डेनमार्क में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है.

अखिलेश मिश्रा टोरंटो में जिम्मेदारी संभालने से पहले नेपाल और भूटान के साथ भारत के संबंधों से निपटने वाले विदेश मंत्रालय के उत्तरी प्रभाग में संयुक्त सचिव तथा बहुउद्देश्यीय आर्थिक संबंध प्रभाग में संयुक्त सचिव रह चुके हैं.

इसके अतिरिक्त अखिलेश काबुल में 'डिप्टी चीफ आफ मिशन' और सैन फ्रांसिस्को में उपमहावाणिज्यदूत रह चुके हैं.

अखिलेश मिश्रा 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी है.

ए के जैन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुख्य अधिकारी नियुक्त

वरिष्ठ राजस्व सेवा अधिकारी ए के जैन को 15 दिसंबर 2015 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया.

मुख्य अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति को मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने भी स्वीकृति प्रदान की. वे जनवरी 2016 तक अल्पावधि कार्यकाल के लिए कार्यरत रहेंगे.

ए के जैन

- वे वर्ष 1978 के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं.
- उन्होंने 30 नवम्बर 2015 को अनीता कपूर के बतौर चेयरमैन पद से सेवानिवृत होने के पश्चात् यह पद ग्रहण किया.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक वैधानिक प्रभाग है जो केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत कार्यरत है.

- इसमें कार्यरत अधिकारी मंत्रालय के डिवीज़न के रूप में कार्य करते हैं तथा करों के भुगतान एवं उनके निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं.

भारतीय मूल के प्रवीण गोरधन दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री नियुक्त

भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ प्रवीण गोरधन 14 दिसंबर 2015 को दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री नियुक्त किये गये.

उनकी यह नियुक्ति दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा द्वारा डेविड वैन रूयेन एवं नहान्ला नेने को वित्त मंत्री के पद से हटाने के बाद की गयी.

इससे पहले प्रवीण गोरधन दक्षिण अफ्रीका में सहकारी शासन और परंपरागत मामलों के मंत्री रह चुके हैं.

प्रवीण गोरधन

- 12 अप्रैल 1949 को जन्में गोरधन ने आरंभ में डरबन में फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत रहे.
- उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जनतांत्रिक संविधान की ड्राफ्टिंग में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई थी.
- वे 1999 से 2009 तक दक्षिण अफ्रीका की राजस्व सेवा में बतौर कमिश्नर कार्यरत रहे.
- वे वर्ष 2009 से 2014 तक वित्त मंत्री पद पर भी कार्यरत रहे.

अहमद जावेद सऊदी अरब के राजदूत नियुक्त

पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद को वर्ष 2015 के दिसम्बर माह में सउदी अरब में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है.

विदित हो सउदी अरब में भारतीय समुदाय की जनसंख्या लगभग 28 लाख है.

वह हामिद अली राव का स्थान लेंगे.

विदित हो रियाद स्थित भारतीय दूतावास में यह पद वर्ष 2015 के अप्रैल माह से रिक्त था.

जावेद महाराष्ट्र कैडर के 1980 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं.

अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व वह मुंबई पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थे.

भारत-सऊदी अरब संबंध

- ज्ञात हो तेल समृद्ध सऊदी अरब भारत की ऊर्जा माँग की पूर्ती करने वाला महत्वपूर्ण देश है.
- सऊदी अरब भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता देश है.
- भारत में आयातित 80 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ती साउदी अरब करता है.
- भारत के दूसरे तेल आपूर्तिकर्ता देश राक, नाइजीरिया, वेनेजुएला और ईरान हैं.

पीके सिंह सेल के चेयरमैन नियुक्त

भारतीय इस्पात प्राधिकरण (स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड) सेल के चेयरमैन के रूप में 57 वर्षीय पीके सिंह ने 10 दिसम्बर 2015 को कार्यभार संम्भाल लिया. इससे पहले वे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में वर्ष 2012 से बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यरत थे.

इस वर्ष जुलाई 2015 में उन्हें इस्को इस्पात संयंत्र के सीईओ का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

पीके सिंह के बारे में-

- श्री सिंह ने आईआईटी रूड़की से मैटलर्जिकल से इंजीनियरिंग किया.
- उन्होंने कॅरियर की शुरुआत 1980 में बोकारो इस्पात संयंत्र से की.
- सेल में नियुक्ति के दौरान वे इस्को, दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों में कार्यरत रहे.
- इन संयंत्रों में अपने कार्यकाल के दौरान वे बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफल रहे. नेतृत्वशीलता के कारण मई 2012 में वे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सीईओ के पद पर नियुक्त हुए.
- सिंह तकनीकी विद ब्लास्ट फर्नेस तथा प्रचालन के विशेषज्ञ हैं.
- उनकी योग्यता के लिए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी समय समय पर सम्मानित किया गया.
- उन्हें प्रदान किए गए पुरुस्कारों में इस्को इस्पात संयंत्र बर्नपुर में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए जवाहर अवार्ड, सीएमईआरआई सीएसआईआर दुर्गापुर द्वारा इंडस्ट्री लीडर अवार्ड, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स दुर्गापुर द्वारा इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इण्डिया दुर्गापुर चैप्टर द्वारा पूर्वी क्षेत्र के लिए

बेस्ट सीईओ अवार्ड शामिल है.

काहेर काजेम जनरल मोटर्स (इंडिया) के प्रमुख नियुक्त

अमेरिकी मोटर कंपनी जनरल मोटर्स ने काहेर काजेम को अपने भारतीय परिचालन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया. काजेम की नियुक्ति 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी.

जनरल मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष और जीएम इंटरनेशनल के अध्यक्ष स्टेफान जैकोबी ने काजेम की नियुक्ति की घोषणा 6 दिसंबर 2015 को की. काजेम वर्तमान में जीएम इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं और वह अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे जिन्होंने सेवा से निवृत्त होने का फैसला किया है.

भारतीय मूल की अमेरिकी डॉ विजय एम राव आरएसएनए की अध्यक्ष नियुक्त

भारतीय मूल की अमेरिकी डॉ विजय एम राव को 2 दिसंबर 2015 को उत्तरी अमेरिका के प्रतिष्ठित रेडियोलॉजिकल सोसाइटी (आरएसएनए) के निदेशकों बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया.

आरएसएनए में नियुक्ति के समय डॉ राव थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के जेफरसन मेडिकल कॉलेज में डेविड सी लेविन प्रोफेसर और रेडियोलॉजी की अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थीं.

डॉ विजय एम राव के बारे में

- वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्नातक हैं.
- वर्ष 2000 में जेफरसन के इतिहास में पहली बार किसी महिला को क्लीनिकल विभाग का अध्यक्षता नियुक्त किया.सी महिला को क्लीनिकल विभाग का अध्यक्षता नियुक्त किया.

आरएसएनए

- आरएसएनए विश्व के रेडियोलॉजिस्ट और चिकित्सा विज्ञानियों का एक संगठन है. इसमें लगभग 54000 सदस्य हैं.
- इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी.

- इसका मुख्यालय ओक ब्रुक, इलिनोइस, यूनाइटेड स्टेट्स में है.

न्यायमूर्ति तीरथ सिंह (टीएस) ठाकुर ने भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने 3 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रतपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई. इसके साथ ही वो देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश बन गए. उन्होंने न्यायमूर्ति एचएल दत्तू का स्थान लिया. जो 2 दिसंबर 2015 को सेवानिवृत हो गए.

न्यायमूर्ति तीरथ सिंह (टीएस) ठाकुर से संबंधित मुख्य तथ्य:

न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की पहली नियुक्ति जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में 16 फरवरी 1994 को अतिरिक्त न्यायधीश के रूप में हुई थी. इससे पहले न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में ही प्रैक्टिस करते रहे थे. उन्हें सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, टैक्स मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है.

मार्च 1994 में न्यायमूर्ति ठाकुर को स्थानांतरित कर कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायधीश नियुक्त किया गया. जुलाई 2004 में न्यायमूर्ति ठाकुर की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में की गई, जहां वे अप्रैल 2008 तक कार्यकारी मुख्य न्यायधीश के पद पर कार्यरत रहे.

विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए

बिहार की 16वीं विधानसभा के लिए 3 दिसंबर 2015 को विजय कुमार चौधरी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया. चौधरी बिहार के सरायरंजन सीट से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं.

बिहार विधानसभा की 3 दिसंबर 2015 को बैठक प्रारंभ होते ही कार्यवाहक अध्यक्ष सदानंद सिंह ने अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ की. उन्होंने सदन को बताया कि 11 सदस्यों ने विजय कुमार चौधरी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया है. इसमें सभी दलों का समर्थन दिया गया है. इसके बाद सर्वसम्मति से चौधरी को अध्यक्ष चुन लिया गया.

विदित हो कि विजय चौधरी एनडीए की सरकार में मंत्री तथा जद (यू) के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

सर वेंकटरमन रामकृष्णन ने रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया

सर वेंकटरमन रामकृष्णन ने 1 दिसंबर 2015 को लंदन में रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया. सोसाइटी कौंसिल ने उन्हें इस पद के लिए मार्च 2015 में चुना, वह इस पद पर पांच साल तक अपनी सेवाएं देंगे.

इस नियुक्ति के साथ ही वह समाज के 61 वें अध्यक्ष बन गए और उस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए जिसके क्रिस्टोफर रेन, सैमूएल पेपिस, आइजैक न्यूटन, यूसुफ बैंकों, हम्फ्री डेवी, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड शामिल है.

सर वेंकटरमन रामकृष्णन के बारे में

- उन्होंने आनुवंशिक जानकारी का अध्ययन किया कि कैसे प्रोटीन और इस प्रक्रिया पर एंटीबायोटिक दवाओं के लिए राइबोसोम द्वारा अनुवाद किया जाए.

भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन ने टॉम स्टित्ज़ और ऐडायोनाथ के साथ 2009 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया.

- 2012 में उन्हें नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया.
- उन्होंने , भारत के बड़ौदा विश्वविद्यालय से भौतिकी में बीएससी और संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो विश्वविद्यालय से पीएचडी की.
- उन्होंने कैलिफोर्निया, सैन डिएगो के विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान का अध्ययन किया और येल विश्वविद्यालय में डोक्टोरल के रूप में काम किया.
- वह 2003 में रॉयल सोसाइटी के फैलो चुने गए, और अमेरिकी नेशनल विज्ञान एकेडमी लेओपॉलदिना (जर्मन विज्ञान अकादमी) और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में विदेशी सदस्य बने.

ब्रिटेन की रॉयल सोसायटी के बारे में

1660 में स्थापित, यह स्वशाषित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की फैलोशिप है.

सोसायटी के मौलिक उद्देश्य, इसके संस्थापक चार्टर्स में पहचान को बढ़ावा देने, विज्ञान के क्षेत्र में समर्थन उत्कृष्टता और मानवता के लाभ के लिए विकास और विज्ञान के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने हेतु परिलक्षित होते हैं.

रिपोर्ट | सर्वेक्षण

वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत: सीईबीआर रिपोर्ट

ब्रिटेन की आर्थिक शोध संस्थान 'सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड रिसर्च' (सीईबीआर) द्वारा दिसंबर 2015 में जारी एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी.

सीईबीआर रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य:

- सीईबीआर की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2029 में अमेरिका को पीछे छोड़ चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. अमेरिका दूसरे स्थान पर होगा, जबकि भारत तीसरे पायदान पर होगा.
- सीईबीआर के शोध अध्ययन के अनुसार, भारत के आगे बढ़ने से फ्रांस और इटली को विशिष्ट जी-8 समूह से बाहर किया जा सकता है, या फिर इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 की जा सकती है और भारत व ब्राजील को इसमें शामिल किया जा सकता है.
- वर्ष 2030 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 10133 अरब डॉलर होगा. अमरीका का जीडीपी 32996 अरब डॉलर और चीन का 34338 अरब डॉलर होगा, हालांकि 2019 में भारत राष्ट्रमंडल में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा. यह उस समय ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा.
- सीईबीआर रिपोर्ट के अनुसार, भारत चीन का पीछा करेगा और वर्ष 2050 के बाद यह चीन को भी पीछे छोड़ देगा. शीर्ष पांच देशों की सूची में ब्रिटेन चौथे व ब्राजील पांचवें स्थान पर रहेगा.
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 15 साल में भारत और ब्राजील यूरोप की तीसरी व चौथी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए जी-8 में उनका स्थान लेंगे.

ग्रीनपीस ने 17 भारतीय शहरों के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया

ग्रीनपीस इंडिया ने दिसंबर 2015 में देश के 17 शहरों के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचनांक (एनएक्यूआई) से पाए आँकड़ों का विश्लेषण जारी किया, जिससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्य सरकारों को भी अपने शहरों में वायु प्रदूषण के रोकथाम पर तुरंत कदम उठाने होंगे. जहाँ पीएम 2.5 की सांद्रता से अधिक प्रदूषण मापा गया है. इसमें बताया गया है कि 32 स्टेशनों में से 23 स्टेशनों पर घोषित राष्ट्रीय मानकों से 70 फीसदी अधिक प्रदूषण पाया गया.

जिन 17 शहरों में प्रदूषण के आँकड़े उपलब्ध हैं उनमें दिल्ली, वाराणसी, पटना, लखनऊ, कानपूर, आगरा, अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर और फरीदाबाद जैसे शहर शामिल है. इनमें से 15 शहरों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा खतरनाक बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2015 से नवबंर 2015 के बीच वायु प्रदूषण के जो आंकड़े एकत्रित किए गए वे मानक स्तर से 50 फीसदी अधिक है जिससे वायु प्रदूषण आपदा का संकेत मिलता है.

कालाधन विदेश भेजने के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर: जीएफआई रिपोर्ट

अमेरिका की अनुसंधान एवं सलाहकार संस्थान ग्लोबल फिनांशल इंटेग्रिटी (जीएफआई) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत कालाधन विदेश में जमा करने के मामले में चौथे स्थान पर है. इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2004 से वर्ष 2013 के बीच देश से 51 अरब डालर सालाना बाहर ले जाया गया.

जीएफआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, चीन सालाना 139 अरब डालर की कालाधन निकासी के साथ इस सूची में शीर्ष पर है जिसके बाद रूस (104 अरब डालर सालाना) और मेक्सिको (52.8 अरब डालर सालाना) का स्थान है. जीएफआई द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2013 के दौरान विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गैरकानूनी धन, कर चोरी, अपराध, भ्रष्टाचार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से पैदा रिकार्ड 1100 अरब डालर कालाधन विदेश में जमा किया गया. इस रिपोर्ट में वर्ष 2013 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं. जीएफआई के अनुमान के मुताबिक कुल मिलाकर वर्ष 2004-2013 तक के दशक के दौरान भारत से 510 अरब डालर की राशि भारत से बाहर गई जबकि चीन से 1,390 अरब डालर और रूस से 1,000 अरब डालर कालाधन विदेश भेजा गया.

डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक खाद्य जनित रोगों पर रिपोर्ट जारी की

खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 दिसंबर, 2015 को वैश्विक खाद्य जनित रोगों पर पहली रिपोर्ट जारी की. शीर्षक (Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases) "एस्टीमेट्स ऑफ़ द ग्लोबल बर्डन ऑफ़ फ़ूडबोर्न डिसीज" नाम से जारी रिपोर्ट दूषित भोजन के स्वास्थ्य पर प्रभाव और बचाव पर आधारित है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार यह अब तक की सबसे व्यापक रिपोर्ट है.

रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों के कारण मानव जीवन में होने वाले प्रभाव विकलांगता, घटना, मृत्यु दर, और बीमारी के पूर्व अनुमान आंकलमन करती है.

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार 2010 में दुनिया भर में 31 खाद्य जनित खतरनाक बीमारियों कीटाणु, वायरस, पैरासाइट्स, टोक्सिन और केमीकल्स 600 मिलियन खाद्य जनित बीमारियां के कारण हैं और इसके कारण 4 लाख 20 हजार लोगों की मृत्यु हुई. खाद्य जनित बीमारी का कारण विशेष रूप से डायरिया रोग के कीटाणु, नोरोवायरस और कैम्पिलोबैक्टर पाए गए.
- खाद्य जनित रोग के कारण बच्चों और वयस्क मृत्यु दर सीमांकित उपक्षेत्र में विचारणीय थी. जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक खाद्य जनित रोग से प्रभावित लोगों की संख्या दक्षिण-पूर्व एशिया के बाद अफ्रीका में थी.
- रिपोर्ट के अनुसार यूँ तो खाद्य जनित रोगों से प्रत्येक आयु वर्ग के लोग प्रभावित है, किन्तु 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में और कम आय वर्ग वाले उपक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के बीच प्रभाव अधिक पाया गया.

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एचआईवी (एड्स) के प्रसार पर रिपोर्ट जारी

30 नवंबर 2015 को यूनिसेफ, यूएनएड्स और भागीदारों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एचआईवी/एड्स के प्रसार पर रिपोर्ट जारी की. इसका शीर्षक एडोल्सेंटः अंडर द रडार इन द एशिया-पेसेफिक एड्स रेस्पॉन्स था और इसे 1 दिसंबर 2015 को मनाए जाने वाले विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जारी किया गया.

रिपोर्ट के अनुसार किशोरों के बीच एचआईवी इस क्षेत्र के दस देशों में सबसे अधिक रहा. एशिया- प्रशांत में 10 से 19 वर्ष के एचआईवी संक्रमित किशोंरो का 98 प्रतिशत इन दस देशों में निवास करता है.

ये देश हैं-कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम.

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं-

- एशिया- प्रशांत क्षेत्र को छिपी हुई महामारी के तौर पर किशोरों में एचआईवी का सामना करना पड़ रहा है.
- साल 2014 में 15-19 वर्ष के किशोरों में 50000 नए एचआईवी संक्रमित किशोरों के जुड़ने का अनुमान था, जो नए संक्रमण का 15 फीसदी होगा.
- इस क्षेत्र में बैंकॉक, हनोई और जकार्ता जो संक्रमणों के नए ठिकाने हैं के साथ अभी करीब 220000 किशोर एचआईवी से पीड़ित हैं.
- हालांकि एचआईवी संक्रमणों के नए मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन ये मुख्य आबादी वाले देशों में किशोरों में खासकर युवा समलैंगिक पुरुषों और अन्य पुरुष जो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, वहां बढ़ रहा है.
- नए संक्रमण में वृद्धि जोखिम भरे व्यवहार जैसे एक से अधिक यौन भागीदार और असंगत कंडोम का प्रयोग, में बढ़ोतरी से सम्बंधित है.
- एचआईवी के उच्च जोखिम वाले किशोरों में समलैंगिक पुरुष और पुरुषों से यौन संबंध बनाने वाले दूसरे पुरुष, किन्नर, इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाएं लेने वाले शामिल हैं.
- किशोरों के बीच एड्स की महामारी को खत्म किए बिना साल 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के तौर पर एड्स को समाप्त करना संभव नहीं होगा.
- स्थिति को बदलने के लिए रिपोर्ट ने सरकारों को किशोरो पर बेहतर आंकड़े जुटाने, एचआईवी की रोकथाम हेतु रणनीतियां और किशोर विशिष्ट कानून एवं नीतियां बनाने की सिफारिश की है.
- इस इलाके के सिर्फ दस देश ही युवाओं में एचआईवी परीक्षण और संबंधित सेवाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र सहमति बनाने हेतु कानून और नीतियों के लिए जाने जाते हैं.
- फिलीपींस में 15-19 वर्ष के किशोरों में नए एचआईवी संक्रमण के मामले चार वर्षों में 50 फीसदी तक बढ़े हैं, 2010 में अनुमानित संख्या 800 से बढ़कर 2014 में 1210 हो गयी है .
- दक्षिण एशिया में 10-19 वर्ष के किशोरों में एड्स संबंधित मौतों में लगभग चार गुना बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2001 में यह 1500 थी जबकि 2014 में यह 5300. पूर्व एशिया और प्रशांत में इसी अवधि में मौतों की

संख्या 1000 से बढ़कर 1300 हो गई.

भारत के संबंध में रिपोर्ट

- साल 2012 में 25 वर्ष से कम आयु वर्ग में एचआईवी का प्रसार 3.5 फीसदी थी, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में यह 4.9 फीसदी था.
- भारत में सेक्स उद्योग की अनुमानित 3 मिलियन महिलाओं में से 40 फीसदी 18 वर्ष से कम की है जब कि 17 फीसदी की उम्र 15 वर्ष से कम है.
- साल 2012 में सेक्स वर्करों के बीच एचआईवी का प्रसार (25 वर्ष से कम) 1.7 फीसदी थी.
- साल 2013 में इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाएं लेने वालों (25 वर्ष से कम) के बीच एचआईवी का प्रसार 5.5 और 7.7 (25 वर्ष से अधिक) था.
- रिपोर्ट में देश में सेक्स वर्क संगठनों के सामुदायिक गतिशीलता, सहकर्मी आधारित स्वास्थ्य संवर्धन, आत्म- नियमन, कानून प्रवर्तन के मुद्दों और कानून एवं नीति सुधार के बारे में बातचीत में सक्रिए भागीदारी पर आधिरत सशक्त दृष्टिकोण अपनाने की प्रभावशीलता के प्रदर्शन की सराहना की गयी है.

निधन

न्यूकैसल यूनाइटेड के पूर्व गोलकीपर पावेल सर्सिनेक का निधन

न्यूकैसल यूनाइटेड के पूर्व गोलकीपर पावेल सर्निसेक का 29 दिसंबर 2015 को चेक रिपब्लिक स्थित ओस्ट्रावा में निधन हो गया. वे 47 वर्ष के थे.

उनका निधन हृदयघात के कारण हुआ.

पावेल सर्निसेक

- सर्सिनेक ने वर्ष 1990 से 2007 तक न्यूकैसल यूनाइटेड के लिए बतौर गोलकीपर खेला.
- वे शेफील्ड वेडनेसडे, पोर्ट्समाउथ एवं वेस्ट हैम यूनाइटेड का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
- वे इटली में ब्रेसिका एवं कोसेनज़ा तथा पुर्तगाल में बीरा-मार एवं चेक रिपब्लिक में बनिक ओस्ट्रावा के लिए खेल चुके हैं.
- उन्होंने वर्ष 1994 से 2001 तक चेक रिपब्लिक के लिए भी खेला जिसमें उन्होंने कुल 49 कैप्स अर्जित कीं.
- वे चेक रिपब्लिक टीम का भाग थे जो यूईएफए यूरो 1996 में दूसरे स्थान पर रही. वे वर्ष 1997 में फीफा कन्फेडरेशन कप एवं यूईएफए यूरो 2000 में भी गोलकीपर थे.
- उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय फुटबॉल से नवम्बर 2001 में संन्यास की घोषणा की.
- संन्यास के पश्चात् वे अपने निजी स्कूल एवं स्पार्टा परागुए के लिए गोलकीपिंग कोच के रूप में कार्य कर रहे थे.

उत्तर कोरिया के प्रमुख सलाहकार किम यांग गोन का निधन

उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभा रहे किम यांग गोन का 29 दिसंबर 2015 को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. वे 73 वर्ष के थे.

उन्हें उत्तर कोरिया के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन का करीबी माना जाता है.

गोन उन अधिकारियों में से थे जो दक्षिण कोरिया के साथ देश के रिश्तों को संभाल रहे थे. वे पूर्व सर्वोच्च नेता किम जोंग इल के समयकाल से ही इन मामलों को देख रहे थे. उनकी मौत से क्षेत्र में असंतुलन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

किम यांग गोन वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी थे. इसके अतिरिक्त, वे यूनाइटेड फ्रंट डेवलपमेंट के अध्यक्ष थे, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया के रिश्तों से जुड़े मामलों को देखता है.

जून-अगस्त 2015 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बेहद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया था कि उत्तर की फायरिंग और लैंडमाइन विस्फोट की वजह से उसके कुछ सैनिक मारे गए. यांग गोन को उस वक्त दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने का श्रेय जाता है.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने वर्ष 2007 में उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख किम जोंग इल और दक्षिण कोरिया राष्ट्राध्यक्ष रोह मू हयान के बीच बैठक कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी.

स्टार ट्रेक के लेखक जॉर्ज क्लेटन जॉनसन का निधन

प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक सीरीज़ स्टार ट्रेक के लेखक जॉर्ज क्लेटन जॉनसन का 25 दिसंबर 2015 को लॉस एंजलिस में निधन हो गया. वे 86 वर्ष के थे एवं लम्बे समय से कैंसर से पीड़ित थे.

अमेरिका के व्योमिंग शहर में 1929 में जन्में जॉनसन ने वर्ष 1959 में मनोरंजन क्षेत्र में कदम रखा. उन्होंने सबसे पहले "अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स" के लिए "आई विल टेक केयर ऑफ़ यू" एपिसोड लिखे थे.

जॉनसन दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया स्कूल ऑफ़ राइटर्स के सदस्य भी थे. इसके अन्य सदस्यों में थियोडर स्टरजन, विलियम एफ नोलां, रे ब्रैडबरी एवं रिचर्ड मैथसन हैं.

उनके परिवार में उनके अतिरिक्त पत्नी लोला जॉनसन, बेटी जूडी ओलिव बेटा पॉल बी जॉनसन हैं.

जॉर्ज क्लेटन जॉनसन

- जॉनसन का प्रसिद्ध साइंस फिक्शन "लोगान्स रन" जिसे विलियम एफ नोलां ने संयुक्त रूप से 1967 में लिखा था उस पर वर्ष 1976 में फिल्म बनी.
- वे अमेरिकी सेना में वर्ष 1946 से 1949 तक टेलीग्राफ़र एवं ड्राफ्ट्समैन के रूप में कार्यरत रहे.
- वे वर्ष 1950 में लॉस एंजलिस चले गये जहां उन्होंने लोला ब्राउनस्टिन से शादी की.
- जॉनसन ने "द ट्वाईलाईट ज़ोन" भी लिखी.
- उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में वर्ष 1960 में लिखी गयी ओशियन्स 11 है जो कि लास वेगास कसीनो में हुई चोरी पर आधारित है.
- उन्होंने वर्ष 1966 में "द मैन ट्रैप" लिखी जो स्टार ट्रेक का प्रीमियर एपिसोड था.

कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएस मालिमत का निधन

कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएस मालिमत का 86 साल की अवस्था में बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में 22 दिसंबर 2015 को निधन हो गया.

उनके परिवार में पत्नी प्रेमा देवी वी मालिमत, एक बेटा और चार बेटियां हैं.

वी एस मालिमत के बारे में-

- उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था. उन्होंने 1952 में लंदन विश्वविद्यालय से एलएलबी में पहली रैंक हासिल की और सार्वजनिक इंटरनेशनल लॉ में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया.
- उन्होंने 1952 में मुबंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और 1956 में बेंगलुरू में स्थानांतरित कर दिए गए.
- मार्च 1970 में उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया.
- 1984 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए.
- 1985 में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया.

- रिटायरमेंट के बाद उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया.
- उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य के रूप में भी कार्य किया.
- उन्होंने भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार समिति का नेतृत्व किया.
- वह नाइजीरिया और श्रीलंका में मानवाधिकारों के प्रवर्तन की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी रहे.
- वह श्रीलंका में जनमत संग्रह की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त रहे.
- जून 2015 में उन्हें कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक सीमा सुरक्षा बल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया.
- उनकी उत्कृष्ट सेवाओं से प्रभावित होकर भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार और कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

जापान की पर्वतारोही केई तानीगुची की चढ़ाई करते वक्त गिरने से मौत

उत्तरी जापान के होक्काइदो में 25 दिसंबर 2015 को बर्फीली दाएसेतसुजान पर्वतमाला पर चढ़ाई करते वक्त गिरने से 43 वर्षीय पर्वतारोही केई तानीगुची की मौत हो गई.

- तानीगुची ने 2007 में माउंट एवेरेस्ट की चढ़ाई थी. 2009 में प्रतिष्ठित पायोले देओर "गोल्डन आईस एक्स" पुरस्कार जीतने वाली वह पहली महिला बनी.
- साथी पर्वतारोही हिरोशी हगिवरा के अनुसार कुरादके पर्वत से उतरते वक्त 1984 मीटर की उंचाई पर आराम करने के लिए रूकीं तभी वहां से गिर पड़ी.
- कुरादके के साथ चार अन्य पर्वतारोही चोटी पर पहुंचे.

हिन्दी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना का निधन

प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना का मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 74 वर्ष की आयु में 25 दिसंबर 2015 को निधन हो गया.

साधना ने 'आरज़ू', 'मेरे मेहबूब', 'लव इन शिमला', 'मेरा साया', 'वक़्त', 'आप आए बहार आई', 'वो कौन थी',

'राजकुमार', 'असली नकली', 'हम दोनो' जैसी कई प्रसिद्ध हिंदी फ़िल्मों में काम किया था.

साधना के बारे में

- साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी था और उनका 'साधना कट' हेयर स्टाइल मशहूर था.
- साधना की पहली फिल्म श्री 420 थी.
- साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को संयुक्त भारत के कराची में हुआ था.
- साधना ने 22 वर्ष के फिल्मी करियर में 35 फिल्में की.
- साधना ने फिल्म निर्देशक आरके नैयर से शादी की थी.
- साधना को दो बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया.
- हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए साधना को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (आईफा) द्वारा वर्ष 2002 में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

ब्रिटिश उपन्यासकार पीटर डिकिंसन का निधन

ब्रिटिश उपन्यासकार पीटर डिकिंसन का विनचेस्टर, हैम्पशायर में 16 दिसंबर 2015 को निधन हो गया. वह वयस्कों और बच्चों के एक उपन्यासकार थे.

पीटर डिकिंसन के बारे में

- उन्होंने लगभग 60 पुस्तकें लिखी हैं, जिनका 53 अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया.
- उनका पहला उपन्यास वेदरमोंगर वर्ष 1968 में प्रकाशित हुआ.
- उनकी दो पुस्तकों तुल्कु (1979) और सिटी ऑफ गोल्ड (1980) ने कार्नेगी पदक जीता.
- वह साहित्य की रॉयल सोसाइटी के फैलो और लेखकों के सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष थे.
- उनकी अंतिम पुस्तक इन द प्लेस ऑफ द खान वर्ष 2012 में प्रकाशित किया गया.

प्रसिद्ध जर्मन कंडक्टर कर्ट मसूर का निधन

दुनिया के मशहूर कंडक्टर कर्ट मसूर का 88 वर्ष की अवस्था में 19 दिसंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया. वह पार्किंसंस रोग से पीड़ित थे.

पुरानी शैली के संगीतज्ञ के रूप में पहचाने जाने वाले मसूर को 1991-2002 तक न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक (एनवाईपी) में संगीत निर्देशक के रूप में सेवा देने के लिए भी जाना जाता था. 11 सितम्बर 2001 में आतंकवादी हमलों के बाद "ब्रह्मस डचेज रिक्विम" में उन्होंने क्षमता के अनुरूप फिलहारमोनिक का नेतृत्व किया.

वह मूल रूप से पूर्वी जर्मनी के निवासी थे. 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद जर्मनी में फैली हिंसा को रोकने में मदद करने का श्रेय भी कर्ट मसूर को जाता है. 1990 में जब दोनों जर्मनी (पूर्वी और पश्चिमी) पुन: हुए तब उन्होने सरकारी समारोह में बीथोवेन नाइन्थ सिम्फनी का निर्देशन किया.

2000 में मसूर लंदन फिलहारमोनिक आर्केस्ट्रा के प्रिंसिपल कंडक्टर बन गए और 2007 तक पदासीन रहे. अप्रैल 2002 में ओर्केस्ट्रा नेशनल डी फ्रांस (ओएनएफ) के संगीत निर्देशक बन गए 2008 तक इस पद पर कार्य करते रहे.

2012 में मसूर ने वेबसाइट पर खुलासा किया की वे पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं.

पूर्व माकपा सांसद नुरुल हुदा का निधन

मार्क्सावादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पूर्व सांसद नुरुल हुदा का 17 दिसम्बर 2015 को निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे.

हुदा को 15 दिसम्बर 2015 को दिल का दौरा पड़ा था और तब से वह कोमा में थे. उन्हें रूबी अस्पताल में एक हफ्ते पहले ब्रोंकाइटिस से पीड़ित होने के कारण भर्ती कराया गया था.

हुदा कोलकाता में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में वर्ष 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे.

नुरुला हुदा ने इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1966 में सिलचर, असम में किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम करना शुरू किया.

वह तीन दशकों तक माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य रहे. ज्ञात हो आपातकाल के दौरान हुदा वर्ष 1975

से 77 तक जेल में थे.

हुदा 1978 से 1983 तक असम विधानसभा के सदस्य थे. इसके अतिरिक्त वर्ष 1973 में नूरुल हुदा सिलचर संसदीय क्षेत्र से संसद निर्वाचित हुए.

उद्योगपति एमएएम रामास्वामी का निधन

84 वर्षीय मशहूर उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद एमएएम रामास्वामी का 2 दिसंबर 2015 को लंबे समय से बीमारी के कारण देहावसान हो गया. उन्होंने दस हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक साम्राज्य चेट्टिनाड समूह खड़ा किया.

संपत्ति विवाद के बाद मशहूर उद्योगपति ने गोद लिए गए बेटे को बेदखल कर दिया और अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी. उनकी इस घोषणा के बाद विवाद पैदा हो गया था.

पूर्व राज्यसभा सांसद को हृदय और किडनी से संबंधित तकलीफों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया. 2 दिसंबर 2015 को बुधवार को उन्होंने शाम 4:30 बजे अंतिम सांस ली. छह दिसंबर को तिरुवोत्तियुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

परोपकारी कार्यों के लिए विख्यात रामास्वामी को जीवन के अंतिम दिनों में पराभव देखना पड़ा. पिछले वर्ष एजीएम में ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी चेट्टिनाड सीमेंट कारपोरेशन में वह निदेशक नहीं चुने जा सके.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सैंडी बर्गर का निधन

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सैंडी बर्गर का 2 दिसम्बर 2015 को कैंसर के कारण निधन हो गया. वे 70 वर्ष के थे.

वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर कार्यरत थे. उन्होंने पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

वर्ष 1997 से 2001 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे बर्गर लम्बे समय से कैंसर से पीड़ित थे. उनके कार्यकाल में वे चीन के साथ संबंधों को लेकर भी चर्चा में रहे. इसके अतिरिक्त इस दौरान वर्ष 1999 में युगोस्लाविया

में नाटो द्वारा हुई बमबारी, 1996 में सऊदी अरब में खोबर टावर में हुए हमले एवं 1998 में केन्या एवं तंज़ानिया में हुए अमेरिकी दूतावासों पर हमलों के दौरान भी उन्होंने उन देशों से संपर्क करने एवं तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के साथ अमेरिका के संबंध सुधरने में उनकी भूमिका का विशेष योगदान बताया है.

सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान का निधन

प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान का 30 नवम्बर 2015 को श्वास की समस्या के कारण नई दिल्ली में निधन हो गया. वे 88 वर्ष के थे.

21 मई 1927 को उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद जन्में सबरी खान सैनिया घराने से ताल्लुक रखते थे जिसका तानसेन के वंश से संबंध माना जाता है.

उन्होंने अपने दादा उस्ताद हाजी मोहम्मद खान से सारंगी वादन सीखा. इसके बाद सबरी खान लगातार अपने पिता उस्ताद छज्जू खान से प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे.

भारतीय शास्त्रीय संगीत में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण उस्ताद सबरी खान को साहित्य कला परिषद, यूपी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. भारत सरकार की ओर से उन्हें वर्ष 1992 में पद्म श्री पुरस्कार एवं वर्ष 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.

कूडियाट्टम् कलाकार मार्गी साथी का निधन

कूडियाट्टम् और नंगियरकूथु के बेहतरीन कलाकारों में से एक मार्गी साथी का 1 दिसंबर 2015 को तिरुवनंतपुरम में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र में निधन हो गया.

वह 50 वर्ष की थी.

मार्गी साथी के बारे में

- मार्गी साथी का जन्म चेरूथुरुथी में इमब्रानथिरी ब्राह्मण परिवार में हुआ, उन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में

कूडियाट्टम् सीखना आरम्भ कर दिया.

- बाद में केरल कलामंडलम में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुईं.
- तत्पश्चात यूनेस्को द्वारा सम्पूर्ण मानवता की अनूठी कलात्मक विरासत के रूप में चयनित 'कूडियाट्टम् थ्रीएटर' में शिक्षक के रूप में कार्य किया.
- उन्हें वर्ष 2002 में केरल संगीता नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2009 में कलादर्पण पुरस्कार और वर्ष 2008 में नाट्यरत्ना पुरस्कारम से सम्मानित किया गया.

कूडियाट्टम के बारे में

कूडियाट्टम शब्द का अर्थ है - 'संघ नाट्य' अथवा अभिनय अथवा संघटित नाटक या अभिनय.

प्राचीन संस्कृत नाटकों का पुरातन केरलीय नाट्य रूप कूडियाट्टम कहलाता है. दो हज़ार वर्ष पुराने कूडियाट्टम को युनेस्को ने 'वैश्विक पुरातन कला' के रूप में स्वीकार किया है.

यह मंदिर-कला है जिसे चाक्यार और नंपियार समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं. साधारणतः कूत्तंपलम नामक मंदिर से जुडे नाट्यगृहों में इस कला का मंचन होता है. कूडियाट्टम प्रस्तुत करने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता है.

पदमुक्त

टाटा स्टारबक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवानी दावदा ने इस्तीफा दिया

टाटा ग्लोबल बिव्रिजेज लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अवानी दावदा ने 17 दिसंबर 2015 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

दावदा ने निजी कारणों से नए अवसर के लिए त्यागपत्र दिया. उन्होंने टाटा स्टारबक्स के कारोबार को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है.

टाटा स्टारबक्स के निदेशक मंडल ने सुमी घोष को 1 जनवरी 2016 से नया सीईओ नियुक्त किया है.

खुदरा उपभोक्ता कारोबार में तीन दशक का अनुभव रखने वाले घोष आठ साल से टाटा स्टारबक्स से जुड़े रहे हैं. स्टारबक्स इस समय भारत में 78 स्टोर चला रहा है.

लातविया की प्रधानमंत्री लैमदोता स्ट्रौजुमा ने अपने पद से इस्तीफा दिया

लातविया की पहली महिला प्रधानमंत्री लैमदोता स्ट्रौजुमा ने 7 दिसंबर 2015 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. स्ट्रौजुमा ने अपना इस्तीफा लातविया की संसद हेतु संपन्न चुनाव के पश्चात् नए सरकार के गठन हेतु दिया. वे वर्ष 2014 में लातविया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं थीं.

लातविया में फिर से लैमदोता स्ट्रौजुमा के नेतृत्व में सरकार गठित होगी जिसमें तीन राजनितिक पार्टियों का गठबंधन (राइट यूनिटी पार्टी, द ग्रीन्स एवं फार्मर्स पार्टी एवं द फार राईट नेशनल एलाइंस) शामिल है.

लातविया से संबंधित मुख्य तथ्य:

लातविया उत्तरपूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और उन तीन बाल्टिक गणराज्यों में से एक है, जिनका द्वितीय

विश्व युद्ध के बाद भूतपूर्व सोवियत संघ में विलय कर दिया गया. इसकी सीमाएं लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस और रूस से मिलती है. इसका कुल क्षेत्रफल 64589 वर्ग किमी और जनसंख्या 223150 (वर्ष 2001 के जनसँख्या अनुसार) है. लातविया की राजधानी है रीगा है. यहाँ की आधिकारिक भाषा है लातवियाई है तथा यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है लात्स है.

कला | संस्कृति

सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध महोत्सव 'लोसर' का लद्दाख क्षेत्र में शुभारम्भ

सबसे बड़े तिब्बती बौद्ध महोत्सव लोसर का 12 दिसंबर 2015 को जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में शुभारम्भ हुआ.

यह त्योहार बौद्धों के लिए नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है.

यह उत्सव प्रत्येक वर्ष पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ क्षेत्रीय लोगों द्वारा मनाया जाता है.

दस दिवसीय यह उत्सव धार्मिक और आवासीय स्थानों में रोशनी के साथ शुरू होता है.

इस उत्सव पर पुरानी परंपरा के अनुसार लोग अपने पूर्वज परिवार के सदस्यों की कब्र पर जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.

उत्सव के तीसरे दिन लोग नए वर्ष के चन्द्रमा को देखने के लिए इंतजार करते हैं.

भारत में लोसर देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले योल्मो, शेरपा, तमांग, गुरुंग, और भूटिया समुदायों द्वारा मनाया जाता है.

यूनेस्को ने वाराणसी और जयपुर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया

भारत के दो शहरों वाराणसी एवं जयपुर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 11 दिसंबर 2015 को पहली बार क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया.

वाराणसी को सिटी और म्यूजिक (संगीत) और जयपुर को सिटी ऑफ़ क्राफ्ट एवं फोक आर्ट (शिल्प कला एवं लोक कला) श्रेणी में शामिल किया गया है.

यूनेस्को के महानिदेशक इरीना बोकोवा ने 33 देशों के 47 शहरों को यूनेस्को के नये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के सदस्य के रूप में घोषित किया.

भारत ने इन श्रेणियों के लिए पहली बार वर्ष 2015 में आवेदन किया था.

वाराणसी : सिटी ऑफ़ म्यूजिक (संगीत का शहर)

- वाराणसी को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताते हुए इसे संगीत में अपनी समृद्ध परंपरा के साथ मंदिरों के शहर के रूप में भी दर्ज किया गया.
- वाराणसी का बनारस घराना इस शहर के नाम पर ही रखा गया है. यहां की सांस्कृतिक शैली जैसे, होरी, चैती, टप्पा, दादरा यहां के समृद्ध संगीत कला को दर्शाती है.
- यहां के घाट, हवेलियां एवं मंदिरों में बनारस घराने को सुना जा सकता है साथ ही बनारस हिन्दू विश्वद्यालय के संगीत और नृत्य विभाग का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है.

जयपुर सिटी ऑफ़ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट (लोक कला एवं शिल्प कला का शहर)

- राजस्थान सरकार ने जयपुर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंतर्गत इसे लोक कला एवं शिल्प कला के शहर के रूप में नामांकित किया था.
- यहां 36 प्रकार की शिल्पकलाएं मौजूद हैं जिसमें मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा और आभूषण बनाना शामिल है.
- 18वीं सदी में राजा सवाई सिंह द्वितीय के समयकाल से अब तक यह शहर कलाकारों का पसंदीदा स्थल है.
- जयपुर की अर्थव्यवस्था का 30 प्रतिशत छोटे पैमाने पर मौजूद शिल्प उद्योगों पर निर्भर है.

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (यूसीसीएन)

इसकी स्थापना वर्ष 2004 में शहरी विकास में रचनात्मकता को महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान दिए जाने के रूप में की गयी थी.

इस नेटवर्क में शामिल होने के पश्चात् यह शहर एक दूसरे से रचनात्मकता शेयर करते हैं जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है ताकि इन्हें निम्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके:

- सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, उत्पादन, वितरण और प्रसार को मजबूत बनाना.
- रचनात्मकता केन्द्रों का विकास करना एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में रचनाकारों और पेशेवरों के लिए अवसरों को विस्तार प्रदान करना.

- सांस्कृतिक जीवन में पहुंच और भागीदारी में सुधार करना, इसमें विशेष रूप से समाज में हाशिए पर अथवा कमजोर समूहों व व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करना.
- विकास योजनाओं में संस्कृति और रचनात्मकता को विशेष स्थान प्रदान करना.

इस नेटवर्क में सात रचनात्मकता क्षेत्रों को शामिल किया गया है: शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिजाइन, पाक-कला, साहित्य और संगीत.

'आईफा उत्सवम' चेन्नई में वर्षा के कारण स्थगित

'आईफा उत्सवम' प्रबंधन ने 3 दिसम्बर 2015 को चेन्नई में भारी वर्षा में फसे लोगों से अपनी सहानभूति प्रकट करने के लिए 'आईफा उत्सवम' के दिसम्बर माह अनुसूचित कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की.

दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया.

विदित हो इस वर्ष यह आईफ उत्सवम का प्रथम संस्करण था. यह कार्यक्रम 4 दिसम्बर से 6 दिसम्बर 2015 के मध्य हैदराबाद के गाचिबावेली स्टेडियम में आयोजित होना था.

आईफा उत्सवम के प्रथम संस्करण में कमल हासन, चिरंजीवी और अक्किनेनी नागार्जुन जैसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय कलाकारों के शामिल होने की संभावना था.

आईफ उत्सवम को आयोजित करने का उद्देश्य दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग को पहचान प्रदान करना है.

ज्ञात हो कि दक्षिण भारत फिल्म उद्योग में तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ फिल्म उद्योग संयुक्त रूप से शामिल हैं.

46वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सम्पन्न

गोवा में आयोजित 46वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 30 नवम्बर 2015 को सम्पन्न हो गया. समापन समारोह के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कारों का वितरण किया गया. समापन समारोह के मुख्य अतिथि पार्श्व गायक एवं संगीतकार ए आर रहमान थे. विदित हो यह समारोह 20 नवम्बर 2015 से 30 नवम्बर 2015 के मध्य आयोजित किया गया.

वितरित किए गए पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है

श्रेणी	विजेता
सर्वश्रेष्ठ फिल्म	'एम्ब्रेस ऑफ़ द सर्पेंट'
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	'पीटर ग्रीनअवे' को फिल्म 'आईसेनस्टेन इन गुआनाजुआतो'
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष)	फ्रांसीसी अभिनेता 'विन्सेंट लिंडन' 'मेज़र ऑफ़ अ मेन' के लिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला)	ग्युनेस सेंसोय, डोगा डूगुसुलो, तुक्बा सनगुरुगुलु ,एलतित्ज़ कान और लाईडा अक्दोगन को तुर्की फिल्म मस्तांग के लिए
विशेष जूरी पुरस्कार	बोलीवियाई फिल्म 'सील्ड कार्गो'
लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार	'निकिता मखाइलखेव'
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के लिए शताब्दी पुरस्कार	संगीतकार 'इलैयाराजा'
आईसीएफटी यूनेस्को फेलिनी अवार्ड	'कौशिक गांगुली' को फिल्म "सिनेमावाला" के लिए

फिल्म महोत्सव के से सम्बंधित अन्य विशेषताएँ -

- इफ्फी 2015 में भारत में प्रथम बार यूनेस्को फेलिनी पदक प्रदान किया गया.
- इफ्फी 2015 के लिए फोकस देश स्पेन था.
- शेखर कपूर की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी में अमेरिका के निर्देशक माइकल रेडफोर्ड, फिलिस्तीन के इजरायली निर्देशक सुहा अर्राफ, जर्मन अभिनेत्री जूलिया जेनेच और दक्षिण कोरिया के फिल्म निर्माता जियोन क्यू- ह्वान थे.
- महोत्सव के दौरान कुल 120 फिल्मों का प्रदर्शन (विश्व, अंतर्राष्ट्रीय, एशिया और भारत) हुआ.
- इस वर्ष महोत्सव ने 540 राष्ट्रीय और 280 अंतर्राष्ट्रीय निर्देशकों, अभिनेताओं, निर्माताओं, तकनीशियनों के साथ ही ऑस्कर अकादमी सदस्यों और हॉलीवुड विशेषज्ञों सहित 820 से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी की.
- उद्घाटन फिल्म- द मैन हू न्यू इनफिनिटी.
- भारतीय पैनोरोमा खंड में 47 फिल्में (फीचर और गैर-फीचर) शामिल की गई.

खोज | आविष्कार

अमेरिका और चीन के खोजी दल ने डायनासोर की नयी प्रजाति का पता लगाया

अनुसंधानकर्ताओं ने डायनासोर की नयी शाकाहारी प्रजाति 'हुआलियानसेराटॉप्स वुकाईवानेंसिस' का पता लगाया है. 10 दिसम्बर 2015 को खोजी गयी इस प्रजाति के बारे में अनुमान है कि यह स्पेनियल (शिकारी कुत्ते की एक किस्म) के आकार का होता था. जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो सकता था. अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार डायनासोर की यह प्रजाति सींग वाले डायनासोरों की सबसे पुरानी प्रजाति 'यिनलौंग डाउनसी' के समकालीन है. इसकी खोज अमेरिका और चीन के प्रोफेसरों के दल ने की है.

अनुसंधान के तथ्य-

- खोज के बाद अनुसंधानकर्ताओं का दल इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस प्रजाति हुआलियानसेराटॉप्स डायनासोरों का शरीर मजबूत और भारी-भरकम होता था.
- शारीरिक रूप से ये काफी हद तक यिनलौंग से मिलते-जुलते हैं.
- जार्ज वाशिंगटन यूनीवर्सिटी में प्राणि विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर रोनाल्ड वीनट्रॉब और जेम्स क्लार्क तथा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रोफेसर शू शिंग के नेतृत्व वाले एक दल ने चीन के शिनजिंयाग प्रांत में एक ही स्थान से डायनासोर की दोनों प्रजातियों के कंकाल के अवशेष खोज निकाले.
- यिनलौंग प्रजाति के डायनासोर के अवशेष 2002 में खोजे गये थे.
- अनुसंधानकर्ताओं ने खोपड़ी और पैर के अवशेष से नये डायनासोर का ढांचा तैयार किया और इसकी तुलना सेराटोप्सिया परिवार के डायनासोर से की.
- अनुसंधानकर्ताओं के दल में शामिल यूनीवर्सिटी के जियोलॉजिकल साइंसेज प्रोग्राम में प्राणिविज्ञान की प्रोफेसर कैथरीन फोर्स्टर ने आशा व्यक्त की है कि "एक ही जगह से दो प्रजातियों के अवशेष मिलने से यह स्पष्ट है कि यहां हमें जितना पता चला है, उससे कहीं ज्यादा विविधता है."

- इस नयी प्रजाति के मिलने से अनुसंधानकर्ताओं को सेराटोप्सिया परिवार के उद्भव के बारे में ज्यादा जानकारियां जुटाने का मौका मिलेगा.
- हुआलियानसेराटॉप्स लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले पाये जाते थे. नये अनुसंधान से खुलासा हुआ है कि सींग वाले शाकाहारी डायनासोर जुरासिक काल के अंत में मांसाहारी डायनासोरों के साथ विचरण करते थे.

चर्चित स्थल

इंदौर: 15,000 से अधिक लोगों ने एक साथ साइकिल चलाकर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड

इंदौर साइक्लोथॉन' के पहले संस्करण के तहत 28 दिसम्बर 2015 को 15,000 से ज्यादा लोगों ने पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल चलाई.

- एक साथ इतनी संख्या में साइकिल चला कर दक्षिण अफ्रीका में बना विश्व रिकॉर्ड भी पीछे छूट गया और नया कीर्तिमान कायम किया गया.
- इंदौर साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्ज ने आधिकारिक मान्यता दी है.
- गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्ज के प्रमुख के अनुसार इंदौर साइकिलिंग एसोसिएशन का विश्व कीर्तिमान का दावा मंजूर करते हुए इस संगठन को बाकायदा प्रमाण पत्र जारी किया गया है.
- इस कार्यक्रम को एक ही आयोजन में सर्वाधिक लोगों द्वारा साइकिल चलाने के विश्व कीर्तिमान के रूप में मान्यता दी गयी है.
- गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्ज में दर्ज ऐसे आयोजनों का पिछला विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में वर्ष 2012 में बनाया गया था.
- इस कार्यक्रम में 8,500 लोगों ने एक साथ साइकिल चलायी थी.
- इंदौर साइकिलिंग एसोसिएशन के आयोजित पहले 'इंदौर साइक्लोथॉन' में लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सहित अन्य लोग बतौर अतिथि शामिल हुए.
- कार्यक्रम का आयोजन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंदौर साइकिलिंग एसोसिएशन ने किया.
- 'इंदौर साइक्लोथॉन' का आयोजन पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागृति फैलाने के लिये किया गया.

- साइक्लोथॉन में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी ने हिस्सा लिया.

साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंदौर साइकिलिंग एसोसिएशन प्रशासन से चर्चा के जरिये कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर के कुछ व्यस्त मार्गों पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर सप्ताह में एक दिन के लिये रोक लगा दी जाये और इन गाड़ियों की जगह साइकिल के इस्तेमाल को मंजूरी दी जाये.

रक्षा-सुरक्षा

अस्त्र मिसाइल की महत्वपूर्ण एंटी जैमिंग क्षमता का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैज्ञानिकों ने अस्त्र मिसाइल की महत्वपूर्ण एंटी जैमिंग क्षमता का सफल परीक्षण किया. कुछ और परीक्षणों के बाद इस मिसाइल को वायु सेना में शामिल किया जाएगा.

अस्त्र मिसाइल के बारे में

यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो हर मौसम में दुश्मन के ठिकानों को भेद सकने में सक्षम है.

यह भारत की पहली दृष्टि से परे (बीवीआर) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. सभी प्रकार की परिस्थितियों में काम करने में सक्षम और आधुनिक तकनीक पर आधारित इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया.

3.8 मीटर लंबी अस्त्र मिसाइल डीआरडीओ की सबसे छोटी मिसाइल है. इसे विभिन्न उंचाइयों से प्रक्षेपित किया जा सकता है. यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किए जाने पर 110 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किए जाने पर 44 किलोमीटर और समुद्र की सतह से प्रक्षेपित किए जाने पर 21 किलोमीटर तक जा सकती है.

भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस गोदावरी सेवानिवृत्त

भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस गोदावरी को मुंबई में नौसेना बेस से 23 दिसंबर 2015 को सेवा से हटा लिया गया.

आईएनएस गोदावरी को 10 दिसंबर 1983 में नौसेना में शामिल किया गया था. पिछले तीन दशक में इसने

अनेक अभियानों में सफलता हासिल की.

इस विशाल जहाज का रडार डी बैन्ड और हॉल माउन्टेड सोनार सिस्टम के साथ था. आईएनएस गोदावरी को हटाए जाने के साथ ही उसका जीवन चक्र पूर्ण हो गया.

पिछले तीन दशक से ज्यादा समय से गोदावरी कई अभियानों में तैनात रहा जिसमें 'ऑपरेशन जूपिटर' - 1988 : श्रीलंका:, 'ऑपरेशन शील्ड' और 'ऑपरेशन बोल्सटर' - 1994 : सोमालिया से भारतीय सेना को वापस लाने और 'अदन की खाड़ी में गश्त' - 2009 और 2011 में अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान शामिल है.

वर्ष 1988 में 'ऑपरेशन कैक्टस' के माध्यम से भारत ने मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को नाकाम कर दिया था, जिसमें आईएनएस गोदावरी की भूमिका महत्वपूर्ण थी.

भारत ने रूस से रक्षा प्रणाली खरीद समझौते को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में 18 दिसंम्बर 2015 को रक्षा खरीद परिषद ने एयर-स्पेस की सुरक्षा करने वाली एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने की मंजूरी दे दी. 23 दिसंबर को मोदी तीन दिवसीय रुस यात्रा पर रवाना होंगे.

पीएम की यात्रा के दौरान इस रक्षा सौदे पर हस्ताक्षार किए जा सकते है. इस डील की कीमत लगभग 30-32 हजार करोड़ रुपये है. भारत वायुसेना के लिए एस-400 मिसाइल की 05 (पांच) फायरिंग यूनिट रशिया से खरीदेगा. हाल ही रशिया ने इस मिसाइल सिस्टम को सीरिया में तैनात किया था.

मिसाइल के बारे में: मारक क्षमता-

- एंटी-बैलिस्टक एस-400, लंबी दूरी की मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को आसानी से लक्ष्य कर सकती है.
- रूस की एस-400 प्रणाली में अलग-अलग क्षमता की तीन तरह की मिसाइलें मौजूद है.
- एस-400 सुपसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम में सुपरसोनिक एवं हाइपर सोनिक मिसाइलें होती हैं.
- यह आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से हमला कर सकती है.
- एस-400 के लांचर से दुश्मन के विमान या मिसाइल पर तीन सेंकड में दो मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं. इससे छूटी मिसाइलें 5 किलोमीटर प्रति सेंकड की रफ्तार से छूटती हैं और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक

वार कर सकती हैं.

- यह रडार की पकड में न आने वाली अमेरिकन एफ-35 फाइटर जेट को भी टारगेट कर सकती है.
- इसकी तैनाती के बाद भारत की उत्तरी, उत्तर पूर्वी और उच्चर पश्चिमी सीमा को जबरदस्त सुरक्षा मिलेगी. संभवतया भारत इस तरह की 6000 मिसाइलें रूस से खरीदेगा.
- इस उपयोगी मिसाइल सिस्टम को चीन ने भी इस रशिया से खरीदा है.
- 30 हजार करोड़ की एस-400 मिसाइल सिस्टम ग्लोबल टेंडर के तहत रशिया से खरीदी जायेगी.

अन्य सौदे: जिन्हें मंजूरी दी गई-

- इसके अलावा रक्षा खरीद परिषद ने एयरफोर्स के लिए 1200 करोड़ की 24 पिचोरा एयर-डिफेंस मिसाइल खरीदने की मंजूरी दी.
- पिचोरा भी रशियन मिसाइल है जो कम दूरी (25-30 किलोमीटर) के लिए इस्तेमाल की जाती है.
- भारतीय वायुसेना पहले से ही पिचोरा मिसाइल इस्तेमाल कर रही है.
- थलसेना के लिए मल्टीबैरल रॉकेट लांचर सिस्टम की 6 अतिरिक्त पिनाक मिसाइल रेजीमेटं तैयार करने की अनुमति दी है.
- पिनाक प्रणाली से पलक झपकते ही एक साथ कई रॉकेटों की बौछार की जा सकती है, जो 38 किलोमीटर के क्षेत्र में विध्वंस करने में सक्षम है.
- इन रेजीमेंट के लिए एलएंडटी, टाटा-पॉवर और बीईएमएल से ये पिनाक मिसाइल खरीदने का प्रवधान है.
- मेक इन इंडिया योजना के तहत होने वाले इस सौदे की कुल कीमत 14 हजार 600 करोड़ रुपये है.
- इसके अलावा नौसेना के लिए 9 हजार करोड रूपये की लागत से 05 फ्लीट स्पोर्ट शिप खरीदने की मंजूरी दी गई.
- साथ ही काउंटर-टेरिरज्म के लिए सेना को 571 बुलेट-प्रूफ गाड़ियां खरदीने की भी मंजूरी दी गई है.
- कुल मिलाकर रक्षा खरीद परिषद ने मेक इन इंडिया के तहत करीब 25 हजार करोड़ रुपये के सैन्य साजो-सामान खरीदने की मंजूरी दी है.

पाकिस्तान ने शाहीन 1-ए प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया

पाकिस्तान ने 15 दिसम्बर 2015 को 'शाहीन 1-ए' प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया. प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण का उद्देश्य उसकी विभिन्न डिजाइन और तकनीकी मानदंडों का सत्यापन करना था. 'शाहीन 1-ए' 900 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है.

इसका परीक्षण स्ट्रेटजिक प्लान डिविजन और स्ट्रेटजिक फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों और सामरिक संगठनों के इंजीनियरों की मौजूदगी में अरब सागर में किया गया.

शाहीन 1-ए के बारे में-

- शाहीन 1-ए का कोड नाम हत्फ-चतुर्थ शाहीन है.
- यह भूमि आधारित मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल है.
- इसे संयुक्त उद्यम नेस्कॉम और नेशनल डिफेंस द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है.
- इसका नाम पाकिस्तान के पहाड़ों में पाए जाने फाल्कन की एक प्रजाति नस्ल के नाम पर नामित किया गया है.
- पाकिस्तान की शाहीन 1-ए और शाहीन 1 दोनों मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्शिंग 1 और पर्शिंग 1 ए मिसाइलों के समकक्ष हैं.
- यह शाहीन 1 का एक उन्नत संस्करण है और बेहतर सटीकता के साथ अपने मिशन को अंजाम दे सकती है. शाहीन 1-ए की क्षमता शाहीन 1 की दोगुना है.
- डीएसआई प्रौद्योगिकी की इस मिसाइल को हथियार से लैस किया जा सकता है.

भारतीय नौसेना की एलसीयू एमके 4 परियोजना के पांचवे पोत का जलावतरण

गोल्डरन रीच शिपबिल्डेर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) कोलकाता द्वारा निर्मित (लैंडिंग क्रॉफ्ट यूटिलिटी) 'एलसीयू - एल 55' पांचवां युद्ध पोत 07 दिसम्ब्र 2015 को भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल के सुपुर्द किया गया. युद्ध पोत एलसीयू एमके 4 परियोजना का हिस्सा है. वाइस एडमिरल ए वी सुभेदार ने

पोत का विधिवत जलावतरण कराया.

'एलसीयू" (लैंडिंग क्रॉफ्ट यूटिलिटी) - एल 55 के बारे में-

- नव निर्मित पोत का नाम 'एलसीयू - एल 55' रखा गया.
- 'एलसीयू - एल 55' आठ लैंडिंग क्रॉफ्ट यूटिलिटी शिप्सय की श्रृंखला का पांचवां पोत है.
- पोत को मैसेर्स/ जीआरएसई ने भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन एवं निर्मित किया है.
- पोत की तैनाती विविध प्रकार की भूमिकाओं वाली गतिविधियों यथा बीचिंग ऑपरेशन्स , मानवीय एवं आपदा राहत कार्यों तथा दूरदराज के टापुओं से लोगों को निकालने के लिए की जाएगी.
- इस पोत को जल्दह ही भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा.
- एलसीयू - एमके 4 श्रेणी के पोतों का बेस पोर्ट ब्ले यर होगा.
- 'एलसीयू - एल 55' श्रेणी के पहले पोत का जलावतरण 12 मार्च 2014 को किया गया था और जीआरएसई में उसका अभ्यामस जारी है.

जीआरएसई के बारे में-

- जीआरएसई कोलकाता स्थित पोत निर्माता कंपनी है. जो भारतीय नौ सेना के लिए पोत का निर्माण करती है.
- जीआरएसई लिमिटेड के अध्योक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल ए के वर्मा (सेवानिवृत्ति) वीएसएम द्वारा नौसेना युद्धपोतों का निर्माण स्वकदेश में ही किया जा रहा है.
- जीआरएसई का 'मेक इन इंडिया' के राष्ट्रीदय लक्ष्या का अनुसरण करने व पोत निर्माण उद्योग की प्रगति की ओर मजबूत कदम है.

एलसीयू एमके 4 परियोजना-

लैंडिंग क्राफ्ट यूनिट मार्क चतुर्थ (एलसीयू एमके चतुर्थ) जीआरएसई द्वारा स्वदेशी डिजाइन और निर्मित शिल्प है. इस परियोजना के तहत श्रृंखलाबद्ध आठ युद्ध पोत जीआरएसई द्वारा भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए जाने हैं, अब तक तैयार किए गए पोतों में एल 55, पांचवां युद्ध पोत है. जीआरएसई निर्मित युद्ध पोत भारतीय तटवर्ती सीमाओं की रक्षा के लिए व दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी के लिए जाना जाता है. तीव्र गति वाले ये युद्धपोत मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी), बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है. एलसीयू एमके चतुर्थ में रिमोट कंट्रोल प्रणोदन, सहायक और बिजली उत्पादन उपकरण के लिए उन्नत एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली के साथ मौजूद हैं. लैंडिंग अभियानों के दौरान फायरिंग के लिए

आयुध गतिवाला दो सीआरएन-91 30 एमएम (CRN-91 30mm) बंदूक प्रणाली भी युद्ध पोत में लगाई गयी है. इसके अलावा इन जहाजों से मानवीय राहत अभियानों, दूर के द्वीपों पर फंसे सैनिकों या नागरिकों को निकालने के लिए, समुद्री सुरक्षा नावों के रूप में सेवा खोज एवं बचाव (एसएआर) और शांति स्थापना मिशनों को भी अंजाम दिया जा सकता है.

अब तक नौसेना को समर्पित लैंडिंग क्राफ्ट यूनिट-

इससे पहले जीआरएसई द्वारा आठ लैंडिंग क्राफ्ट उपयोगिता श्रृंखला परियोजना के तहत चार युद्ध पोत भारतीय नौसेना के सुपुर्द किए जा चुके हैं. जो निम्न है:

एलसीयू -एल 51,12 मार्च 2014 को भारतीय नौसेना के सुपुर्द किया गया.

एलसीयू -एल 52, दूसरे युद्ध पोत का 23 सितंबर 2014 को जलावतरण कराया गया.

एलसीयू -एल 53, भारतीय नौसेना को 16 जनवरी 2015 को सौंपा गया.

एलसीयू -एल 54 अब से नौ माह पूर्व 23 मार्च 2015 को भारतीय नौसेना की सेवा में आया.

भारत-रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, इंद्रा नेवी-15, विशाखापत्तनम में आरंभ

भारत और रूस के मध्य 7 दिसंबर 2015 को द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास विशाखापत्तनम में आरंभ हुआ. यह भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास और दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों का प्रतीक है.

आईएनडीआरए (इंद्रा) नेवी का 8वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में 12 दिसम्बर 2015 तक आयोजित किया जाएगा.

इंद्रा नेवी 2015

- इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता बढ़ाना और सामुद्रिक सुरक्षा से जुड़े प्रचालनों के बारे में समान समझ विकसित करना है.
- इसमें सामुद्रिक प्रचालनों के दायरे के अंतर्गत बंदरगाह चरण के दौरान व्यापक पैमाने पर व्यवसायिक सम्पर्क और समुद्र चरण में विविध प्रकार की परिचालन संबंधी गतिविधियां शामिल की जाएंगी.
- इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी बेड़ा आईएनएस सह्याद्री, लक्षित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक आईएनएस रणविजय और सहायक पोत बेडा़ आईएनएस शक्ति करेंगे.

- रशियन फेडरेशन नेवी (आरएफएन) का प्रतिनिधित्व विडीम रैबुखिन आंद्रे, डिप्टी कमांडर और व्लादिवोस्तक स्थित प्रशांत बेड़े के पोत करेंगे.
- यह अभ्यास दो चरणों में, विशाखापत्तनम में बंदरगाह चरण (7 से 9 दिसम्बमर) और समुद्री चरण (10 से 12 दिसम्बर) विशाखापत्तनम तट से परे समुद्र चरण में चलाया जाएगा.
- बंदरगाह चरण में, समुद्र की ओर प्रस्थान करने से पूर्व टेबल-टॉप एक्सरसाइज और किनारे पर सम्मेलनों का आयोजन शामिल होगा.

पुरस्कार | सम्मान

भारतीय मूल के कैंसर विशेषज्ञ हरपाल सिंह कुमार नाइटहुड से सम्मानित

भारतीय मूल के कैंसर विशेषज्ञ हरपाल सिंह कुमार को महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 2015 को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की. 31 दिसंबर 2015 को प्रकाशित वार्षिक न्यू ईयर्स ऑनर्स सूचीं में प्रभावशाली कार्य के लिए सिंह का नाम कई अन्य भारतीय मूल के लोगों के साथ शामिल किया गया. हरपाल सिंह को कैंसर संबंधी अनुसंधान में उनकी सेवाओं और कैंसर से जुड़ी देखभाल और कैंसर की रोकथाम, उसके शीघ्र निदान और उपचार में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में अत्यधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया. देश के विभाजन के समय उनके माता-पिता पाकिस्तासन छोड़कर भारत चले आए थे और फिर वे लंदन जाकर बस गए.

कैंसर विशेषज्ञ हरपाल सिंह कुमार के बारे में

- कैंब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े 50 वर्षीय कुमार प्रमुख चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कैंसर रिसर्च यूके (सीआरयूके) के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं.
- केमिकल इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षण लेने के बाद कुमार ने वर्ष 1992 में मैककिन्सेश के साथ हेल्थलकेयर कंसल्टेंट के रूप में काम किया.
- उनके नेतृत्व में सरकार ने धूम्रपान को कम करने और 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सन-बेड प्रतिबंधित करने का काम किया.
- उन्होंने इंडीपेंडेंट कैंसर टास्कफोर्स की भी अध्यक्षता की और जुलाई 2015 में प्रकाशित एनएचएस कैंसर रणनीति अचीविंग वर्ल्ड क्लास कैंसर आउटकम्स ए स्ट्रेटजी फोर इंग्लैंड 2015-20 का भी लेखन किया.
- इसके अलावा पैलेस आफ वेस्टमिंस्टर के बिल्डिंग सर्विसेस इंजीनियर गुरमीत कालसी को सरे में सिख समुदाय की स्वैछिक सेवाओं और संसदीय सेवाओं के लिए इस सूची में शामिल किया गया.

शाइमा कासिम अब्दुलरहमान मिस इराक 2015 चुनी गईं

ईराक के किरकुक नामक शहर की शाइमा कासिम अब्दुलरहमान को 19 दिसम्बर 2015 को वर्ष 2015 की मिस इराक चुना गया.

यह प्रतियोगिता ईराक की राजधानी बग़दाद में आयोजित की गई थी. जबकि पूर्व में इस प्रतियोगिता का आयोजन बसरा नामक इराक के शहर में निर्धारित था परन्तु आतंकवादियों की धमकी के कारण यह स्थान बदलना पड़ा.

इससे पूर्व मिस इराक सौंदर्य प्रतियोगिता पर वर्ष 1972 मैं आयोजित की गई थी जब अहमद हसन अल बक्र इराक के राष्ट्रपति थे अर्थात चार दशक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई. उस वक्त तेल संपदा से समृद्ध इस देश की शासन व्यवस्था पर कट्टरपंथी हावी नहीं थे.

शाइमा अर्थशास्त्र की छात्रा हैं.

इराक में कट्टरपंथी तत्वों की धमकी के बावजूद यह सौंदर्य प्रतियोगिता की गई. आयोजकों को खूंखार आतंकी संगठन आईएस की ओर से लगातार धमकियां मिल रहीं थीं. आतंकियों ने प्रतियोगिता के होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी.

इस वजह से आयोजकों ने स्विम सूट सेशन नहीं कराया. प्रतियोगिता के फाइनल के सीधे प्रसारण पर भी रोक थी। जिस होटल में प्रतियोगिता हुई, उसके बाहर जबरदस्त पहरा था. धमकियों के कारण इससे पहले एक बार प्रतियोगिता की तारीख टालनी पड़ी थी.

इराक के एक तिहाई भाग पर आईएस का कब्जा है. आतंकी महिलाओं को शरीर ढके रहने का फरमान जारी करते रहते हैं. यहां के कबीलाई नेता और कट्टरपंथी संगठन सौंदर्य प्रतियोगिता को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं. हालांकि इराक में एक तबका ऐसा भी है, जो ऐसे आयोजनों के पक्ष में है.

प्रतियोगिता के लिए 150 से अधिक लड़कियों ने आवेदन किए थे.

फिलीपींस की पिया अलोंज़ो वर्त्ज़बैक मिस यूनिवर्स-2015 बनीं

अमेरिका के लॉस वेगास शहर में 20 दिसंबर 2015 को आयोजित 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस फिलीपींस पिया अलोंज़ो वर्त्ज़बैक ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता.

मिस कोलंबिया एड्रियाना गुटिरेज फर्स्ट रनर अप और मिस यूएस ओलिविया जॉर्डन सेकंड रनर अप रहीं. गौरतलब है कि कार्यक्रम का संचालन कर रहे स्टीव हार्वे ने गलती से मिस कोलंबिया को इस खिताब के लिए घोषित किया लेकिन बाद में उन्होंने गलती सुधारते हुए मिस फिलीपींस ने नाम की घोषणा की.

मिस यूनिवर्स 2015 प्रतियोगिता

- भारत की ओर से भाग ले रहीं उत्तराखंड की उर्वशी रौतेला टॉप 15 में भी स्थान हासिल नहीं कर पायीं.
- लास वेगास के प्लेनेट हॉलिवुड रिजॉर्ट एंड कैसिनो में मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था.
- प्रतियोगिता में 80 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया.
- जजों द्वारा यह पूछने पर कि उन्हें क्यों मिस यूनिवर्स होना चाहिए, इस सवाल के जवाब में मिस फिलीपींस ने कहा, 'मिस यूनिवर्स का खिताब मेरे लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों होगा. यदि मैं मिस यूनिवर्स होती हूं तो युवाओं की आवाज बनूंगी. मैं लोगों में एचआईवी को लेकर समस्याग्रस्त देशों में जागरूकता का प्रसार करूंगी.'

मिस स्पेन मिरिया लालागुना रायो 'मिस वर्ल्ड 2015' चुनी गईं

मिस स्पेन मिरिया लालागुना रायो ने 19 दिसम्बर 2015 को विश्व सुंदरी 2015 का खिताब जीत लिया.

वर्ष 2015 में इस प्रतियोगिता का आयोजनकर्ता देश चीन था. यह प्रतियोगिता चीन के सान्या नाम शहर में आयोजित की गई थी.

विदित हो इस वर्ष यह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 65वां संस्करण था.

प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब मिस रशिया सोफिया निकितचुका को और सेकेण्ड रनरअप का खिताब मिस इंडोनेशिया मारिया हार्फंती को प्रदान किया गया.

विदित हो इस वर्ष भारत की ओर से मिस इंडिया अदिति आर्या ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था. प्रतियोगिता के दौरान अदिति आर्या शीर्ष 20 में जगह बनाने में नाकाम रहीं. हालांकि पीपुल्स च्वॉइस अवॉर्ड जीतने के बाद उन्हें प्रतियोगिता के आखिरी दौर में सीधे प्रवेश मिली थी. लेकिन वह शीर्ष 20 में शामिल नहीं हो सकीं.

मिस वर्ल्ड 2015 प्रतियोगिता और विवाद

इस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता उस वक्त विवादों में आ गई, जब चीन ने मिस कनाडा अनास्तासिया लिन

के चीन आने पर प्रतिबंध लगा दिया.

ज्ञात हो लिन चीनी मूल की हैं और चीन की धार्मिक नीतियों की कड़ी आलोचक हैं. वह फालुन गोंग मेडिटेशन पे्रक्टिस की फॉलोवर हैं. यह प्रेक्टिस चीन में 1999 से प्रतिबंधित है.

लिन का कहना है कि जब उन्होंने चीन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मिस कनाडा प्रतियोगिता जीती, तो चीन के सुरक्षा एजेंट चीन में रह रहे उनके पिता के पास गए और उन्हें धमकाया.

एंडी मरे वर्ष 2015 के 'बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ़ द इयर' चुने गए

ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे को 20 दिसम्बर 2015 को वर्ष 2015 के'बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ़ द इयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

यह पुरस्कार उत्तरी आयरलैंड की राजधानी, बेलफास्ट के एसएसई अरीना में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया.

मरे को आयरलैंड के महान बॉक्सिंग खिलाड़ी बेरी मैक गुइगन द्वारा सम्मानित किया गया.

सामरोह के दौरान रग्बी लीग प्लेयर केविन सिन्फील्ड को रनरअप जबकि ब्रिटिश महिला एथेलीट जेसिका एन्निस हिल को तीससे स्थान पर चुना गया.

विदित इस विजेता के चयन के लिए एक चुनाव आयोजित किया गया था जिसमे मरे को कुल मत का 35 प्रतिशत प्राप्त हुआ. जबकि सिन्फील्ड को 28 और जेसिका को 8 प्रतिशत मत प्राप्त हुए.

ज्ञात हो इस बार एंडी मरे आस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में पहुंचे जबकि फ्रेंच और विंबलडन के सेमी फाइनल में. वर्ष के अंत में वह विश्व रैंकिंग के दूसरे स्थान पर रहे.

उन्हें वर्ष 2004 में भी 'स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ़ द इयर' चुना गया था.

ध्यातव्य हो 79 वर्षों बाद वर्ष 2015 में एंडी मरे ने ब्रिटेन को डेविस कप जीतने में सफलता दिलाई.

समारोह में अन्य विजेता

- बीबीसी ओवरसीज़ स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी ऑफ़ द इयर - डेनियल विलियम कार्टर
- यंग स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी ऑफ़ द इयर - एले डाउनि, 16 वर्षीय ब्रीटिश जिमनास्ट
- कोच ऑफ़ द इयर - माइकल ओ नेल, वर्तमान में उत्तरी आयरलैंड की फुटबाल तेम के प्रबंधक.

- हेलेन रोलसन - बैले मैथ्यूस, ब्रिटेन का 8 वर्षीय बच्चा जो सेरेब्रल पैलेसी नामक बीमारी से पीड़ित है. जिसने ट्रायलन कही जाने वाली प्रतियोगिता को पूरा किया जिसके अंतर्गत दौड़, तैराकी और साइकिलिंग शामिल होती है.
- स्पोर्ट्स अनसंग हीरो - डैमें लिंडसे, पश्चिमी बेलफास्ट में एक फ़ुटबाल कोच.
- लाइफ़टाईम अचीवमेंट - एपी मेकॉय - उत्तरी आयरलैंड के जॉकी

पति- पत्नी क्लाउड और नोर्मा अल्वारेस को 2015 सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया

18 दिसंबर 2015 को पति- पत्नी क्लाउड और नोर्मा अल्वारेस को सेंचुरी एशिया पत्रिका ने 2015 सेंचुरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया.

दूसरी तरफ भारत में वन्यजीव अपराधों के खिलाफ लड़ने वाले अग्रदूतों में से एक और भारत वन्यजीव ट्रस्ट के सेवामुक्त अध्यक्ष अशोक कुमार को सेंचुरी लीजेंड का खिताब दिया गया. साल 2015 के लिए सेंचुरी लाइफटाइम अवार्ड्स में यह नई श्रेणी है.

वाइल्डलाइफ सर्विस अवॉर्स पांच हस्तियों को दिया गया-

- नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, बेंगलुरु के वैज्ञानिक वरद गिरी को सांपों, गेको, मेढ़कों और सेसिलियनों की नई प्रजातियों की खोज समेत ज्ञात छोटी प्रजातियों को समझने और उनके वर्गीकरण में योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- पहले अरुणाचल प्रदेश पक्षी महोत्सव की आयोजक नंदिनी वेल्हो.
- उत्तराखंड के प्रशिक्षित भूविज्ञानी और वन अधिकारी, परम जीत सिंह.
- हिम तेंदुआ ट्रस्ट के भारत कार्यक्रम के निदेशक यश वीर भटनागर. इन्होंने एशियाई आईबेक्स पर दीर्घ कालिक अध्ययनों में से एक का भी आयोजन किया था. इन्होंने लद्दाख में लीक से हटकर वैज्ञानिक अन्वेषण भी किया था.
- गिर शेर संरक्षण टीम.

क्लाउड और नोर्मा अल्वारेस के बारे में

- क्लाइड और नोर्मा अल्वारेस भारतीय समाजसेवक, पर्यावरण कार्यकर्ता, वकील और पर्यावरण कार्य समूह गोवा फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हैं.
- गोवा फाउंडेशन के तत्वाधान में नोर्मा ने 1987 में गोवा के रेत के टीलों को बचाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी. राज्य में दायर की जाने वाली यह पहली जनहित याचिका थी.
- ये पशु समर्थन समूह पीपुल्स फॉर एनिमल्स की अध्यक्ष हैं और पर्यावरणीय पहलों अदर इंडिया बुक स्टोर और अदर इंडिया प्रेस की संस्थापक हैं.
- साल 2002 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था.
- क्लाउड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के गोवा तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य हैं.
- ये भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ पर बनी सुप्रीम कोर्ट निगरानी समिति (एससीएमसी) के भी सदस्य हैं.

सेंचुरी एशिया के बारे में

- सेंचुरी एशिया भारत की पहली और अग्रणी पर्यावरणीय खबरिया पत्रिका है.
- इसका प्रकाशन निजी स्वामित्व के अधीन है. यह स्वतंत्र उद्यम है और किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करता.
- प्रसिद्ध पर्यावरणविद् फतेह सिंह राठौड़ के आदेश पर इसकी स्थापना 1981 में बिट्टू सहगल ने की थी.
- यह पर्यावरणीय सक्रियता, विशेष संरक्षण कारणों के लिए चलाए जाने वाले मीडिया अभियानों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है.

केयर्न इंडिया सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित

देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्खनन और उत्पादक कंपनी केयर्न इंडिया को 17 दिसम्बर 2015 को कॉर्पोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 2015 का सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

आईटीसी के अध्यक्ष वाई. सी. देवेश्वर, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी

और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पूर्व महानिदेशक आर. ए. माशेलकर ने केयर्न इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक असहर को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया.

केयर्न इंडिया के बारे में

- केयर्न इंडिया का मुख्यालय गुड़गांव, भारत में है.
- यह कम्पनी भारत में लगभग पंद्रह से अधिक वर्षों से सक्रिय है.
- यह वेदांत रिसोर्सेज की सहायक कंपनी है.
- केयर्न और उसके संयुक्त उद्यम भागीदार भारत के घरेलू बाजार में कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग पांचवा हिस्सा वहन करते हैं.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सार्वलौकिक नवाचार में उत्कृष्ट वैश्विक मागदर्शन के लिए गारवुड पुरस्कार से सम्मानित

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हास स्कूल ऑफ बिजनेस (कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय) की ओर से 'सार्वजनिक नवाचार में उत्कृष्ट वैश्विक मार्गदर्शन' के लिए 17 दिसंबर 2015 को गारवुड पुरस्कार से सम्मानित किये गए. गारवुड सेंटर फॉर कॉरपोरेट इनोवेशन के कार्यकारी निदेशक प्रो.सोलोमन डारविन ने राष्ट्रपति को यह पुरस्कार प्रदान किया.

विदित हो कि विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हास स्कूल ऑफ बिजनेस ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से सार्वलौकिक नवाचार को प्रोत्साहन और सहायता देने वाले व्यक्ति के उत्कृष्ट कार्यो के लिए गारवुड पुरस्कार की स्थापना की.

उपरोक्त पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रपति भवन में समावेशी नवाचारों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में वैश्विक नवीन अविष्कारों के संयोजन और मेजबानी के लिए पहल करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जमीनी स्तर पर अभिनवों के संवर्द्धन के लिए तकनीकी, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों के वैश्विक प्रमुखों को एक साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रपति भवन में प्रथम नवाचार उत्सव का संयोजन करने, प्रारंभिक स्तर से अभिनव की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए प्रथम 'इन-रेजीडेंस' कार्यक्रम का शुभारंभ करने, उच्चतीर शिक्षण संस्थानों और जमीनी स्तर पर नवाचार के लिए कार्य कर रहे अविष्कारकों के बीच समन्वय के लिए एक नवाचार समूह की स्थापना के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रमुखों से अपील करना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम में वित्तीय समावेशन के लिए अभिनव समाधान की

दिशा में सार्थक प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सफलता को प्रोत्साहन एवं नवाचार, अनुसंधान एवं विकास एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के अंतरमहाद्वीपीय माध्यम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षाविदों, उदयमियों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करने जैसे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया गया.

वायलिन वादक इत्जहक पर्लमैन ने जीता वर्ष 2016 का जेनेसिस पुरस्कार

जेनेसिस प्राइज़ फाउंडेशन ने 14 दिसम्बर 2015 को विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक इत्जहक पर्लमैन को वर्ष 2016 के जेनेसिस पुरस्कार विजेता के रूप मे चुना.

जेनेसिस पुरस्कार के रूप में विजेता को 1 मिलियन यूएस डॉलर की राशि प्रदान की जाती है.

विदित हो जेनेसिस प्राइज़ को 'द जेविश नोबेल/ यहूदी नोबेल' भी कहा जाता है.

ज्ञात हो वर्ष 2014 में यह पुरस्कार न्यूयॉर्क मेयर और समाजसेवक माइकल ब्लूमबर्ग को प्रदान किया गया था.

वर्ष 2015 में यह पुरस्कार एकेडमी पुरस्कार विजेता, निर्माता, समाज सेवक माइकल डाइलॉग को प्रदान किया गया.

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू 23 जून 2016 को यरूशलेम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार पर्लमैन को प्रदान करेंगे.

इत्जहक पर्लमैन के बारे में

- पर्लमैन का जन्म फिलिस्तीन के तत्कालीन ब्रिटिश जनादेश वर्तमान में इसराइल में वर्ष 1945 में तेल अवीव नामक शहर में हुआ.
- मात्र चार वर्ष की आयु में उन्हें पोलियो हो गया था और उनके पैरों में लकवा मार गया था.
- वर्ष 1993 की जॉन विलियम की 'शिंडलर्स लिस्ट' नामक फिल्म से उन्होंने एकल वायलिन वादन से अपने कैरियर की शुरुआत की.
- वह वाईट हाउस के नियमित मेहमान भी रह हैं.
- उन्हें वर्ष 2008 में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- उन्हें 16 ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.

जेनेसिस प्राइज़ के बारे में

- यह पुरस्कार वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था.
- यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और जिन्होंने अपने अच्छे कार्यों से यहूदी समुदाय एवं इसराइल के लोगों के लिए प्रेरक की भूमिका निभाई हो.
- यह पुरस्कार इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय, जेनेसिस प्राइज़ फाउंडेशन और जेविश एजेंसी के अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने बप्पी लाहिड़ी, कुमार सानू को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने वरिष्ठ संगीतकार बप्पी लाहिड़ी और गायक कुमार सानू को 14 दिसंबर 2015 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में आयोजित संगीत सम्मान पुरस्कार समारोह में दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया.

उपरोक्त के साथ ही साथ बॉलीवुड संगीतकार शांतनु मोइत्रा को संगीत महासमान और गायक नचिकेता एवं अजय चक्रवर्ती को विशेष संगीत समान से नवाजा गया. इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोक कलाकारों को अब सरकारी विज्ञापन का काम दिया जायेगा ताकि उन्हें काम मिल सके. उन्होंने 23 दिसंबर 2015 से लाल दिघी में एक लोक संस्कृति उत्सव मनाए जाने की भी घोषणा की.

अभिनेता दिलीप कुमार पद्म विभूषण से सम्मानित

भारतीय सिनेमा के अभिनेता दिलीप कुमार को 13 दिसम्बर 2015 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें यह सम्मान उनके मुंबई स्थित निवास पर प्रदान किया.

केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2015 को 66वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म विभूषण के लिए दिलीप

कुमार को चुना था.

दिलीप कुमार के बारे में

- दिलीप कुमार का जन्म पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में पठान फल व्यापारी गुलाम सरवर के घर 11 दिसंबर, 1922 को हुआ था.
- उनका बचपन महाराष्ट्र में बीता पहली बार उन्होंने अपना घर एक कैंटीन चलाने के लिए छोड़ा था.
- उनकी पहली फिल्म बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित ज्वार भाटा थी.
- दिलीप कुमार को 'मुग़ल-ए-आज़म', 'नया दौर 'देवदास, 'मधुमति, 'गंगा-जमुना, 'आजाद', 'लीडर' और 'मशाल' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.
- फ़िल्मी कैरियर में उन्होंने अपनी दूसरी पारी वर्ष 1981 की फिल्म 'क्रांती' से की.
- फिल्म जगत में उन्हें 'ट्रेजेडी किंग' के नाम से भी जाना जाता है.
- वर्ष 2000 में उन्हें राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था और वह वर्ष 2006 तक सांसद रहे.
- उनकी आत्मकथा 'द सब्सटेंस एंड द शेडो' लेखक और पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर द्वारा तैयार की गई है.
- उन्हें वर्ष 1991 में पद्म भूषण, वर्ष 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया.
- एक भारतीय अभिनेता के रूप में अधिकतम जीतने के लिए उनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है.

भारतीय मूल के लेखक जेएम साली ने 2015 साउथ ईस्ट एशियन अवार्ड फॉर सिंगापुर पुरस्कार जीता

भारतीय मूल के तमिल लेखक जमालुद्दीन मोहम्मद साली को 11 दिसंबर 2015 को 2015 साउथ ईस्ट एशियन अवार्ड फॉर सिंगापुर प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया.

बैंकॉक में 14 दिसंबर 2015 को आयोजित समारोह में साली को साहित्यिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

जे एम साली कौन है?

- वर्ष 1939 में मद्रास में जन्मे, जेएम साली को 25 वर्ष की उम्र में तमिल मुरासु अखबार के संस्थापक जी. सारंगपानी ने सिंगापुर आमंत्रित किया और उन्हें अखबार में सहायक संपादक नियुक्त किया.
- साली ने वहां रेडियो पत्रकार के रूप में स्थानीय प्रसारण स्टेशन और सिंगापुर प्रसारण निगम के लिए काम किया.
- उन्होंने मार्शल आर्ट आइकन ब्रूस ली और प्रसिद्ध मुक्केबाज मुहम्मद अली समेत कई मशहूर लोगों पर पुस्तके लिखी.
- वह पत्रकारिता में पूर्णकालिक लेखन और अनुवाद कार्य से 2000 में सेवानिवृत्त हुए.

उनकी प्रसिद्ध लघु कहानियों और उपन्यासों में वेल्ली कोदुगल (वाइट लाइन्स) और अलैगल पेसुजिंराना (लहरों की ध्वनि) हैं. वे अब सिंगापुर और भारतीय विश्वविद्यालयों में तमिल साहित्य के छात्रों को पढ़ा रहे हैं.

साउथ ईस्ट एशियन राइट अवार्ड के बारे में-

- साउथ ईस्ट एशियन राइट अवार्ड (एसईए राइट अवार्ड) 1979 से कवियों और दक्षिण पूर्व एशिया के लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है.
- पुरस्कार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन में शामिल देशों में से प्रत्येक देश के लेखक को दिया जाता है. आसियान देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी देशों के पत्रकारों को नहीं हैं.
- पुरस्कार कभी- कभी लेखक द्वारा किए गए उसके विशेष कार्य के लिए दिया जाता है या आजीवन उपलब्धि के लिए भी सम्मानित किया जा सकता है.
- पुरस्कार विभिन्न विषयों कविता, लघु कथाएँ, उपन्यास, नाटक, लोकगीत, विद्वानों और धार्मिक कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है.

विप्रो ने आईओटी में नवाचार के लिए 2015 एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार जीता

विश्व की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो को 11 दिसंबर 2015 को इंटरनेट (आईओटी) हेतु समाधान विकसित करने के लिए “2015 एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार” का विजेता घोषित किया गया.

विप्रो को आईओटी समाधान व विकास, यूनिवर्सल डेटा पार्सर (यूडीपी), के कारण इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया.

एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार के बारे में-

- एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार की स्थापना, एजिस स्कूल ऑफ़ बिजनेस के तत्वावधान में टेलीफोन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को श्रद्धांजलि देने लिए की.
- पुरस्कार दूरसंचार, इंटरनेट, मीडिया और एड्युटेनमेंट (टीआईएमई) के क्षेत्र में नवाचार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और भारत में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए आरम्भ किया गया.
- पुरस्कार भारत सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन (सीओएआई), और उत्कृष्ट भारतीय दूरसंचार केन्द्रों (टीसीओइ) के सहयोग से आयोजित किया जा रहे हैं.

सलमान रुश्दी मेलर पुरस्कार से सम्मानित

भारत में जन्में लेखक सलमान रुश्दी को 10 दिसंबर 2015 को लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए प्रख्यात मेलर प्राइज़ से सम्मानित किया गया. अमेरिकन आर्टिस्ट लौरी एंडरसन ने रुश्दी को न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन के प्रैट इंस्टिट्यूट में सम्मानित किया.

यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने स्वतन्त्र लेखन के माध्यम से किसी मुद्दे पर बहस छेड़ी हो.

सलमान रुश्दी

- उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं - मिडनाइट चिल्ड्रेन एवं द सेटेनिक वर्सेस
- उनका हाल ही में प्रकाशित हुआ उपन्यास, टू इयर्स ऐट मंथ्स एंड ट्वेंटी ऐट नाइट्स, सितंबर 2015 में प्रकाशित हुआ.
- वे ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ़ लिटरेचर के मानद सदस्य हैं.
- उन्हें दो बार व्हिटब्रेड पुरस्कार, राइटर्स गिल्ड अवार्ड, यूरोपियन यूनियन्स आर्टिस्टियन प्राइज़ फॉर लिटरेचर, लंदन इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड एवं यूएस नेशनल आर्ट्स अवार्ड.
- उन्हें छह यूरोपियन एवं छह अमेरिकन विश्विद्यालयों द्वारा मानद उपाधि द्वारा सम्मानित किया जा चुका है. वे एमआईटी में मानविकी विषय के मानद प्रोफेसर भी हैं तथा इमोरी यूनिवर्सिटी में विशिष्ट प्रोफेसर हैं.

मेलर प्राइज़

- यह अमेरिकन लिटररी पुरस्कार वर्ष 2009 में द नार्मन मेलर सेंटर एवं द नार्मन मेलर राइटर्स कॉलोनी द्वारा स्थापित किया गया था.
- इसका नाम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक नार्मन मेलर के नाम पर रखा गया है.
- यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिनके लेखन द्वारा विश्व भर के पाठकों की सोच को प्रभावित किया हो.

इससे पहले सम्मानित लेखक हैं:

- डॉन डीलिल्लो - 2014
- माया अंगेलो - 2013
- जॉयस कैरोल ओट्स - 2012
- एली वीज़ल - 2011
- ओरहन पामुक - 2010
- टोनी मॉरिसन - 2009

चार भारतीय शिक्षक 'वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2016' के लिए मनोनीत

चार भारतीय शिक्षकों को 9 दिसम्बर 2015 को 'शिक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार' कहे जाने वाले वार्की जीईएमएस फाउन्डेशन ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2016 के लिए मनोनीत किया गया.

इन चार भारतीय शिक्षकों को विश्व के 148 देशों के 8000 मनोनयन में से अंतिम 50 में जगह मिली है.

इन शिक्षकों में दो शिक्षक मुंबई, 1 शिक्षक दिल्ली और एक बंगलुरु के हैं.

विजेता को पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूएस डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी.

मनोनीत किए गए चार भारतीय शिक्षक निम्न हैं

- रॉबिन चौरसिया - गैर-लाभकारी संगठन क्रांति के संस्थापक हैं जो मुंबई के रेड लाइट क्षेत्रों की लड़कियों

के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है.

- धवल बाठिया, मुंबई
- सांथी कारामचेती - ईडी वेंचर, बेंगलुरु
- रश्मि कथूरिया - कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल, दिल्ली

अंतिम 10 विजेता की घोषणा वर्ष 2016 के फरवरी माह में की जाएगी और पुरस्कारों का वितरण ग्लोबल एजुकेशन एण्ड स्किल्स फोरम के दौरान मार्च, 2016 में किया जाएगा.

वार्की जीईएमएस फाउन्डेशन ग्लोबल टीचर प्राइज़

- इस पुरस्कार का शुभारम्भ वर्ष 2014 में वार्की फाउंडेशन एट द ग्लोबल एजुकेशन एण्ड स्किल फोरम द्वार किया गया.
- यह पुरस्कार अध्यापन के पेशे के महत्व को पहचान करने के लिए शुरू किया गया.

वार्की फाउंडेशन की स्थापना सन्नी वार्की द्वारा की गई थी.

वर्ष 2015 में 'वार्की जीईएमएस फाउन्डेशन ग्लोबल टीचर प्राइज़(2014)' की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षक 'नैन्सी एटवेल' थीं.

ब्रिटेन में दो भारतीयों ने जीता क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड

ब्रिटेन में दो भारतीयों ने 09 दिसम्बर 2015 को क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड जीता है. यह पुरस्कार उन्हें दूसरों की जिंदगी में बदलाव और अपने समुदाय में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए दिया गया है.

ब्रिटेन में 60 लोगों को वर्ष 2016 के क्वीन यंग लीडर अवार्ड के लिए चुना गया हैं. अवार्ड जीतने वालों में 21 वर्षीय कार्तिक साहनी और 28 वर्षीया नेहा स्वैन भारतीय हैं. अगले वर्ष जून में बकिंघम पैलेस में ब्रिटेन की महारानी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी.

अवार्ड विजेता कार्तिक व नेहा के बारे में

जन्म से ही दृष्टिहीन कार्तिक अपने असाधारण काम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने शिक्षा की पहुंच आम जन मानस तक पहुंचाने के लिए असाधारण काम किया.

दृष्टिहीन छात्रों को पेश आने वाली मुश्किलों से जूझ चुके कार्तिक को 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए संघर्ष

करना पड़ा. उन्होंने एसटीईएमएक्सेस प्रोजेक्ट की स्थापना की.

एक गैर सरकारी संगठन रूबरू की युवा समन्वयक और सह-संस्थापक नेहा इंटरैक्टिव कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुकूल उनके नेतृत्व कौशल को विकसित करने हेतु युवाओं को समावेशी स्थान प्रदान करती है.

रूबरू की टीम भारत के स्कूलों में नि:शुल्क कार्यशाला प्रदान करती है और गैर सरकारी संगठन ने अब तक हैदराबाद शहर में लगभग 2,000 युवाओं के साथ काम किया है.

क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड क्या है?

"दूसरों के जीवन को बदलने में योगदान देने वाले और उनके समुदायों में स्थायी परिवर्तन के लिए काम करने वाले युवाओं को राष्ट्रमंडल के 53 देशों में से क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड के लिए चयन किया जाता है.

क्वीन यंग लीडर्स अवार्ड, महारानी एलिजाबेथ डायमंड जुबली ट्रस्ट द्वारा 2014 में कॉमिक रिलीफ और रॉयल कॉमनवेल्थ सोसायटी की साझेदारी में स्थापित किया गया था. पुरस्कार के तहत किसी भी प्रकार की नकद प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है. पुरस्कार विजेताओं को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी सामग्री का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है.

नसीरुद्दीन शाह वर्ष 2015 के डीआईएफएफ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित

नसीरुद्दीन शाह को दुबई में आयोजित दुबई इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 12 संस्करण के दौरान 9 दिसम्बर 2015 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

नसीरुद्दीन शाह के अतिरिक्त फ्रांसीसी अभिनेत्री कैथरीन डेनेयुव को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

नसीरुद्दीन शाह के बारे में

- नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरूद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया.
- नसीरूद्दीन शाह का कॅरियर नसीरूद्दीन शाह ने अपने कॅरियर की शुरुआत फिल्म 'निशांत' से की थी

जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी अभिनेत्रियां थीं.

- वर्ष 1977 में टॉम ऑल्टर और बेंजामिन गिलानी के साथ साथ नसीरुद्दीन शाह ने मोटले प्रोडक्शंस नामक एक थिएटर समूह का गठन किया.
- नसीरुद्दीन शाह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और फिल्म और टेलीविजन के एशियाई अकादमी के टेलीविजन क्लब के अजीवन सदस्य हैं.
- उन्हें वर्ष 1987 में पद्म श्री और वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
- नसीरुद्दीन की आत्म कथा " एण्ड देन वन डे" है.

विदित हो दुबई इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी. वर्ष 2014 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया था.

एडिडास इंडिया के पुलिन कुमार प्रतिष्ठित आईएनबीए पुरस्कार से सम्मानित

एडिडास इंडिया के वरिष्ठ कानूनी और अनुपालन निदेशक पुलिन कुमार को 26 नवम्बर 2015 को ने दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय बार एसोसिएशन की ओर से वर्ष के जनरल परामर्शदाता- खुदरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने 66वें राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया.

कुमार को कानूनी क्षेत्र में 21 वर्षों तक देश में और देश के बाहर दिए गए योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

आईएनबीए पुरस्कार के बारे में

- इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन ने प्रौद्योगिकी, बुनियादी सुविधाओं, रियल एस्टेट, रिटेल, कॉर्पोरेट, गोपनीयता और डेटा संरक्षण, कानूनी फर्म और बीमा के क्षेत्र में सामान्य अधिवक्ता के लिए 12 पुरस्कार श्रेणियों का गठन किया है.
- यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं.
- पुरस्कारों के चयन के लिए गठित की गई जूरी में कानूनी क्षेत्र से प्रसिद्ध लोग भाग लेते हैं.

प्रख्यात वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम आईटीसी संगीत सम्मान से सम्मानित

प्रख्यात वायलिन वादक लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम आईटीसी संगीत सम्मेलन 2015 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में संगीत सम्मान से सम्मानित किए जाएँगे.

1 दिसंबर 2015 को आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी के कार्यकारी निदेशक रबी श्रीनिबासन ने पुरस्कार के लिए संगीत कलाकार के नाम की घोषणा की.

23 जुलाई 1947 को जन्मे सुब्रमण्यम शास्त्रीय कर्नाटक संगीत परंपरा और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत कला में पारंगत हैं. संगीतज्ञ सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में रचनाओं, तकनीकी बारीकियों और आर्केस्ट्रा संलयन में तकनीक की भूमिका के लिए जाना जाता है.

मीरा नायर द्वारा निर्देशित सलाम बॉम्बे और मिसिसिपी मसाला जैसी फिल्मों में वायलिन वादक सुब्रमण्यम द्वारा वायलिन पर दी गयी मधुर ने भी फिल्म के लिए दर्शकों की संख्या को बढाया.

सुब्रमण्यम को 2012 में रिकार्ड लिम्का बुक द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 1963 में बेस्ट वायलिन वादक के लिए ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रपति पुरस्कार भी उन्ही के नाम है. 2001 में प्रसिद्ध वायलिन वादक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया

एंब्रेस ऑफ द सर्पेट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार

गोवा में संपन्न भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआइ) में 30 नवंबर 2015 को कोलंबियन फ़ीचर फिल्म 'एंब्रेस ऑफ द सर्पेट' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया. उत्कृष्ट मौलिकता और शानदार कथानक के लिए 'एंब्रेस ऑफ द सर्पेट' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया. निर्माता निर्देशक शेखर कपूर की अध्यक्षता में चयन समिति ने इसे स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया.

'एंब्रेस ऑफ द सर्पेट' फिल्म का निर्देशन सायरो गुएरा ने किया है. उनकी अनुपस्थिति में इसके कला निर्देशक रामसेस बेंजुमिया ने पुरस्कार ग्रहण किया. पुरस्कृत फिल्मों की सूची में एकमात्र भारतीय फिल्म 'सिनेमावाला' (कौशिक गांगुली) का रहा. इस फिल्म को इसी वर्ष शुरू आइसीएफटी-यूनेस्को फेलिनी मेडल से नवाजा गया था. यह फिल्म पश्चिम बंगाल में सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल की दुर्दशा पर बनाई गई है.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा डॉ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड प्रदान किये गये

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 30 नवम्बर 2015 को 18 राज्यों के 27 जिलों से 40 स्कूलों के बच्चों को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड प्रदान किये.

यह पुरस्कार 31 जमीनी स्तर के अविष्कारों के लिए आईआईएम अहमबदाबाद में प्रदान किये गये. इस समय राष्ट्रपति गुजरात में तीन दिन से राजकीय दौरे पर हैं.

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गुजरात सरकार एवं आईआईएमए को कुछ अविष्कारों को लागू करने का निर्देश दिया है ताकि किसानों को सुविधा दिलाई जा सके.

डॉ अब्दुल कलाम इग्नाइट 2015 अवार्ड

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी विकास के लिए 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों द्वारा किये गए अविष्कारों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है.

यह प्रतियोगिता नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), हनी बी नेटवर्क एवं अन्य राज्यों के शिक्षा बोर्ड्स के सहयोग से आयोजित की गयी.

प्रत्येक वर्ष डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर 15 अक्टूबर को इग्नाइट अवार्ड की घोषणा की जाती है. इस दिन को बच्चों की क्रियात्मकता के तौर पर मनाया जाता है.

हिंदुजा ब्रदर्स को एशियन बिज़नेस लीडरशिप फोरम 2015 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया

29 नवम्बर 2015 को एशियन बिज़नेस लीडरशिप फोरम, दुबई (एबीएलएफ) 2015 में हिंदुजा ब्रदर्स को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया.

यह पुरस्कार सबसे अधिक प्रभावशाली बिज़नेस लीडर्स को प्रदान किये जाते हैं.

एबीएलएफ के रॉयल पैट्रन एवं यूएई के संस्कृति मंत्री शेख नहयान मुबारक अल नहयान ने हिंदुजा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के को-चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा को यह अवार्ड प्रदान किया.

एशियन बिज़नेस लीडरशिप फोरम

- यह भारत की महत्वपूर्ण वार्षिक बिज़नेस बैठक है जिसमें प्रतिष्ठित बिज़नेस लीडर्स को सम्मानित किया जाता है.
- एबीएलएफ को सऊदी अरब अमीरात की शाही सहायता प्रदान की जाती है.
- एबीएलएफ की अध्यक्षता गवर्नर बोर्ड द्वारा की जाती है जो इसके उद्देश्य, कार्यनीति एवं व्यापक संभावनाओं को तय करती है.
- इसके दो आयाम हैं: एबीएलएफ फोरम एवं एबीएलएफ अवार्ड्स.

पुस्तक - लेखक

द बोस ब्रदर्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस-एन इनसाइडर्स अकाउंट : माधुरी बोस

द बोस ब्रदर्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस- एन इनसाइडर्स अकाउंट : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी माधुरी बोस द्वारा लिखित माधुरी बोस द्वारा लिखित पुस्तक द बोस ब्रदर्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस-एन इनसाइडर्स अकाउंट 1 नवंबर 2015 को जारी की गई.

यह पुस्तक उस समय चर्चा में आई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी और पुस्तक की लेखक माधुरी बोस ने 17 दिसंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक की एक प्रति सौपी.

पुस्तक के माध्यम से लेखिका ने शरत और सुभाष चंद्र बोस के जीवन को पेश करने की कोशिश की है.

यह पुस्तक शरत और सुभाष चंद्र बोस द्वारा अनुभव किए गए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के राजनीति को दर्शाती है.

इस पुस्तक के द्वारा चितरंजन दास, जिन्ना, मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और महात्मा गांधी, शरत बोस जैसे समकालीन नेताओं के साथ उनकी बातचीत का पता चलता है.

बोस के परिवार के सदस्य द्वारा लिखित इस पुस्तक में नेताजी और शरत चंद्र बोस की अप्रकाशित सामग्री को प्रकाशित किया गया, जिसमें डॉयरी, नोट्स और फोटोग्राफ आदि शामिल हैं.

शरद पवार की आत्मकथा "लाइफ ऑन माय टर्म्स" का विमोचन किया

लाइफ ऑन माय टर्म्स: जमीनी स्तर से सत्ता के गलियारों तक: शरद पवार

लाइफ ऑन माय टर्म्स: जमीनी स्तर से सत्ता के गलियारों तक मराठा दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता (राकांपा) शरद पवार की आत्मकथा का 75 वें जन्मदिन पर 10 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया.

पुस्तक में मराठा नेता पवार ने 50 साल के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया है. उन्होंने पुस्तक में राजीव गांधी के साथ संबंधों के बारे में बताया है. खास मुद्दों पर पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गाँधी से अंतरंगता के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है. पुस्तक में उन्होंने चंद्रशेखर के साथ उनकी निकटता और उसके कारण राजीव गाँधी के साथ अपने संबंधों के बारे में भी बताया है.

शरद पवार के बारे में-

- महाराष्ट्र में बारामती तहसील के कातेवाडी गांव में 12 दिसंबर 1940 को जन्मे शरद पवार अकेले मराठा नेता हैं जो 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं.
- वह कांग्रेस नीत केंद्र सरकार में भी कई बार कैबिनेट मंत्री बने.
- राष्ट्रीय राजनीति के दिग्गज और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार अपने जीवन के ने 75 बसंत देख चुके हैं और वे राजनीतिक सफर में भी 55 साल पूरे कर चुके है.

पूर्व पत्रकार अनुज धर द्वारा लिखित पुस्तक "व्हाट हैपेंड टू नेताजी ?" का विमोचन

"व्हाट हैपेंड टू नेताजी ?": अनुज धर

पूर्व पत्रकार अनुज धर द्वारा लिखित पुस्तक "व्हाट हैपेंड टू नेताजी ?" का अक्टूबर 2015 में विमोचन किया गया. पुस्तक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है, कि वे भेष बदलकर अज्ञात रूप में लम्बे अरसे तक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले एवं अन्य स्थानों पर रहे.

पुस्तक में नेताजी बोस की मृत्यु के रहस्य के बारे में तीन प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है. फैजाबाद में अज्ञात प्रवास के दौरान उनके साथ क्या - क्या हुआ इस विषय पर भी चर्चा की गयी है.

पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनके जीवन- मृत्यु जैसे विवादस्पद तथ्यों पर ध्यान आकर्षण और 1945 में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु के बारे में तथ्यात्मक प्रकाश डाला गया है.

पुस्तक में सुब्रमण्यम स्वामी के कथन कि नेताजी को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कहने पर सोवियत रूस में मारा गया पर भी विचार विमर्श किया गया है. इस पुस्तक में अतीत और वर्तमान के चर्चित नाम महात्मा गांधी और सरदार पटेल से लेकर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किस प्रकार लंबे समय तक विवादों में रहे ओपर भी चर्चा की गयी है.

इस पुस्तक में फैजाबाद के गुमनामी बाबा पर भी प्रकाश डाला गया है तथा यह सवाल उठाया गया है कि यदि

गुमनामी बाबा ही वास्तव में नेता जी थे तो वे आम भारतीयों के सामने क्यों नहीं आए? अंत में पुस्तक में यह जानने की कोशिश की गयी है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सामने कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से नेता जी की मौत के रहस्य की फाइलों को उजागर नहीं किया जा रहा? इसका जवाब भी दिया गया है और कहा गया है कि सच्चाई, कल्पना से परे है ऐसा विश्वास पाठकों को करना होगा.

नंदन निलेकणी एवं विराल शाह द्वारा लिखित पुस्तक रीबूटिंग इंडिया का लोकार्पण

रीबूटिंग इंडिया: रियलाईजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन्स: नंदन निलेकणी एवं विराल शाह

नंदन निलेकणी एवं विराल शाह द्वारा लिखित पुस्तक, रीबूटिंग इंडिया: रियलाईजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन्स का 4 नवम्बर 2015 को लोकार्पण किया गया.

पुस्तक में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में विस्तार से बताया गया है. यह माना जा रहा है कि वर्ष 2020 तक 64 प्रतिशत आबादी (लगभग 800 मिलियन) सहित भारत विश्व की सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा.

इसमें कहा गया है कि यदि भारत समाज में फैले विरोधाभासों और सामाजिक अंतराल को कम नहीं करता तो वह विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता.

पुस्तक द्वारा निलेकणी तथा शाह ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारत की 1.2 बिलियन जनसंख्या को उनके वास्तविक मूल्यों की पहचान कराये जाने की आवश्यकता है. उनका मानना है कि यह केवल तकनीकी विकास द्वारा संभव है.

रिबूटिंग इंडिया द्वारा बहुत से सिटिज़न फ्रेंडली, हाई-टेक सार्वजानिक संस्थानों पर प्रकाश डाला गया है जो कम कीमत पर बेहतर परिणाम प्रदान कर सकते हैं.

आधार के अनुभव से सीख लेते हुए निलेकणी एवं शाह के अनुसार सरकार इन प्रयासों पर वार्षिक एक लाख करोड़ रुपये की बचत कर सकती है. यह भारत की कुल जीडीपी का एक प्रतिशत है तथा 200 मंगलयान कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त है.

इसमें लोगों की बहुत बड़ी संख्या की भी आवश्यकता नहीं होती. इसमें एक छोटी फोकस्ड तथा उच्च क्षमतावान टीम से कार्य किया जा सकता है.

इनफ़ोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी आधार के संस्थापक अध्यक्ष थे. वे दो बार टाइम द्वारा 100

प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हो चुके हैं. वर्ष 2014 में उन्हें द इकोनॉमिस्ट इनोवेशन अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया. वे एक गैर-लाभकारी संस्था एक स्टेप के अध्यक्ष भी हैं.

विराल शाह ने आधार की नीति कार्यान्वयन एवं तकनीक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने इस सरकारी प्लेटफ़ॉर्म में भुगतान करने के सिस्टम को विकसित किया. वे जूलिया प्रोग्राम लैंग्वेज के सह-अविष्कारक हैं तथा फोर्थलायन टेक्नोलॉजिज़ के सह-संस्थापक हैं. उन्होंने सांता बारबरा स्थित केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है.

राधा कांत भारती द्वारा लिखित इंटरलिंकिंग ऑफ़ इंडियन रिवर्स का लोकार्पण

इंटरलिंकिंग ऑफ़ इंडियन रिवर्स : राधा कांत भारती

राधा कांत भारती द्वारा लिखित "इंटरलिंकिंग ऑफ़ इंडियन रिवर्स" पुस्तक का 3 नवम्बर 2015 को केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष (सीडब्ल्यूसी) अटल बिहारी पंड्या द्वारा लोकापर्ण किया गया. पुस्तक में नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित विभिन्न तकनीकी विद्वानों, मीडिया कर्मियों एवं राजनीतिज्ञों के विचारों का संकलन किया गया है.

इस पुस्तक में बताया गया है कि कृषि प्रधान देश भारत में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. पुस्तक में व्यापक अनुसंधान के पश्चात् नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक, आर्थिक एवं कमर्शियल लाभ बताये गए हैं. पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय जल नीति के बारे में तथा भारतीय उपमहाद्वीप में नदियों को जोड़ने पर होने वाले विवाद पर भी प्रकाश डाला गया है.

राधा कांत भारती

राधा कांत भारती का जन्म बिहार स्थित नालंदा में वर्ष 1939 में हुआ, वे भूगोल के प्रख्यात विद्वान हैं. वे जल संसाधन से संबंधित पत्रिका 'भागीरथ' का कई वर्षों तक सम्पादन करते रहे हैं. उनके द्वारा लिखित भूगोल, पर्यटन, समाजशास्त्र आदि में विभिन्न लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं. उनके द्वारा भारतीय नदियों पर बनाई गयी डाक्यूमेंट्री को लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है.

योजना | कार्यक्रम

केंद्र सरकार ने शहरी नियोजन एवं आवासीय सुविधा हेतु 42,000 करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2015 को शहरी नियोजन और विकास की नई बुनियादी शहरी ढांचे और आवासीय सुविधा में 42,000 करोड़ रूपये के निवेश को अपनी मंजूरी दी.

उपरोक्त निर्णय के तहत सरकार ने वर्ष 2015 में शहरी योजना के लिए फिर से मानक तय किये. जिसमें जलापूर्ति, मल निकासी नेटवर्क, तीव्र जल लाइनें, शहरी यातायात और खुली जगहों के मामले में बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए 19,170 करोड़ रूपये का निवेश भी शामिल है. इस साल जून में शुरू हुए पुनर्सुधार और शहरी परिवर्तन संबंधी अटल मिशन 'अमृत' के अंतर्गत 18 राज्यों के 474 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया. इसके साथ ही 22,000 करोड़ रूपये से ज्याशदा निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 11 राज्यों के 227 शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 4,25,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा उद्योग के लिये संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2015 को कपड़ा उद्योग के लिये संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को अपनी मंजूरी दी. संशोधित योजना से कपड़ा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा.

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कपड़ा उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआर-

टीयूएफएस) के स्थान पर 'संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)' का शुभारंभ करने के लिए अपनी मंजूरी दी. यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी.

नई योजना की मुख्य विशेषता:

- परिधान और गारमेन्ट उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ाना. इससे विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और वैश्विक निर्यात में भारत के हिस्से में बढ़ोत्तरी होगी.
- निर्यात और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र तकनीकी वस्त्रों को प्रोत्साहन देना.
- गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए वर्तमान करघों को बेहतर प्रौद्योगिकी के करघों में बदलने को बढ़ावा देना.
- प्रसंस्करण उद्योग में बेहतर गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना और गारमेन्ट्स क्षेत्र द्वारा कपड़ों के आयात की जांच करना.
- संशोधित योजना से कपड़ा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा.
- इस योजना से एक लाख करोड़ रूपये के निवेश को आकर्षित करने और 30 लाख से अधिक रोजगारों के सृजन की उम्मीद है.
- इसके लिए 17,822 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गयी है, जिसमें से वर्तमान योजनाओं के अधीन प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 12,671 करोड़ रुपये और एटीयूएफएस के अधीन नए मामलों के लिए 5,151 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
- ऐसे मामले जो सभी तरह से पूर्ण हैं और कपड़ा आयुक्त के कार्यालय में लंबित है उन्हें मौजूदा योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और नई योजनाओं को भविष्य में प्राप्य प्रभाव से सहायता प्रदान की जाएगी.
- कपड़ा आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन किया जा रहा है. इसके कार्यालय प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाएंगे.
- नई योजना के तहत प्रस्तावों की जांच, बैंकरों के साथ संयुक्त रूप से सृजित परिसंपत्तियों के सत्यापन और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ तालमेल रखने सहित उद्योग की स्थापना के लिए कपड़ा आयुक्त कार्यालय के सभी अधिकारी उद्यमियों के साथ नजदीकी संबंध स्थापित करेंगे.
- इस योजना के कार्यान्वयन का 01 अप्रैल, 2015 में शुरू की गई आईटीयूएफएस के अधीन ऑनलाइन निष्पादन और निगरानी की जाएगी.

जलवायु परिवर्तन से संबंधित चार परियोजनाओं को मंजूरी

केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित चार परियोजनाओं को 28 दिसंबर 2015 को अपनी मंजूरी दी. इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर आठवीं राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससीसी) ने तमिलनाडु, केरल और पंजाब से संबंधित चार परियोजनाओं को मंजूरी दी.

उपरोक्त एनएससीसी के बैठक के एजेंडे में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) द्वारा वित्त पोषण के लिए तमिलनाडु और केरल सरकार द्वारा सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर विचार करना शामिल था. इसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन एक्शन प्रोग्राम (सीसीएपी) के तहत सौंपी गई परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण भी शामिल था.

तमिननाडु सरकार द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट का शीर्षक 'तटीय निवासियों का पुनर्वास एवं प्रबंधन और तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तथा सतत आजीविका के लिए जैव विविधता'था. इस परियोजना की कुल लागत 24.74 करोड़ रुपये होगी और इसके तहत तूतीकोरिन जिले के 23 तटीय गांवों को कवर किया जाएगा. चार साल की इस परियोजना के चार बड़े उद्देश्य हैं - आधारभूत भेद्यता अध्ययन, मूंगा पुनर्वास, समुद्री घास पुनर्वास, 6000 कृत्रिम चट्टान (एआर) मॉड्यूल की तैनाती और परियोजना के तहत आने वाले गांवों में आर्थिक विकास की गतिविधियां. इस परियोजना से बहुप्रतीक्षित 'मूंगा एवं समुद्री घास को फिर से लगाने की योजना अथवा व्यापक रणनीति' को तैयार करने में मदद मिलेगी. यह कोरल पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजाति विविधता, मछली पकड़ने/प्रयास, मानवीय दबाव और प्रवास एवं जीवित रहने की दर पर आधारित डेटाबेस को बढाने में मददगार होगी. परियोजना की गतिविधियों से प्रत्येक गांव में 15 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता खुलेगा और 6,900 महिलाओं को फायदा होगा. यह परियोजना मत्स्य पालन विभाग, वन विभाग, टीएनएससीसी, जीओएमबीआरटी, आईआईटी चेन्नई, अन्ना विश्वविद्यालय जैसे विभागों की नियमित बैठक के जरिये ज्ञानवर्धन के लिए एक मंच तैयार करेगी और भविष्य के संरक्षण के प्रयासों के रोडमैप के लिए योजना बनाएगी. अनुमान है कि इस परियोजना के जरिए मछुआरा समुदाय के लिए प्रतिवर्ष 1.84 करोड़ रुपये और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 1.03 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की क्षमता है. पर्यावरण विभाग एवं तमिलनाडु की राज्य संचालन समिति परियोजना के समूचे कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे.

एक अन्य परियोजना केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई. इसका शीर्षक 'केरल की तटीय झीलों में कईपड और पोक्कली की समन्वित कृषि प्रणाली को बढ़ावा' था. एकीकृत कृषि पद्धति की कल्पना वाली इस परियोजना की कुल लागत 33.73 करोड़ रुपये है. चार साल की परियोजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र 600 हेक्टेयर (कन्नूर जिले में 300 हेक्टेयर और एर्नाकुलम, त्रिशूर और अलाप्पुझा जिलों में 300 हेक्टेयर) है. इसके व्यापक उद्देश्यों में - पर्याप्त ऊंचाई के साथ मजबूत बाहरी 'बांध' के लिए मुख्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना; नमकीन

पानी में भी होने वाले लंबी किस्म के धान का उपयोग, धान की खेती को बढ़ाने के लिए एकीकृत मत्स्य पालन और स्थायी जल कृषि के माध्यम से अंतर्देशीय मछली का उत्पादन बढ़ाना शामिल है. इस परियोजना के लिए एक्वाकल्चर विकास एजेंसी (अदक), मत्स्य विभाग और केरल सरकार निष्पादित इकाई होगी. यह परियोजना ऐसी निचली झीलों में चावल की खेती और झींगा/मछली पालन में मददगार होगी, जहां पहले यह नहीं किया गया है। इससे होने वाली उच्चतम सुलभ आय के जरिए स्थानीय किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा. यह ताजे पानी की उपलब्धता में सुधार करेगा, क्योंकि परिधीय 'बांध' ताजा पानी के स्रोतों में समुद्र के पानी के रिसाव को रोक देंगे. इससे किसानों की क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी, महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा और आस-पास के क्षेत्रों से मजदूरों के विस्थापन को कम किया जा सकेगा. इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि झीलों में कार्बन सिंक के रूप में काम करने की अच्छी क्षमता होती है. ऐसा अनुमान है कि इस परियोजना के तहत 23.25 करोड़ रुपये वार्षिक का संभावित राजस्व जुटाया जा सकता है.

विदित हो कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्रोग्राम के तहत, समिति ने तीन परियोजनाओं पर विचार किया. इनमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत 'आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए समन्वित खेती प्रणाली के माध्यम से लचीलापन' परियोजना, पंजाब सरकार द्वारा पेश 'धान के भूसे के लाभकारी उपयोग के लिए तकनीकी संयोजन (वर्तमान में खेत पर ही जला दिया जाता है), इसमें जीवाश्म ईंधन के बदले ईंधन का उपयोग होगा' और तमिलनाडु सरकार द्वारा पेश 'मन्नार की खाड़ी में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तटीय निवासियों का पुनर्वास, दक्षिण पूर्व भारतः पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और मछुआरों की आजीविका में सुधार' परियोजना शामिल थीं. समिति ने पंजाब और तमिलनाडु सरकार की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. इन पर क्रमशः 3.54 करोड़ और 67 लाख की अनुमानित लागत आएगी.

वस्त्र मंत्रालय ने एनएचडीसी की ईआरपी प्रणाली की शुरुआत की

वस्त्र मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) की उद्यमी संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणाली की शुरुआत की. इसके तहत केन्द्रीय वस्त्र मंत्री संतोष गंगवार ने वाराणसी में ईआरपी प्रणाली की शुरुआत की.

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल के साथ बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए इस प्रणाली को क्रियान्वित करने का फैसला किया. इस तरह एनएचडीसी वस्त्र मंत्रालय के अधीन ईआरपी प्रणाली प्रारंभ करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया.

विदित हो कि ईआरपी उन बुनकरों के लिए महत्वापूर्ण फायदे की प्रणाली सिद्ध होगी जो भारत सरकार की सप्लाई स्कीम के लाभपात्र हैं. इससे बुनकरों को एनएचडीसी सामग्री जल्दी मिलेगी. इसके साथ ही इससे निगम की गतिविधियों में सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी.

एनएचडीसी की ईआरपी प्रणाली का मुख्य लाभ:

- इससे वाणिज्यिक गतिविधियां पारदर्शी होगी.
- किसी भी प्रकार के विलंब की पहचान बुनकर और अन्य हितधारक आसानी से कर सकेंगे.
- कागजी कार्यों से छुट्टी मिल जाने और पारदर्शिता आने से काम को सरल होने से आपूर्ति श्रृखंला का प्रभावी और जवाबदेह बनाने में सुधार होगा.
- इससे खरीद, वस्तु सूची प्रबंधन और मांग की भविष्यवाणी में सुधार के कारण ग्राहकों की सेवा में गुणात्मक परिणाम मिलेगा.
- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता से देश भर के बुनकरों को सबसे अधिक प्रतियोगी कीमतों पर धागा उपलब्ध होगा.
- बुनकर मोबाइल एप्प पर किसी भी समय सूचना प्राप्त कर सकेंगे.
- वे अपनी मांग सूची दे सकते हैं. वे अपनी मांग सूची की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
- वे भेजी गई सामग्री का विवरण भी एसएमएस के जरिये ले सकते हैं.
- बुनकरों को अब एनएचडीसी में जाने या डाक से पत्र व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे उनका समय और धन बचेगा.
- 10 प्रतिशत स्कीम के मामले में बुनकर अपने बचे कोटे के बारे में किसी भी समय जानकारी ले सकते हैं.
- आदेश की सुनिश्चितता और पहचान के लिए मिलों को भी एकीकृत किया जाएगा जाकि ये ऑनलाइन ईआपी का हिस्सा बने.

देश के विश्वविद्यालयों में पटाखों से प्रदूषण पर होगी पढ़ाई

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब छात्रों को पटाखों के दुष्प्रभाव, इनका पर्यावरण पर प्रभाव, और प्रभावित वातावरण के बार में अध्ययन कराया जाएगा. यूजीसी के निर्देश पर स्नातक स्तर पर चलने वाले पर्यावरण

अध्ययन के कोर्स में पटाखों के दुष्प्रभाव सम्बन्धी मॉड्यूल को भी शामिल किया जाएगा.

- यूजीसी ने यह निर्देश 16 दिसम्बर 2015 को सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है.
- छात्रों को पटाखों से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए और भी अन्य कदम उठाने की सलाह दी गई है.
- जिसमें विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इस मुद्दे पर चर्चा करना, संगोष्ठी और कार्यशाला आयोजित करना आदि शामिल है.
- इसके हानिकारक प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है? इस पर सुझाव व समाधान भी दिए जा सकते हैं.
- आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों और छात्रों का एक समूह बनाया जाएगा जो इस मुद्दे पर प्रेजेंटेशन तैयार करेगा.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- यूजीसी ने यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के 16 अक्तूबर के निर्देशों के बाद लिया.
- सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्तूबर को पटाखों से होने वाले नुकसान पर चिंता जताई थी.
- पटाखों से निकलने वाले रसायन कई तरह से मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं.
- अस्थमा के मरीजों को लिए यह काफी नुकसान दायक होता है. हार्मोन में असंतुलन पैदा करता है.
- पटाखों से निकलने वाले रसायन मृदा और पानी को भी नुकसान पहुंचाते है.
- पेरिस में पर्यावरण के मुद्दे आयोजित सम्मेलन में पृथ्वी के संरक्षण के मुद्दे पर हुई चर्चा का जिक्र किया गया है.

कॉयर उद्यमी योजना: सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय की एक पहल

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय अपने एक सार्थक सहायता पहल के रूप में कॉयर उद्यमी योजना (नारियल जटा उद्यमी योजना) का संचालन कर रहा है. मुख्य रूप से कॉयर उद्यमी योजना, नारियल जटा क्षेत्र की एक क्रेडिट लिंक अनुदान योजना है.

कॉयर उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की 40 प्रतिशत लागत भारत सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दी जाती है, शेष 60 प्रतिशत राशि में से 5 प्रतिशत राशि हितग्राही को अंशदान के रूप में देनी होती है, बकाया 55 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की लागत और इस लागत की 25 प्रतिशत राशि वर्किंग कैपिटल वाली किसी भी प्रकार की कॉयर आधारित परियोजना को लिया जा सकता है.

इस योजना के लिए सहायक या तृतीय पक्ष की गारंटी के बगैर ऋण दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ व्यक्ति, कंपनी, स्व सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं, उत्पादक सहकारी संस्थाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप ले सकते हैं. बाजार में भागीदारी के लिए इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना के माध्यम से मंडल इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण और सेमिनार आदि का आयोजन करता है.

केंद्र सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की

केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2015 को नि:शक्त जनों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की. नि:शक्त जनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता लक्ष्य हासिल करने के लिए सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया गया.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ सुगम्य भारत अभियान लांच किया. राष्ट्रव्यापी यह अभियान नि:शक्तजनों को सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने, विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने, स्वतंत्र जीविका तथा समावेशी समाज के सभी पक्षों में उनकी भागीदारी में सहायक होगा. इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्यों के राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के पचास प्रतिशत को जुलाई 2018 तक नि:शक्तजनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा.

सुगम्या भारत अभियान के तहत देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा ए1,ए तथा बी श्रेणी के स्टेशनों को जुलाई 2016 तक नि:शक्त्जनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा. मार्च 2018 तक देश में सरकारी क्षेत्र के परिवहन वाहनों को नि:शक्तजनों के लिए सुगम बना दिया जाएगा. इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेजों का कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा नि:शक्तजनों के लिए पहुंच मानकों को पूरा करेंगे.

दिवस | वर्ष | सप्ताह

भारतीय सेना ने 28 दिसंबर 2015 को 44वां नागी दिवस मनाया

भारतीय सेना (थल सेना) ने 28 दिसंबर 2015 को नागी दिवस मनाया. 44वां नागी दिवस श्रीगंगानगर सेना स्टेशन और नागी (पाकिस्तान से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब श्री करनपुर में स्थित एक छोटा सा गांव) में मनाया गया. इसे 27-28 दिसम्बर 1971 को नागी की प्रसिद्ध लड़ाई के दौरान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सेना के वीर सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है.

विदित हो कि नागी-युद्ध भारत-पाक युद्ध के संघर्ष विराम की घोषणा के 10 दिनों बाद लड़ा गया था, जिसमें भारतीय सैनिकों द्वारा की गयी बहादुर कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया था. युद्ध के दौरान तीन अधिकारियों सहित 21 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था.

सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को संपूर्ण भारत में मनाया गया

25 दिसम्बर: सुशासन दिवस

सुशासन दिवस 25 दिसम्बर 2015 को संपूर्ण भारत में मनाया गया. यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है.

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्री जेपी नड्डा ने नागरिक केन्द्रित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चार नए आईटी आधारित पहलों की घोषणा की.

इन पहलों में किलकारी, मोबाइल एकेडमी और एम सेशेसन तीन एप्लिकेशन शामिल हैं. इसेक अलावा टीबी रोगियों को परामर्श और उपचार सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 शुरु किया.

सुशासन दिवस के उद्देश्य

- सरकारी प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाकर देश में एक "खुला और जवाबदेह प्रशासन" प्रदान करना
- सुशासन दिवस देश में एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मुहैया कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है.
- यह भारत में आम नागरिकों के कल्याण और भलाई को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है.
- सरकार के कामकाज के मानकीकरण के साथ-साथ यह भारतीय लोगों के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और जवाबदेह शासन के लिए मनाया जाता है.
- यह भारत में सुशासन के एक मिशन को पूरा करने के लिए अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए मनाया जाता है.
- यह सरकारी अधिकारियों को आंतरिक प्रक्रियाओं और उनके काम के लिये प्रतिबद्ध करने के लिये मनाया जाता है.
- सुशासन के माध्यम से देश में वृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए.
- नागरिकों को सरकार के करीब लाकर सुशासन की प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय भागीदार बनाने के लिए.

इसके साथ ही 'सुशासन दिवस' के मौके पर आयोजित एक समारोह में ईपीएफओ के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट का उद्घाटन किया गया.

सुशासन दिवस के बारे में

भारत सरकार ने वर्ष 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90वें जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी. विदित हो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्यप्रदेश में हुआ था.

24 दिसंबर : राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस

30वां राष्ट्रीय उपभोक्ताओं अधिकार दिवस भारत में 24 दिसंबर 2015 को मनाया गया.

यह दिवस उपभोक्ता आंदोलन को अवसर प्रदान करता है और उसके महत्व को उजागर करता है और इसके साथ ही हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरुक करने की प्रेरणा देता है.

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में

भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्रीके य उपभोक्ताव दिवस घोषित किया, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ऐतिहासिक उपभोक्तो संरक्षण अधिनियम, 1986 विधेयक पारित किय गया था.

इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किये गए. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया. परिणामस्वारूप उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

- यह अधिनियम उन सभी उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित करता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया. इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित किए गए है.
- सुरक्षा का अधिकार: जीवन के लिए नुकसानदेह/हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ संरक्षण प्रदान करना
- सूचना का अधिकार: उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमतों /सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, वजन और कीमतों की जानकारी ताकि गलत व्यापारिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी उपभोक्ता को ठगा नहीं जा सके.
- चुनने का अधिकार: प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के अनेक प्रकारों तक यथासंभव पहुंच को निश्चित करना.
- सुने जाने का अधिकार: उपयुक्त फोरम पर सुने जाने का अधिकार और यह आश्वासन कि विषय पर उचित ध्यान दिया जाएगा.
- उपचार का अधिकार: गलत या प्रतिबंधित कारोबारी गतिविधियों/शोषण के खिलाफ कानूनी उपचार की मांग करना.
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: उपभोक्ता शिक्षा तक पहुंच

22 दिसंबर को 'राष्ट्रीय गणित दिवस' के रूप में मनाया गया

22 दिसंबर: राष्ट्रीय गणित दिवस

22 दिसंबर 2015 को 'राष्ट्रीय गणित दिवस' (National Mathematics Day) के रूप में मनाया गया. भारत

में प्रत्येक वर्ष 22 दिसम्बर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की स्मृति में 'राष्ट्रीय गणित दिवस' मनाया जाता है.

विदित हो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर 2012 को चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीनिवास रामानुजम को श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष एवं रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था.

श्रीनिवास रामानुजन से संबंधित मुख्य तथ्य:

श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसम्बर 1887 को मद्रास से 400 किलोमीटर दूर ईरोड नगर में हुआ था. इनकी गणना आधुनिक भारत के उन व्यक्तितत्वों में की जाती है, जिन्होंने विश्व में नए ज्ञान को पाने और खोज़ने की पहल की. रामानुजन की आरम्मभिक शिक्षा कुम्भकोणम के प्राइमरी स्कूल में हुई. तदोपरांत वर्ष 1898 में उन्होंने टाउन हाई स्कूल में प्रवेश लिया और सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए. यहीं पर रामानुजन को जी. एस. कार की गणित पर लिखी पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला. इसी पुस्तक से प्रभावित हो उनकी रूचि गणित में बढ़ने लगी और उन्होंने गणित पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया. युवा होने पर घर की आर्थिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु रामानुजन ने क्लर्क की नौकरी कर ली, जहां वह अक्सर खाली पन्नों पर गणित के प्रश्न हल किया करते थे. एक दिन एक अँग्रेज़ की नजर इन पन्नों पर पड़ गई जिसने निजी रूचि लेकर उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रो. हार्डी के पास भेजने का प्रबंध कर दिया. प्रो. हार्डी ने उनमें छिपी प्रतिभा को पहचाना जिसके बाद उनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई.

श्रीनिवास रामानुजन के गणित पर लिखे लेख तत्कालीन समय की सर्वोत्तम विज्ञान पत्रिका मं प्रकाशित होते थे. अथक परिश्रम के कारण रामानुजन अस्वास्थ्य रहने लगे और मात्र 32 वर्ष की आयु में ही उनका भारत में निधन हो गया. उनके निधन के पश्चात् उनकी 5000 से अधिक प्रमेयों (थ्योरम्स) को छपवाया गया और उनमें से अधिकतर को कई दशक बाद तक सुलझाया नहीं जा सका. रामानुजन की गणित में की गई अदभुत खोजें आज के आधुनिक गणित और विज्ञान की आधारशीला बनी. संख्या-सिद्धान्त पर रामानुजन अद्भुत कार्य के लिए उन्हें 'संख्याओं का जादूगर' माना जाता है. अपने महान गणितीय अवदान के लिए रामानुजन को "गणितज्ञों का गणितज्ञ" भी कहा जाता है.

विश्वस्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया

18 दिसम्बर : अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस

विश्वस्तर पर 18 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया.

वर्ष 2014 से अब तक 5000 से ज्यादा लोग बेहतर जीवन और संरक्षण के लिए जीवन क्षति का सामना कर चुके हैं.

वर्ष 2015, मानवीय पीड़ा और प्रवासी त्रासदियों के रूप में याद किया जाएगा.

प्रत्येक हजार लोगों में दस मानव तस्करों के दुर्व्यवहार और शोषण का सामना कर रहे हैं.

परन्तु वर्ष 2015 में सम्पूर्ण विश्व ने सतत विकास के लिए प्रवासियों के महत्व को समझा है. सतत विकास के लिए 2030 एजेंडें को आपने के बाद समस्त विश्व के नेताओं ने प्रवासियों के अधिकारों के संरक्षण और मनाव तस्करी को समाप्त करने की बात कही है.

अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसम्बर 2000 को सम्पूर्ण विश्व में बढ़ते प्रवासियों की संख्या को देखते हुए को 18 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की.
- महासभा द्वारा 18 दिसंबर 1990 को सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपनाया गया.
- वर्ष 2013 के अक्टूबर माह में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और विकास पर उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान विकास के लिए प्रवास के योगदान को पहचानने पर एक घोषणा को अपनाया.

देश भर में व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया

ऊर्जा की बचत का महत्व रेखांकित करने के उद्देश्य से 14 दिसंबर 2015 को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस दिवस पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए. विभिन्न उद्योग समूह की कंपनियों को ऊर्जा संरक्षण में मूल्यवान योगदान देने हेतु राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए.

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल एक विशेष विषय के साथ कुछ लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लोगों के बीच अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये मनाया जाता है.

- यह लोगों के बीच जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के महत्व का संदेश भेजने के लिए मनाया जाता है
- ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को बढावा देने के लिये पूरे देश में बहुत से कार्यक्रमों जैसे: विचार विमर्श,
- सम्मेलनों, वाद-विवाद, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना
- अत्यधिक और फालतू ऊर्जा के उपयोग के स्थान पर कम ऊर्जा के प्रयोग के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना
- ऊर्जा की खपत में कमी और कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना

भारतीय संसद ने देश के ऊर्जा स्रोतों को संरक्षण देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पारित किया. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है. यह अधिनियम ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिसिएंशी (बीईई) द्वारा लागू किया गया है, जो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है. अधिनियम पेशेवर, योग्य ऊर्जा लेखापरीक्षकों तथा ऊर्जा प्रबंधन, वित्त-व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में कुशल प्रबंधकों का एक कैडर बनाने का निर्देश देता है.

16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया गया

16 दिसंबर: विजय दिवस

पूरे देश में 16 दिसंबर 2015 को विजय दिवस के रूप में मनाया गया. भारतीय सेना द्वारा वर्ष 1971 में पाकिस्तान सेना पर जीत (16 दिसंबर 1971) के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाया जाता है.

विदित हो कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) में पाकिस्तानी सेना को पराजित किया एवं पाकिस्तानी सेना के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 96,000 सैनिकों के साथ बिना शर्त आत्म समर्पण कर दिया. जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ.

1971 युद्ध से संबंधित संछिप्त जानकारी:

वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी फौजी तानाशाह याहिया खान के उस आदेश के बाद हुई थी, जिसमें उन्होंने 25 मार्च 1971 को पूर्वी बांग्लादेश के जन विद्रोह को दबाने की कमान पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना को दे दी और इसका निर्णायक मोड पाकिस्तान की ही गलती से आया, जब पाकिस्तान ने शाम ढलते ही 3 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसैनिक अड्डों पर हमला किया.

भारतीय सेना ने हमले के आदेश के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानि आज के बांग्लादेश को पूरब की तरफ से घेरना

शुरू किया, साथ ही उत्तर की ओर से भी हमला शुरू हुआ. ये वो लड़ाई थी, जिसमें भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तानी नौसेना को मात दी, भारतीय सेना ने कराची में धुएं का बादल बना दिया. तेल डिपो को आग में झोंक दिया. उसकी पनडुब्बी को मार गिराया. पश्चिमी मोर्चे पर भारत ने दबाव बनाया, तो पूरब में पाकिस्तान तिलमिलाने लगा. यूं तो लड़ाई 3 दिसंबर की जगह 23 नवंबर से ही शुरू हो चुकी थी, पर आधिकारिक ऐलान तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 3 दिसंबर 1971 को किया. इस दौरान हिली की लड़ाई सबसे खौफनाक रही, जिसपर फतह हासिल कर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया, और 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे ढाका में प्रवेश किया. जहां दोपहर के समय जनरल नियाजी ने पिस्तौल समर्पित कर पाकिस्तानी सेना के समर्पण को स्वीकार किया.

उस समय भारतीय सेना की पूर्वी कमान के स्टाफ़ ऑफ़िसर लेफ़्टिनेंट जनरल जेएफ़आर जैकब सबसे पहले ढाका पहुंचने वाले अधिकारी थे. जिन्हें बांग्ला मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी समझकर घेर लिया. उन्होंने अपने बारे में बताया, तब उन्हें रास्ता दिया गया. उन्होंने ही नियाजी को आत्मसमर्पण की शर्तें सुनाई.

विश्वभर में मानवाधिकार दिवस मनाया गया

10 दिसम्बर : मानवाधिकार दिवस

10 दिसंबर 2015 को विश्वभर में मानवाधिकार दिवस मनाया गया. इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के दो पहलुओं का प्रसार करना था इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी (आईसीईएससीआर) एवं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी (आईसीसीपीआर) शामिल हैं.

इस दिवस के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता नामक अभियान आरंभ किया जिसका उद्देश्य विश्व भर में नागरिकों के अधिकारों के लिए उन्हें जाग्रत करना है.

इसके द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का विधेयक शामिल है जिसमें स्वतंत्रता से संबंधित विशेष पहलू जोड़े गये हैं जैसे - भय से स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता.

पृष्ठभूमि

- इसका आरंभ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के उपरांत से हुआ.
- वर्ष 1950 में महासभा ने विधेयक 423 (V) पारित किया जिसमें सभी देशों एवं संगठनों से इसे अपनाने

के लिए कहा गया.

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 में सभी मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उच्चायुक्त का जनादेश जारी किया.
- पहला मानवाधिकार दिवस वर्ष 1950 में मनाया गया.

नरसंहार पीड़ितों की गरिमा हेतु अन्तरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया

9 दिसंबर : नरसंहार पीड़ितों की गरिमा बनाये रखने हेतु अन्तरराष्ट्रीय स्मरणोत्सव एवं अपराध की रोकथाम दिवस

9 दिसम्बर 2015 को नरसंहार पीड़ितों की गरिमा बनाये रखने हेतु अन्तरराष्ट्रीय स्मरणोत्सव एवं अपराध की रोकथाम दिवस मनाया गया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 11 सितंबर 2015 को यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 9 दिसम्बर को नरसंहार पीड़ितों की गरिमा बनाये रखने हेतु अन्तरराष्ट्रीय स्मरणोत्सव एवं अपराध की रोकथाम दिवस मनाया जायेगा.

इस सन्दर्भ में अर्मेनिया द्वारा महासभा में प्रस्ताव लाया गया तथा विश्व भर में नरसंहार द्वारा मारे गये लोगों के सम्मान में जागरुकता फ़ैलाने का निर्णय लिया एवं भविष्य में इस प्रकार के अपराध पर रोकथाम हेतु उचित कदम उठाने के लिए हर संभव कदम उठाने का भी निर्णय लिया.

इस प्रस्ताव को 193 सदस्यों वाली सभा में बिना मतदान के पारित कर दिया गया. साथ ही यह भी कहा गया कि प्रत्येक देश का उत्तरदायित्व है कि वह लोगों को नरसंहार से बचाने हेतु उचित कदम उठाये.

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसम्बर को यह दिवस मनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वर्ष 1948 में पहली बार इसी दिन नरसंहार सम्मेलन आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों के लिए आयोजित पहला सम्मेलन था.

इसके उपरांत इस सम्मेलन को विश्व भर में सराहा गया तथा अन्य देशों द्वारा प्रोत्साहन भी दिया गया.

नरसंहार

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नरसंहार किसी विशेष राष्ट्रीय, जातीय या धार्मिक समूह के खिलाफ किया जाने वाला अपराध है. इसके अतिरिक्त उस विशेष समूह का विनाश करना भी नरसंहार का उद्देश्य हो सकता है.

भारत में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया गया

7 दिसम्बर : सशस्त्र सेना ध्वज दिवस

भारत भर में 7 दिसंबर 2015 को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया गया. इसका आयोजन भारत में नागरिकों द्वारा सेना के समाज कल्याण हेतु धनराशि जमा करने के लिए किया जाता है.

ध्वज दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय थल सेना, वायु सेना एवं नेवी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराये गये जिसमें सेना द्वारा देश की सुरक्षा हेतु किये गये प्रयासों को दर्शाया गया.

सशस्त्र सेना ध्वज दिवस

- रक्षा मंत्री समिति ने वर्ष 1949 को प्रत्येक वर्ष 7 दिसम्बर को ध्वज दिवस मनाने का निर्णय लिया.
- इस दिन टोकन अथवा कारों पर झंडे लगाकर सेना के लिए चंदा इकठ्ठा किया जाता है जिसमें भूतपूर्व सैनिक, सैनिकों की विधवा पत्नियां एवं विकलांग सैनिक शामिल हैं.
- टोकन फ्लैग और कार फ्लैग गहरे नीले, हल्के नीले एवं लाल रंग के होते हैं जो जिला सैनिक, केंद्रीय सैनिक बोर्ड एवं राज्य सैनिक बोर्ड को दर्शाते हैं.

विश्व स्तर पर मनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस (आईवीडी) 5 दिसम्बर 2015 को "दुनिया बदल रही है" द वर्ल्ड इज चेंजिंग क्या आप? इसके सह भागी हैं! विषय के साथ दुनिया भर में मनाया गया.

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस का इस वर्ष का विषय हाल में शुरू किए गए वैश्विक लक्ष्यों, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करने और उसका हिस्सा बनने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए एक चुनौती है. व्यक्ति स्वयंसेवा के माध्यम से, समुदायों और सरकारों को गतिशील और व्यस्त करके, सतत विकास के एजेंडे को प्रभावित कर सकते हैं.

यह दिन नए वैश्विक लक्ष्यों को लागू करने के लिए काम कर रहे स्वयंसेवकों व संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों को अपने ही समुदायों, सामूहिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के बीच उनके काम को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों का जश्न मनाने और प्रोत्साहित करने हेतु स्वयंसेवकों और संगठनों के लिए एक अनूठा अवसर के रूप में देखा जाता है.

यह दिन नई वैश्विक लक्ष्यों को लागू करने के लिए काम कर रहे स्वयंसेवकों को विशेष श्रद्धांजलि देने का भी दिन है.

पृष्ठभूमि

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस (आईवीडी) 17 दिसम्बर 1985 को संकल्प 40/212 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासभा द्वारा स्थापित किया गया था.

तभी से सभी सरकारें, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और नागरिक सामाजिक संगठन सफलतापूर्वक 5 दिसंबर को दुनिया भर में स्वयंसेवकों दिवस मनाने के लिए शामिल एकत्रित होते हैं.

4 दिसंबर को मनाया गया 44 वां नौसेना दिवस

4 दिसंबर: नौसेना दिवस

44 वां नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2015 को मनाया गया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना कर्मियों को बधाई दी और राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए उनके समर्पण की सराहना की.

इस अवसर डीडी नेशनल पर "एम्पोवेरिंग इण्डिया थ्रू मेरीटाइम सिक्यूरिटी एंड इन्डिजिनिसेशन" समुद्री सुरक्षा और स्वदेशीकरण के माध्यम से भारत सशक्तीकरण शीर्षक से नौसेना की गतिविधियों पर टेलीफिल्म्स 2015 दिखाई गयी.

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान कराची हार्बर पर भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के उपलक्ष्य में हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है.

भारतीय नौसेना के एक रात के हमले में पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची बंदरगाह पर तीन जहाज डूब गए. ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का प्रयोग किया गया.

विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया

2 दिसंबर:अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस

गुलामी उन्मूलन के लिए 2 दिसंबर 2015 को वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी, बाल श्रम और आधुनिक गुलामी को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार प्रत्येक वर्ष निजी अर्थव्यवस्था में लगभग 21 मिलियन बेगार पीड़ितों की वजह से 150 बिलियन अवैध मुनाफा होता है.

इस समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने और 2016 तक इसे समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल को अपनाने का प्रयास किया है.

अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के बारे में

अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के शोषण विषय पर हुए सम्मेलन में 2 दिसंबर 1929 को प्रथम बार मनाया गया था.

इन दिन गुलामी के परंपरागत रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरदस्ती शादी और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती से सम्बंधित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के साथ सफल परिणाम प्राप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया जाता है.

विश्वस्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया

3 दिसम्बर - अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस

विश्वस्तर पर 3 दिसम्बर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया. यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है. वर्ष 2015 हेतु अन्तरराष्ट्रीय विकलांग दिवस का विषय - "समावेशन :सभी क्षमताओं के लोगों के लिए उपयोग और सशक्तिकरण".

उद्देश्य

अन्तरराष्ट्रीय विकलांग दिवस का उद्देश्य आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के साथ हो रहे भेद-भाव को समाप्त किया जाना है. इस भेद-भाव में समाज और व्यक्ति दोनों की भूमिका रेखांकित होती रही है. भारत सरकार द्वारा किये गए प्रयास में, सरकारी सेवा में आरक्षण देना, योजनाओं में विकलांगो की भागीदारी को प्रमुखता देना, आदि को शामिल किया जाता रहा है.

वर्ष 2015 के लिए इस दिवस का उपविषय निम्न है -

- शहरों को सभी के लिए सुलभ और समावेशी बनाना
- विकलांगता डेटा और आँकड़े में सुधार
- अदृश्य विकलांगता युक्त व्यक्तियों की समाज और विकास में भागीदारी

मुख्य बिंदु

- सयुंक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अन्तरराष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी.
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अन्तरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था.
- सयुंक्त राष्ट्र महासभा ने सयुंक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर वर्ष 1983-92 को अन्तरराष्ट्रीय विकलांग दिवस दशक घोषित किया था.
- भारत में विकलांगों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आधीन होता है.
- विदित हो संगम योजना का संबंध भारत में विकलांगों से संबंधित है.

भारत में विकलांगता से सम्बंधित निम्न अधिनियम, नीति, और कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं-

- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
- भारत पुनर्वास परिषद अधिनियम,1992
- एडीआईपी योजना
- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

प्रदर्शनी | मेला

भारतीय हथकरघा प्रदर्शनी का नई दिल्ली में शुभारंभ

केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में 22 दिसंबर 2015 को भारतीय हथकरघा प्रदर्शनी का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ. इस प्रदर्शनी का थीम 'भारतीय हथकरघा: परंपरा और रुझान' है. केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में भारतीय हथकरघा उत्पादों के उत्कृष्ट संग्रह की इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया.

इस प्रदर्शनी में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन उत्पादों के प्रोत्साहन की गतिविधियों के माध्यम से हथकरघा उत्पादों की नवीनतम श्रृंखला को प्रदर्शित किया गया. भारतीय हथकरघा: परंपरा और रुझान नामक यह श्रृंखला न सिर्फ भारत के हथकरघा बुनकरों की समृद्ध परंपरा और उच्च कौशल को प्रतिबिंबित करती है बल्कि हथकरघा कपड़ों के घर में बने स्टॉल, शॉल के साथ-साथ वस्त्रों के एक शानदार संग्रह को प्रस्तुत करती है.

इस प्रदर्शनी में 160 विभिन्न हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें देश में बनने वाले सभी प्रमुख ब्रांड शामिल हैं. इन उत्पादों को बनाते समय घरेलू और निर्यात बाजारों की मांग को ध्यान में रखा गया.

विदित हो कि भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय देश के हथकरघा बुनकरों के लिए विभिन्न विकासात्मक और कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास को प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की घोषणा की थी. भारतीय हथकरघा ब्रांड योजना का भी उनके द्वारा इसी वर्ष चेन्नई में शुभारंभ किया गया.

राष्ट्रीय संग्रहालय की आर्ट गैलरी का शुभारंभ

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महेश शर्मा ने 9 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय संग्रहालय की आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया. इस आर्ट गैलरी का शुभारंभ दिल्ली स्थित उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर

किया गया.

उपरोक्त आर्ट गैलरी हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय ने उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन को भारतीय कला द्वार के रूप में विकसित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ समझौता किया है. इस प्रयास से मेट्रो का उपयोग करने वालों को राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रहण को देखने का मौका मिलेगा ताकि लोग समृद्ध भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत को अधिक से अधिक जान सकें.

विदित हो कि उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन को भारतीय कला द्वार बनाने के उद्देश्य से 17 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय संग्रहालय और दिल्ली मेट्रो रेल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. संस्कृति मंत्रालय के स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय संग्रहालय अपुने पहुंच कार्यक्रम के तहत मेट्रो उपयोग करने वाले लगों को आकर्षित करना चाहता है ताकि अधिक संख्या में लोग संग्रहालय देखने जा सकें.

प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईटी-दिल्ली में प्रारंभ

प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईटी-दिल्ली में 4 दिसंबर 2015 को प्रारंभ हुआ. यह विज्ञान महोत्सव 4 से 8 दिसंबर 2015 तक चलेगा. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा और लगभग 400 शोध पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे. इस महोत्सव का उद्देश्य सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'स्मार्ट विलेजेज एंड 'स्मार्ट सिटीज' जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है.

उपरोक्त के साथ ही इस महोत्सव का एक अन्य मुख्य उद्देश्य आम जनता के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को उजागर करना, लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए रणनीति तैयार करना एवं वर्षों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान को दर्शाने के अलावा ज्ञान और विचारों का आदान- प्रदान करने के लिए युवा वैज्ञानिकों के लिए मंच उपलब्ध कराना है. इसके साथ ही आईआईएसएफ 2015 का उद्देष्य विचारों और ज्ञान को साझा करने के उद्देष्य से बातचीत करने के लिए वैज्ञानिकों के लिए एक मंच उपलब्द करना भी है.

इस महोत्सव में प्रतिनिधियों के रूप में देश के लगभग 3 हजार युवा वैज्ञानिकों के भाग लेने की उम्मीद है. जिनके लिए युवा वैज्ञानिकों का सम्मेलन, टेक्नो-इंडस्ट्रियल एक्सपो, विज्ञान फिल्म महोत्सव, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता, इंडस्ट्री-एकेडेमिया कॉन्क्लेव, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल साइंस लैब डेमो, इंटरैक्टिव कार्यशालाओं और जानकारीपूर्ण सत्रों का आयोजन होगा.

आयोग | समिति

दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में भ्रष्टाचार मामले की जांच हेतु एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया

दिल्ली सरकार ने राजधानी के क्रिकेट निकाय डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 21 दिसंबर 2015 को एक सदस्यीय जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी. जांच आयोग की अध्यक्षता पूर्व सॉलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम करेंगे.

यह निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किए गए.

विदित हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर 13 साल तक डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली सरकार ने आरोप लगायें हैं. वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया.

वन रैंक वन पेंशन के लिए न्यायिक समिति का गठन

केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) योजना के क्रियान्वयन पर गौर करने के लिए 14 दिसंबर 2015 को एक न्यायिक समिति गठित की. न्यायिक समिति की अध्यक्षता पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी करेंगे. यह समिति उन विसंगतियों या त्रुटियों को दूर करने के उन उपायों पर गौर करेगी, जो 7 सितंबर 2015 को सरकार की ओर से जारी वन रैंक वन पेंशन संबंधी अधिसूचना को लागू करने की राह में बाधा बन सकते हैं. इसके साथ ही समिति अपनी संस्तुतियों में इसकी सिफारिशों के आर्थिक प्रभाव पर विचार करेगी.

समिति के मुख्य कार्य:

- सरकार की ओर से 7 नवम्बर, 2015 को अधिनियमित वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लागू करने में आ

सकने वाली अड़चनों को दूर करने संबंधी कदम उठाना.

- 7 नवम्बर, 2015 को सरकार द्वारा अधिसूचित ओआरओपी आदेश के क्रियान्वयन के लिए सेनाओं के तीनों अंगों के समक्ष आने वाली संभावित विसंगतियों को दूर करने संबंधी कदम उठाना.
- सैन्य सेवाओं के मामलों में संबद्धता.
- केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी या संबंधित मामलों के लागू होने संबंधी तथ्यों की जाँच.

विदित हो कि न्यायिक समिति का अपना मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा रक्षा मंत्रालय के तहत सक्रिय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सहयोग समिति को मुहैया कराया जाएगा.

सुब्रमण्यन समिति ने रिपोर्ट में जीएसटी हेतु स्टैंडर्ड रेट लगाने की सिफारिश की

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में बनाई गयी समिति ने 4 दिसम्बर 2015 को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी.

सुब्रमण्यन समिति ने अपनी रिपोर्ट में 17 से 18 प्रतिशत का स्टैंडर्ड रेट लगाने की सिफारिश की. समिति ने जीएसटी विधेयक में प्रस्तावित एक प्रतिशत के अतिरिक्त टैक्स सहित इंटर स्टेट ट्रेड पर अन्य सभी टैक्सेज को समाप्त करने की भी सिफारिश की.

मुख्य सिफारिशें

- सीईए ने अपनी सिफारिश में जीएसटी का लो रेट 12 प्रतिशत जबकि हाई रेट 40 प्रतिशत तय करने की सिफारिश की.
- जीएसटी के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15 से 15.5 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया गया.
- समिति ने ऐल्कॉहॉल और पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की.
- समिति के अनुसार इससे राजस्व में कोई नुकसान नहीं होगा.

इसके अतिरिक्त समिति ने संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी दर डालने की बात नहीं की.

इसके लागू होने पर जीएसटी द्वारा भारत में कर भुगतान सिस्टम में सुधार होगा तथा भारत तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा.

विज्ञान | अंतरिक्ष

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सिंगापुर के छह उपग्रहों को प्रक्षेपित किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 16 दिसंबर 2015 को सिंगापुर के छह उपग्रहों को प्रक्षेपित किया. इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी- सी-29) द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के छह उपग्रहों को प्रक्षेपित किया.

इसरो की विश्वसनीय पीएसएलवी अपनी इस 32वीं उडान में छह उपग्रहों को भूमध्यरेखा की ओर 15 डिग्री के झुकाव पर स्थित 550 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगी. जिन छह उपग्रहों को स्थापित किया जाना है, उनमें से 400 किलोग्राम वजन वाला टीईएलईओएस-1 प्राथमिक उपग्रह है. अन्य पांच उपग्रहों में दो माइक्रो उपग्रह और तीन नैनो उपग्रह हैं. टीईएलईओएस-1 सिंगापुर का ऐसा पहला व्यवसायिक उपग्रह है, जो पृथ्वी पर्यवेक्षण के लिए समर्पित है. इसे 'रिमोट सेंसिंग' के अनुप्रयोगों के लिए निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा.

विदित हो कि इसरो की व्यवसायिक शाखा 'एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड' अबतक कुल 20 ग्राहक देशों के 51 उपग्रहों के लिए पीएसएलवी के जरिए प्रक्षेपण की सेवाएं उपलब्ध करवा चुकी है.

गेल ने पाइपलाइनों की निगरानी के लिए 'भूवन गेल पोर्टल' का शुभारम्भ किया

गेल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक इकाई नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के सहयोग से 4 दिसम्बर 2015 'भूवन गेल पोर्टल' नाम का एक पाइपलाइन निगरानी भू-पोर्टल लॉन्च किया.

इस पोर्टल का शुभारम्भ बी.सी. त्रिपाठी अध्यक्ष गेल (इंडिया) और वी.के. दध्वाल एनआरएससी, इसरो निदेशक

की उपस्थिति में किया गया.

गेल पाइपलाइन की निगरानी करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है.

विदित हो वर्तमान में गेल का यह पाइपलाइन नेटवर्क के 13000 किलोमीटर से अधिक का है. इसके अतिरिक्ति इन पाइपलाइनों की मासिक निगरानी हेलीकॉप्टर का माध्यम से की जाती है.

वर्ष 2016 के जनवरी माह तक गेल, पाइपलाइन की उपग्रह निगरानी शुरू कर देगा.

इसके अतिरिक्त गेल उन्नत मानवरहित यान (यूएवी) जैसे कुछ वैकल्पिक तरीकों को भी इस प्रणाली के साथ एकीकृत करने के प्रति प्रयासरत है.

भूवन-गेल पोर्टल के साथ एक रिपोर्ट प्रणाली को भी एकीकृत किया गया है जो एसएमएस के माध्यम से प्रासंगिक अधिकारियों को अलर्ट भेजने में सक्षम होगा.

घटना | दुर्घटना

बीएसएफ का एक चार्टेड विमान सुपरकिंग दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त

बीएसएफ का एक चार्टेड विमान सुपरकिंग दिल्ली के द्वारका सेक्टर-8 के शाहाबाद गांव में 22 दिसंबर 2015 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया,जिसमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई.

विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट से रांची जाने के लिए उड़ान भरी थी. यह दुर्घटना सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर उस समय हुई जब विमान किसी तकनीकी खामी के चलते उड़ान भरने के महज पांच मिनट बाद ही हवाई अड्डे के जल शोधन संयंत्र के पास खड़े एक पेड़ से टकरा गया.

विमान में बैठी टेक्निकल टीम चॉपरों की मरम्मत के लिए रांची जा रही थी. विमान में सवार 10 लोगों में एक चालक (एसआईबी में सेकेंड-इन-कमांड रैंक अधिकारी), सह चालक (डिप्टी कमांडेंट), छह तकनीशियन, एक इंजीनियर और चालक दल का एक सदस्य शामिल था. बीएसएफ डीजी ने मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया.

कुल 11 सीटों वाला यह विमान वर्ष 1994-95 में बीएसएफ में शामिल किया गया था. सुपरकिंग को सीमा सुरक्षा बल में वर्ष 1994-95 में शामिल किया गया था.

सम्मलेन | बैठक

द्वितीय विश्व इंटरनेट सम्मेलन (डब्लूवाईसी) चीन के वुजेन शहर में संपन्न

तीन दिवसीय द्वितीय विश्व इंटरनेट सम्मेलन (डब्लूवाईसी) चीन के वुजेन शहर में 18 दिसंबर 2015 को संपन्न हुआ. वुजेन शहर पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में स्थित है.

यह सम्मेलन चीन के साइबरस्पेस प्रशासन और झेजियांग प्रांत के पीपुल्स सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया.

इस सम्मेलन में सभी देशों से इंटरनेट संप्रभुता का सम्मान, संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा की रक्षा, खुले दिमाग के साथ सहयोग और एक साथ मिलकर इंटरनेट गवर्नेस में सुधार के प्रयत्न हेतु आग्रह किया गया

यह सम्मेलन जिनेवा इंटरनेट मंच के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जो स्विट्जरलैंड की एक पहल है.

इस सम्मेलन में करीब 1200 घरेलू और विदेशी प्रतिभागियों ने इंटरनेट गवर्नेस और साइबर स्पेस सहयोग पर चर्चा की.

एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों की 14वीं बैठक ज़ेंगज़ो, चीन में आयोजित

शंघाई सहयोग संगठन (सीएसओ) में शामिल सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुखों की परिषद की दो दिवसीय 14वीं बैठक 15 दिसंबर 2015 को आयोजित की गयी. इसका आयोजन ज़ेंगज़ो में किया गया जो पूर्व-मध्य चीन में हेनान प्रांत की राजधानी है.

इसमें कजाखिस्तान के प्रधानमंत्री के मासिमोव, चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री टी सरिएव, रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेददेव, तजाखिस्तान के प्रधानमंत्री के रासुल्ज़ोदा एवं उज्बेकिस्तान के प्रथम उप प्रधानमंत्री आर अज़िमोव अपने-अपने देशों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे.

भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने भाग लिया. इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की.

उन्होंने आपसी समझ को और मजबूत बनाने एवं सदस्य राष्ट्रों के बीच पारंपरिक सहयोग बढ़ाने हेतु आर्थिक और मानवीय सहयोग की संभावनाओं और उपायों पर भी चर्चा की.

बैठक के अंत में, सदस्यों ने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर एक साझा बयान भी जारी किया जिसमें चीन की 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल के विकास एवं इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला गया.

शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) अथवा शंघाई पैक्ट एक अंतरसरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गयी. इसके संस्थापक छह राष्ट्र थे, चीन, कज़ाकिस्तान, किरगिज़, रूस, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान.
- इसके उद्देश्य हैं - सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना.
- राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक श्रेणियों में सहयोग बढ़ाना. साथ ही उर्जा, परिवहन, पर्यटन एवं पर्यावरण सुरक्षा पर भी सहयोग बढ़ाने हेतु इसका निर्माण किया गया है.
- इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग बनाये रखना.
- एशियन देशों के सहयोग से एक लोकतांत्रिक, न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाना.
- जुलाई 2015 में भारत और पाकिस्तान को इसकी पूर्ण सदस्यता प्रदान की गयी.
- चार पर्यवेक्षक राज्य हैं - अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया एवं ईरान.

भारत-लाओस: अंतर-सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

पर्यटन एवं संस्कृति राज्यं मंत्री (स्वसतंत्र प्रभार) महेश शर्मा ने 11 दिसंबर 2015 को 'भारत-लाओस: अंतर-सांस्कृतिक संबंध' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. यह सम्मेलन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली द्वारा श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ सरंक्षिणी महासभा, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया.

भारत और लाओस के सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों हेतु यह सम्मलेन आयोजित किया गया. जिनमें ऐतिहासिक संबंध; सांस्कृतिक संबंध; हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में धार्मिक संबंध; लाओस के संदर्भ में जैन धर्म का सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव; साहित्य और पुरालेख संबंध; और संपर्क स्थापित करने वाली कला, पुरातत्व, त्योहार इत्यादि प्रमुख हैं.

विदित हो कि भारत और लाओस सदियों से एक सांस्कृतिक विरासत साझा करते रहे हैं. भारतीय संस्कृति के विस्तार में व्यापार का सबसे अहम योगदान रहा है एवं व्यापारिक समुदाय, जो कि ज्यादातर जैन थे, ने जैन धर्म प्रचलन में लाया और तीर्थंकरों की पूजा की.

11वें यूआईसी वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ

रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने 9 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में दो दिवसीय 11वें यूआईसी वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन का शुभारंभ किया. इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (यूआईसी- जिसका मुख्यालय पेरिस में है) के सहयोग से भारतीय रेल सुरक्षा निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है. इस सम्मेलन का शीर्षक 'रेल प्रणालियों, अभियानों और व्यवसायिक गतिविधियों की सुरक्षा' है.

रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे. इस दो दिवसीय सम्मेलन में यूआईसी के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय रेल, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न देशों की रेलवे प्रणाली के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ (यूआईसी) के महानिदेशक जीन-पायरे लुबिनोक्स और सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया. यूआईसी के उपाध्यक्ष जरज़ी विसनिवस्की ने भी उद्घाटन सत्र में भाग लिया.

विदित हो कि यूआईसी विश्व सुरक्षा सम्मेलन के लिए विषयों को विचारों के आदान-प्रदान के आधार पर तैयार किया गया है ताकि प्रतिनिधि अपनी प्रणालियों में इन्हें कार्यान्वित करने के लिए इनकी जानकारी ले सकें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें जागरण फोरम को संबोधित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित जागरण प्रकाशन समूह द्वारा आयोजित 9वें जागरण फोरम को संबोधित किया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने डीस्कोर्सेज आफ डेमोक्रेसी (Discourses of Democracy) नामक पुस्तिक का भी विमोचन किया.

प्रधानमंत्री ने जागरण फोरम में अपने संबोधन के दौरान लोकतंत्र में जागरूकता के महत्व पर जोर देने के लिए 'सतत जागरूकता, स्वतंत्रता का मूल्य है' को उद्धृत किया. उन्होंने कहा जीवंत लोकतंत्र के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कैसे स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदल दिया. उन्होंने कहा कि 'जन आंदोलन' का यह मॉडल देश की विकास प्रक्रिया पर भी लागू किया जाना चाहिए.

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन, स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की भागीदारी और रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने के अभियान के उदाहरण दिए. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे प्रधानमंत्री जन-धन योजना और 'स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया' पहल सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रही है. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन' यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण की व्याख्या की.

विविध

नौकरशाहों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार प्रारंभ करने हेतु नए नियम की घोषणा

केंद्र सरकार ने नौकरशाहों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार प्रारंभ करने हेतु नए नियम की 21 दिसंबर 2015 को घोषणा की. इसके तहत उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार शुरू करने से पहले खासकर अपनी ईमानदारी और एनजीओ के साथ लेनदेन को लेकर स्पष्ट सेवा रिकॉर्ड घोषित करने की जरूरत होगी.

उपरोक्त के साथ ही साथ व्यावसायिक रोजगार प्रारंभ करने वाले सेवानिवृत्ति नौकरशाहों को यह भी उल्लेख करना होगा कि प्रस्तावित वेतन और आर्थिक लाभ का प्रस्ताव उद्योग मानकों के अनुरुप है. नए नियमों में सरकार से किसी व्यावसायिक रोजगार की पूर्व अनुमति मांगने की अवधि भी दो साल से घटाकर एक साल कर दी गई है. इसके साथ ही अधिकारियों को संशोधित आवेदन में यह घोषणा करनी होगी कि जिस संगठन में वे नौकरी मांग रहे हैं वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं है जिसका भारत के विदेश संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू सद्भाव के साथ टकराव हो.

उपरोक्त नए नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) समेत दूसरे अधिकारियों पर लागू होंगे. यह कदम इस लिहाज से अहम है क्योंकि सरकार नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इनमें से कुछ पर ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप हैं जो देश के आर्थिक विकास में रुकावट बन रही हैं.

नमामि गंगे परियोजना हेतु जल संसाधन मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया

नमामि गंगे परियोजना की सफलता हेतु जल संसाधन मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ 9 दिसंबर 2015 को एक समझौता किया. गंगा नदी को अविरल एवं स्वच्छ बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई है.

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्री उमा भारती ने नमामि गंगे कार्यक्रम की सफलता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ दीर्घकालिक सहयोग हेतु समझौता किया. जिसके तहत नमामि गंगे कार्यक्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका सुनिश्चित की जा सके. इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट का पुनर्उपयोग, गंगा पर केन्द्रित करते हुए पर्यावरण पर व्यस्क शिक्षा, सर्वाधिक प्रदूषित उपनदियों, रामगंगा, काली और यमुना के लिए खासतौर पर विकास परियोजनाएं, ई-प्रभा और जनभागीदारी का निर्धारण शामिल है.

बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के सम्मान में 125 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिसम्बर 2015 को डॉ बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर 125 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किये.

डॉ बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर

- उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश स्थित म्हाओ में हुआ.
- वे एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और सामाजिक सुधारक थे.
- उन्होंने आधुनिक बौद्ध आन्दोलन एवं दलित समाज के विरुद्ध हो रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया तथा महिलाओं एवं मजदूरों के हित की भी बात की.
- वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे तथा संविधान निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी.
- वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया.
- उनके सम्मान में विभिन्न स्मारकों का निर्माण किया गया.

टीडीएस का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा के प्रावधान संबधी सर्कुलर को 3 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया.

इसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वेतन पर टीडीएस के बारे में वार्षिक सर्कुलर को अधिसूचित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के वेतन से आयकर कटौती करने में विफल रहने तथा भुगतान में डिफॉल्ट करने पर उतनी ही राशि का जुर्माना देना पड़ेगा.

सीबीडीटी के सर्कुलर में कहा गया है कि धारा 276बी के तहत अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के पास तय समय में स्रोत पर कर कटौती जमा करने या उस पर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे तीन माह से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. सर्कुलर में कहा गया है कि संबंधित तिमाही के टीडीएस की तिमाही रिपोर्ट जमा करने से पहले ब्याज का भी भुगतान करना होगा.

विश्व समसामयिकी दिसंबर 2015

1 दिसम्बर 2015

- रूसी फ़िल्मकार एल्डर रयाज़ानोव का निधन
- हिंदुजा ब्रदर्स को एशियन बिज़नेस लीडरशिप फोरम 2015 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया

2 दिसम्बर 2015

- ब्रिक्स देशों का पहला मीडिया शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित
- जर्मनी की कैबिनेट ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ सैन्य सहायता को मंजूरी दी
- रोच मार्क क्रिस्टियन काबोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति निर्वाचित
- एंब्रेस ऑफ द सर्पेंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार
- आईसीबीसी बना टाटा समूह का रणनीतिक सहयोगी

3 दिसम्बर 2015

- आईएमएफ ने चीन की मुद्रा युआन को विशिष्ट वर्ग आरक्षित मुद्रा के रूप में मंजूरी दी
- ब्राज़ील में दीर्घ आर्थिक मंदी का दौर
- भारत और फ्रांस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारम्भ
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा हेतु भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान के साथ डीटीएसी समझौते को मंजूरी प्रदान की
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग पर इजरायल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु विश्व के उद्योगपतियों ने समझौता किया
- विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया
- विश्वस्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया
- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सैंडी बर्गर का निधन
- रॉबर्ट लेवांडोवस्की को नौ मिनट में पांच गोल करने पर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया

4 दिसम्बर 2015

- अमेरिकी सेना में सभी लड़ाकू भूमिकाएं निभाएंगी महिलाएं
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीजा सुविधा पर भारत और ईरान के बीच समझौता करने को मंजूरी दी
- भारतीय मूल की अमेरिकी डॉ विजय एम राव आरएसएनए की अध्यक्ष नियुक्त
- संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एचआईवी (एड्स) के प्रसार पर रिपोर्ट जारी
- जल और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर पेरिस संधि की घोषणा

5 दिसम्बर 2015

- चीन में बिजली संचालित प्रथम विमान आरक्स 1 ई (RX1E) के उत्पादन को मंजूरी दी
- विश्व स्तर पर मनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस
- डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक खाद्य जनित रोगों पर रिपोर्ट जारी की
- ओला ने किया दुनिया की चार दिग्गज कंपनियों के साथ करार

6 दिसम्बर 2015

- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर शीर्ष पर
- ईंधन के रूप में इथेनॉल से बेहतर बुटेनॉल: शोध

7 दिसम्बर 2015

- बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए परिवर्तनकारी कार्बन एसेट सुविधा शुरू की गयी
- भारत को कनाडा से यूरेनियम की पहली खेप प्राप्त
- एटलस वी रॉकेट सिग्नस कार्गो अंतरिक्ष यान आईएसएस के लिए लांच
- ईंधन के रूप में इथेनॉल से बेहतर बुटेनॉल: शोध
- भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया
- ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी विश्व लीग फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराया
- भारत ने जीता इंडो-पाक निःशक्त क्रिकेट सीरीज
- बुब्बा वाटसन हीरो वर्ल्ड चैलेंज चैम्पियन बने

8 दिसम्बर 2015

- बीजिंग में पहली बार वायु प्रदूषण पर रेड अलर्ट जारी
- 100 मिलियन हेक्टेयर वन की पुनर्स्थापना के लिए अफ्रीकन रेस्टॉरेशन इनिशिएटिव का शुभारम्भ

9 दिसम्बर 2015

- एंटी-कैंसर अणुओं की खोज
- फीफा रेफरी एसके भट्टाचार्य का निधन
- क्रिसन इल्युमज़िनोव ने विश्व शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दियास्पेन की कैरोलीन बनीं साल की सर्वश्रेष्ठ महिला बैडमिंटन खिलाड़ीअंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने टायसन फ्यूरी से विश्व आईबीफ खिताब वापस लिया
- ओप्पोसीशन डेमोक्रेटिक यूनिटी राउंड टेबल ने वेनेजुएला संसद चुनाव में जीत दर्ज की.
- न्यूजीलैंड औपचारिक रूप से एआईआईबी का नया सदस्य बना

10 दिसम्बर 2015

- मेक्सिको ने विश्व के पहले डेंगू टीके को मंजूरी प्रदान की
- यस बैंक द्वारा क्लाइमेट एक्शन के लिए 2020 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यवस्था की घोषणा
- म्यांमार ने यांगून स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन किया
- क्रूगर वैन वाइक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की
- चेन लॉन्ग एवं कैरोलिना मरीन ने वर्ष 2015 का बीडब्ल्यूएफ प्लेयर अवार्ड जीता
- महेला जयवर्धने एमसीसी के मानद आजीवन सदस्य के रूप में चयनित
- वर्ष 2016 को इंग्लैंड-भारत शिक्षा अनुसंधान एवं नवाचार वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया
- अमेरिकी सदन ने वीजा वीवर प्रोग्राम इंप्रूवमेंट एक्ट ऑफ 2015 को पारित किया

11 दिसम्बर 2015

- भारत एवं जापान के बीच दोहरे कराधान समझौते में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीन में प्रताड़ना के खिलाफ अपील जारी
- भारत-पाकिस्तान ने 8 सूत्रीय समग्र वार्ता को 10 सूत्रीय व्यापक द्विपक्षीय वार्ता से बदलने पर सहमति जताई
- आईसीसी टी-20 विश्वकप 2016 का कार्यक्रम घोषित
- यूएन ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के लिए 'साहेल ह्यूमेनिटेरियन अपील फॉर 2016' का शुभारम्भ किया

12 दिसम्बर 2015

- देबोरा हेरल्ड विश्व रैंकिंग में भारत की पहली और विश्व की चौथी साइकिल चालक बनीं

13 दिसम्बर 2015

- जापान की नोजोमी ओकुहरा, केंटो मोमोता ने वर्ल्ड दुबई सुपर सीरीज फाइनल का एकल खिताब जीता

14 दिसंबर 2015

- फिलिपींस में 'मेलर तूफान' के कारण नौवहन बंद और अलर्ट जारी
- विश्व बैंक ने शॉक वेव्स : मैनेजिंग द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पोवर्टी नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की
- खेल पत्रिका स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने सेरेना विलियम्स को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना
- अमेरिका और चीन के खोजी दल ने डायनासोर की नयी प्रजाति का पता लगाया
- भारतीय मूल के प्रवीण गोरधन दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री नियुक्त
- यूएनडीपी ने वर्ष 2015 की मानव विकास रिपोर्ट जारी की
- वायलिन वादक इत्जहक पर्लमैन ने जीता वर्ष 2016 का जेनेसिस पुरस्कार

15 दिसंबर 2015

- आतंकवाद के विरुद्ध सऊदी अरब ने की 34 देशों के गठबंधन की घोषणा
- आईएईए ने ईरान परमाणु कार्यक्रम पर 12 वर्ष लम्बी जांच समाप्त की
- रोरी मैक्लराय ने यूरोपियन टूर गोल्फर आफ द ईयर का खिताब जीता
- एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों की 14वीं बैठक ज़ेंगज़ो, चीन में आयोजित
- पाकिस्तान ने शाहीन 1-ए प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया

16 दिसंबर 2015

- भारत और स्पेन के बीच बंदरगाह मामलों में सहयोग हेतु समझौते पत्र को मंजूरी
- ब्रिटिश उपन्यासकार पीटर डिकिंसन का निधन

17 दिसंबर 2015

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से आईएस की धन की आपूर्ति रोकने का फैसला किया

- रिलायंस इंटरटेनमेंट तथा ड्रीमवर्क्स ने फिल्म निर्माण कंपनी एंबलिन पार्टनर्स के गठन की घोषणा की

18 दिसंबर 2015

- विश्वस्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया
- डैन कार्टर वर्ष 2015 के 'बीबीसी ओवरसीज़ स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी ऑफ़ द इयर' चुने गए
- ग्रीक टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर जेकुपोविक पर लगा आजीवन प्रतिबंध
- द्वितीय विश्व इंटरनेट सम्मेलन चीन के वुजेन शहर में संपन्न
- जेफ विलियम्स एप्पल इंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त

19 दिसंबर 2015

- प्रसिद्ध जर्मन कंडक्टर कर्ट मसूर का निधन

20 दिसंबर 2015

- मिस स्पेन मिरिया लालागुना रायो 'मिस वर्ल्ड 2015' चुनी गईं
- सिंगापुर स्लैमर्स ने अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग 2015 का खिताब जीता
- शाइमा कासिम अब्दुलरहमान मिस इराक 2015 चुनी गईं
- फिलीपींस की पिया अलोंज़ो वर्त्ज़बैक मिस यूनिवर्स-2015 बनीं
- एंडी मरे वर्ष 2015 के 'बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ़ द इयर' चुने गए

21 दिसंबर 2015

- यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध की अवधि को छह महीने बढ़ाया
- अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने सेप ब्लेटर और माइकल प्लातिनी पर आठ वर्ष का प्रतिबंध लगाया
- दारियास चेनाई ने 59वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरूषों की ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता

- अमेरिकी सीनेट द्वारा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने हेतु आईएमएफ के सुधारों को स्वीकृति
- एंडी मरे वर्ष 2015 के 'बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ़ द इयर' चुने गए
- अभय सिंह ने जीता सिंगापुर ओपन का खिताब
- टाटा मोटर्स शोध एवं विकास में निवेश के मामले में दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों की सूची में शामिल
- युजेंसन लिंगदोह और बाला देवी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में सम्मानित
- आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले पहले कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन बने
- वर्ष 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा
- फुटबॉल क्लब बार्सीलोना ने फीफा क्लब विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट का खिताब जीता
- द्वितीय विश्व इंटरनेट सम्मेलन (डब्लूवाईसी) चीन के वुजेन शहर में संपन्न
- सिंगापुर स्लैमर्स ने अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग 2015 का खिताब जीता
- शाइमा कासिम अब्दुलरहमान मिस इराक 2015 चुनी गईं
- फिलीपींस की पिया अलोंज़ो वर्त्ज़बैक मिस यूनिवर्स-2015 बनीं
- मिस स्पेन मिरिया लालागुना रायो 'मिस वर्ल्ड 2015' चुनी गईं

22 दिसम्बर 2015

- स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस और भारत की सानिया मिर्जा को महिला डबल्स विश्व चैंपियन चुना गया.
- स्पेन के आम चुनाव में कंजरवेटिव पीपुल्स पार्टी ने जीत दर्ज की
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने तालिबान पर लगे प्रतिबंधो को विस्तारित किया
- रॉनी स्क्रूवाला की कम्पनी एर्री ने अपाल्या टेक्नोलॉजीज़ का अधिग्रहण किया
- न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने की सन्यास की घोषणा
- याहू ने वर्ष 2015 में सर्वाधिक चर्चित रहे मुद्दों, घटनाओं और आयोजनों की वार्षिक समीक्षा के तहत यह सूची जारी की.
- स्पेस एक्स ने फेल्कन 9 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण और अवतरण किया

- श्रीलंका पर आसान जीत के साथ ट्राई सीरीज पर भारतीय अंडर-19 का कब्जा
- नेपाल सरकार मधेसियों की समस्या हल करने हेतु संविधान में संशोधन के लिए सहमत
- फेड कप में भारत का नेतृत्व करेंगी सानिया मिर्ज़ा

23 दिसंबर 2015

- जिम्बॉब्वे ने चीनी मुद्रा युआन को आधिकारिक तौर पर अपनाने की घोषणा की
- माइकल ब्रैडली अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबाल खिलाड़ी घोषित
- ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में पांच हजार करोड़ रूपये के निवेश को मंजूरी
- 12 करोड़ साल पुराने टिड्डे का जीवाश्म मिला
- मेक इन इंडिया: विवो ने ग्रेटर नोएडा में पहला प्रोडक्शजन प्लां ट लगाया
- स्टीव स्मिथ वर्ष 2015 के आईसीसी क्रिकेटर ऑफ़ द इयर चुने गए
- चीन ने डीएएमपीई उपग्रह का प्रक्षेपण किया
- सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी महिला युगल विश्व चैम्पियन घोषित
- आईटीएफ ने अमेरिका की सेरेना विलियम्स और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को वर्ष 2015 का आईटीएफ विश्व चैम्पियन घोषित किया.
- ब्रुनेई में क्रिसमस मनाये जाने पर प्रतिबन्ध
- डेंगू के टीके को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना फिलिपीन्स

24 दिसंबर 2015

- भारतीय मूल के अमेरिकी राकेश के जैन अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान पदक 2015 के लिए चयनित
- विप्रो ने अमेरिकी कंपनी विटिओस का अधिग्रहण करने की घोषणा की
- गौतम एच बंबावाले पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त
- योनेक्स ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न

25 दिसंबर 2015

- जापान की पर्वतारोही केई तानीगुची की चढ़ाई करते वक्त गिरने से मौत
- संजीता, रमन्ना को राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल

26 दिसंबर 2015

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में अफगानिस्तान संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया
- रूस के भारोत्तोलक अलेक्सी लवचेव अस्थायी रूप से निलंबित
- भारत और रुस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए
- रिलांयस डिफेन्स लिमिटेड और रूस अलमाजआंते के बीच एयर डिफेन्स मिसाइल प्रणाली विकसित करने हेतु समझौता

27 दिसंबर 2015

- चीन ने पहला आतंकवाद रोधी कानून पारित किया
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काबुल में अफगानिस्तान संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया
- भारत और रुस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

28 दिसंबर 2015

- गोल्फर एस चिक्कारंगाप्पा ने मैक्लोरॉड रासेल टूर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता
- भारत के ल्यूज खिलाड़ी शिवा केशवन ने एशियाई लूज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता
- चीन ने पहला आतंकवाद रोधी कानून पारित किया
- चीन ने किया संशोधन नए साल से दो बच्चे पैदा करने की छूट
- फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का ख़िताब जीता
- सत्यवती बरेरा बिग फोर समूह की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त

- ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 शतक बनाने वाली पहली टीम बनीं
- एंटी-डोपिंग टेस्ट में पॉज़ीटिव पाए जाने के बाद पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह निलंबित
- वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत: सीईबीआर रिपोर्ट
- स्टार ट्रेक के लेखक जॉर्ज क्लेटन जॉनसन का निधन

29 दिसंबर 2015

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी देश गिनी को इबोला मुक्त घोषित किया
- जलवायु परिवर्तन से संबंधित चार परियोजनाओं को मंजूरी

30 दिसंबर 2015

- रूस ने कामोव 226टी हेलीकाप्टर बनाने के लिए एचएएल के साथ समझौता किया

31 दिसंबर 2015

- शहरी विकास मंत्रालय और ब्लूम्बर्ग फिलेंथ्रोपीज़ के बीच स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु समझौते को मंजूरी

भारत समसामयिकी दिसंबर 2015

1 दिसम्बर 2015

- कांग्रेस विधायक सदानंद सिंह ने बिहार विधानसभा के प्रो-टेम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली
- 46वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सम्पन्न
- केंद्र सरकार ने आईपीवी इंजेक्शन का शुभारंभ किया
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा डॉ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड प्रदान किये गये
- अनिल कुंबले का मुंबई इंडियंस के 'चीफ मेंटर' पद से इस्तीफा

2 दिसम्बर 2015

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'ज्ञान' योजना का शुभारम्भ
- सरकार ने पीएफ निकालने में ख़त्म किया नियोक्ता का हस्तक्षेप
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि
- ठाकुर अनूप सिंह ने मिस्टर वर्ल्ड-2015 का खिताब जीता
- सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान का निधन
- कूडियाट्टम् कलाकार मार्गी साथी का निधन
- विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए
- सर वेंकटरमन रामकृष्णन ने रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया
- प्रख्यात वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम आईटीसी संगीत सम्मान से सम्मानित
- रेल मंत्रालय ने वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन योजना (एटीएएस) 'विकल्प' प्रारंभ की

3 दिसम्बर 2015

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नए आईआईटी को मंजूरी प्रदान की
- एक्सिस बैंक द्वारा देश के पहले डिस्प्ले डेबिट कार्ड का शुभारम्भ
- उद्योगपति एमएएम रामास्वामी का निधन
- न्यायमूर्ति तीरथ सिंह (टीएस) ठाकुर ने भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली
- एडिडास इंडिया के पुलिन कुमार प्रतिष्ठित आईएनबीए पुरस्कार से सम्मानित
- विकलांगो के लिए फिल्म महोत्सव की घोषणा
- स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को गति देने के लिए मिशन इनोवेशन का शुभारंभ
- अमेरिकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी अरिसेंट ने नैसकॉम फाउंडेशन के साथ समझौता किया

4 दिसम्बर 2015

- टीडीएस का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान
- भारतीय मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय मानक निकाय बनाने के लिए विधेयक पारित
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश एन्क्लेव के लिए पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी
- एनटीसी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता किया
- आईफा उत्सवम' चेन्नई में वर्षा के कारण स्थगित
- प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईटी-दिल्ली में प्रारंभ
- केंद्र सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की
- एमओईएफ द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम 2015 जारी
- गेल ने पाइपलाइनों की निगरानी के लिए 'भूवन गेल पोर्टल' का शुभारम्भ किया

5 दिसम्बर 2015

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया

6 दिसम्बर 2015

- देश की पहली डबल डेकर गोवा-मुंबई शताब्दी रेलगाड़ी शुरू

7 दिसम्बर 2015

- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर शीर्ष पर
- देश की पहली डबल डेकर गोवा-मुंबई शताब्दी रेलगाड़ी शुरू
- उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुआ राज्य का पहला 'बर्ड फेस्टिवल'

8 दिसम्बर 2015

- लोकसभा में परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तावित
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांगों की श्रेणी में रखने का निर्देश
- आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र के लिए संशोधित ऋण मानदंडों की घोषणा की
- पंजाब मार्शल टीम ने चैपियंस टेनिस लीग-2015 का ख़िताब जीता
- टेनिस लीग के फाइनल में पंजाब ने हैदराबाद एसेस को हराकर खिताब अपने नाम किया.
- प्रीमियर बैडमिंटन लीग हेतु खिलाडियों की नीलामी में साइना और ली चोंग वेई सबसे महंगे खिलाड़ी बनें
- आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने गैरी कर्स्टन को मुख्य प्रशिक्षक पद से हटाया
- भारत के वन क्षेत्रों में 5081 वर्ग किमी का विस्तार : भारत राज्य वन रिपोर्ट

9 दिसम्बर 2015

- सार्वजनिक ऋण में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि
- एमएसडीई एवं डीएचआई ने विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
- पुणे और राजकोट सीएसके एवं आरआर के स्थान पर आईपीएल की अंतरिम फ्रैंचाइज़ी चयनित

- प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में प्रस्तावित सम - विषम नंबर प्लेट योजना

10 दिसम्बर 2015

- भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर को अमेरिकी सेना से सौर पैनल पर अनुसंधान और विकास हेतु अनुबंध प्राप्त
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण उद्योग के लिए 4000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2015 को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी
- रोहित शर्मा प्रो रेस्लिंग लीग में यूपी वरियर्स के सह-मालिक बनें

11 दिसम्बर 2015

- केंद्र सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटाकर 400 डॉलर प्रति टन किया
- भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट: पोषण 2015 जारी

12 दिसम्बर 2015

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को स्थायी और सांविधिक निकाय बनाने की सिफारिश
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 'भारत के राष्ट्रपति की वेबसाइट' पर बच्चों के खंड का आरंभ
- एलिज़ाबेथ कोशी ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

13 दिसम्बर 2015

- विजय कुमार ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

14 दिसंबर 2015

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
- नैटको, हेटेरो को हेपेटाइटिस सी की जेनेरिक दवा बाजार में लाने की मंजूरी दी
- इनफ़ोसिस ने "स्टार्टअप" में 20 करोड़ रुपए निवेश किया
- टेक महिंद्रा एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिनिनफेरिना का अधिग्रहण किया
- ऊर्जा संरक्षण के तहत उप्र सरकार ने नया पोर्टल शुरू किया
- पश्चिम बंगाल सरकार ने बप्पी लाहिड़ी, कुमार सानू को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया
- वन रैंक वन पेंशन के लिए न्यायिक समिति का गठन

15 दिसंबर 2015

- शिवा, मंदीप एवं अन्य चार भारतीय मुक्केबाज आईओसी छात्रवृत्ति हेतु चयनित
- अपूर्वी चंदेला और चैन सिंह ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता
- लाहिड़ी बने एशियन टूर जीतने वाले चौथे भारतीय गोल्फर
- सीआईआई-आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2015 की घोषणा
- सीआईआई औद्योगिक नवाचार पुरस्कार 2015 की घोषणा
- स्नैपडील ने हिंदी एवं तेलगु में मोबाइल वेबसाइट आरंभ की
- ग्रीनपीस ने 17 भारतीय शहरों के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया
- देश के विश्वविद्यालयों में पटाखों से प्रदूषण पर होगी पढ़ाई
- वरिष्ठ राजनयिक अखिलेश मिश्रा मालदीव में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त
- ए के जैन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुख्य अधिकारी नियुक्त
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सिंगापुर के छह उपग्रहों को प्रक्षेपित किया

16 दिसंबर 2015

- छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 47.1 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत हुई

- विश्व बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण को मंजूरी दी
- आईआईएसएल ने देश के तीन प्रमुख व्यापारिक घरानों के लिए सूचकांकों की शुरुआत की
- खाद्य भुगतान के लिए आईआरसीटीसी और पेटीएम के मध्य समझौता
- अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित
- 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया गया
- न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल ने दिल्ली के लोकायुक्त पद की शपथ ली
- द बोस ब्रदर्स एंड इंडियन इंडिपेंडेंस-एन इनसाइडर्स अकाउंट : माधुरी बोस
- गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद मुख्य अतिथि होंगे

17 दिसंबर 2015

- यूएसएफ ने राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम स्नातकोत्तर फैलोशिप आरम्भ की
- हॉकी इंडिया लीग का प्रायोजक होगा कोल इंडिया लिमिटेड
- मुख्यमंत्री ने लगभग 585 करोड़ की 148 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया
- लोकसभा में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 को पारित
- ललित मोदी पुन: आरसीए अध्यक्ष नियुक्त
- पूर्व माकपा सांसद नुरुल हुदा का निधन
- केयर्न इंडिया सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित
- भारत ने रूस से रक्षा प्रणाली खरीद समझौते को मंजूरी दी
- पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर नए सीआईसी नियुक्त

18 दिसंबर 2015

- सुनील जोशी ओमान टीम के गेंदबाजी कोच नियुक्त
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग पर लगाया प्रतिबन्ध

- भारतीय पुरुष टीम ने 20वीं अवध राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण
- भारत संयुक्त राष्ट्र के आपात प्रतिक्रिया कोष में पांच लाख डॉलर का योगदान देगा
- मनोज प्रभाकर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाज़ी कोच नियुक्त

19 दिसंबर 2015

- उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उदय योजना में शामिल हुआ

20 दिसंबर 2015

- चेन्नईयन एफसी ने इंडियन सुपर लीग 2015 का खिताब जीता
- युजेंसन लिंगदोह और बाला देवी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में सम्मानित
- वस्त्र मंत्रालय ने एनएचडीसी की ईआरपी प्रणाली की शुरुआत की

21 दिसंबर 2015

- वित्त वर्ष 2015-16 में आयकर दाताओं की संख्या में 27 लाख की वृद्धि
- चेन्नईयन एफसी ने एफसी गोवा को हराकर इंडियन सुपर लीग खिताब जीता
- उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उदय योजना में शामिल हुआ

22 दिसम्बर 2015

- राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 को मंजूरी दी
- राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 लोकसभा में पारित
- एलएनजी पोत बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को लाइसेंस दिया
- गुजरात झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए पीपीपी परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2014-15 जारी

- राज्यसभा द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक-2015 पारित
- पर्यावरण नियंत्रण हेतु नोएडा-एनसीआर सात जोन में विभाजित

23 दिसंबर 2015

- नौकरशाहों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार प्रारंभ करने हेतु नए नियम की घोषणा
- भारतीय रेल आईआईटी के साथ शोध केंद्र स्थापित करेगा
- पवन कुमार अग्रवाल एफएसएसएआई के सीईओ नियुक्त
- बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय योजना लागू करने का निर्णय लिया
- जेट एयरवेज़ ने अमित अग्रवाल को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण-1ए को मंजूरी दी
- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की
- पश्चिम बंगाल के तट पर ईल की नई प्रजाति जिमनोथोरेक्स मिश्रई खोजी गई
- ग्रॉसरी शॉपिंग सेवा पेपरटेप ने बेंगलुरु की डिलीवरी स्टार्टअप जिफसौर का अधिग्रहण किया
- फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और सांसद हेमामालिनी हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एंबेसडर नियुक्त
- सलमा बांध के निर्माण की संशोधित लागत को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

24 दिसंबर 2015

- मानव मूत्र से पैदा की जा सकेगी बिजली
- पेंडोरम टेक्नोलॉजी ने 3 डी प्रिंटिंग का उपयोग करते हुए भारत का पहला कृत्रिम वृक्क ऊतक विकसित किया
- लोकसभा द्वारा बोनस भुगतान संशोधन विधेयक-2015 को मंजूरी दी गयी
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु पटना में प्रतिबंधित की जाएंगी 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां
- केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों के लिए दो मोबाइल एप्प लांच किएआईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग हेतु आईआरसीटीसी के साथ गठबंधन किया

- पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने पांच ब्रांड्स का अधिग्रहण किया
- डब्ल्यू वी रमन, नरेंद्र हिरवानी और टी ए शेखर एनसीए के कोच नियुक्त

25 दिसंबर 2015

- आइडिया भारत में 4जी सेवा शुरू करने वाला तीसरा मोबाइल ऑपरेटर बन
- हिन्दी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना का निधन गया
- पूर्व भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी कर्नल सी के नायडू पुरस्कार के लिए चयनित

26 दिसंबर 2015

- पर्यटकों का पसंदीदा राज्य बना उत्तरप्रदेश: एसोचैम
- कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएस मालिमत का निधन
- डिजिटल सेवाएं: देश में छत्तीसगढ़ प्रथम, 28 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार
- भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस गोदावरी सेवानिवृत्त

27 दिसंबर 2015

- उत्तर भारत के पहले केबल पुल का जम्मू-कश्मीर के बसोहली में उद्घाटन
- विकास ठाकुर ने भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया

28 दिसंबर 2015

- आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रौद्योगिकी पहल हेतु माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- भारत पेट्रोलियम की नई क्रूड डिस्टीलेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित
- इंदौर: 15,000 से अधिक लोगों ने एक साथ साइकिल चलाकर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड
- अस्त्र मिसाइल की महत्वपूर्ण एंटी जैमिंग क्षमता का सफल परीक्षण

- कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में 99 प्रतिशत मतदान का राष्ट्रीय रिकार्ड बना
- केंद्र सरकार ने चार आईटी-आधारित स्वास्थ्य सेवा पहलों की घोषणा की
- सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को संपूर्ण भारत में मनाया गया

29 दिसंबर 2015

- केरल सरकार के शराब बिक्री नियमन पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति
- पीपीपी मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट जारी
- भारतीय सेना ने 28 दिसंबर 2015 को 44वां नागी दिवस मनाया
- अमिताभ कांत को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया
- गुजरात ने दिल्ली को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता

30 दिसंबर 2015

- वरिष्ठ गायक सुबीर सेन का निधन

31 दिसंबर 2015

- राष्ट्रीय पुस्तकालय को संस्कृति मंत्रालय द्वारा 400 करोड़ रूपये की मंजूरी
- लक्ष्मी रतन शुक्ला का क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा
- भेल ने उत्तर प्रदेश में 660 मेगावाट की प्रयागराज सुपर तापीय बिजली परियोजना प्रारंभ की

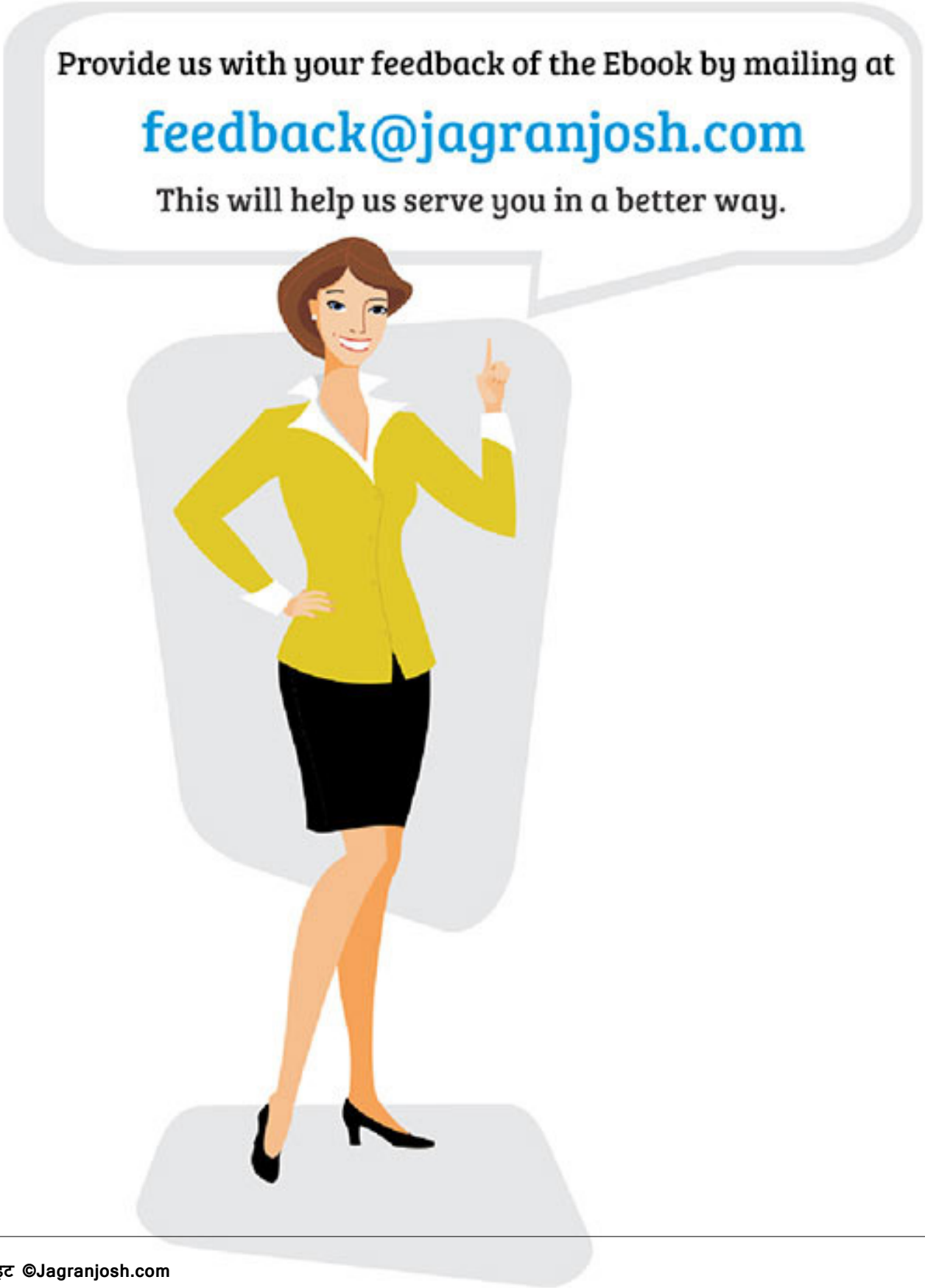

कॉपीराइट ©Jagranjosh.com

सर्वाधिकार सुरक्षित. इस ई-बुक का कोई भी खण्ड या संपूर्ण ई-बुक को किसी भी रूप में (इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी भी अन्य माध्यम से) प्रतिलिपिकरण, पुनःप्रकाशन, पुनःप्राप्ति योग्य भण्डारण और किसी भी घटना, परिस्थिति और प्रणाली में उल्लेख तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि कॉपीराइट प्राप्तकर्ता से लिखित अनुमति न प्राप्त हो. यदि उपरोक्त में से कोई भी या संबंधित गतिविधि का कोई भी प्रमाण मिलता है या सूचित किया जाता है तो कड़ी दण्डात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.